राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 3 **सोलहवीं विधान सभा के तीसरे सत्र का पैंतीसवां दिवस** संख्या: 16

गुरुवार,
06 मार्च 2025

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल। श्री अमित चाचाण।

तारांकित प्रश्नोत्तर

हनुमानगढ़ जिले में तस्करी के दर्ज प्रकरण

304. श्री अमित चाचाण (नोहर)(श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर) के स्थान पर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला हनुमानगढ में विगत तीन वर्षों में चिठ्ठा मादक पदार्थ की तस्करी के कितने प्रकरण दर्ज हुए? उक्त दर्ज प्रकरणों में कितने अपराधियों को गिरफ्तार किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ड्रग्स की तस्करी रोकने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, गृह (श्री जवाहरसिंह बेढ़म): (1) जिला हनुमानगढ में विगत 03 वर्षों में चिट्टा मादक पदार्थ की तस्करी के कुल 404 प्रकरण दर्ज हुए हैं।

उक्त दर्ज 404 प्रकरणों में 894 मुलज़िमों को गिरफ्तार किया गया तथा 354 प्रकरणों में चालान न्यायालय में पेश किये गये व 50 प्रकरण अनुसंधानाधीन है। विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। सरकार द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिये किये गये प्रयासों/कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है।

श्री अमित चाचाण (नोहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर व गैर राजनीतिक मुद्दा है। नशे की बदौलत आज हमारे समाज में रिश्ते तार-तार हो रहे हैं, बेटा बाप को मार रहा है, बाप पत्नी को मार रहा है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछो।

श्री अमित चाचाण (नोहर): मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं, साहब। नशे की हालत यह है कि सारा क्राइम नशे की वजह से हो रहा है चाहे चोरी हो, डकैती हो, हत्या हो। कार्यवाही तो मैं कह रहा हूं कि कर रहे हैं हनुमानगढ़ जिले में लेकिन यह नाममात्र की है। जिस तरह से आपने बताया कि 2022 में 2023 में और 2024 में, 136 एफ.आई.आर. हुई और 138 हुई। यह मात्र इसकी एवरेज देखें तो 3.771 किलोग्राम, 3.896 किलोग्राम, मात्र 30 ग्राम की एवरेज आ रही है। यह कार्यवाही करने के लिये सिर्फ इनको गिरफ्तार किया जाता है। जमानत योग्य इन पर मुकदमा बनाया जाता है जो तस्कर हैं सप्लायर हैं उनको आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछो।

श्री अमित चाचाण (नोहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि मात्र इसमें सिर्फ जो जमानत योग्य मुकदमे बनाये जा रहे हैं क्या विशेष अभियान चला कर जो सप्लाई कर रहे हैं नशा, क्योंकि यह महंगा नशा है जिससे पूरे युवा हमारे हनुमानगढ़ जिले के कई परिवारों ने अपने युवाओं को खोया है, अपने बेटे को खोया है, उनकी हत्या हुई है, उनकी मृत्यु हुई है नशे की बदौलत तो मंत्री महोदय, आप यह बतायें कि क्या विशेष अभियान चला कर जो सप्लायर हैं जो बड़ी सप्लाई कर रहे हैं उनको गिरफ्तार करने का भी आप अब कोई अभियान चलायेंगे क्या?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है वह निश्चित रूप से राजस्थान में जिस तरह से युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ी है उसको रोकने के लिये समय-समय पर सरकारों ने विभिन्न परिपत्र जारी करके अभियान चला करके इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये समाज में भी अवेयरनेस कैम्प लगाने की कोशिश की है, प्रयास किये हैं, लगाये हैं और प्रशासनिक स्तर पर मुकदमे दर्ज कर उनमें कार्यवाहियां की गई हैं। हमने पूर्व में भी विशेष अभियान चला कर के अपराधियों को गिरफ्तार किया है, चालान पेश किये हैं। अवैध मादक पदार्थों को जब्त करके उनके खिलाफ कार्यवाही भी की है और मैं सदन को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि अवैध मादक पदार्थों ही नहीं जो भी अपराध राजस्थान में घर करते जा रहे हैं उनके खिलाफ सरकार पूरी सजग है और विशेष अभियान चला करके अपराधियों के खिलाफ मादक पदार्थों में भी और अन्य अपराधों में कार्यवाही करने के लिये दृढ़ संकल्पित हैं।

श्री अध्यक्ष: पहले उनका कोई है क्या दूसरा पूरक?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे आग्रह है क्योंकि बहुत ही गम्भीर यह प्रकरण है और गम्भीर विषय है। मेरे दो प्रश्न हैं। पहला तो यह है क्या इस प्रकार के मामलों में पुलिस गठजोड़ की शिकायतें प्राप्त हुई हैं क्या? नम्बर 1, नम्बर 2 - चूंकि नशा लगातार बढ़ता जा रहा है इसको रोकने की सरकार की कोई कार्ययोजना है क्या? आपने क्या प्लानिंग की है वो आप बताइये?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जी ने अपना पूरक प्रश्न इसमें पूछा है, निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार ने समय-समय पर और माननीय उच्च न्यायालय ने भी स्वत: संज्ञान लेकर एडवाइजरी जारी करने का काम किया है। हमारे डी.जी. साहब की ओर से, सरकार की ओर से विशेष अभियान चला करके विशेष टीमें गठित करके इनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये ये परिपत्र जारी किये हैं। मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। दूसरा जो आपका है पुलिस गठजोड़ का, मेरे संज्ञान में अभी तक ऐसी कोई बात आयी नहीं है। यदि आपके पास हो तो निश्चित रूप से हमें अवगत करायें और मैं सदन के माध्यम से आपको यह सुनिश्चित करना चाहूंगा कि पुलिस गठजोड़ की कहीं भी हमको शिकायत मिलेगी, पुलिस गठजोड़ ही नहीं इस धन्धे में लिप्त कोई भी व्यक्ति हमारे संज्ञान में आयेगा, उसके खिलाफ हम कठोर कार्यवाही करेंगे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मंत्री जी, कार्ययोजना? देखिये, हाई कोर्ट ने निर्देश दिये हैं वो तो अपना फेलियर है कि सरकार नहीं कर रही है तो हाई कोर्ट कह रहा है वह तो उलटा आपकी कमी है। मैं तो यह कह रहा हूं कि आपका कोई प्लान है क्या कि हम इस-इस प्रकार से नशे को रोकने का अभियान चलायेंगे, काम करायेंगे, हमारी प्लानिंग यह है जिससे कि नशा रुकेगा? अब यह तो जनरल बात कह दी आपने।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): माननीय अध्यक्ष जी, यह माननीय उच्च न्यायालय ने जो एडवाइजरी जारी की है वो भी आपके समय पर ही की है। वो फेलियर भी आपका ही है, लेकिन हमने आने के बाद सभी एस.पीज को क्योंकि पूरे राजस्थान में जिन-जिन जिलों में यह मादक पदार्थों की तस्करी के प्रकरण हमारी नजर में आये हैं, सब जगह जिला पुलिस अधीक्षक को हमने निर्देश दिये हैं और कार्ययोजना बना कर विशेष टीमें गठित करके ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): पर्ची आ गयी।

श्री अध्यक्ष: वह तो रोज मैं भी निकालता हूं।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): निश्चित रूप से वह तो काम ही है अधिकारियों का कि वो समय पर देंगे।

हमने एन.डी.पी.एस. का जो एक्ट है उसमें उनकी सम्पत्ति को जब्त करना, गिरफ्तार करना इसके विशेष अभियान कार्ययोजना बना कर ही चालू किये हैं कि जो अपराधी आईडेंटीफाई होंगे उनकी सम्पत्तियों को जब्त किया जा रहा है। विशेष अभियान चलाये जा रहे हैं। नशा मुक्ति केन्द्र भी संचालित करने के लिये सरकार ने विशेष अभियान चला करके, क्योंकि जो एडिक्ट हो गया जो आदी हो गया किसी कुसंगत की वजह से उसकी संरक्षा, सुरक्षा करना भी सरकार का धर्म बनता है तो हम नशा मुक्ति केन्द्रों में उसका कर रहे हैं और बजटीय प्रावधान किये गये हैं कि इन मादक पदार्थों की तस्करी को विशेष अभियान

चला करके हम रोकेंगे इसका पूरा प्रयास कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। हो गया, दो हो गये आपके भी। श्री जब्बर सिंह सांखला।

रघुनाथपुरा से शम्भूगढ़ वाया आसीन्द स्टेट मेगा हाईवे का निर्माण

305. श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार उपखण्ड आसीन्द के रघुनाथपुरा से शम्भूगढ़ वाया आसीन्द (दूरी 27 कि.मी. विथ कोजवे) स्टेट मेगा हाईवे-133 के अधूरे कार्य को पूर्ण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उपखण्ड आसीन्द के नेशनल हाईवे 148 डी व 158 डी सोपुरा (आसीन्द) से महाराजपुरा चौराहे (आसीन्द) को स्टेट हाईवे 133 को जोड़ने वाली सड़क पर अत्यधिक यातायात के कारण नवीन सर्विस रोड़ निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (सुश्री दिया कुमारी): (1) विधानसभा क्षेत्र आसीन्द के उपखण्ड आसीन्द के रघुनाथपुरा से शम्भुगढ़ वाया आसीन्द मय कॉजवे (आसीन्द) भीलवाड़ा सड़क के 27 किलोमीटर में से 8.00 किलोमीटर लम्बाई में सड़क अच्छी स्थिति में है एवं शेष रहे 19 किलोमीटर सड़क के रिपेयर तथा उन्नयन हेतु बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के बिन्दु संख्या 15(I) की क्रम संख्या 65 के अनुसार राशि रुपये 8.10 करोड़ की घोषणा की गई है। शीघ्र ही प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है।

(2) विधानसभा क्षेत्र आसीन्द में नेशनल हाईवे 148डी व 158 पर सोपुरा जंक्शन (आसीन्द) (किमी 67/930) से महाराजपुरा जंक्शन (आसीन्द) स्टेट हाईवे 75 (किमी 74/630) के मध्य की दूरी 6.700 किलोमीटर में दो लेन मय पेव्ड शोल्डर डामर सड़क है। इस सड़क पर 6.70 किलोमीटर में से 1.70 किलोमीटर लम्बाई में चिन्हित आबादी क्षेत्र में सड़क के दोनों तरफ आवश्यकतानुसार सर्विस रोड़ निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है। जिसमें से 1.00 किलोमीटर सर्विस रोड़ का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष 0.70 किलोमीटर लम्बाई में भूमि अवाप्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। भूमि अवाप्ति के पश्चात सर्विस रोड़ बनाया जाना प्रस्तावित है। शेष 5.00 किलोमीटर लम्बाई में आबादी क्षेत्र नहीं होने के कारण सर्विस रोड़ बनाया जाना प्रस्तावित नहीं है।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): अध्यक्ष महोदय, जवाब मेरे पास आ गया है।

श्री अध्यक्ष: चलिये, पूरक पूछिये।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा का और हमारी वित्त मंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी को बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने हमने मांग नहीं की, उससे पहले ही जो यह सड़क है जो पिछली सरकार ने...।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिये न।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): मैं वो ही पूछ रहा हूं, अध्यक्ष महोदय।

पिछली सरकार ने जगदीश भगवान से देवनारायण मन्दिर देवमाली तक इस सड़क की घोषणा की थी उसको मेरे विधान सभा क्षेत्र में लाकर के छोड़ दिया था। माननीय वित्त मंत्री जी ने अभी इस बजट में घोषणा की है मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं और एक दूसरा मेरा प्रश्न है, जो बाईपास है आसीन्द शहर में जो नया बाईपास बना उससे लेकर के खारी नदी तक जो 700 मीटर का टुकड़ा है उसकी भी प्रक्रिया चालू है, लेकिन मेरा निवेदन रहेगा अधिकारियों को आदेशित करके यह आप थोड़ा जल्दी करवा देंगे तो आपका बहुत-बहुत आभार होगा। धन्यवाद।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलकुल जो इन्होंने दो सड़कों की बात की थी, वो काम तो इनका शुरू हो गया। अभी जो यह सड़क के बारे में बात रखी है तो बिलकुल उसको एक बार उसका परीक्षण करवा देंगे और अगर लगता है कि फिजिबल है और सब कुछ तो बिलकुल उसका काम भी जल्दी ही शुरू हो जायेगा।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री कांति प्रसाद।

जनता क्लिनिक में ओपीडी पर्चियों का इन्द्राज

306. श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पूर्ववर्ती सरकार द्वारा खोली गयी जनता क्लिनिक पर नियन्त्रण सीएचसी प्रभारी का होता है या खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी का?

(2) प्रदेश में जनता क्लिनिक पर प्रतिदिन की ओपीडी पर्चियां इन्द्राज करने के लिये क्या व्यवस्था है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के शहरी चिकित्सालय का शहरी स्वास्थ्य कल्याण केन्द्र जनता क्लिनिक में परिवर्तन किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त में कार्यरत स्थायी सरकारी कर्मचारियों के पद समाप्त करने का विचार रखती हैं?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह): (1) शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर (पूर्व नाम जनता क्लिनिक) का प्रशासनिक रिपोर्टिंग एवं पर्यवेक्षण नियंत्रण निकटतम शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से किया जाता है एवं जहां पर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है वहां शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर (पूर्व नाम जनता क्लिनिक) का प्रशासनिक रिपोर्टिंग एवं पर्यवेक्षण नियंत्रण निकटतम सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/उप जिला अस्पताल के अधीन होता है।

(2) शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर (पूर्व नाम जनता क्लिनिक) पर प्रतिदिन की ओपीडी पर्चियां इन्द्राज, फार्मासिस्ट द्वारा किया जाता है।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के शहरी चिकित्सालय (शहरी डिस्पेंसरी) का शहरी स्वास्थ्य कल्याण केन्द्र (जनता क्लिनिक) में परिवर्तन किया जाकर वर्तमान में शहरी

आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में संचालित हैं।

उक्त संस्थान पर कार्यरत स्थायी कर्मचारियों के पद समाप्त करना विचाराधीन नहीं है।

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर आ गया है।

मैं तो आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मेरे यहां शहरी चिकित्सालय चालू हैं और शहरी चिकित्सालय को बन्द करके आपने जनता क्लिनिक चला ली तो क्या उसको वापस जनता क्लिनिक के स्थान पर चलाना चाहते हो या शहरी चिकित्सालय में चलाना चाहते हो?

दूसरा प्रश्न है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पी.एच.सी., सी.एच.सी. में कंप्यूटर ऑपरेटर आपने पर्ची काटने के लिये लगा रखे हैं तो क्या इन जनता क्लिनिक्स में भी कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट लगाना चाहते हो या नहीं लगाना चाहते हो?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जनता क्लिनिक 2019-20 में गहलोत सरकार ने खोली थी और आश्चर्य की बात है कि पूरे राजस्थान के अन्दर केवल पन्द्रह थी। यह दिल्ली के जो मोहल्ला क्लिनिक के आधार पर इन्होंने खोली थी उसके बाद माननीय मोदी जी ने,

Kas/rtm/06.03.2025/11.10/1b

केन्द्र ने इसको 2021-22 में शहरी स्वास्थ्य कल्याण केन्द्र का दर्जा दे दिया, लेकिन यह राजस्थान में केवल 15 रहे। उसके पश्चात मोदी जी ने 2020-21 में अरबन आयुष्मान आरोग्य, जिसको हम कहते हैं युवाम कहते हैं, वो उन्होंने राजस्थान में खोले। मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि उन्होंने जनता क्लिनिक से भी बड़ी फैसेलिटी के खोले और आज ये पूरे राजस्थान में 357 ऑपरेटिव हैं। उसमें पूरी फंडिंग केन्द्र सरकार से है। आपके जनता क्लिनिक में दानदाताओं से, सीएसआर फंड से चलते थे और एक शैड के नीचे या नट-बोल्ट जोड़कर, स्टील का फेब्रिकेशन करके करते थे। इसमें 70 लाख रुपये ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: उत्तर तो सुनिए। आपका प्रश्न नहीं है, आपका प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य, आप पुराने सदस्य हैं। ....(व्यवधान).... आप तो बैठो, मंत्री जी का जवाब तो आने दीजिए।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष जी, जनता क्लिनिक तो डिफंक्ट हो गया है, वो तो है ही नहीं, अब बात करते हैं युवाम की ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: जब आपका नंबर आये, तब बोलना।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 70 लाख रुपये प्रतिवर्ष इन 357 युवाम को हमारी केन्द्र सरकार, मोदी जी हर साल देते हैं। इसमें सैलरीज, रेंट, माइनर रिपेयर्स, आल्टेशन, फर्नीचर, इक्युप्मेंट, स्टाफ का प्लेसमेंट, 1 डाक्टर, 2 एएनएम, 2 जीएनएम, 1 लैब टेक्निशियन, 1 फार्मसिस्ट, 1 हैल्पर, 1 स्वीपर, इतना हमें मैन पावर दे रहे हैं। इसके अलावा ओपीडी और वैक्सीनेशन, एएमसी, फैमिली वैल्फेयर और 120 मेडिसिन,

इसका दायरा इसमें बहुत बढ़ा दिया है।

मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान में मोदी जी ने 2021-22 में 142 दिये, 2022-23 में 147 दिये, 2023-24 में 143 दिये और 2024-25 में 180 दिये हैं। आपके जो भी अधिकारी लगे हैं वो कांट्रेक्चुअल हैं। आप जो अपने थानागाजी की बात कर रहे हैं, उसमें से किसी को नहीं हटाया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक है, हो गया, चलिए अगला प्रश्न। श्री अमीन कागजी।

एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट

307. श्री अमीन कागजी (किशन पोल): क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या सरकार द्वारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधेयक में संशोधन करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश में न्यायालयों के परिसरों की सुरक्षा करने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

विधि एवं विधिक कार्य मंत्री (श्री जोगाराम पटेल): (1) जी हां। पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा राजस्थान राज्य में अधिवक्ताओं की सुरक्षा हेतु विधानसभा में प्रस्तुत एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 15वीं विधानसभा के अष्टम सत्र में दिनांक 21.03.2023 को विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया है, जिस पर महामहिम राष्ट्रपति महोदया की स्वीकृति (Assent) अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

महामहिम राष्ट्रपति महोदया की स्वीकृति (Assent) प्राप्त होने पर राजस्थान राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लागू करने हेतु राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा।

(2) जी नहीं। पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा राजस्थान राज्य में अधिवक्ताओं की सुरक्षा हेतु विधानसभा में प्रस्तुत एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 15वीं विधानसभा के अष्टम सत्र में दिनांक 21.03.2023 को विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया है, जिस पर महामहिम राष्ट्रपति महोदया की स्वीकृति (Assent) प्राप्त नहीं हुई है।

(3) जी हां। राजस्थान के 31 जिला एवं सेशन न्यायालय परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था की हुई है, जिनमें वर्तमान में 33 हैड कांस्टेबल तथा 131 कांस्टेबल सुरक्षा गार्ड उपलब्ध हैं।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर परिसर में सुरक्षा हेतु पुलिस चौकी थाना कुडी हाउसिंग बोर्ड से 01 सहायक उप निरीक्षक, 03 हैड कांस्टेबल तथा प्रथम बटालियन आरएसी की ए कंपनी से 01 सीसी, 20 हैड कांस्टेबल, 71 कांस्टेबल नियोजित कर सुरक्षा दी जा रही है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच परिसर में 01 उप निरीक्षक, 02 सहायक उप निरीक्षक, 12 हैड कांस्टेबल, 24 कांस्टेबल, 05 महिला कांस्टेबल कुल 44 सुरक्षाकर्मी द्वारा सुरक्षा दी जा रही है।

श्री अमीन कागजी (किशन पोल): अध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब मिल गया है, लेकिन जवाब में एक कांट्राडिक्शन है, उसका मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कहा है कि अभी इसकी राष्ट्रपति जी से एप्रुवल नहीं मिली है। पहली बात तो यह है कि इन्होंने कब-कब रिमाइंडर डाले और उसके एप्रुवल आने की क्या संभावना है?

दूसरी बात, आपने इसमें कहा है कि आप इस एक्ट को लागू करेंगे और दूसरा मैंने इसमें यह पूछा था कि क्या इसमें अमेंडमेंट करने का भी आपका विचार है? तो आपने यह तो मना कर दिया कि अमेंडमेंट नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ आप यह कह रहे हैं कि हम इस पर विचार करेंगे। तो विचार क्यों करेंगे, जब आपको अमेंडमेंट भी नहीं करना और लागू भी नहीं करना और कब तक लागू करेंगे, यह बताएं आप तो।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद व आभार व्यक्त करूंगा कि सदन के सामने यह वकीलों की सुरक्षा का अधिनियम, जो पूर्ववर्ती सरकार में इसी विधान सभा से पारित हुआ और उसके उपरांत इसको राष्ट्रपति महोदय सहमति हेतु भेजा गया। राष्ट्रपति महोदय की सहमति हेतु यह कब भेजा गया, इसमें लिखा हुआ है। राष्ट्रपति महोदय की सहमति जब तक प्राप्त नहीं हो, तब तक वह अधिनियम का रूप प्राप्त नहीं करेगा और जब तक वह अधिनियम का रूप प्राप्त नहीं करेगा, तब तक उसमें संशोधन होने या नहीं होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त हो जायेगी और माननीय सदस्यों या पब्लिक का सुझाव होगा और उसमें आवश्यकता महसूस होगी, तो संशोधन किया जायेगा, यही मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री अमीन कागजी (किशन पोल): लेकिन इसकी कब तक संभावना है, एक तो यह बताएं। आपने तो जो बात कही है ना सिर्फ उसका जवाब दे दें कि आप इसमें एक तरफ यह कह रहे हैं कि आप इस एक्ट को लागू करेंगे और दूसरी तरफ साथ के साथ यह भी कह रहे हैं कि हम विचार भी करेंगे। तो विचार करेंगे, इसका मतलब आपको अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, प्रयास क्या किये, एक तो यह बताएं और अमेंडमेंट की क्या संभावना है, यह बताएं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): किसी कानून में अमेंडमेंट पेश करने के लिये विधान सभा में आता है, अमेंडमेंट कोई बाहर नहीं होता है, सरकार नहीं करती है, विधान सभा में ही हो सकता है। जब तक राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त नहीं हो जावे, उससे पूर्व संशोधन की, विचार की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि विधान सभा ने अधिनियम पारित किया है, हम इसे लागू करेंगे।

श्री अमीन कागजी (किशन पोल): लेकिन आपने इसमें जवाब यह दिया है कि आप फिर भी विचार करेंगे। आपने इसमें लिखा है एडवोकेट प्रोटेक्शन लागू करने हेतु राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा। जब अमेंडमेंट हो कर जायेगा, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जायेगी, उसके बाद आपने यह प्रश्न चिह्न क्यों लगाया कि आप फिर भी विचार करेंगे।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): कानून लागू होगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, जब यह जनहित का मामला था, वकीलों की भारी डिमांड थी, उसके बाद ये लेकर आये थे। जल्दी हो जाये, इसके लिये आप राष्ट्रपति जी से अनुरोध करेंगे या नहीं, यह बात है।

श्री अध्यक्ष: हो गया। अगला प्रश्न। श्री यूनुस खान। राष्ट्रपति जी से आने दो, फिर करेंगे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): ये प्रयास करेंगे या नहीं करेंगे?

श्री अध्यक्ष: यह इनके हाथ में थोड़े ही है कि राष्ट्रपति महोदय कब देंगे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): फिर सप्लीमेंट्री पूछने का मतलब क्या हुआ? आप प्रयास करोगे या नहीं करोगे, यह बता दो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय, राष्ट्रपति कार्यालय में जाने के बाद उसमें आपकी सुविधा हो तो लैटर ऑफ रिक्वेस्ट लिख सकते हैं, इससे ज्यादा हम लिख नहीं सकते, क्योंकि वो उनका प्रेरोगेटिव है, कब स्वीकार करना, सहमति देना, असहमति देना, कमेंट्स करना, यह प्रेरोगेटिव माननीय राष्ट्रपति महोदय का है। अगर नियमानुसार होगा, तो हम राष्ट्रपति महोदय से रिक्वेस्ट भी कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री युनूस खान।

खाद्य विभाग द्वारा गठित समितियां

308. श्री यूनुस खान (डीडवाना): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा विभिन्न समितियों का गठन किया जाता है? यदि हां, तो किन-किन समितियों का, किस नियम के तहत? समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त समितियों में वर्तमान में किन-किन व्यक्तियों को किस नियम के तहत सदस्य बनाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त समितियों में सदस्य बनाने की क्या योग्यता निर्धारित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त समितियों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी सदस्य मनोनीत किया जाता है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री सुमित गोदारा): जी हां।

क्र.सं.	समिति का नाम	आदेश/नियम
1.	तहसील स्तरीय आवंटन सलाहकार समिति (नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र)	विभागीय आदेश दिनांक 17.03. 2016, राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश-1976 के खण्ड-3 (1)
2.	खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समिति(राज्य/जिला/तहसील/	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 29 की पालना में विभागीय आदेश दिनाक 07.09

	उचित मूल्य दुकान स्तरीय खाद्य एवं सतर्कता समिति)	2017 एवं 23.05. 2018 के द्वारा।

(2) तहसील स्तरीय आवंटन सलाहकार समिति उचित मूल्य दुकान आवंटन हेतु जारी दिशा-निर्देश दिनाक 17.03.2016 के बिन्दु संख्या 03 के अनुसार नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र तहसील स्तरीय आवंटन सलाहकार समिति मे पदेन (स्थाई) एवं गैर सरकारी सदस्यों मनोनयन के संबंध में जारी विभागीय दिशा-निर्देश की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

राज्य/जिला/तहसील/उचित मूल्य दुकान खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समिति - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 29 की पालना में विभागीय परिपत्र दिनांक 07.09.2017 एवं 23.05.2018 के द्वारा खाद्य सुरक्षा सतर्कता समितियों में पदेन (स्थाई) सदस्यों एव गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन के संबंध में जारी विभागीय परिपत्र की प्रति परिशिष्ट-2 व 3 पर संलग्न है।

(3) उक्त समितियों में पदेन (स्थाई) सदस्यों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों के मनोनयन हेतु योग्यता का प्रावधान नहीं है।

(4) जी, हां। इस संबंध में जारी विभागीय दिशा-निर्देश/परिपत्र दिनांक 17.03.2016 परिशिष्ट-1, दिनांक 07.09.2017 परिशिष्ट-2 एवं दिनांक 23.05.2018 परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे को जवाब मिल गया। मैं मंत्री महोदय से इतना ही पूछना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे जो परिशिष्ट 2 दिया है, उसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिये तहसील स्तर पर समिति बनाई है और उसमें एमएलए को भी मेम्बर बनाया है और बाकी सारी नियुक्तियां एसडीएम करेगा, बहुत लंबी सूची है, वह मैं नहीं पढ़ूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि क्या मंत्री जी उपखंड अधिकारी की उस कमेटी में सदस्य के रूप में उसकी अध्यक्षता में बैठना पसंद करेंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 29 के प्रावधान के अनुसार कमेटियों का निर्धारण किया गया है और उसमें जो इन्होंने तहसील स्तरीय कमेटी के बारे में बताया, उसमें अध्यक्ष उपखंड अधिकारी को नियमित किया गया है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा के तहत ही इसमें अध्यक्षता उपखंड अधिकारी ही करता है।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): मेरा तो यही पूछना था कि मंत्री जी यह बता दें कि वो उनकी अध्यक्षता में बैठना पसंद करेंगे क्या? क्योंकि वो भी एमएलए हैं, आप भी एमएलए हो माननीय अध्यक्ष जी।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): यह तो बहुत जगह नियम है, बैठना पड़ता है और हम जन सेवक हैं, बैठने में क्या है? जो नियम हैं, उसके अनुसार चलेंगे। ऐसा

थोड़े ही है कि आप विधायक बन गये तो सिस्टम से ऊपर हो गये, जो नियम हैं, उसी हिसाब से बैठना पड़ेगा, इसमें क्या है?

श्री यूनुस खान (डीडवाना): मेरा दूसरा प्रश्न है, क्या सरकार इसमें संशोधन करने का विचार रखती है?

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सरकार नियमानुसार चलती है और आप तो खुद पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, आपको पता है कि किस तरह से चलते हैं। हमने तो आपको भी देखा था, किस तरह नियमों में चलते हुए आप राजस्थान की सारी सड़कें नागौर ले गये थे, तब भी हमने देखा था कि किस तरह नियम चलते हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गोपाल लाल शर्मा।

श्री तिलस्वा महादेव मन्दिर ट्रस्ट का चुनाव

309. श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के धार्मिक स्थल श्री तिलस्वा महादेव मंदिर के वर्तमान ट्रस्ट द्वारा विगत 20 वर्षों से आय-व्यय का विवरण विभाग को प्रस्तुत नहीं किया गया है? यदि हां, तो उक्त के संबंध में सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) मंदिर ट्रस्टों में ट्रस्ट/ ट्रस्टियों के चुनाव व कार्यकारिणी गठन की प्रक्रिया के क्या प्रावधान हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार श्री तिलस्वा महादेव मंदिर ट्रस्ट का निष्पक्ष चुनाव करवाकर नवीन कार्यकारिणी बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

देवस्थान मंत्री (श्री जोराराम कुमावत): (1) विधानसभा क्षेत्र माण्डलगढ के धार्मिक स्थल श्री तिलस्वा महादेव मंदिर प्रन्यास द्वारा विगत 20 वर्षों में से ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2022-23 व 2023-24 तक सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, अजमेर में प्रस्तुत की गई है। प्रति वर्ष ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने की स्थिति में ट्रस्ट से स्पष्टीकरण लेते हुए नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। तदनुरूप कार्यवाही की जा सकती है।

(2) प्रावधान का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) राजस्थान लोक न्यास अधिनियम, 1959 के अंतर्गत पंजीकृत प्रन्यासों में कार्यकारिणी का परिवर्तन उनके विधान में निहित प्रावधानों के अनुसार प्रन्यास के स्तर पर ही होता है। उक्त प्रन्यास में राजस्थान लोक न्यास अधिनियम की धारा-23 के अंतर्गत नवीनतम कार्यकारिणी परिवर्तन के संबंध में प्रपत्र-8 दिनांक 10.09.2024 को सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत हुआ है जो विचाराधीन है। प्रकरण में राजस्थान लोक न्यास अधिनियम, 1959 में विहित प्रावधानों के अनुसार जांच कर उचित

कार्यवाही की जाएगी।

Msk/rtm/05.03.25/1120/1c

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यहां पर हर तरीके की बीमारी का इलाज अभी इस युग में भी होता है, परन्तु 20 वर्षों से कुछ आदमी उस ट्रस्ट पर कब्जा करके बैठे हैं। लाखों रुपये आते हैं, परंतु उस क्षेत्र की जनता उनसे आय-व्यय पूछती है, परंतु वे देना नहीं चाहते हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि देवस्थान विभाग अजमेर में भी इन्होंने इतने सालों से हिसाब पेश नहीं किया तो आप क्या इनके खिलाफ कोई कार्यवाही करना चाहते हैं या नहीं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि भीलवाड़ा जिले की माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में तिलस्वा ग्राम में श्री तिलस्वा महादेव मन्दिर स्थित है। मन्दिर अराजकीय श्रेणी है। मन्दिर का संचालन राजस्थान प्रन्यास अधिनियम, 1959 की धारा 17 के तहत दिनांक 27.01.1998 को गठित व देव स्थान विभाग में रजिस्टर्ड किये गये ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। इस ट्रस्ट के प्रथम अध्यक्ष देवीलाल जी लौहार बने थे। 2004 में इनकी मृत्यु हो गयी। इसके बाद क्रमश: 20 वर्षों से अध्यक्ष बने हुए हैं। 10.09.2024 को नवीन कार्यकारिणी का गठन हुआ। अध्यक्ष व इनकी गठित प्रबंध कार्यकारिणी के सौजन्य से तिलस्वा महादेव मन्दिर का संचालन किया जा रहा है। मन्दिर के आय-व्यय का ब्यौरा प्रतिवर्ष देवस्थान विभाग को प्रेषित करना होता है। प्रतिवर्ष की ऑडिट रिपोर्ट भी देवस्थान विभाग को भेजनी होती है। ऑडिट रिपोर्ट देवस्थान विभाग को प्राप्त नहीं होने पर विभाग ट्रस्ट से स्पष्टीकरण लेता है। स्पष्टीकरण में सत्यता नहीं होने पर या आय-व्यय में गड़बड़ की आशंका होने पर कार्यवाही करने का भी प्रावधान है। माननीय अध्यक्ष महोदय, तिलस्वा महादेव मन्दिर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन 1998 में हुआ। 1998 से सन 2011-12 तक ट्रस्ट द्वारा ऑडिट रिपोर्ट देवस्थान विभाग को प्रेषित नहीं की गयी। सन 2012-13 से 2023-24 तक 11 वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग अजमेर को प्रस्तुत की गयी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि वहां 20 वर्षों से चुनाव नहीं हो रहे थे और अभी जो चुनाव हुए, वे अनियमित हुए। सही तरीके से नहीं हुए। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि प्रन्यास में पांच व्यक्तियों की मृत्यु होने पर 12 लोगों की नयी कार्यकारिणी गठित कर उक्त प्रन्यास में राजस्थान लोक न्यास अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत नयी कार्यकारिणी के परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रपत्र-8 दिनांक 10.09.2024 को सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत हुआ है, जो विचाराधीन है।

प्रकरण में राजस्थान लोकन्यास अधिनियम 1959 में विहित प्रावधानों के अनुसार जांच

कर उचित कार्यवाही की जायेगी। साथ ही, माननीय सदस्य ने यह भी चाहा है कि लंबे समय से एक ही ट्रस्ट काम कर रहा था और वहां कई तरह की अनियमितताएं हुई हैं। उनकी जांच होगी या नहीं होगी, इस सम्बन्ध में भी माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूंगा कि 20 साल तक किसी ने उस ट्रस्ट की कोई शिकायत नहीं की, लेकिन अभी तिलस्वा महादेव मन्दिर प्रन्यास के विरूद्ध अनियमितता किये जाने की शिकायत दिनांक 08.01.2025 को प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर राजस्थान लोक न्यास अधिनियम, 1959 की धारा 38 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर जांच सहायक आयुक्त, अजमेर ने प्रारंभ कर दी है। शिकायतकर्ता भवानी शंकर, पिता रघुवीर जी, जाति अहीर और अन्य चार हैं। निश्चित रूप से इनकी शिकायत पर देवस्थान विभाग जांच करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूंगा कि देवस्थान विभाग ट्रस्टों को रजिस्टर्ड करता है और ट्रस्ट में किसी तरह की अनियमितता होने पर देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त उसकी जांच करते हैं। देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त को सिविल लॉ न्यायालय की सारी शक्तियां प्राप्त हैं। पूरा जांच करने का अधिकार उनको ही होता है। जो भी वे फैसला देंगे, उसके अनुसार सरकार उसको लागू करेगी।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अभी जो जवाब दे रहे थे, उसमें कहा कि वापस ट्रस्ट का चुनाव हुआ। 20 साल से कब्जा करके बैठे हैं। पूरा क्षेत्र विरोध में है। आये दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल भी। आपके अधिकारियों को सब पता है। आप अभी यह कह रहे थे कि वहां पर वापस चुनाव हो गया। कौनसा चुनाव? आपको कोई कागजों में चुनाव करके दे दिया हो। जो आदमी कब्जा करके बैठे हैं, वे अधिकारियों को सैट करके। पूरा क्षेत्र नाराज है और 20 साल से वहां चुनाव नहीं हुए। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप वहां चुनाव कराना चाहते हैं या नहीं? आज यह जवाब दीजिये।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 11815 ट्रस्ट हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन देवस्थान विभाग में किया हुआ है, लेकिन वहां मंदिरों की व्यवस्था है, ट्रस्ट की व्यवस्था है, उसको वह प्रन्यास या ट्रस्ट ही चलाता है। उनमें यदि किसी तरह का गबन/घोटाला होता है, शिकायतें आती हैं तो देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त नियमों के तहत उसकी जांच करते हैं। देवस्थान विभाग में नये चुनाव करवाने होते हैं और वह भी प्रक्रिया के तहत, चुनाव भी देवस्थान विभाग की मॉनिटरिंग में, देखरेख में होता है, लेकिन ट्रस्ट वालों को ही करवाना होता है।

श्री अध्यक्ष: नहीं हुए हों तो आप निर्देश दे दें।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): इस सम्बन्ध में जैसे उन्होंने प्रपत्र-8 भरकर दिया कि हमने नये चुनाव कराये। उसकी जांच करवा लेंगे, यदि वह गलत है तो वह निरस्त होगा। कोर्ट फैसला हो और सही है तो वह आगे चलेगा। अगर किसी तरह की अनियमितता है तो उसकी भी जांच होगी और जांच के तहत पूरी तरह से, देवस्थान विभाग के कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर को सिविल न्यायालय की पॉवर प्राप्त है। इसमें सरकार

डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सरकार उनके आदेशों की पालना करेगी।

श्री अध्यक्ष: श्री विश्वनाथ मेघवाल।

रेंज चम्बल पालीघाट में घडियाल संरक्षण केन्द्र की स्थापना

310. डॉ. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला) (श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल के स्थान पर): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार रणथम्भौर बाघ परियोजना प्रथम की रेंज चम्बल पालीघाट में घडियाल संरक्षण केन्द्र बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, वन (श्री संजय शर्मा): (1) जी हां। वर्ष 2025-26 के बजट घोषणा के बिन्दु सं. 129 के सब बिन्दु 2 के अनुसार 'घड़ियाल संरक्षण की दृष्टि से सवाई माधोपुर में पालीघाट के निकट घडियाल Rearing Center स्थापित किया जायेगा' की गयी है। आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में घोषणा के अनुरूप कार्य करवाया जावेगा।

(2) जी हां। उपरोक्तानुसार।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डॉ. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से पूरक प्रश्न है कि बारिश के दिनों में जब भी चंबल नदी का बहाव तेज आता है तो घड़ियाल के अण्डे व छोटे बच्चे उस बहाव में बह जाते हैं व उनकी मृत्यु हो जाती है। जबकि प्रकृति को मेंटेन करने के लिए घड़ियाल का इस दृष्टि से बहुत ही महत्व है। अतः हमारा घड़ियाल अधिक से अधिक से जीवित रहे, इसके लिए हैचरिंग पाइंट/उपचार केन्द्र बनाया जाना आवश्यक है। मंत्री महोदय बतायें कि क्या उपचार केन्द्र बनायेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थिति मुरैना घड़ियाल संरक्षण केन्द्र की तर्ज पर रणथम्भौर बाघ परियोजना सवाई माधोपुर में पालीघाट में घड़ियाल सेंचुरी की अत्यधिक आवश्यकता है। इस पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही घड़ियाल संरक्षण केन्द्र बन जाने घड़ियाल की विलुप्त होती प्रजाति को बचाया जा सकता है। रणथम्भौर, गणेश जी का मन्दिर, सेंचुरी, पर्यटकों के लिए अच्छा गेस्ट हाउस और बोट उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था क्या माननीय मंत्री महोदय करायेंगे?

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, उसके सन्दर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान में पालीघाट सवाई माधोपुर में घड़िया Rearing Center स्थापित किया जाकर घड़ियाल के अण्डों को नदी के आसपास के क्षेत्र से उठाकर इनक्यूबेशन पिट में रखा जाकर उनका पालन किया जायेगा। उसके उपरान्त हैचलिंग बच्चों के निकलने के बाद तकरीबन एक से दो वर्ष तक घड़ियाल के आकार के अनुरूप अलग-अलग पानी के कुण्डों में हैचिंग पूल, क्वारंटाइन पूल, रियरिंग पूल में रखा जायेगा। अंत में बड़े पानी के कुण्ड रियरिंग पूल में रखने के उपरांत नदी में छोड़ा जायेगा।

उक्त घड़ियाल को नदी में छोड़े जाने के पूर्व इनकी टैगिंग की जायेगी। इसके उपरान्त इनके जीवंतता के सम्बन्ध में टैगिंग के कार्य की प्रभावी रूप से मॉनिटरिंग की जायेगी।

mdp/rtm/06.03.25/11:30/1d

जहां तक आपने गेस्ट हाउस की बात की है, परीक्षण करवा लेंगे और वित्तीय उपलब्धता के आधार पर सरकार निर्णय करेगी।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री हरीश चौधरी।

स्थायी पूर्ण दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति

311. श्री हरीश चौधरी (बायतू): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में स्थाई पूर्ण दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकम्पा नियुक्ति नियम, 2023 के अंतर्गत आश्रितों को लाभ मिला है तथा कितने लंबित हैं? विभागवार विवरण सदन की मेज पर रखे।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): (1) राजस्थान स्थाई पूर्ण दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकम्पा नियुक्ति नियम, 2023 के अंतर्गत ऐसे आश्रितों को पात्रतानुसार लाभ देने हेतु उक्त नियम, 2023 के प्रावधानानुसार नियुक्ति देने की कार्यवाही की जाती है। प्रदेश में उक्त नियम के अंतर्गत अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित एवं निर्णीत प्रकरणों की विभागवार सूचना परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): स्पीकर महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, जो मैंने मूल प्रश्न किया और जो प्रश्न अंकित किया गया है, वह बिलकुल ही अलग है। मेरा व्यक्तिगत आपसे अनुरोध है कि आप यह फैसला कर लीजिए कि क्या विधायक के तौर पर जो मेरा अधिकार है मूल प्रश्न करने का, उसको बदलने का सरकार के पास अधिकार है या किसी और के पास अधिकार है या नहीं है?

स्पीकर महोदय, जो यह योजना है, उस योजना के अंतर्गत 7 सरकारी कर्मचारियों ने आवेदन किया है और 7 के अन्दर 4 रिजेक्ट हो गयी है और 3 प्रक्रियाधीन हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये 4 चार जो रिजेक्ट हुए हैं, वे किस कारण रिजेक्ट हुए हैं?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें प्रावधान ये हैं कि एप्लाई करने वाले की एज, तो जो 4 रिजेक्ट हुए हैं, उसमें 3 तो अधिक उम्र के कारण हुए हैं और 1 जो रिजेक्ट हुआ है, जिला कलक्टर, चित्तौडगढ़ का, उसको ड्यूटी के दौरान अयोग्यता प्राप्त नहीं हुई है, ड्यूटी के अलावा हुई है। इसलिए 3 का कारण तो एज है और 1 का ड्यूटी के दौरान नहीं हुआ, ये चारों के कारण हैं।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): अध्यक्ष महोदय, जो सरकारी कर्मचारी के साथ इस तरह के

हालात बनते हैं, वह मानवीय दृष्टिकोण रखकर हम लोगों ने पहले भी इनके लिए ये योजना बनायी। क्या सरकार मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए इसके अन्दर शिथिलता या नियमों में परिवर्तन करने की मंशा रखती है या नहीं?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मैं धन्यवाद भी करूंगा माननीय सदस्य का, कि नियमों में शिथिलता रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, लेकिन अभी 2023 में ये नियम बने हैं और उस वक्त भी अगर सभी माननीय सदस्य, मैं कोई आरोप-प्रत्यारोप, मेरी आदत में नहीं है, अगर ये प्रावधान बना देते तो शायद आपका प्रश्न नहीं होता। अब जो नियम हैं, नियमों के अनुसार चलना पड़ता है। अगर शिथिलता की कोई एप्लीकेशन आयेगी, सरकार विचार करेगी, महसूस करेगी, अभी 2023 के अन्दर लागू हुए है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। 7 एप्लीकेशन आयीं, जिनमें से 4 निरस्त हुई हैं और 3 पेंडिंग हैं। इस सम्बन्ध में सरकार गंभीरता से विचार करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आवश्यकता और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री राजेन्द्र।

महवा में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

312. श्री राजेन्द्र (महवा): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र महवा में आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 0-3 वर्ष व 03 से 06 वर्ष के बच्चे, किशोरी बालिकाओं, गर्भवती व धात्री महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है? यदि हां, तो विगत पांच वर्षों में लाभार्थियों का वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में विगत पांच वर्षों में कितने कुपोषित, अतिकुपोषित बच्चों व किशोरियों की पहचान की गई? क्या चिह्नित किये गये बच्चों को लाभान्वित किया गया है? यदि हां, तो योजनावार व वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्र कहां-कहां संचालित हैं तथा केन्द्र खोलने के मानदण्ड पूर्ण करने वाले कितने गांव व ढाणियों में आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री दिया कुमारी): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र महवा में संचालित कुल 250 आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 0-3 वर्ष व 03 से 06 वर्ष के बच्चे, गर्भवती व धात्री महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। विगत 5 वर्षो में लाभान्वितों की संख्या परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। किशोरी बालिकाओं के लिये योजना केवल 5 आशान्वित जिलो में संचालित हैं, जिसमें दौसा जिला शामिल नहीं है।

(2) विधान सभा क्षेत्र महवा में विगत 5 वर्षों में चिन्हित किये गये एवं पूरक पोषाहार से लाभान्वित किये गये कुपोषित, अतिकुपोषित बच्चों की संख्या का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। विधान सभा क्षेत्र महवा में किशोरी बालिकाओं के लिये योजना लागू नहीं है।

(3) विधान सभा क्षेत्र महवा में कुल 250 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं, जिनकी ग्राम पंचायत/नगरपालिकावार सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र महवा में आंगनबाडी केन्द्र खोलने का मापदंड पूर्ण करने वाले कुल 8 गांव/ढाणी जहां आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं हैं, की सूची परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

श्री राजेन्द्र (महवा): माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिल गया है। मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहूंगा।

मेरे विधान सभा क्षेत्र महवा में अधिकांश आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों के लिए पर्याप्त बैठने की व्यवस्था नहीं है और एकाध कमरे भी हैं तो उनमें सामान रखने की जगह नहीं है। क्या सरकार आंगनबाड़ी केन्द्रों में सुविधाओं का विस्तार एवं नवीन भवन निर्माण करने की मंशा रखती है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि सरकार आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सुविधाओं का विस्तार करने हेतु कटिबद्ध है। बजट घोषणा 2024-25 के क्रम में प्रदेश के 2365 आंगनबाड़ी केन्द्रों को आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों में भवर मरम्मत, सुदृढ़ीकरण, विद्युत फिटिंग, विद्युत उपकरण जैसे पंखे, लाइट, पानी की टंकी, नल एवं पाइप फिटिंग, बाल सुलभ शौचालय, विद्युत मोटर, रसोईघर में स्लेब वाला पेटिंग, बाल सुलभ फर्नीचर, पोषण वाटिका आदि कार्य करवाए जा रहे हैं। आगामी वित्तीय वर्ष में 5 हजार आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों की मरम्मत का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। विभागीय भवन विहिन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटित होने पर विभाग द्वारा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार प्राथमिकता से भवन निर्माण के कार्य करवाए जाते हैं।

श्री राजेन्द्र (महवा): मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है माननीय मंत्री महोदय से कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत का वेतन बढ़ाने या उनको नियमित करने की मांग काफी समय से चल रही है। क्या सरकार उनको पूरा करने की मंशा रखती है? साथ ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि फेस कैप्चर से पोषाहार का जो वितरण किया जा रहा है, उसमें सबसे बड़ी समस्या है कि के.वाई.सी. और ओ.टी.पी. के कारण लोग ओ.टी.पी. दे नहीं पाते। फेस कैप्चर होने के बाद तीन साल तक सिर्फ फोटो वाले सदस्य को ही पोषाहार मिलेगा। अन्य किसी सदस्य को नहीं मिल पा रहा है। हर बार जब पोषाहार देंगे तो ओ.टी.पी. बार-बार मांगनी पड़ती है, लेकिन लोग दे नहीं पाते। गर्भवती और धात्री महिला पोषाहार लेने नहीं आती, घर का सदस्य अगर पोषाहार लेने जाता है तो पोषाहार नहीं मिलता। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि सरकार कुछ इसमें सरलता लाने पर विचार रखती है या नहीं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के देय मानदेय में समय-समय पर बढ़ोत्तरी की जाती है। वर्ष 2025-26 की बजट घोषणा के क्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को देय मानदेय में आगामी वर्ष दस प्रतिशत की वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही, इनकी सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त ग्रेच्युएटी का प्रावधान भी किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के नियमितीकरण के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

दूसरी बात जो इन्होंने की कि ये जो ओ.टी.पी. की प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल डिफिकल्टीज आ रही हैं, वैसे तो ये केन्द्र सरकार का प्रोविजन है। इसमें अभी तक तो कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन अगर कोई ऐसी शिकायतें आ रही हैं, टेक्निकल डिफिकल्टीज आ रही हैं, तो उस पर हम लोग जो भी कर सकते हैं, जिससे थोड़ा और आसान हो जाए, उसके लिए कोशिश करेंगे। लेकिन अभी ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

श्री राजेन्द्र (महवा): मेरा लास्ट पूरक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: दो हो गये। श्री लक्ष्मण राम।

श्री राजेन्द्र (महवा): पूर्ववर्ती सरकार के समय खोचपुरी ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी केन्द्र बना था।

श्री अध्यक्ष: श्री लक्ष्मण राम। आप विराजिए। दो की अनुमति ही होती है।

श्री लक्ष्मण राम।

उप जिला अस्पताल, मेड़ता में स्वीकृत पद

313. श्री लक्ष्मण राम (मेड़ता): क्या चिकित्सा एंव स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

राजकीय उप जिला अस्पताल, मेड़ता में कौन-कौनसे संवर्ग के, कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? संवर्गवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजकीय उप जिला अस्पताल मेडता सिटी, जिला नागौर में राजपत्रित एवं अराजपत्रित संवर्ग के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट अ एवं ब पर संलग्न है।

अध्यक्ष महोदय, जवाब आ गया।

श्री अध्यक्ष: आप बोलिए।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मेड़ता का जो सी.एच.सी. है, वह 2024-25 के बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो एक लोंग ओवरड्यू डिजर्विंग था, उसको क्रमोन्नत किया गया। 75 से 100 बेड उसको क्रमोन्नत करके किया गया और वहां पर जो स्टॉफ के बारे में माननीय विधायक महोदय ने चिंता व्यक्त की है, मैं आपके माध्यम से ये अवगत कराना चाहूंगा कि जो डाक्टर्स और स्पेशलिस्ट हैं, स्वीकृत पद हैं 28, उसमें अभी 13 कार्यरत है। नॉन-गजिटेड जो नर्सिंग स्टॉफ है, 72 में से 41 वहां पर अभी कार्यरत हैं। ट्रोमा सेंटर वहां पर ऑपरेटिव है। सर्जन और आर्थो वहां पर पोस्टेड हैं।

अभी जमीन का विवाद चल रहा है, दानदाताओं के साथ में। अभी तक हम बिल्डिंग के अन्दर कुछ भी एक्सपेंशन नहीं कर पाए, परंतु अभी इसका एसटीएच बनने के बाद में जो हम प्रगति देख रहे हैं, मेड़ता के एसटीएच के अन्दर, इनके 21 हजार 750 ओ.पी.डी. प्रति महीने हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: ये तो केवल पद पूछ रहे हैं।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): पद के अन्दर मैंने बता दिया। जो पद मैंने बताए इनको कि 7 जो पद हैं, जो स्पेशलिस्ट वगैरह हैं। जैसे एन्स्थेटिक्स की जरूरत है, इनको ओपथोलमेजी, आंखों के डाक्टर की जरूरत है, रेडियोलॉजिस्ट की है, सर्जरी की है, एनस्थिसिया की है एक आर्थोपेडिक और चाहिए। ये इनके जो 7-8 स्पेशलिस्ट चाहिए, जिसकी वजह से बाधा आ रही है। महीने भर के अन्दर इनके लगा दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला पूरक है और है?

श्री लक्ष्मण राम (मेड़ता): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में चार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोठन, मेड़ता रोड, रिया, बड़ीरेन में आधे से अधिक पद रिक्त हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिए, कह दिया लगा देंगे। अन्य कोई पूरक है तो पूछिए।

श्री लक्ष्मण राम (मेड़ता): नहीं है, साहब।

Ans/rtm 11.40 1e 06.03.2025

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री बाबू सिंह राठौड़।

जोधपुर के रसद कार्यालयों में स्वीकृत पद

314.श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं उसके प्रभावी संचालन हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वितरण प्रणाली में अनियमितता को रोकने हेतु प्रभावी ढंग से समयबद्ध तरीके से जांच नहीं की जा रही हैं? यदि हां, तो क्यों? इसके लिये कौन दोषी है व सरकार दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही कर रही है? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(4) जिला जोधपुर में विभाग के अधीन कितने पद स्वीकृत, कार्यरत तथा कितने पद रिक्त हैं? सरकार उक्त रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री सुमित गोदारा): (1) जी हां। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु पीडीएस कंट्रोल आर्डर 2015 में दिये गये निर्देशों के क्रम में जारी दिशा निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमितता भ्रष्टाचार एवं अनियमित वितरण आदि को रोकने हेतु प्रभावी ढंग से समयबद्ध तरीके से जांच हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के द्वारा निरीक्षण निलंबन तथा निरस्तीकरण की कार्यवाही किये जाने के प्रावधान है।

(3) जी हां। समय समय पर सामाजिक अंकेक्षण के दौरान प्राप्त सुझावों एवं पीडीएस कंट्रोल आर्डर 2015 में दिये गए दिशा निर्देशों के अनुरूप वन नेशन वन राशन कार्ड बायोमेट्रिक आधार पर पोस मशीन द्वारा वितरण एवं सप्लाई चैन मैनेजमेन्ट के तहत रिसाव मुक्त आपूर्ति आदि सुधार किए गए है।

(4) जिला जोधपुर में विभाग के अधीन स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

जी हाँ। विभाग में रिक्त पदों को भरने हेतु अभ्यर्थनाऐं भर्ती एजेन्सी को भिजवाई गई है।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, जवाब आ गया है। पूरक प्रश्न पूछना चाहूंगा। पहला पूरक प्रश्न, क्या सरकार राशन विक्रताओं को कमीशन के बजाय गुजरात राज्य की तर्ज पर मासिक मानदेय देने एवं राशन विक्रताओं को दो किलो प्रति क्विण्टल देने का विचार रखती है, यदि हो तो कब से, नहीं तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, मैं शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि अभी मानदेय का सरकार का विचार नहीं है पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट घोषणा में, जो उचित मूल्य दुकानदार है उनकी लगातार मांग आ रही थी कि उनका कमीशन बढ़ाया जाए, तो उनके कमीशन को 10 प्रतिशत बढ़ाकर 137 रूपये से 150 रूपये 70 पैसे कर दिये गये हैं।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): क्या यह सही है कि खाद्य सुरक्षा योजना में अंगूठा घिसने के कारण दिक्कत आ रही है व लाभार्थियों की सहूलियत के लिये 62 करोड़ की लागत से खरीदे गये आईरिस स्कैनर घटिया साबित हो रहे हैं, धूप में काम नहीं कर रहे हैं, इसके लिए उपभोक्ताओं को तौलिया व चादर आना पड़ रहा है, ताकि चेहरा ढककर, घूँघट निकालर सत्यापन, स्कैनर करा सके, इसमें सरकार क्या करना चाहती है। पोस मशीनों में नेटवर्क की समस्या होने के कारण उपभोक्ताओं को दो-दो घंटे इंतजार करना पड़ता है। कई बार नेटवर्क नहीं मिलने से उपभोक्ताओं को बिना राशन लिये ही लोटना पड़ता है। वर्तमान में पोस मशीनों से एक दिन में मात्र तीन उपभोक्ताओं को ओटीपी के माध्यम से राशन वितरण हो जाता है। क्या सरकार नेटवर्क सम्बन्धी समस्या का समाधान करने और जिनके फिंगर प्रिंट नहीं आ

रहे हैं उनको ओटीपी के माध्यम से राशन वितरण करने का विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वह एक गंभीर विषय सामने लेकर आए। यह सत्य है कि कई जगह फिंगर प्रिंट नहीं आते है तो इसीलिए आईरिस मशीनें खरीदी गई थी। यह बात सही है कि जहां धूप ज्यादा होती है, सूर्य की किरणों के कारण तापमान ज्यादा होता है वहां यह कम काम करती है। यह सभी तकनीकी चीजों में है चाहे मोबाइल या और कोई हो। उसको दुकान के अन्दर करने का नियम तो यह है, पर फिर भी आप जो यह विषय लेकर आय हो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगले तीन दिन में समस्त आईरिस मशीनों पर कवर वितरण कर दिया जाएगा, जिससे लोगों को बाहर धूप में खड़ा नहीं होना पडेगा, अगर होना पड़ेगा तो कवर के द्वारा आईरिस मशीन से उनकी पहचान कर ली जाएगी।

दूसरा विषय है कि पोस मशीन में आवंटन में समस्या आ रही है। कई बार टैक्निकल आए तो बात अलग है, बाकी ज्यादातर जगह यह समस्या नहीं है। अगर कहीं ऐसा हो तो आप मुझे व्यक्तिगत, प्रयास करेंगे जहां भी होगा समाधान कराए जाएंगे।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): इसका सरलीकरण थोड़ा जल्दी करना।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आईरिस मशीन का कवर अगले तीन दिन में वितरित करा दिया जाएगा ताकि समस्या का समाधान हो सके।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गोपीचन्द मीणा।

भीलवाड़ा की पंजीकृत गौशालाएँ

315. श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कितनी गौशालाएं, नन्दीशालाएं पंजीकृत हैं? सरकार द्वारा पंजीकृत गौशालाओं को क्या-क्या सुविधा, आर्थिक सहायता एवं छूट दिये जाने का प्रावधान है?

(2) जिला भीलवाड़ा की पंजीकृत कौन-कौनसी गौशाला नियमानुसार अनुदान व सहायता से वंचित हैं? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) जिला भीलवाड़ा में संचालित कौन-कौनसी गौशाला व नन्दीशाला को भूमि आवंटन लम्बित है? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

गोपालन मंत्री (श्री जोराराम कुमावत): (1) प्रदेश में 4140 गोशालाएँ पंजीकृत है एवं नन्दीशालाओं का संचालन पंजीकृत गोशालाओं द्वारा ही किया जाता है।

प्रदेश में गौ संवर्धन एवं संरक्षण हेतु निम्न योजनाएं संचालित की जा रही है :

राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम 2016 संशोधित नियम 2021 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार पात्र गोशालाओं में संधारित गौ वंश को भरण-पोषण हेतु सहायता राशि।

पंचायत समिति स्तरीय नन्दीशाला योजना जनसहभागिता योजना।

ग्राम पंचायत गोशाला/पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना।

गोशाला विकास जन सहभागिता योजना।

गौ काष्ठ मशीन योजना।

उक्त योजनाओं में पात्र पंजीकृत गोशालाओं को गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु गोशालाओं में संधारित गौ वंश को चारे-पानी एवं पशु आहार हेतु अनुदान तथा आधारभूत परिसम्पतियों के निर्माण हेतु सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है।

(2) भीलवाड़ा ज़िले की नियमानुसार अनुदान व सहायता से वंचित अपात्र गोशालाओं की विधानसभा वार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) भीलवाडा जिले में गोशालाओं एवं नन्दिशालाओं को भूमि आवंटन का कोई प्रकरण लंबित नहीं है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने अनुदान राशि समय पर दी उसके लिए पहले सरकार को धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मेरे भीलवाड़ा जिले में खण्ड दो में परिशिष्ट अ में 21 गोशलाएं अपात्र मानी है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि इन 21 अपात्र गोशालाओं में क्या कमियां है, इनको पात्र में लाने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 21 में से श्री नीलकण्ड महादेव गोशाला सेवा समिति रघुनाथपुरा कोटडी, श्री देवनारायण गोशाला सेवा समिति रोपा, श्री राधे कृष्ण गोसेवा समिति काबरी जहाजपुर, श्री गोपाल गोशाला रावतखेड़ा, श्री बिजासन गो सेवा समिति कुचलवाड़ा खुर्द।

श्री अध्यक्षः प्रश्न पूछो।

श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): इन गोशालाओं को आप पात्र माने और विधिवत चल रही है तो मेरा सरकार से निवेदन है कि इनमें अनुदान देने का विचार रखती है, पात्रता सूची में जुड़वाने का?

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बतानाचाहूंगा कि राजस्थान में 4140 गोशालाएँ वर्तमान में संचालित है।

श्री अध्यक्षः आप तो इनके क्षेत्र का उत्तर दे दो।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): इनके क्षेत्र की बता रहा हूं।

पूरे राजस्थान में 4140 में से 3043 गोशालाएँ इस साल पात्र है। पात्रता का कारण भी मैं बताता हूं, जिस गोशाला में 100 गोवंश होंगे उसी को हम अनुदान की सहायता राशि देते हैं। भीलवाड़ा जिले में 37 गोशालाएं ऐसी हैं जो पात्र हैं और उनको इस वर्ष का अनुदान भी जारी हो चुका।

श्री अध्यक्षः इनका देंगे या नहीं देंगे यह हां-ना में बता दो।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): इनकी विधान सभा क्षेत्र में, पूरे भीलवाड़ा जिले में 37 तो पात्र है और 21 अपात्र है। 21 में से इनके विधान सभा क्षेत्र में तीन

गोशालाएं अपात्र है, नीलकण्ठ महादेव गोशाला सेवा समिति रघुनाथपुरा कोटडी, श्री देवनारायण गोशाला सेवा समिति रोपा, श्री राधे कृष्ण गोसेवा समिति काबरी जहाजपुर, यह इनकी विधान सभा की है। 21 अपात्र हैं। मैं तो माननीय सदस्य को भी निवेदन करनाचाहूंगा इन गोशालाओं में 100 की संख्या करें और 100 की संख्या होने पर इनको अनुदान भी दिया जाएगा तथा दूसरी विकास की जितनी योजनाएं हैं वे भी उनमें लागू होंगी, यह मेरा आग्रह है।

श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, अनुदान दे रहे हैं उसमें बढ़ोतरी की है, लेकिन पूरे ही प्रदेश की गोशालाओं की यह डिमांड है कि जो अनुदान 09 महीने मिल रहा है उसको सरकार 12 महीने करने की इच्छा रखती है क्या?

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रतिपक्ष के माननीय नेता को जानकारी देना चाहूंगा कि प्रदेश में 09 महीने का अनुदान गोशालाओं को देते हैं और जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी पिछले बजट में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा की,इस बार भी 15 परसेंट बढ़ोतरी की, दोनों साल बढ़ोतरी की घोषणा की है। 09 महीने का अनुदान देने का मैं कारण बताता हूं कि प्रथम चरण में हम अप्रैल, मई, जून, जुलाई इन चार महीने का अनुदान देते हैं। जुलाई के बाद जैसे बरसात का मौसम आता है तो पूरे क्षेत्र में चारा खूब मात्रा में होता है।

श्री अध्यक्ष: संक्षेप में।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): उस समय गायों को चरने के लिए गोचर में या अन्य जगह जाना पड़ता है। दूसरे चरण में नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च इन महीनों में अनुदान पांच महीनों का। बीच में तीन महीने का इसलिए छोड़ रखा है कि उस समय चारे पानी की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में होती है। इसलिए हम इन तीन महीने कानहीं देते।

श्री अध्यक्ष: मेरा सभी से आग्रह है कि हम सब जितना उत्तर पूछा है उतना उत्तर दे। नियम, बंधन वह अपने नियमों में पढ़ लेंगे।

अगला प्रश्न। डॉ. जसवंत यादव।

बहरोड़ में संचालित औद्योगिक इकाइयां

316. डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में संचालित कौन-कौनसी औद्योगिक इकाइयां प्रदूषण मानदण्डों को पूर्ण करती हैं? प्रदूषण जांच की अवधि क्या है? सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र में प्रदूषण मानदण्ड को पूरा नहीं करने वाली कितनी औद्योगिक इकाइयों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में शराब व बीयर की औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले

अपशिष्ट पदार्थ का निस्तारण करने की क्या प्रक्रिया है?

(3) क्या यह सही है कि एम.वाई.के. सोतानाला, डेडेन्ट सोतानाला, प्रनोड कारोडा व ग्लॉबस श्यामपुरा औद्योगिक इकाइयां अत्यधिक मात्रा में प्रदूषण फैलाती है? यदि हां, तो उक्त की जांच विगत पांच वर्षों में कब-कब की गई व प्रदूषण जांच की अवधि क्या है?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

राज्य मंत्री, पर्यावरण (संजय शर्मा): (1) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा औद्योगिक इकाइयों को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 एवं जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अंतर्गत वायु व जल प्रदूषण की रोकथाम हेतु समुचित व्यवस्था स्थापित व संचालित करने के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 में निहित जल व वायु प्रदूषण कारकों के मानदण्डों की पालना सुनिश्चित करने की शर्त के साथ स्थापना एवं संचालन सम्मति जारी की जाती है।

विधानसभा क्षेत्र बहरोड़ की औद्योगिक इकाइयों का राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा समय-समय पर निरीक्षण एवं मॉनिटरिंग कर जल एवं वायु प्रदूषण कारकों के निर्धारित मानदंडों की अनुपालना सुनिश्चित करवाई जाती है। विगत वर्ष में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा किये गये निरीक्षण के दौरान मानदंडों के अनुसार संचालित उद्योगों का ईकाईवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा कार्यालय आदेश F12 (5-Adm)RSPCB/1672-1681 दिनांक 24.08.2023 में निर्धारित अवधि के अनुसार निरीक्षण किया जाता है। आदेश दिनांक 24.08.2023 की प्रति परिशिष्ट 'ब' संलग्न है।

विगत वर्ष में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा किये गये निरीक्षण के दौरान मानदंडों की पूर्ण पालना नहीं करते उद्योगों की सूची एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(2) शराब बीयर की औद्योगिक इकाइयों से जनित उच्छिष्ट (Effluent) के उचित उपचार हेतु उच्छिष्ट उपचार संयंत्र (ई.टी.पी.) स्थापित किया जाता है, ईकाईवार स्थापित उच्छिष्ट उपचार संयंत्रों (Effluent Treatment Plant) एवं निस्तारण की वर्तमान स्थिति का विवरण परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है।

(3) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा समय समय पर मेसर्स एम.वाई. के सोतानाला, मेसर्स रेडियंट एनोडाईज़र सोतानाला, मेसर्स पर्नोड रिकार्ड व मेसर्स ग्लोबस श्यामपुरा का निरीक्षण किया गया। उक्त उद्योगों की जांच की अवधि एवं गत पांच वर्षों में किये गये निरीक्षण, अंतिम निरीक्षण (Last) Inspection) की अनुपालना स्थिति एवं उद्योगों के विरुद्ध राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'य' पर संलग्न है।

VPS-RTM-06.03.2025-11.50-1f

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): बीम ग्लोबल स्प्रिट्स एण्ड वाइन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, गांव कारोरा, बहरोड़, एवं परनोड रिकार्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गांव कारोरा, बहरोड। वाइन बेवरेज बोटलिंग प्लांट, जगतजीत इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सोतानाला बहरोड और अन्य इसी तरह की फैक्ट्रीज हैं, उन से जो अपशिष्ट निकलता है, वेस्टेज निकलता है तो वह नियमों की पालना नहीं करते हैं और चाहे जहां पर ही उसको डाल देते हैं, ज्यादातर वह नदी के अन्दर डालते हैं, यहां पर साहबी नदी है, अभी तो उसमें पानी नहीं है पर डाल देते हैं उसके अन्दर। अभी बहरोड़ को भी हम वहां से पानी सप्लाई करवाना चाहते हैं। वहां पर बोरिंग हुआ तो टोटल पानी केमिकल का निकला। उसके अन्दर टी.डी.एस. इतना था कि कोई आदमी ले नहीं सकता। अब आप भी अलवर के ही रहने वाले हैं। वहां हर गांव के अन्दर कैंसर, हर गांव में टीबी और अस्थमा की बीमारी इतनी जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है कि यह इंडस्ट्री वाले बस में नहीं आ रहे हैं तो मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन कर रहा हूं कि क्या आप ऐसी कोई कमेटी बनाएंगे जिसकी पावर अच्छी हो, जो इनके बस में नहीं आये और वह कमेटी इनके खिलाफ कार्यवाही कर सके या आपको रिपोर्ट पेश कर सके तो आप कमेटी बनाने की इच्छा रखते हैं या नहीं रखते और रखते हैं तो कब तक बना देंगे?

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रदूषण को लेकर चिंता व्यक्त की है, निश्चित रूप से जिस प्रकार की बीयर फैक्ट्री हो या शराब की फैक्ट्री हो, उनके द्वारा जो उच्छिष्ट या वहां से निकलने वाले लोगों को स्मेल या बदबू का सामना करना पड़ता है, वह बहुत दु:खद है। क्योंकि आप बहुत वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं और आपने जो पीड़ा व्यक्त की है, वह हकीकत में वहां के किसानों की और आमजन की पीड़ा है, उसको लेकर मैं मुख्य पर्यावरण अभियंता, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल की अध्यक्षता में एक समिति बनाने की घोषणा करता हूं। उसमें कोटपूतली बहरोड के ए.डी.एम. भी रहेंगे और हमारे वहां के रीजनल ऑफिसर भी रहेंगे और यह समिति एक माह के अन्दर तमाम उद्योगों की, जो आपने उल्लेख किया है और जो आपने उल्लेख नहीं भी किया है, उनकी जांच करके एक माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष: अगला। आपका हो गया?

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अध्यक्षजी, आपके माध्यम से मैं दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि श्रीजी प्राइवेट लिमिटेड व श्रीनाथ कम्पनी, सोतानाला व श्रीनाथ कम्पनी केसवाना से जो जहरीली गैस निकलती है, आस-पास आदमी खड़ा नहीं हो सकता। वह जहरीली गैस निकलती है और दुर्गंध युक्त होती है, सांस लेना भी वहां पर मुश्किल होता है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: इन्होंने सभी के लिए कह दिया, चाहे आपने नाम लिया है या नहीं लिया है, सभी के लिए ही करेंगे।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): नहीं, वह था बीयर का और यह केमिकल फैक्ट्रीज हैं

जो गैस निकालती हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): ये अलग-अलग हैं। ...(व्यवधान)...

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ये अलग-अलग हैं। इनसे गैस निकलती है, आदमी खड़ा नहीं हो सकता, अस्थमा हो जाता है तो इन फैक्टरीज से इतना बुरा हाल हुआ है कि हजारों बीघा जमीन, फसल बरबाद हो गयी पर किसी ने कोई मुआवजा नहीं दिया। घिरोट से जो गैस निकली है, यह कांगरेट की जगह वह कांग्रेस रख लेते ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछो।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): इसमें साहब, कांगरेट एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी है तो मैं तो यह कह रहा हूं कि अगर वह कांगरेट की जगह कांग्रेस रख लेते तो ज्यादा ठीक रहते तो इतना नुकसान दे रही है कि हजारों बीघा सरसों तबाह हो गयी है।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछो। आप प्रश्न पूछो कि सरकार क्या करेगी।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मेरा प्रश्न यह है कि सरकार क्या क्योंकि यह तो बहुत लम्बे समय से चल रहा है, सरकार क्या उन किसानों की रक्षा करेगी?

श्री अध्यक्ष: हां, यह है।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): उनको मुआवजा देने का कोई प्रावधान करेगी या आगे से ऐसी घटना नहीं घटे इसके लिए क्या उपाय उठाये जा रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: हां, यह प्रश्न है। माननीय मंत्रीजी।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस कांगरेट एग्रोपैक प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री का उल्लेख किया है वह घिलोट, नीमराना में स्थित है और यह इकाई कीटनाशक का निर्माण करती है। इस कम्पनी का 20.01.2025 को निरीक्षण किया गया था एवं पायी गयी कमियों के लिए नोटिस भी दिया गया है। नोटिस का उत्तर संतोषजनक नहीं पाये जाने पर सात दिन का फाइनल नोटिस दिया जा चुका है। प्रत्युत्तर प्राप्त होने के पश्चात नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

साथ ही साथ, मैं इस सदन के माध्यम से कृषि अधिकारियों को भी यह निर्देशित कर रहा हूं कि वह उस जगह जाकर, क्योंकि जो मुझे जानकारी आयी है कि वहां पर इस गैस के रिसाव के कारण 700 मीटर की परिधि में फसल का नुकसान हुआ है तो वहां पर मिट्टी का सैम्पल भी लेंगे, फसल खराबे का भी सैम्पल लेंगे और यह प्रयास करेंगे कि विभाग द्वारा उनको उचित मुआवजा दिलवाया जाये।

श्री अध्यक्ष: श्री ललित मीना।

चम्बल कमांड एरिया की नहरों के कार्यों की जांच

317. श्री ललित मीना (किशनगंज): क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सिंचित क्षेत्र विकास द्वारा दाईं एवं बाईं मुख्य नहर सीएडी चम्बल कमान्ड एरिया में नहरों के सुदृढ़ीकरण के कार्यों में गुणवत्ता का क्या मानदण्ड रखा गया है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कार्यों में गुणवत्ताहीन कार्य करवाने की शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त शिकायतों की उच्च स्तरीय जांच करवाने का विचार रखती है?

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)(सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री के स्थान पर): (1) सिंचित क्षेत्र विकास चम्बल कमाण्ड एरिया में अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई वृत व बाईं मुख्य नहर वृत सीएडी कोटा के अधीन नहरों के सुदृढ़ीकरण के कार्यो के अन्तर्गत मुख्य रूप से नहरों की लाईनिंग के कार्य करवाये जा रहे हैं। नहरों में सीसी लाईनिंग M-15 कंक्रीट से करायी जा रही है तथा टाईल लाईनिंग 600mm×300mm×50mm एवं 300mm×300mm×50mm साईज की M-15 कंक्रीट टाईल से करवाये जा रहे हैं।

(2) जी हाँ, सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग को गुणवत्ताहीन कार्य करवाने की कुल 07 शिकायत प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 04 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है एवं 03 शिकायतों में जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग द्वारा चम्बल कमाण्ड एरिया के अन्तर्गत करवाये जा रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता संबंधी जांच जल संसाधन विभाग की गुण नियंत्रण इकाई द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाती है एवं तदनुसार उचित कार्यवाही की जा रही है।

श्री ललित मीना (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर आ गया है। मैं पूरक प्रश्न पूछ लेता हूं?

श्री अध्यक्ष: चलिये। पूछिये।

श्री ललित मीना (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना है कि सीएडी जो चम्बल नदी है उससे दो नहरें निकल रही हैं बाईं और दाईं। एक बाईं है जो बारां होकर एम.पी. में जाती है और एक बूंदी की तरफ जाती है तो मेरा यह निवेदन है कि इसमें इस बजट में भी पैसा दिया गया है सीएडी की नहरों की मरम्मत के लिए और वर्तमान में जो मेरा क्वेश्चन था उसमें बाईं नहर का तो जवाब है लेकिन दाईं नहर का नहीं है तो मेरा सदन के माध्यम से यह निवेदन है पिछले तीन साल में जो काम हुए हैं सीएडी में बाईं और दाईं में, जो काम किया है, उसकी जांच हुई है, उन जांच में आपके सीएडी के अधिकारियों ने ही जांच की है और इसमें सात शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सात में से चार संतोषजनक पाई है तो मेरा सदन के माध्यम से यह निवेदन है कि हम सीएडी के बाहर से, सिंचाई विभाग से या क्वालिटी कंट्रोल, जयपुर से इसकी जांच करवाने का विचार रखते हैं? क्योंकि जो फर्में वहां काम कर रही हैं उन्होंने उनके रिश्तेदारों से कम्पनी बनाकर, काम लेकर सबलेट कर दिया और उनको ही संतोषपूर्ण बता दिया तो मेरा यह निवेदन है कि हम इसका सीएडी के बाहर से, सिंचाई विभाग से या क्वालिटी कंट्रोल, जयपुर से दुबारा पिछली तीन

साल की जांच करवाने का विचार रखते हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि जो सात शिकायतें आयी थीं, उनके सम्बन्ध में एक कमेटी बनी। सीएडी, आयुक्त, एस.ई., एक्स.ईएन. और ए.ईएन. की, सात में से इंवेस्टिगेशन करने के पश्चात चार को दोषी नहीं पाया गया और तीन की अभी जांच चल रही है। अभी क्योंकि नहर में पानी है 25 मार्च तक, पानी जब रोका जायेगा तो उसी टाइम इंस्पेक्शन कर पाएंगे कि जो टाइल्स लगायी हैं या जो भी कंस्ट्रक्शन का कार्य हुआ है, उसके अन्दर क्या कमी है, वह एक्चुअली फिजिकल इंस्पेक्शन होने पर ही उसके बारे में जांच होगी, परंतु माननीय सदस्य अगर यह सोचते हैं कि कमेटी ने सही जांच नहीं की है तो जरूर क्वालिटी कंट्रोल, जयपुर के थ्रू हम इसके अन्दर दुबारा जांच करके संतुष्ट करेंगे आपको।

श्री ललित मीना (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि किसानों ने, यह जो आपकी दाईं नहर है, उसमें भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उसमें उनकी जांच नहीं की है और न ही इसमें उत्तर में दिया है तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि खुद सीएडी के चेयरमैन ने, खुद ने सातवीं शिकायत की है इटावा ब्रांच के लिए तो उसमें भी हम वहां सीएडी से नहीं लेकर बाहर से जांच करायें, यह मेरा इस सदन के माध्यम से निवेदन है क्योंकि वे तो संतोषजनक ही दे रहे हैं सीएडी से तो क्वालिटी कंट्रोल, जयपुर से करवाने का विचार रखते हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब टाइम हो रहा है। आप उत्तर पूछ लो। माननीय मंत्रीजी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: नहीं, अभी तो इनके दूसरे पूरक प्रश्न का उत्तर आ रहा है। मैं तो करवाने को तैयार हूं। ...(व्यवधान)...

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अभी पहले भी बोला था कि जयपुर क्वालिटी कंट्रोल से इसकी जांच करवा देंगे और जब नहर का पानी रुकेगा मार्च के अन्दर, उसके अन्दर जब फिजिकल वैरिफिकेशन हो जायेगा कि क्या कमियां हैं उसके निर्माण में, कंस्ट्रक्शन में तो इसका हम दुबारा से, जो भी आप संतुष्ट नहीं हो या आप जो सोचते हो कि यह कमेटी वन-वे डिसिजन, बायस्ड डिसिजन ले रही है तो हम इसका बैठकर, दुबारा से जांच करवा लेंगे।

श्री ललित मीना (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, दाईं नहर की पूछ रहा हूं मैं, जो दाईं नहर है उसका जवाब नहीं आया है तो क्या उसकी भी जांच करवाएंगे या नहीं करवाएंगे तो उसका आश्वासन तो दिलायें।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों का करवाकर हम आपको संतुष्ट करेंगे। ...(व्यवधान)...

ssy/rtm/06.03.2025/12.00/1g

श्री अध्यक्षः प्रश्नकाल समाप्त। मैं पीछे भी देख रहा हूं। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैः-

1. श्री मनीष यादव, सदस्य की ओर से प्रदेश की सरकारी नौकरियों में स्थानीय अभ्यर्थियों को वरीयता दिये जाने के संबंध में।

2. श्री जाकिर हुसैन गैसावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मकराना के खनन क्षेत्र में सड़क निर्माण नियम अनुरूप नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

3. डॉ. सुभाष गर्ग, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के ग्रामीण क्षेत्र में जल भराव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

4. डॉ. शिखा मील बराला, सदस्य की ओर से चौमू में फूड प्रोसेसिंग यूनिट के अभाव में मूँगफली उत्पादक किसानों को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

5. श्री रफीक खान, सदस्य की ओर से जयपुर में मंदिर माफी की जमीन का बेचान कर इन्द्राज किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

6. श्री थावर चन्द, सदस्य की ओर से भीलवाड़ा के बिजौलिया में पुलिस द्वारा बेकसूर आदिवासी युवाओं को प्रताडित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

7. श्री मनोज कुमार (सादुलपुर), सदस्य की ओर से राजगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में अधूरे विकास कार्यों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

8. श्री पूसाराम गोदारा, सदस्य की ओर से कार्मिकों के अभाव में रतनगढ़ कस्बे का बस स्टेण्ड बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूँ।

9. श्री गणेशराज बंसल, सदस्य की ओर से हनुमानगढ़ जिले में राजस्व रिकॉर्ड को ऑनलाईन किये जाने से हो रही समस्या के संबंध में।

10. श्री मनोज कुमार (सुजानगढ), सदस्य की ओर से राजस्व ग्राम हरिनगर को बीदासर नगर पालिका क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के प्रस्ताव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

11. श्री ललित यादव, सदस्य की ओर से नीमराना में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

12. श्री डूंगरराम गेदर, सदस्य की ओर से राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम की छबड़ा इकाई में निगम कर्मचारियों द्वारा किये जा रहे धरने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये। अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री गणेशराज

बंसल, श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़), श्री ललित यादव एवं श्री डूंगरराम गेदर को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनिट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से कोटा में वन भूमि पर बसी कॉलोनियों का राजस्व भूमि में प्रत्यावर्तन किये जाने के संबंध में।

2. डॉ. सुभाष गर्ग, सदस्य की ओर से यमुना जल समझौता 1994 के अनुसार प्रदेश के हिस्से का पूरा पानी दिये जाने के संबंध में।

3. श्री अमित चाचाण, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नोहर में मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण के संबंध में।

4. श्री सुरेश मोदी, सदस्य की ओर से जिला चिकित्सालय नीम का थाना में कैंसर रोग चिकित्सा इकाई की स्थापना किये जाने के संबंध में।

5. श्री रेवन्तराम डांगा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खींवसर में लाइम स्टोन के छोटे ब्लॉक बनाकर खनन पट्टे जारी किये जाने के संबंध में।

6. डॉ. प्रियंका चौधरी, सदस्य की ओर से बाड़मेर मेडिकल कॉलेज का निर्माण शीघ्र पूर्ण किये जाने के संबंध में।

7. श्री उदयलाल भडाणा, सदस्य की ओर से पंचायत समिति सदस्यों को अधिकार दिये जाने के संबंध में।

8. श्री प्रताप सिंह सिंघवी, सदस्य की ओर से राजस्व रिकार्ड में माफियात तथा माफियात रिज्यूमेशन के अंकन को हटाये जाने के संबंध में।

9. श्री कैलाश चन्द वर्मा, सदस्य की ओर से धार्मिक नगरी गोनेर का समग्र विकास किये जाने के संबंध में।

10. श्री देवेन्द्र जोशी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में वन भूमि पर बसी कच्ची बस्तियों का नियमन किये जाने के संबंध में।

11. श्री हाकम अली खां, सदस्य की ओर से प्रदेश में नायक जाति को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित किये जाने के संबंध में।

12. श्री विकास चौधरी, सदस्य की ओर से किशनगढ़ शहर की बदहाल व्यवस्था को सुधारने के संबंध में।

13. श्री ललित मीना, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के फूल डोल उत्सव को पर्यटन कैलेण्डर में सम्मिलित किये जाने के संबंध में।

14. श्री अनिल कुमार कटारा, सदस्य की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पूर्व-प्राथमिक शिक्षक के पद पर समायोजित किये जाने के संबंध में।

15. श्री नाना लाल निनामा, सदस्य की ओर से पंचायत समिति पीपलखूंट में विद्युत आपूर्ति की स्थिति सुधारने के संबंध में।

माननीय सदस्य, कल भी रात को सवा 12 बजे तक कार्यवाही चली है और आज का भी

जो विषय है, वह बहुत ही लंबा है। अतः 295 पढ़ा हुआ माना जायेगा।

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयी विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट .... देखें।)

पर्ची

आज दिनांक 06.03.2025 को शून्यकाल में बोलने के लिए 34 पर्चियां प्राप्त हुई, जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां चयनित की गई, जो निम्नानुसार हैः-

क्रम संख्या	माननीय सदस्य का नाम	विषय
1.	श्री गणेश घोगरा	टीएसपी क्षेत्र के डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालयों में व्याख्याताओं के रिक्त पद भरने के संबंध में।
2.	श्री श्रीचन्द कृपलानी	खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत उपयोग में ली जाने वाली पोस मशीनों में आ रही तकनीकी खराबी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
3.	श्री हरिमोहन शर्मा	प्रदेश में पुलिस द्वारा अपराधियों से सुरक्षा हेतु राशि जमा किए जाने के निर्णय से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
4.	श्री अरुण चौधरी	नवीन जिला बनने के बाद वहाँ पदस्थापित कर्मचारियों को अपना जिला चयन करने की छूट दिलाकर पदस्थापित करने के संबंध में।

श्री गणेशराज बंसल।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ ऑर्डर।

श्री अध्यक्षः जीरो ऑवर हो जाये। आप क्या देने वाले हैं, मेरे को पहले पाइंट लिखकर दे दो। पाइंट ऑफ ऑर्डर जैसा है कि नहीं है, भेज दीजिये मेरे पास। मैं अलाऊ कर दूंगा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

हनुमानगढ़ जिले में राजस्व रिकॉर्ड को ऑनलाइन किये जाने से कारित समस्या

श्री गणेशराज बंसल (हनुमानगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपने प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 50 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति प्रदान की उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉर्डेनाइजेशन प्रोग्राम (DILRMP) योजना के तहत तहसील हनुमानगढ़ का रिकॉर्ड दिनांक 05.10.2021 को ऑनलाइन किया गया था, जिसके उपरान्त तहसील में समस्त प्रकार के नामांतरण ऑनलाइन पद्धति से दर्ज किये जा रहे हैं।

रिकॉर्ड को ऑनलाइन करते समय तहसील हनुमानगढ़ के अलग-अलग गांवो के लगभग

850 खाते ऐसे थे जिनमें खातेदारों की भूमि का योग, खाता के कुल योग से मिलान नहीं हो रहा था, उन्हें भू-प्रबन्ध आयुक्त के आदेशों से अपवादित दर्ज कर ऐसे समस्त खातो में समस्त प्रकार के नामांतरण दर्ज करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस प्रकार अपवादित खातों के काश्तकारों को अपनी भूमि का बेचान, रहन, खाता तकसीम, शुद्धि, लोन, ट्यूब वेल कनेक्शन आदि में भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

तहसील ऑनलाइन होने के लगभग 3 वर्ष बाद भी 850 में से केवल 70-80 खातों का ही निस्तारण हुआ है। जो कि अति मंद गति से हो रहा है और शेष लगभग 770 खाते अभी भी अपवादित श्रेणी में ही है।

अपवादित खाता का निस्तारण उपखण्ड न्यायालय में डिक्री द्वारा किया जा सकता है, परन्तु भू-राजस्व अधिनियम और काश्तकारी अधिनियम में इन्हें निस्तारण करने की प्रक्रिया काफी जटिल है। अपवादित खाता के निस्तारण हेतु प्रक्रिया में सरलीकरण किया जाना अति आवश्यक है। अन्यथा पीड़ित कृषक बिना किसी दोष के दंडित हो रहे हैं।

अतः नियम 50 के तहत सदन की कार्यवाही को स्थगित कर चर्चा कराने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़)।

हरिनगर राजस्व ग्राम को बीदासर नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलन का प्रस्ताव

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद कि नियम 50 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में हाल ही में हरिनगर के नाम से एक नया गांव बना था जो बीदासर कस्बे के पास में है। अभी 28 तारीख को वहां एस नाम के व्यक्ति द्वारा जिला कलेक्टर को लेटर लिखा जाता है, जिसमें कहा जाता है कि हरिनगर को बीदासर नगरपालिका क्षेत्र में शामिल किया जाये। उसी दिन शाम को 6 बजकर 17 मिनट पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा एसडीएम बीदासर को निर्देश दिया जाता है कि आप तथ्यों की जांच कर, ईओ से तथ्यों को प्राप्त कर अपनी अभिशंसा भिजवायें।

उसी दिन एसडीएम द्वारा तहसीलदार एवं ईओ से जांच कर भिजवा दी जाती है। जबकि 6 बजकर 17 मिनट पर उनको लेटर मिलता है। तहसीलदार का पद बीदासर में रिक्त है।

spp/rtm/06.03.2025/12.10/1h

नायब तहसीलदार को चार्ज नहीं है। दूसरे उपखंड के तहसीलदार को वहाँ चार्ज है और मज़े की बात यह है कि नगरपालिका, जो खुद बीजेपी की है, जो बीजेपी का बोर्ड है, वो उसका विरोध कर देता है कि ये अनुशंसा नहीं जानी चाहिए। ई.ओ. नगर पालिका बीदासर वहाँ से छुट्टी पर रहता है और वो अनुशंसा नहीं करता और कोई कार्मिक अनुशंसा नहीं करता तो रात को एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जो चौकीदारी करता है, राजूसिंह, उसके द्वारा

वह अनुशंसा भिजवाई जाती है ई.ओ. की मोहर लगाकर और उसी दिन एस.डी.एम. कलेक्टर को वह रिपोर्ट भेजता है, जबकि पूरा गांव विरोध कर रहा है। एस.सी. का यह गांव है, 751 इसकी जनसंख्या बताई गई है, जबकि जनगणना के बाद में यह गठित हुआ गांव है और जिसमें 495 एस.सी. के व्यक्ति हैं, जिनका जबरदस्त विरोध है। वहाँ जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, वह बीजेपी के हैं। कांग्रेस, बीजेपी ये सब विरोध कर रहे हैं। पूरा गांव विरोध कर रहा है, फिर भी एक व्यक्ति विशेष के निर्देश पर इस राजस्व गांव को नगर पालिका क्षेत्र में शामिल करने का प्रस्ताव किया जाता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस को तत्काल रोककर इस पर कार्रवाई कराएं और इस पर एक चर्चा कराये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री ललित यादव।

नीमराना में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय की स्थापना

श्री ललित यादव (मुण्डावर): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, मुझे नियम 50 पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, नीमराना उपखंड मुख्यालय पर अपर जिला एवं सेशन न्यायालय खुलवाने को लेकर के लंबे समय से वकीलों का वहाँ धरना चल रहा है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि नीमराना खंड पर वर्तमान में ग्राम न्यायालय, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संचालित हैं और वहाँ नीमराना क्षेत्र में करीब 84 गांव आते हैं वहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र है। काफी सारे हॉस्पिटल हैं और हमारा जो आखिरी का गांव लगता है, वह बहरोड़ क्षेत्र जाने के लिए करीब 70 किलोमीटर उनको वहाँ जाना पड़ता है। इसलिए बहरोड़ न्यायालय परिसर काफी दूर है। मेरा आपसे निवेदन है कि वहाँ पर वकीलों की मांग के ऊपर न्यायालय खोला जाना चाहिए, जिसमें हर वर्ष दो हजार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होती है। उसके बाद उपखण्ड सिविल न्यायालय, फौजदारी प्रकरणों की संख्या 2,500 है, जिनकी सुनवाई के लिए एडीजे संख्या-2 बहरोड़ विचाराधीन करते हैं, जिनका क्षेत्राधिकार नीमराना है। ऐसी स्थिति में नीमराना में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय खोला जाना न्यायसंगत है, जिससे आमजन एवं अधिवक्ताओं को इससे लाभ मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहरोड़ में भी काफी लंबे समय से वहाँ वकीलों की हड़ताल चल रही है। डी.जे. कोर्ट खोलने को लेकर के, वहाँ भी नया जिला कोटपूतली-बहरोड़ बना तो बहरोड़ के अंदर भी कुछ कार्यालय खोले जाने चाहिए। उसको लेकर भी हमारे वकील साथी काफी लंबे समय से धरना दे रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वहाँ भी उस इस बात को मानकर के कुछ कार्यालय वहाँ खुल जाएं। जैसे डी.जे. कोर्ट खुल जाएं तो यह रहे कि कोटपूतली-बहरोड़ जिला है, जिससे हमें भी यह लगे कि हाँ, ये बहरोड़ जिला है। इसमें कुछ कार्यालय खुले हैं। तो मेरा अनुरोध है मंत्री महोदय से, कि उनकी बात मानकर भी वहाँ भी कोर्ट को खोला जाने का आप काम करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री डूंगरराम गेदर।

राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम की छबड़ा इकाई में निगम कर्मचारियों का धरना

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 50 स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। राजस्थान प्रदेश के अंदर राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के कर्मचारी पिछले 130 दिन से धरने प्रदर्शन पर हैं और गांधीवादी तरीके से उत्पादन ज्यादा करके वो प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि राजस्थान की सरकार जिस तरह से ईआरसीपी के MOU को राजस्थान सरकार ने नहीं दिखाया, इसी तरह से ज्वांइट वेंचर के नाम से सरकार चुपके-चुपके निजी संयुक्त उद्यम के माध्यम से छबड़ा की संचालित इकाइयों को एनटीपीसी को दिया जा रहा है और इसी तरह से एनटीपीसी ने पूरे भारत के अंदर पहले भी कई निजी उद्यम स्थापित किए हैं। उनकी दक्षता का परीक्षण या ऑडिट भी किसी तरह से इस सरकार ने नहीं करवाया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एक तरफ तो राजस्थान की सरकार युवाओं को नौकरी देने के नए नए अवसर सृजन करने की घोषणाएं कर रही हैं, लेकिन दूसरी ओर अपने स्वामित्व वाली इकाइयों को बेचकर युवाओं के रोजगार को खत्म करने का काम है, वो कर रही है। राज्य सरकार व उत्पादन निगम द्वारा ज्वाइंट वेंचर की पूरी कार्रवाई को गोपनीय रखा जा रहा है, जिससे अधिकारियों व कर्मचारियों में मैं अविश्वास पैदा हुआ है, उनमें आक्रोश व्याप्त है तथा अंदेशा है कि भविष्य में पदोन्नतियां बाधित हो जाएंगी तथा थर्मलकर्मियों को समय पर वेतन, पेंशन अन्य परिलाभ, जो वर्तमान में मिल रहे हैं, वो मिलने दूभर हो जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार ज्वाइंट वेंचर, JV पर JV किए जा रहे हैं, लेकिन इन JV में वर्तमान में कार्यरत आरवीयूएन के कितने एम्प्लाई रखे जाएंगे, ये अभी तक तय नहीं है और ज्वाइंट वेंचर में नई भर्तियां कैसे की जाएंगी, यह भी अभी तय नहीं है। उनका अनुपात क्या होगा? यह भी अभी तय नहीं है। और उनके अंदर आरक्षित वर्ग जो शिड्यूल्ड कास्ट है, शिड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसी हैं, उनके लिए क्या-क्या प्रावधान होंगे, वो भी अभी तय नहीं है। इसी तरह से सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन की सुपर क्रिटिकल इकाई, जो बहुत अच्छी चल रही है, उसको भी O&M नाम की किसी एक कंपनी को देने की योजना है, वो राजस्थान की सरकार बना रही है और इससे राजस्थान के अंदर रोजगार छिनेंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ई.डब्ल्यू.एस, एम.बी.सी., ये सारे जो वर्ग हैं, उनको विशेष तौर से नौकरियों में बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए स्थगन के माध्यम से मैं आप के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार इस पर संज्ञान ले और चुपके चुपके यह काम करना बंद करे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।

श्री अध्यक्ष: पर्ची। श्री गणेश घोगरा।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

डूंगरपुर के राजकीय महाविद्यालयों में व्याख्याताओं के रिक्त पद

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, टीएसपी एरिया में मेरे विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर जिले में व्याख्याताओं के जो रिक्त पद पड़े हुए हैं, वह रिक्त पद भरे जाएं। एस.बी.पी.गवर्नमेंट कॉलेज में 8 हजार छात्र छात्राएं हैं, उसमें व्याख्याताओं के 81 पद स्वीकृत हैं और 60 पद रिक्त हैं और 21 पद भरे हुए हैं। उसमें से भी एक पद डेपुटेशन पर है, कहीं और कार्यरत है और तनख्वाह एस.बी.पी.गवर्नमेंट कॉलेज से उठ रही है। इसी तरह से राजकीय विधि महाविद्यालय के 10 पद स्वीकृत हैं। दस के दस पद ही रिक्त हैं। इसी तरह से राजकीय महाविद्यालय रामसागड़ा में 10 पद स्वीकृत हैं, दस के दस पद, ये भी रिक्त हैं। राजकीय महाविद्यालय पालदेवल में भी 10 पथ व्याख्याताओं के स्वीकृत हैं। दस के दस पद रिक्त हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से राजकीय कालीबाई भील कन्या महाविद्यालय में 25 पद स्वीकृत हैं और इसमें 15 रिक्त हैं तो जो बिछीवाड़ा में पांच पद भरे हुए हैं, उसमें से भी चार डेपुटेशन पर हैं और तनख्वाह वहाँ से उठा रहे हैं। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, टीएसपी क्षेत्र को देखते हुए, जनजाति बाहुल्य क्षेत्र को देखते हुए उन विद्यार्थियों का भविष्य खराब हो जायेगा। वो बच्चे कैसे पास होंगे? वो बच्चे गुरु के बिना क्या सीखेंगे? आगे कम्पीटिशन कैसे दे पाएंगे? सदन के माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, विनम्र निवेदन है जो रिक्त पद हैं, जल्दी से जल्दी भरे जाएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री श्रीचन्द कृपलानी।

पोस मशीनों में अनुभूत तकनीकी खामियां

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत माह फरवरी, 2025 को खाद्यान्न वितरण की अवधि बढ़ाने के लिए सरकार ने एक आदेश जारी किए हैं और वो आदेश 10 तारीख तक के हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रदेश में, जो पूरे स्टेट की बात कर रहा हूँ, प्रदेश में जो राशन वितरण हेतु राशन की दुकानों पर संचालित पोस मशीन लगी हुई हैं उस पर अचानक खराबी आने की वजह से विगत एक माह से राशन वितरण में दिक्कत आ रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यही निवेदन करूँगा कि राज्य सरकार द्वारा जो व्यवस्था में मशीन की तकनीकी खराबी आने के कारण दिक्कत आ रही है और एक माह से राशन वितरण नहीं हो पा रहा है, हालांकि आपने 10 मार्च तक इसको बढ़ाने के आदेश कर दिए हैं, लेकिन फिर भी आज पूरे राजस्थान में 10% लोग ऐसे होंगे जिनको अभी तक राशन नहीं मिला है। मैं, माननीय मंत्री महोदय जी से यह निवेदन करूँगा जब तक पूर्णतया वो मशीनें ठीक नहीं हो जाएं उस आदेश को 31 मार्च तक कर दें ताकि लोगों को राशन समय पर मिल सके और राशन नहीं मिलने की वजह से बाजार से

उनको महंगा राशन लाना पड़ रहा है, उसमें उनको राहत मिलेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप के माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूँगा कम से कम ये आश्वासन दे दें कि इसको 31 मार्च तक बढ़ा देंगे ताकि राजस्थान के गरीबों को बहुत बड़ी राहत मिल सके।

jyg/rtm/06.03.25/12.20/1j

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से आश्वासन चाहूंगा कि 31 मार्च तक इसको कर देंगे तो बचे हुए लोग हैं उनको समय पर राशन मिल जायेगा। माननीय मंत्रीजी से निवेदन कर रहा हूं, ये आपके आदेश का इंतजार कर रहे हैं कि माननीय अध्यक्ष महोदय कहें तो मैं बोल दूं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): ये बोलना चाह रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: बोलते तो अब तक खड़े हो जाते। ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य, एक मिनट। माननीय मंत्रीजी कुछ बोलना चाह रहे हैं।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात बतायी है उसमें वास्तव में कुछ लोगों को नहीं मिल पाया है तो हम 31 मार्च तक इन्होंने जो निवेदन किया उसके अनुसार 31 मार्च तक खाद्यान्न आपूर्ति का 31 मार्च तक बढ़ा देंगे।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री हरिमोहन शर्मा।

पुलिस द्वारा अपराधियों से सुरक्षा हेतु राशि जमा किये जाने का निर्णय

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का गठन ही इसलिए किया जाता है, विकास की बात तो बाद में है लेकिन कानून और व्यवस्था बनाये रखकर जानमाल की रक्षा करने का काम सरकार का है और यह उसका प्राथमिक कर्तव्य भी है। नहीं तो सरकार की आवश्यकता ही नहीं है अगर जानमाल की रक्षा न कर पाये तो।

मान्यवर, अफसोस की बात है कि आज जेल में जो गैंग, जो गैंगस्टर काम करके अपराधों को बढ़ाने के लिए वहां बैठे-बैठे आपकी कस्टडी में होते हुए अपने लोगों से, बाहर के लोगों से फिरौती वसूल करने की साजिश रचे तो पहले तो आप जेल में उन अपराधियों पर नियंत्रण नहीं रख पाये यह सबसे बड़ी आपकी विफलता है। इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद अगर जिस आदमी को दो करोड़ रुपये वसूली की धमकी दी, उसके बाद वो सुरक्षा मांगने के लिए गया तो आपके अधिकारियों ने सुना ही नहीं। दूसरी बार गया, नहीं सुना, फोन बताया, नहीं सुना, तीसरी बार जब अधिकारी आये, वो गया कि यह फिर कॉल आया है मेरे पास दो करोड़ रुपये वसूली का तब जाकर, तब जाकर आपके अधिकारियों ने, तब जाकर आपके अधिकारियों ने वेरिफाई किया तो वाकई वो उस गैंग का निकला। उस गैंग के निकलने के बाद सुरक्षा की व्यवस्था करना तो आपकी जिम्मेदारी थी, आपने सुरक्षा देने के नाम पर वहां

पर जो सुरक्षा उनको दी और उस सुरक्षा के बाद आपने उनको 76 लाख 17 हजार रुपये का बिल दिया कि आप अगर हमसे जानमाल की सुरक्षा चाहते हो तो सरकार में आपको 75 लाख रुपये जमा कराओ। ज्यादा बेहतर होता ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः सारे मैटर सीरियस हैं। ...(व्यवधान)... बैठिये। ...(व्यवधान)... पर्ची पर जवाब आवश्यक नहीं है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर विषय है। ...(व्यवधान)... आज के अख़बार में भरतपुर सांसद ने अवैध वसूली के आरोप लगाये हैं। ...(व्यवधान)... वीडियो जारी किया है, मुख्य मंत्रीजी का और गृह मंत्रीजी का...

श्री अध्यक्षः अंकित नहीं। ...(व्यवधान)... श्री अरुण चौधरी। ...(व्यवधान)... श्री अरूण चौधरी। ...(व्यवधान)... No. I can't allow it.

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में आकर नारेबाजी)

नवीन जिला निर्माण पदस्थापित कार्मिकों को जिला चयन की छूट

श्री अरूण चौधरी (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका कोटि-कोटिआभार कि आपने मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का मौका दिया। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः यह पर्ची पर नहीं, पर्ची पर आओगे तो, I will take an action. पर्ची है? पर्ची पर नहीं। ...(व्यवधान)... पर्ची पर नहीं।

श्री अरूण चौधरी (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, नवीन जिला बनने के बाद वहां पर पदस्थापित कर्मचारियों को अपना जिला चयन करने की छूट करने बाबत मैंने यह पर्ची लगायी थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि अभी हाल ही में माननीय मुख्य मंत्रीजी श्री भजन लाल जी शर्मा के द्वारा प्रदेश में आमजन के हितकारी, प्रदेश में 8 जिलों की घोषणा की, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का हृदय की गहराई से अभिनन्दन और स्वागत करता हूं कि उन्होंने ठोस निर्णय किया। मेरा एक ही पोइंट है माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सरकार से यह मांग करता हूं कि जिस प्रकार हमारे बाड़मेर और बालोतरा जिले के दो टुकड़े हुए उसमें आधे कर्मचारी बालोतरा में हैं और आधे बाड़मेर में हैं, मैं चाहता हूं कि जो कर्मचारी जिस जिले में रहना चाहता है उसको उस जिले की छूट मिलनी चाहिए, यही मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री रामस्वरूप लाम्बा। श्री रामस्वरूप लाम्बा। ...(व्यवधान)... यह अच्छा नहीं है ध्यानाकर्षण में। ध्यानाकर्षण लगाने के बाद अगर कोई सदस्य नहीं आता तो उसको आगे से किसी जगह बोलने का आप नाम काट दें। ...(व्यवधान)...

श्री सुरेश गुर्जर। ...(व्यवधान)... श्री सुरेश गुर्जर। ...(व्यवधान)...। श्री सुरेश गुर्जर। ...(व्यवधान)...

सदन की कार्यवाही 1.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.25 बजे 13.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

MLS/RTM/06.03.2025/13:00/1n

(समय: 13:00 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री श्रीचन्द कृपलानी।

याचिका

छोटी सादड़ी की ग्रा.पं. पीलीखेड़ा में आखेरपुर गांव से जाप नदी तक क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार पंचायत समिति छोटी सादड़ी में ग्रा.पं. पीलीखेड़ा में आखेरपुर गांव से जाप नदी तक क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कर डामरीकरण करवाने के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री बाबूसिंह राठौड़।

शेरगढ़ में सेखाला पुलिस चौकी का पुलिस थाने में क्रमोन्नयन एवं नाथड़ाऊ व चाबा में नवीन पुलिस चौकियों की स्वीकृति

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में पुलिस चौकी सेखाला को पुलिस थाना में क्रमोन्नत करवाने एवं नाथड़ाऊ व चाबा में नवीन पुलिस चौकी स्वीकृत करवाने के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री ललित मीना (अनुपस्थित)।

अनुदान की मांगों पर विचार। श्री गजेन्द्र सिंह।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 27 - चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की प्रस्तुति

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 27 - चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 133,28,96,25,000/- (एक सौ तैंतीस अरब अट्ठाईस करोड़ छियानवे लाख पच्चीस हजार) तक की रशि प्रदान की जाये।

(मांग संख्या 27 - चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें।)

मांग संख्या 28 - चिकित्सा शिक्षा की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 28 - चिकित्सा शिक्षा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले

व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 61,31,82,57000/- (इकसठ अरब इकतीस करोड़ बयासी लाख सत्तावन हजार) तक की रशि प्रदान की जाये।

(मांग संख्या 28 - चिकित्सा शिक्षा पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें।)

श्री अध्यक्ष: आज की बहस प्रारम्भ हो, अपने बोलने वाले ज्यादा हैं। आज 9 बजे तक दोनों पक्षों के लोग पूरी तरह बोल लें, दोनों माननीय सचेतकों से भी कह रहा हूं, टाइम इस तरह एडजस्ट करें, निर्दलीय समेत 9 बजे तक बहस, 9 बजे माननीय मंत्री जी इसका उत्तर दें तथा 10 बजे तक सदन की कार्यवाही समाप्त हो, नहीं तो आज भी मैं देख रहा था, कल की थकावट अभी भी सबकी दूर हुई नहीं है।

श्री कालीचरण सराफ।

मांग संख्या 27 - चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व

मांग संख्या 28 - चिकित्सा शिक्षा पर विचार

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27 - चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व मांग संख्या 28 - चिकित्सा शिक्षा पर विचार-विमर्श हो रहा है। मैं भी इन दोनों मांगों पर अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। सबसे पहले तो माननीय मुख्य मंत्री जी, उप मुख्य मंत्री, वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद पहली बार स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पहले बजट में 27 हजार 760 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा। पूरे बजट का 8.26 प्रतिशत केवल चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर खर्च होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान भाजपा सरकार का पहला बजट जुलाई में पारित हुआ। 7 महीने के छोटे-से कार्यकाल में हमारी सरकार की यह कोशिश रही कि प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा मिले, छोटे शहरों व कस्बों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी दूर हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के लोकप्रिय प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी 2014 में जब देश के प्रधान मंत्री बने तो उन्होंने इस लक्ष्य ''सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास'' की घोषणा की। हमारे देश के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज होने चाहिये, यह उन्होंने घोषणा की। उसी के अनुरूप देश की आजादी के बाद हमारे राजस्थान में केवल 7 मेडिकल कॉलेज थे।

जयपुर में था, उदयपुर में था, कोटा में था, जोधपुर में था, बीकानेर और झालावाड़ में था। चरणबद्ध रूप से आज मुझे खुशी है यह कहते हुए कि सभी जो पुराने जिले थे, उनमें मेडिकल कॉलेज खुल गये। पूर्ववर्ती सरकार में हमारे अशोक गहलोत जी मुख्य मंत्री, उनकी तो राजनीति करने की आदत तो उन्होंने 3 मेडिकल कॉलेज जो रह गये थे, उनके लिए कहा कि केन्द्रीय सरकार पैसा नहीं देती तो क्या मतलब है, हम वो खोलेंगे और उसके लिए 1 हजार करोड़ की घोषणा की। क्या हुआ? मैं लीडर ऑफ अपोजिशन को पूछना चाहता हूं कि 1 हजार करोड़ की पूर्व मुख्य मंत्री जी ने जो घोषणा की थी, वह केवल एक चुनावी घोषणा रह गयी और उसमें कुछ भी नहीं हुआ।

(समय: बजे)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

हमारे मुख्य मंत्री जी के नये कॉलेज खुले। इसमें बारां, बांसवाड़ा, झुंझुनूं, नागौर और सवाई माधोपुर, नये मेडिकल कॉलेज तो खोल दिये पिछली सरकार ने, पर वहां पर डॉक्टर्स नहीं, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं, नर्सिंग स्टाफ नहीं। निजी क्षेत्र में जोधपुर में दो और कोटा में एक नया मेडिकल कॉलेज खुला। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जहां एमबीबीएस की 850 सीटों में बढ़ोतरी हुई, पीजी में 353 तथा सुपर स्पेशियलिटी की 46 सीटों में वृद्धि हुई। हमारी सरकार ने जो बजट घोषणा की थी कि हम चिकित्सा शिक्षा में एक वर्ष के दौरान रिक्त पदों को भरने का कार्य प्राथमिकता से करेंगे, उसी के अनुरूप एक वर्ष में राजमेस के प्राचार्य के साथ 665 चिकित्सा शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है।

इतना ही नहीं, राजमेस के मेडिकल कॉलेजों में इस वर्ष फैकल्टी में कुल 1 हजार 192 नवीन पदों का सृजन किया गया है। वहीं 4 हजार 466 नर्सिंग तथा 676 पैरामेडिकल के रिक्त पदों को भरने के लिए राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड को कुल 5 हजार 142 पदों के लिए अभ्यर्थना भिजवायी जा चुकी है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो-जो घोषणाएं की थीं पहले बजट में, उनको कार्य रूप में परिणत किया। मैं यदि उन सबका वर्णन करूंगा तो समय ज्यादा हो जायेगा, पर मैं बताना चाहता हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है, वह करती है और जो करती है, वह कहती है। इसी प्रकार से, इस बार भी बजट में जो घोषणाएं हुई हैं, उनको भी निश्चित रूप से हमारी सरकार पूरा करेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में करीब 3 हजार छोटे-बड़े सरकारी अस्पताल हैं, जिनमें से 2500 से ज्यादा अस्पताल छोटे जिलों और दूर-दराज के गांवों में हैं। 75 प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मी, चाहे वे डॉक्टर हों, नर्सिंगकर्मी हों, चाहे पैरामेडिकल का स्टाफ हो, उनकी पोस्टिंग इन-इन स्थानों पर होती है, परन्तु जहां उनकी पोस्टिंग होती है, वहां वे जाना नहीं चाहते। चाहे सरकार किसी भी दल की हो, अपने राजनीतिक रसूखों के चलते वे शहरों में डेपुटेशन पर लग जाते हैं और उसका परिणाम क्या होता है कि दूर-दराज के गांवों में रहने वाला गरीब व्यक्ति यदि बीमार होता है तो या तो वह जिला अस्पताल में जाता है या सम्भागीय केन्द्र पर जाता है और यदि कोई बहुत ज्यादा गम्भीर बीमारी है तो वह राजस्थान की राजधानी जयपुर में इलाज कराने के लिए जयपुर में आता है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि नये डॉक्टर्स की नियुक्ति हो तो कम से कम उससे एक बॉन्ड भरवाएं, 50 लाख का बॉन्ड भरवाएं और उसको पाबन्द करें, क्योंकि सरकार की एक नियुक्ति में 30 से 35 लाख रुपया खर्चा होता है। उससे आप बॉन्ड भरवाएं कि उसे पांच साल तक दूर-दराज के गांवों में पहली पोस्टिंग के लिए जाना पड़ेगा। यही शर्त पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ के लिए होनी चाहिये। मैं तो यह भी मांग करना चाहूंगा कि

लोगों का समुचित इलाज हो, दूर-दराज के गांवों में रहने वालों का इलाज हो, इसके लिए जैसे गुजरात में ट्रांसफर की पॉलिसी है, महाराष्ट्र में ट्रांसफर की पॉलिसी है, कई स्टेट्स में ट्रांसफर की पॉलिसी है, यहां पर भी यदि ट्रांसफर पॉलिसी कम से कम बाकी जगह की रहने दीजिये, पर लोगों को अच्छा इलाज मिले, इसके लिए डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए निश्चित रूप् से ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिये।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा, कितनी मजेदार बात है कि जो शहर में डॉक्टर लगता है, उसको शहरी भत्ता देते हैं हम, मकान किराया देते हैं, यह गलत है। इनका यह भत्ता बन्द करिये और जो गांवों में पोस्टिंग होती है डॉक्टरों की, उसको आप 15-20 परसेंट अतिरिक्त दीजिये, इंसेंटिव दीजिये।

MKD/RTM/06.03.2025/13:10/1o

मेरे कई डॉक्टर मित्र हैं, उनसे बातचीत होती रहती है तो वे कहते हैं कि साहब, हम तो गांवों में सर्विस कर लेंगे, पर हमारे बच्चे, क्योंकि गांवों में अच्छे स्कूल नहीं हैं तो वहां कैसे पढ़ेंगे।

मैं यह भी मांग करना चाहूंगा, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी कि जो जयपुर के अच्छे स्कूल हैं, जो सम्भागीय केन्द्रों पर अच्छे स्कूल हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं, जैसे एसएमएस स्कूल है, विद्याश्रम है, माहेश्वरी पब्लिक स्कूल है, नीरजा मोदी स्कूल है तो इनमें प्राथमिकता के आधार पर इनके बच्चों के लिए सीटों का आरक्षण हो। जिससे उनका यहां एडमिशन हो जाए और वे डॉक्टर निश्चिंत होकर, जहां उनकी पोस्टिंग है, वहां अपना काम कर सके।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि एसएमएस में न्यूरोलॉजी का वार्ड है। वहां के सात डॉक्टर, डॉ. भावना शर्मा, टी.सी. श्रीवास्तव, डॉ. दिनेश खण्डेलवाल, डॉ. शैलेष दीक्षित, डॉ. राकेश अग्रवाल, डॉ. किशोर कुमार, डॉ. दीपक जैन और राहुल गुप्ता। इन्होंने खुद के पैसों से सात लाख रुपये खर्च करके 45 बेड का न्यूरोलॉजी का जो वार्ड है, उसका रिनोवेशन करवाया।

आज जब हम उस न्यूरोलॉजी के वार्ड में जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी निजी हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजी वार्ड में आ गए। इसके लिए मैं आपके माध्यम से उन डॉक्टरों को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं तो आपको यह कहूंगा कि उनको प्रशंसा पत्र दीजिये, जिससे बाकी डिपार्टमेंट में जो डॉक्टर्स हैं, उनको भी इससे नसीहत मिले और वे भी इसके लिए काम करें।

इसी प्रकार राजस्थान देश का पहला राज्य है, जहां हर जिला अस्पताल में लीवर क्लिनिक खोलने का आपने निर्णय किया है। 10 जगह ट्रायल चल रहा है, इलाज के साथ ट्रांसप्लांट भी होंगे।

इसी प्रकार से एचआइवी पीड़ित महिलाओं की स्क्रीनिंग के साथ-साथ वीआईए तकनीकी से इलाज की सुविधा भी राजस्थान में आपने प्रारम्भ कर दी है, इसके लिए भी आपको धन्यवाद।

मैं केन्द्रीय सरकार को भी इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि मोदी जी के प्रधान मंत्री बनने के बाद, उन्होंने डेढ़ लाख रुपये तक का इलाज, हाइवेज पर जो लोग एक्सीडेंट में घायल हो जाते हैं, उनका डेढ़ लाख का इलाज मुफ्त, चाहे वह निजी अस्पताल हो, जितना पास में निजी अस्पताल होगा, उसको भी यह इलाज करना पड़ेगा।

पहले पायलट प्रोजेक्ट हरियाणा और पंजाब और 6 राज्यों में चलाया था। वह सफल हो गया। अब मुझे खुशी है कि वह पूरे देश में लागू होगा तो राजस्थान में भी यह लागू होगा। मरीजों का जो गोल्डन पीरियड होता है, तो इससे बच सकेंगे।

इसी प्रकार से एसएमएस हॉस्पिटल, हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। यहां पर लगभग 15 हजार की ओपीडी है। वसुन्धरा जी राजस्थान की मुख्य मंत्री थी तो हमने एसएमएस हॉस्पिटल और ट्रोमा सेंटर के बीच में अंडरपास बनवाया था।

मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपने जवाब में यह बतायें। मेडिकल कॉलेज और एसएमएस हॉस्पिटल के बीच में जेएलएन मार्ग आता है। वहां आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। रेजीडेंट्स डॉक्टर्स भी आते हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं, मरीज भी आते हैं, तो इसके लिए एसएमएस मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के बीच अंडरपास होना चाहिए।

इसी प्रकार से, आर्किटेक्चर अनूप बरतरिया जी, मेरी उनसे बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा कि पूरा प्रोजेक्ट बना रखा है कि एसएमएस हॉस्पिटल में रिंग रोड बन जाए। मान लीजिए, किसी को धन्वंतरि से इमरजेंसी जाना है, तो वह मरीज ढूंढता रहता है कि कैसे जाऊं। यदि रिंग रोड होगा और होटल्स में जैसे इलेक्ट्रिक वैन चलती है, उसी प्रकार से यदि वह चले तो मरीजों को और परिजनों को दूसरे स्थान पर जाने में सुविधा रहेगी।

एक बात मैं और कहना चाहूंगा। मैंने पहले भी कहा है, आपने महाराजा कॉलेज की जमीन मांगी, उन्होंने मना कर दिया। आपके सी एस और डी जी, इन दोनों के बंगले मुख्य मंत्री जी को कभी काम हो, किसी मंत्री को काम हो, तो उनको वहां जाने में टाइम लगता है। मैं कहूंगा कि ये 6-6 हजार गज में ये दोनों बंगले हैं, इनको आप खाली करवाये और एसएमएस हॉस्पिटल को दीजिये। इनको मुख्य मंत्री जी के बगल में, जो मंत्रियों के लिए आरक्षित हैं, ऐसे बंगलों में इनको शिफ्ट कीजिये। जिससे कि वे कभी भी सरकार का काम पड़ता रहता है, तो वे वहां ठीक रहेंगे। सी एस और डी जी के बंगले वहीं बनाइये। इस जगह को खाली करवाइये।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): कौन-से मंत्री का बंगला खाली करवाये?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): हां, करवा लो खाली। वे तो अपनी ही सरकार के लोग हैं। एसएमएस हॉस्पिटल का निर्माण 1936 में हुआ था। कभी फाल्स सीलिंग गिरती है, कभी चूना गिरता है। हमने इसका एमएनआइटी से सर्वे करवाया था और एमएनआइटी ने इस बिल्डिंग को 88 साल हो गये, जर्जर घोषित कर रखा है।

हम एक साथ तो पूरी बिल्डिंग को डिमोलिस नहीं कर सकते, परन्तु मैं यह चाहूंगा कि आप इसका जो एक-एक हिस्सा है, इसको डिमोलिस करके और यदि इसका रिनोवेशन होगा,

क्योंकि कभी कोई बड़ा हादसा हो गया, जैसे अभी कुम्भ में हादसा हुआ ना, तो विपक्षी दलों को मौका मिल जाएगा। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, इसलिए एक-एक विंग का रिनोवेशन कराने के लिए आप फंड रिलीज करें और इसको रिनोवेट करवाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि एसएमएस हॉस्पिटल में 15 हजार की ओपीडी है। जब वसुन्धरा जी की सरकार थी तो हमने जयपुर के चारों ओर, जयपुर के पश्चिम में कांवटिया हॉस्पिटल, जयपुर के उत्तर में गणगौरी हॉस्पिटल, जयपुर के पूर्व में सैटेलाइट हॉस्पिटल सेठी कॉलोनी और जयपुर के दक्षिण में जयपुरिया हॉस्पिटल। हमने इनको स्ट्रेंथन किया और वहां सुविधाएं उपलब्ध करवाईं। उसका परिणाम यह था कि कांवटिया में दो हजार की जगह चार हजार का आउटडोर हो गया। गणगौरी हॉस्पिटल में एक हजार की जगह दो हजार का आउटडोर हो गया। सेठी कॉलोनी का भी आउटडोर बढ़ गया। जयपुरिया हॉस्पिटल, जो मेरी कांस्टीट्यूएंसी में आता है, वहां केवल साढ़े तीन सौ का आउटडोर था, वह बढ़कर साढ़े तीन, चार हजार का हो गया। हमने वहां पर सुविधाएं उपलब्ध करवाईं। सीटी स्कैन की सुविधा, एमआरआइ की सुविधा, टू डी इको की सुविधा, टीएमटी की सुविधा, एसएनसीयू वार्ड बनवाया, ट्रोमा वार्ड, इमरजेंसी वार्ड, नये मेडिकल कॉटेज और टाटा ट्रस्ट द्वारा टीआइसीयू कॉटेज वार्ड आदि की सुविधाएं उपलब्ध करवाईं, पर हुआ क्या? जो हमारी पिछली सरकार थी, हमारे जो तत्कालीन मंत्री थे, उन्होंने एक साथ वहां से अधिशेष बताकर 27 डॉक्टर्स को हटा दिया। जो 11 डॉक्टर्स प्रतिनियुक्ति पर लगे हुए थे, उनको हटा दिया।

आज वहां स्थिति यह है कि जहां पहले 100 बैड थे, उसकी जगह 150 बेड हुए। 2013 में 100 बेड थे, 2015 में 150 बेड हुए और 2017 में 470 बेड हो गये। आप देखिये, 400-500 लोगों की सर्जरी वहां पर हो रही थी। महिलाओं की ढाई सौ से तीन सौ की संख्या में डिलीवरी हो रही थीं। आईपीडी में ऑक्यूपेंसी 95 परसेंट थी, परन्तु डॉक्टरों के हटने के कारण, क्योंकि स्वीकृत पद नहीं हैं, स्वीकृत पद केवल 48 हैं।

आपने इस बार बजट में घोषणा की है कि आप 750 नये चिकित्सक लगायेंगे तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जयपुरिया हॉस्पिटल में कम से कम 100 नये डॉक्टरों के पद स्वीकृत करें और वहां 100 डॉक्टर नये लगाये। इसी प्रकार से पैरामेडिकल स्टाफ भी वहां पर लगायें। जिससे एसएनसीयू, ट्रोमा वार्ड, एमआरआई, सीटी स्कैन, इमरजेंसी, नये वार्ड, ये सब जो स्टाफ की कमी के कारण बन्द हैं, वे चालू हो सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं, केवल मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र के ही नहीं, मालवीय नगर, चाकसू, सांगानेर, बस्सी यहां के लोग भी यहां इलाज कराने के लिए आते हैं।

Bhs/Rtm/06.03.25/13.20/1p

एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जब यह आर.यू.एच.एस. यूनिवर्सिटी बना था उस समय क्योंकि उसका कोई सेपरेट हॉस्पिटल नहीं था इसलिये जयपुरिया हॉस्पिटल को उसके साथ एफिलियेटेड कर दिया था क्योंकि कॉलेज के साथ हॉस्पिटल होना आवश्यक है। अब वहां आर.यू.एच.एस. हॉस्पिटल बन गया तो मैं यह चाहूंगा कि जैसे कांवटिया हॉस्पिटल, जैसे गणगौरी हॉस्पिटल, जैसे सेटेलाइट हॉस्पिटल, सेठी कॉलोनी, ये एस.एम.एस. हॉस्पिटल के साथ एफिलियेटेड हैं वैसे ही इसको आर.यू.एच.एस. से हटा करके और एम.एम.एस. हॉस्पिटल से एफिलियेटेड करिये क्योंकि आर.यू.एच.एस. इसमें ध्यान नहीं दे पा रहा है।

इसी प्रकार से मैं आपको कहना चाहूंगा कि बच्चों का सबसे बड़ा हॉस्पिटल राजस्थान का ही नहीं उत्तर भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जे.के. लॉन हॉस्पिटल बच्चों का हॉस्पिटल। अब पूरे प्रदेश के ही नहीं पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के लोग भी अपना इलाज कराने के लिये वहां पर आते हैं। वहां पर केवल नौ सौ बेड हैं। प्रति वर्ष चार लाख पच्चीस हजार से ज्यादा की ओ.पी.डी. है। पचास हजार का आई.पी.डी. है और जब मौसमी बीमारियां होती हैं उस समय यह स्थिति होती है कि बच्चों के इलाज के लिये एक-एक बेड पर तीन-तीन बच्चे सुलाने पड़ते हैं। इस बात के लिये तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा और आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बच्चों की दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिये जे.के. लॉन हॉस्पिटल में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस फोर रेयर डिजीज की स्थापना के लिये स्वीकृति प्रदान कर दी। सरकार के इस निर्णय से वहां दुर्लभ बीमारियों के साथ-साथ जिन्दगी की जंग लड़ रहे बच्चों का इलाज हो पायेगा। परन्तु मैं इसके साथ-साथ एक बात और कहना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार के सहयोग से पूर्ववर्ती सरकार ने, आई.पी.डी. टावर बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने 11 सौ करोड़ रुपये आवंटित किये थे, उसमें से 70 प्रतिशत पैसा केन्द्रीय सरकार का था और 30 प्रतिशत पैसा राजस्थान सरकार का था। पांच सौ करोड़ रुपये आपने एस.एम.एस. हॉस्पिटल के लिये आवंटित किये। 75 करोड़ रुपये जनाना हॉस्पिटल, चांदपोल के लिये आवंटित किये। 117 करोड़ रुपये महिला चिकित्सालय, 108 करोड़ रुपये गणगौरी हॉस्पिटल के लिये, पचास करोड़ रुपये टी.बी. हॉस्पिटल के लिये और 250 करोड़ रुपये आपने स्टेट कैन्सर हॉस्पिटल के लिये आई.पी.डी. बनाने के लिये दिये। परन्तु सबसे बड़ा बच्चों का हॉस्पिटल, इसके लिये आपने एक पैसा भी नहीं दिया।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि हमने इसका पूरा एस्टीमेट बनवा लिया है। अस्सी करोड़ रुपये की लागत से इसका आई.पी.डी. टावर दस मंजिल का बनेगा। इसमें कांफ्रेंस हॉल भी होगा। मेडिकल कॉलेज से एफिलियेटेड है तो यहां पी.जी. और यू.जी. के स्टूडेंट भी आते हैं उनके लिये कांफ्रेंस हॉल व केन्टीन भी होगी। अभी बच्चों के लिये नौ सौ बेड हैं उनके लिये कम से कम पन्द्रह सौ बेड होने चाहिये। इसके लिये हम आपसे जगह भी नहीं मांगेंगे। जगह भी हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। आप तो, पिछली सरकार ने बाकी हॉस्पिटल्स में आई.पी.डी. टॉवर बनाने के लिये पैसा आवंटित किया, मैं आपसे अनुरोध करना

चाहूंगा कि जे.के. लॉन हॉस्पिटल जो प्रदेश का बच्चों का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, आई.पी.डी. टॉवर बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान करें।

अब मैं आपको बताना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, 200 करोड़ रुपये की लागत से एस.एम.एस. सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल का निर्माण किया, तीन साल बीतने के बाद भी अभी तक वहां लैब की सुविधा नहीं है। अभी तक लैब की सुविधा नहीं हो पायी है। इसकी वजह क्या है कि लैब में जो जांच मशीनें होनी चाहिये वो अभी तक वहां पर उपलब्ध नहीं हैं। यहां यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, गेस्ट्रोएंट्रोलॉजी जैसे विभाग की ओ.पी.डी., आई.पी.डी., सर्जरी और ट्रांसप्लांट हो रहे हैं एवं लैब की सुविधा नहीं होने के कारण लैब के नाम पर कलेक्शन सेन्टर संचालित हो रहा है। जांचें, रोजाना एक हजार से ज्यादा सेम्पल एस.एम.एस. हॉस्पिटल की सेन्टर लैब में भेजे जा रहे हैं। परिजन जहां गम्भीर किडनी और लीवर फेल्योर जैसी गम्भीर समस्याएं होती हैं, जिन्हें तत्काल जांच की आवश्यकता होती है, ऐसे मरीजों के परिजनों को निजी अस्पतालों में जांच के लिये जाना पड़ता है। अतः जल्द से जल्द जांच के लिये आवश्यक मशीनें जो अभी तक नहीं आयी हैं उनकी आप स्वीकृति प्रदान करें और उनको मंगवाये जाने का कष्ट करें।

मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आर.यू.एच.एस. हॉस्पिटल को एम्स की तर्ज पर रिम्स में बदलने की घोषणा तो की परन्तु अभी तक मुख्य मंत्री जी की घोषणा धरातल पर नहीं उतर पायी है। मैं आपको आर.यू.एच.एस. हॉस्पिटल के बारे में बताना चाहूंगा कि वसुन्धरा जी जब राजस्थान की मुख्य मंत्री थी उस समय राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार के सहयोग से आर.यू.एच.एस. हॉस्पिटल का निर्माण करवाया और आपको यह जानकर खुशी होगी कि उसमें 12 सौ बेड की कैपेसिटी है। दो सौ बेड आई.सी.यू. के लिये रिजर्व हैं। जब कोरोना काल आया था तो वहां के डॉक्टर्स ने बड़ा शानदार काम किया। नहीं तो क्या पता कितनी जानें जाती। मैं गवाह हूं। मैं भी वहां दस दिन कोरोना हो गया था, तो मैं भी वहां भर्ती रहा और तत्कालीन चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी भी वहां भर्ती रहे और वहां उनका समुचित इलाज हुआ और आज स्थिति यह है कि पूर्ववर्ती सरकार ने वहां न तो फैकल्टी नॉमिनेट की, न वहां पैरा मेडिकल स्टाफ लगाया, न वहां नर्सिंग स्टाफ लगाया। आपने अभी वहां पच्चीस-तीस डॉक्टर लगाये हैं परन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं है। 12 सौ बेड की कैपेसिटी का हॉस्पिटल फुलफ्लेज्ड चले और पर्याप्त मात्रा में वहां डॉक्टर्स, नर्सिंग, पैरा मेडिकल स्टाफ यदि लगेगा तो निश्चित रूप से इसका फायदा लोगों को मिलेगा।

एक बात मैंने पिछली बार भी कही थी और अबकी बार फिर कहना चाहता हूं कि उदयपुर में पूर्व मुख्य मंत्री मोहन लाल जी सुखाड़िया, उनके नाम से उदयपुर यूनिवर्सिटी का नाम हमने मोहन लाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी कर दिया। पूर्व मुख्य मंत्री हरिदेव जी जोशी, पत्रकारिता यूनिवर्सिटी का नाम उनके नाम से कर दिया। मैं चाहूंगा कि हमारे प्रदेश के तीन बार मुख्य मंत्री रहे और हमारे देश के उप राष्ट्रपति रहे आदरणीय भैरोंसिंह जी शेखावत के नाम से आप आर.यू.एच.एस. हॉस्पिटल का नाम यदि आप भैरोंसिंह शेखावत यूनिवर्सिटी

ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज कर देंगे तो हमारे पूरे प्रदेश में इसकी वाहवाही होगी।

एक बात मैं आपके माध्यम से और कहना चाहूंगा कि मैंने एक मामला उठाया था, आपने जवाब भी दिया था कि आर.एम.एस.सी.एल. में जो डायलिसिस मशीनें खरीदे जाने में अनियमितताएं हुई थीं, आपने वित्त विभाग से उसकी जांच भी करवायी। वित्त विभाग ने जांच करके उसमें कमियां भी पाई, विसंगतियां भी पाई पर आपने उसमें कार्यवाही क्या की? इसके बारे में निश्चित रूप से आप बतायेंगे तो ठीक रहेगा। इसी प्रकार से कांवटिया हॉस्पिटल, उसके बगल में ट्रॉमा सेन्टर के लिये और सुपर स्पेशियलिटी बनाने के लिये जमीन उपलब्ध थी। आप यह देखिये कि जहां 78 हजार रुपये वर्ग गज की बोली लगी उस जमीन को आपने 60 हजार रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से बेच दिया। पांच करोड़ में वह जमीन बेच दी। निश्चित रूप से इसमें घपला हुआ है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप इसकी जांच करवायें और जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करें और इस नीलामी को आप निरस्त करें क्योंकि कांवटिया हॉस्पिटल पश्चिमी जयपुर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और वहां यदि जो जमीन है वहां यदि ट्रॉमा सेन्टर बनेगा, सुपर स्पेशियलिटी का हॉस्पिटल बनेगा तो निश्चित रूप से उससे जयपुर की जनता को निजात मिलेगी। इसलिये मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि उस नीलामी को कैन्सिल करें ओर उस नीलामी में जो घपला हुआ है जो घोटाला हुआ है ऐसे अधिकारियों को चिह्नित करके एक जांच कमेटी बैठाइये और जांच करके जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की कृपा करें।

माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने कहा था कि तीस मिनट में बोलना है और 29 मिनट और 10 सेकंड हुए हैं इसलिये आपके आदेश की पालना करते हुए मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं और यही अनुरोध करना चाहता हूं कि जो मैंने बातें कहीं हैं उन पर आप गम्भीरता से विचार करें और उन पर कार्यवाही करें। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः शान्त रहें। श्री हरीश चौधरी।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): सभापति महोदय, जो यह स्वास्थ्य है, हैल्थ है, यह व्यक्तिगत और समाज का आधार क्या है, एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिये अच्छी सांस जो हवा है, अच्छा पानी, आहार और जो फिजिकल फिटनेस है हमारे शरीर की,

Kas/rtm/06.03.2025/13.30/1q

इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या इस सवाल का उत्तर जानने का राजस्थान के हर नागरिक को अधिकार है या नहीं है? इसकी कोई न कोई तो जिम्मेदारी लेगा। यह जिम्मेदारी हेल्थ डिपार्टमेंट की है या किसी और डिपार्टमेंट की है? अगर हेल्थ डिपार्टमेंट की है, तो जो राजस्थान में इन चारों पैरामीटर्स की स्थिति है, उसके सन्दर्भ में क्या हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिये? आज जो हम लोग सांस ले रहे हैं, उस हवा के राजस्थान में क्या हालात हैं, यह कौन बतायेगा? हेल्थ डिपार्टमेंट बतायेगा या नहीं बतायेगा? आज राजस्थान में सबसे

ज्यादा प्रदूषित कोई जिला है, उसमें क्या हनुमानगढ़ है या नहीं है, इसका जवाब कौन देगा? राजस्थान में सबसे अच्छी हवा, जो एयर पॉल्यूशन के पैरामीटर्स हैं, उनमें बाड़मेर और सिरोही है या नहीं, इसका जवाब कौन देगा? सरकार और समाज के नाते जो आने वाले समय में सबसे बड़ी चुनौती है सांस की, और सांस तो सबको लेनी पड़ेगी और इसी हवा में से सांस लेनी पड़ेगी, उसके सन्दर्भ में हमको प्राथमिकता रखनी चाहिये या नहीं रखनी चाहिये? अवेयरनैस कैम्पेन या और किसी माध्यम से हम लोगों को इस बात के लिये अपने जीवन की व्यवस्था में प्राथमिकता बनानी चाहिये या नहीं बनानी चाहिये? अगर नहीं बनायेंगे, तो आने वाली पीढ़ी हम लोगों के लिये अच्छी सोच नहीं रखेगी। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।

पानी के सन्दर्भ में, हम लोग जो पानी पी रहे हैं, उस पानी की गुणवत्ता क्या है? आईजीएनपी के माध्यम से जो पानी एक बड़े हिस्से में मिल रहा है और दूसरे पानी के स्रोतों से मिल रहा है, क्या वह पानी सर्वोत्तम है या नहीं? अगर सर्वोत्तम है, तो सरकार को और विशेषकर हेल्थ डिपार्टमेंट को यह कहना चाहिये कि जो सर्वोत्तम पानी है और जिसको पी सकते हैं, वह आप लोगों को आईजीएनपी के माध्यम से मिल रहा है और नहीं है, तो ईमानदारी से यह कहना चाहिये कि नहीं, यह सर्वोत्तम पानी नहीं है। जो बरसात का पानी टांकों के माध्यम से हम लोग पी रहे हैं, वो अगर सबसे बेहतरीन पानी है, तो यह कौन कहेगा? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी हेल्थ डिपार्टमेंट की है। इसकी तुलना करने की जिम्मेदारी हेल्थ डिपार्टमेंट की है। चाहे अंडरग्राउंड वाटर, जिसमें फ्लोराइड कंटेंट हैं, बोलने के लिये तो बोल देते हैं कि आर ओ वॉटर। आर ओ वॉटर के लिये जो स्पेशलिस्ट है यू एन का या बाकी जो ग्लोबल स्पेशलिस्ट हैं, वो आरओ वॉटर के लिये क्या सोच रखते हैं, इसको कौन बतायेगा? सिर्फ दोषारोपण करते हैं। आज पूरे के पूरे तंत्र में अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं है और इसका दोषी कौन हैं? दोषी हम लोग हैं। कोई भी मंत्री खड़ा होकर यह बात करता है, वो उसका चरित्र दिखाता है। मैं जब वहां पर मंत्री के तौर पर था, मैंने कभी भी यह बात नहीं की कि पहले की सरकार ने यह किया। मैं राजस्व मंत्री हूं, चाहे पहले की सरकार है या आज की सरकार है, मेरे मंत्री रहते हुए पूर्णतः कोई जिम्मेदार है, तो मंत्री के तौर पर मैं हूं। मैंने कभी दूसरी बात नहीं की, आप रिकार्ड देख लें। अगर आप यह बात करोगे, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन में क्या संदेश दे रहे हो? एक ब्यूरोक्रेट जो अपनी कुर्सी पर बैठा है, वह पूरी कि पूरी जिम्मेदारी इस तरह से अपने से दूर रख ले कि देखो, पहले के ब्यूरोक्रेट ने नहीं किया। यह संदेश अपन लोग दे रहे हैं, यह जिम्मेदारी हम लोगों की है।

सभापति महोदय, पानी के सन्दर्भ में मैं आपके माध्यम से देश और दुनिया को बताना चाहता हूं, दुनिया में इजरायल मॉडल की बहुत चर्चा होती है, उस इजरायल मॉडल से बेहतरीन पीने के पानी का स्रोत का मॉडल कहीं है, तो इसी राजस्थान में है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि उसका प्रचार-प्रसार हम लोग नहीं करते हैं। थार में जो टांके बने हुए हैं, बहुत कम बारिश के बावजूद उन टांकों में जो क्वालिटी ऑफ वॉटर मिल रहा है, आज वह हम

लोगों के पास है, लेकिन उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, उसको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। बाड़मेर में नरेगा के माध्यम से एक लाख टांके बनाये गये। इस तरह का दुनिया में उदाहरण नहीं है। यह समाज की स्वीकार्य की हुई पद्धति है, पर इसके बारे में हम अवेयरनैस नहीं कर रहे हैं। बड़ा सा किसी व्यक्ति विशेष का होर्डिंग बना देंगे, उसका महिमा-मंडन करना हमारी प्राथमिकता है, हमारे प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य की हम लोगों की प्राथमिकता नहीं है। यह एप्रोच कौन बदलेगा? यह एप्रोच हम लोग नहीं बदलेंगे, तो कौन बदलेगा?

सभापति महोदय, आज हम लोग राजस्थान के नागरिकों को खिला क्या रहे हैं? अगर इसका ईमानदारी से कोई उत्तर ढूंढने लगेगा, तो उसको रात को नींद नहीं आयेगी। कितना मिलावटी खाना हम लोग खा रहे हैं। कम से कम इसकी शुरूआत तो करें हम लोग, जो सच्चाई है वो समाज में हम लोग बताएं। राजस्थान की जनता को बताएं कि जो खाना वो खा रहे हैं, उसकी गुणवत्ता क्या है। यह कौन बतायेगा? इंडियन एक्सप्रेस में बड़ा आर्टिकल आया कि वेजिटेबल ऑयल अगर दुनिया में सबसे ज्यादा कहीं आ रहा है, तो हिन्दुस्तान में आ रहा है। उस वेजिटेबल ऑयल से हमारे स्वास्थ्य पर क्या फर्क पड़ रहा है, सही है या गलत है, उसकी चर्चा करके उसका निर्णय कौन करेगा? आज हम लोग जो सब्जियां खा रहे हैं, आज जो हम फल खा रहे हैं, उसमें पेस्टिसाइड कंटेंट कितने हैं? हम फल और सब्जियां खा रहे हैं या जहर खा रहे हैं? आज जो गेहूं हम खा रहे हैं, उस गेहूं के क्या हालात हैं? आज दूध कैसा मिल रहा है, हम सबको पता है, पर आंखें बंद कर रहे हैं, मुंह मोड़ रहे हैं। राजस्थान में कितना मिलावटी दूध आ रहा है और कानून हम लोगों ने क्या बना रखा है, मिलावट। क्या यह मिलावट है? दूध में अगर पानी है, तो वह मिलावट है? दूध में अगर यूरिया है, तो यह मिलावट है क्या? यह इंसान को जहर देने का काम हो रहा है और कानून में नियम नहीं बनाने की हमारी प्राथमिकता है। कौन बनायेगा? यह सदन बनायेगा। तेरा-मेरा करके हम लोग अपनी जिम्मेदारी को धकेल रहे हैं और राजस्थान को जहर खिलाया जा रहा है। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि जो दूध दे रहे हैं, वह जहर है। आज हम लोग बहुत कहते हैं, जय गौ माता। पूरी कि पूरी प्राथमिकता गाय के पूजन में लगाये रखते हैं, पर आज राजस्थान को घी कैसा मिल रहा है? पहले डाक्टर लोगों की घी के सन्दर्भ में अलग ओपिनियन थी, दुनिया में वो ओपिनियन बदली है, लेकिन बाजार से जो घी आ रहा है, वो कैसा मिल रहा है? सभापति महोदय, वह 90 प्रतिशत से ज्यादा खाने योग्य नहीं है। हम संतुष्ट हैं कि हम गाय का घी खा रहे हैं। गाय की नस्ल क्या है, ज्यादा से ज्यादा इस सवाल का उत्तर ढूंढने के बाद हम लोग पूर्णतः संतुष्ट हो जाते हैं कि नहीं? अच्छी गाय की नस्ल है, गिर की है, थारपारकर है, साहीवाल की है तो हमको बेहतरीन दूध और घी मिल रहा है। सभापति महोदय, गाय जो आहार ले रही है, आहार में, चारे में जो पेस्टिसाइड हैं, क्या वह दूध के माध्यम से हम लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? इसका उत्तर है, मिल रहा है। राजस्थान में कितने शुद्ध आहार से इन पशुओं के माध्यम से हम लोगों को दूध मिल रहा है, उसके प्रतिशत के अध्ययन करने का अगर कोई प्रयास करेगा तो हमें आईना अपने

आप पता चल जायेगा। ऐसी बात नहीं है कि राजस्थान में ऐसे मॉडल नहीं है, पर हमारे समाज और सरकार की प्राथमिकता नहीं है। मेरे पड़ोस में कोलू गांव में पृथ्वी सिंह कोलू हैं, अच्छा व्यापारी है। वो आहार के सन्दर्भ में प्राथमिकता रखता है। मेरे खुद के गांव से 400 किलोमीटर दूर जैसलमेर में पोचीना में उसने गायें रखी हैं और उन गायों को जो आहार दे रहा है, वह सर्वश्रेष्ठ आहार दे रहा है और उसका घी सबसे सर्वश्रेष्ठ है। छोटू सिंह जी आपको पता है। बाबू सिंह जी के माध्यम से वो घी अमित शाह जी और बाकी नेताओं के पास पहुंचा। मेरे को भी वो मिला, उम्मेदाराम जी को भी मिला और पृथ्वी सिंह जी ने मेरे को भी कहा कि आप भी अपने नेताओं को यह घी दो। मैं किस मुंह से वो घी दूं? मेरा परिवार तो किस तरह का घी खा रहा है और मैं दिखाने के लिये वो घी ले जाकर नेताओं को दूं। मैंने सोचा और मेरी हिम्मत नहीं हुई देने की, क्योंकि राजस्थान में वो घी है कितना? ....(व्यवधान).... के.के. जी, थोड़ी बहुत मुझे राजस्थान से मुहब्बत है। मैं सिर्फ पद पाने के लिये इस राजस्थान को नहीं देखता हूं। इस राजस्थान ने मेरे को बहुत कुछ दिया है।

Msk/rtm/05.03.25/1340/2a

मैं योग्य नहीं हूं, उससे ज्यादा इस राजस्थान ने मेरे को दिया है। सभापति महोदय, आहार कौन करेगा? सबसे ज्यादा खतरनाक चीज कि जो यह जहर मिला रहे हैं, उनके सन्दर्भ में हमने नियम क्या बनाये हुए हैं? बड़े कमजोर नियम बनाये हुए हैं। नॉन कॉग्नीजेबल ऑफेंस हम लोगों ने बनाये हुए हैं, सिर्फ मिलावट के लिए। उससे भी और अधिक हम लोगों के चेहरे पर एक धब्बा है कि उसके अन्तर्गत जो दोषी हैं, उनके केस विदड्रा कर रहे हैं और हम लोग सुन्न एवं मौन हैं। पूरा का पूरा सदन सुन्न और मौन है। यह मैं नहीं बताना चाह रहा हूं कि किस साल में हुए और किसने किये। वही बात हो जायेगी कि आरोप-प्रत्यारोप के अन्दर, वे ही राजस्थान के अन्दर हुए हैं। इस मिलावट के सन्दर्भ में जो केस रजिस्टर्ड हुए हैं। क्या हम लोगों के पास मानव संसाधन हैं? हम लोगों के पास हेल्थ इंस्पेक्टर्स कितने हैं? लेबोरेटरीज कितनी हैं? क्या इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे? हमारी पूरी की पूरी सोच, हमारी प्राथमिकता केंद्रित हो रखी है। बड़े-बड़े लोग, हम लोगों के परिवार शहरों में रह रहे हैं और हम उन्हीं शहरों के साथ अन्याय भी कर रहे हैं। मेरे से पूर्व वक्ता की अपनी 26 मिनट की बात के अन्दर जो पूरा केंद्रित रहा, वह जयपुर के अन्दर स्वास्थ्य की व्यवस्था एसएमएस के अन्दर अगर 15 हजार ओ पी डी आ रही है तो क्या यह एक अच्छा संकेत है? यह बिल्कुल अच्छा संकेत नहीं है। आप लोग पूरी दुनिया के अन्दर देख लें। कहीं भी जहां स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है, वह केंद्रीकृत है या विकेंद्रीकृत है, आपको उत्तर मिलेगा, वह डी-सेंट्रलाइज्ड हैं। मैं केवल यही नहीं कह रहा हूं कि आप जापान का मॉडल जो कि दुनिया के अन्दर सबसे बेहतरीन है, ऑस्ट्रेलिया का मॉडल बेहतरीन है, स्वीडन का मॉडल बेहतरीन है, उसको लागू करो, नहीं। हमारे राजस्थान की परिस्थिति से राजस्थान का मॉडल बनना चाहिए। मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि साउथ का मॉडल लेकर आ जाओ,

क्योंकि आज आंकड़े कह रहे हैं कि साउथ का मॉडल बहुत अच्छा है, मैं केरल के मॉडल के लिए भी नहीं कह रहा हूं कि वह लेकर आ जाओ, क्योंकि केरल के अन्दर, साउथ के अन्दर, जब देश आजाद हुआ और उसके बाद जो हेल्थ पैरामीटर्स हैं, उनमें कितना सुधार आया। परन्तु सीखना तो चाहिए। उनका सीखकर हम अपना खुद का मॉडल तो बनायें। पूरा का पूरा हम लोगों का फोकस हो गया है, सेंट्रलाइज्ड करो। एसएमएस कम पड़ रहा है। अगर एसएमएस कम पड़ रहा है तो क्या एसएमएस को बढ़ाना ही हल है? सभापति महोदय, यह हल नहीं है। हमको पूरी की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था डी-सेंट्रलाइज्ड करनी चाहिए। ये जो बहुत महिमामण्डन कर रहे हैं। कोरोना के वक्त में जो सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था थी, वह कहां गयी? आप कह रहे हैं कि पूरा का पूरा संसाधन वहां झोंको। पूरा का पूरा मानव संसाधन, पूरा का पूरा आर्थिक संसाधन। कोरोना के वक्त में उसने साथ नहीं दिया। कोरोना के वक्त में जो डी-सेंट्रलाइज्ड कोरोना सेंटर्स बने और छोटी-छोटी जगह बनें।

सभापति महोदय, राजस्थान को क्या चाहिए? राजस्थान को चाहिए कि जो सब-सेंटर्स, वे बेहतरीन से बेहतरीन सब-सेंटर्स कैसे बन सकें? जो पीएचसी है, उसके अन्दर व्यवस्था करें। प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए, अगर ओपीडी के लिए एमडीएम और एसएमएस में आ रहा है तो यह हम लोगों की नीतियों की गलती है। इसको पहले स्वीकार करना चाहिए कि प्राइमरी इलाज के अन्दर यदि हम लोग इन अस्पतालों में या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अन्दर क्या इस तरह की व्यवस्था नहीं बनायें? क्या सिर्फ रेफरल हॉस्पिटल होने चाहिए? जो प्राइमरी ट्रीटमेंट हैं, उन ट्रीटमेंट के लिए सब-सेंटर, पीएचसी और सीएचसी तक ही हम लोगों को करना चाहिए। अगर कोई क्रिटिकल है, फिर हम अपने मतदाताओं को खुश करने के लिए कहते हैं कि मेरी विधान सभा के अन्दर इतना बड़ा हॉस्पिटल बना है। आप अपने शहरी मतदाताओं की व्यवस्थाओं में बाधक बन रहे हैं। आप जाकर देख लें कि एसएमएस के अन्दर कितने प्रतिशत यहां के स्थानीय जयपुर के नागरिक हैं? 90 प्रतिशत लोग गांव से आ रहे हैं, क्योंकि उनको वहां ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है और जयपुर के नागरिक, जिनको ट्रीटमेंट जयपुर में मिलना चाहिए, वहां वे दर-दर भटक रहे हैं और निजी अस्पतालों के अन्दर जा रहे हैं। यह बात करेंगे तो विवाद करने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आप यह तर्क दे देंगे तो शहर और गांव के बीच में झगड़ा कर रहे हैं। आपने यह जो सेंट्रलाइजेशन किया, केन्द्रीयकृत किया, उसके अन्दर अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी को हो रहा है, उसमें शहर को भी हो रहा है। इस बात को समझने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, कोरोना के वक्त में हर कोई दौड़ गया था। उन कोरोना के मरीज के साथ खड़े होने वाले उनके परिवार के लोग भी नहीं रहे। कौन रहा? क्या आज हम लोगों को उनके सन्दर्भ में अपनी प्राथमिकता रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। ईश्वर न करे कि इस तरह की अगर कोई परिस्थिति आगे बने, तो उसके अन्दर जो योगदान कर रहे हैं, वे इस तरह की सोच रखें कि हमको सरकार की तरफ से, जो हमारा समाज की तरफ योगदान है, उसको जब भी वक्त पड़ेगा नजरंदाज कर लेंगे। सभापति महोदय, चंद प्रशासनिक अधिकारी

उन वार्डों के अन्दर गये होंगे। कोविड सेंटरों के अन्दर डॉक्टरों की तादाद बहुत कम थी। अगर कोरोना से किसी ने लड़ाई लड़ी तो नर्सिंग स्टॉफ ने लड़ी। मैं नर्सिंग स्टाफ को सैल्यूट करना चाहता हूं, जिन्होंने इस कोरोना की लड़ाई में जब परिवार ने साथ छोड़ दिया, व्यवस्थाओं ने साथ छोड़ दिया तो नर्सिंग स्टाफ हमारे कोरोना से पीड़ित जो मरीज थे, उनके बीच में रहे। उसके अलावा भी बहुत अच्छे मॉडल थे, ऐसी बात नहीं है कि मॉडल नहीं थे। पांच दवाई की किट के मॉडल का फैसला राजस्थान में जिस किसी भी अधिकारी ने लिया, मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी उस वक्त भी धन्यवाद दिया कि पांच दवाई के किट की व्यवस्था के फैसले के माध्यम से जिस किसी को भी थोड़ा बहुत लग रहा था, उन सबको पहुंचाया। तो क्या इस पद्धति को हमें आगे नहीं बढ़ाना चाहिए? यूटीबी के माध्यम से उन नर्सिंग कर्मचारियों ने अपनी जान को हथेली पर लेकर कोरोना के वक्त में योगदान किया और आज हम लोगों ने उनके लिए आंख मीच ली। क्या यह जिम्मेवारी हम लोगों की नहीं है? हम लोग कुतर्क दे रहे हैं कि पूरी की पूरी भर्ती हो गयी है। भर्ती के सन्दर्भ में भी क्या हालात हैं? सब पदों पर भर्ती हुई या नहीं? सभापति महोदय, नहीं हुई। हम लोगों को सिर्फ उन यूटीबी से जो जीएनएम थे, नर्सिंग अधिकारी थे। जिनके योगदान का कोई ईमानदारी से आकलन कर ले, सर्वश्रेष्ठ था। श्रेय लेने के लिए तो सब कुछ था, पर धरातल पर उन लोगों ने ही संघर्ष किया था। आज मेरे से तो बहुत स्नेह है। मंत्री जी, मेरे को तो यहां पर बहुत गंभीरता से सुन रहे हैं। मंत्री जी, बायतू उप जिला चिकित्सालय के अन्दर 38 स्वीकृत पद हैं, उनमें से सिर्फ 13 कार्यरत हैं और 25 रिक्त हैं। जैसलमेर जिले में 40.. (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) समय हो गया? मुझे यह बोला गया कि 30 मिनट।

श्री सभापति: 20 मिनट।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): या तो ये सही हैं या आप सही हैं।

श्री सभापति: 20 मिनट बोलने हैं, बोलने वाले वक्ता बहुत ज्यादा हैं। 25 मिनट नहीं बोल पायेंगे, 20 में ही अपनी बात समाप्त करें।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): समय कितना निर्धारित हैं? मेरे सचेतक महोदय ने कहा कि 25 मिनट।

श्री सभापति: फिर आपके बाकी लोग कम करने पड़ेंगे।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): यह अधिकार मेरा नहीं है। समय-सीमा तय करने का अधिकार स्पीकर को है और पार्टी में आपस में समय-सीमा तय करने का अधिकारी एलओपी और सचेतक को है। अगर इन्होंने 20 मिनट कहा तो मैं 20 ही करुंगा। इन्होंने 2 का कहा तो 2 ही करुंगा। ...(व्यवधान)... ये तो करना ही चाहते हैं। ये तेरे-मेरे के अन्दर या किसी पर आरोप-प्रत्यारोप करेंगे।

सभापति महोदय, आज राजस्थान के अन्दर सबसे ज्यादा स्टेरॉयड के माध्यम से हम लोगों के शरीर की क्या स्थिति हुई है? कहीं भी चले जायें, क्योंकि स्टेरॉयड जीवन रक्षक दवाई है। सरकार की तरफ से उसमें बहुत कम टैक्स लगता है और वह सबसे सस्ती होती

है। जो कोई भी बीमारी हो स्टेरॉयड के माध्यम से हमें तत्काल राहत मिलती है। पूरे के पूरे राजस्थान में झोला क्वैक हैं, एमबीबीएस एवं एमडी किये हुए डॉक्टर हैं, जल्दी इलाज की हमारी प्रवृत्ति है कि एकदम तत्कालीन राहत मिले, उसके कारण स्टेरॉयड दे रहे हैं। स्टेरॉयड के कारण राजस्थान के लोगों के स्वास्थ्य में क्या स्थिति है? स्टेरॉयड के सन्दर्भ में हम लोगों को नीति नहीं बनानी चाहिए। एंटीबायोटिक, छोटा-सा भी जुकाम हो, तो एंटीबायोटिक ज्यादा से ज्यादा एमजी की लेते हैं। इस एंटीबायोटिक के सन्दर्भ में हम लोगों को नीति बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि तत्कालीन राहत मिलती है। तत्कालीन राहत मिलती है तो मरीज को यह लगता है, अवेयरनैस नहीं है। मरीज को लगता है कि नहीं, यह डॉक्टर तो सबसे अच्छा है। यह डॉक्टर हम लोगों को बहुत अच्छी दवाई दे रहा है। क्या ये चीज हम लोगों को समाज के अन्दर, क्योंकि कोविड के वक्त में सबसे ज्यादा क्रिटीकल केस गांवों में हुए हैं और सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं।

mdp/rtm/06.03.25/13:50/2b

सभापति महोदय, मेरा निजी अनुभव है, कोविड के अन्दर एक दिन भी ऐसा नहीं था कि मैं कोविड सेंटर में नहीं गया। एक बार नहीं, मैं दस-दस बार कोविड सेंटर के अन्दर जाता था। मेरा निजी अनुभव है स्टेरॉयड के कारण सबसे ज्यादा केसेज खराब हुए हैं और स्टेरोइड के कारण ही सबसे ज्यादा मौतें हुई। स्टेरॉयड के सन्दर्भ में हम लोगों को नीति बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए?

सभापति महोदय, जो चिरंजीवी योजना के माध्यम से, अगर स्कीम के माध्यम से ही बात करें तो उसके माध्यम से 25 लाख तक, इस 25 लाख तक के सन्दर्भ में भी विवाद किया गया कि कितने मरीज हैं? न्यूनतम सुरक्षा देने की किसकी जिम्मेवारी है कि अगर 25 लाख तक भी इलाज की लागत लगेगी तो सरकार खड़ी है सिर्फ इस मंशा से चिरंजीवी के अन्दर 25 लाख, इसमें एक कुतर्क दिया जा रहा है कि कितने मरीजों को? अगर दस-बीस परिवार भी हैं तो इसकी जिम्मेवारी राजस्थान सरकार की है याकिसी और की है? 50 लाख मरीजों का इलाज हुआ। आज उस चिरंजीवी योजना का नाम बदलकर मां कर लिया, यह आपका अधिकार है, आपको मुबारकबाद। आपने जो भी किया, वह आपके अधिकार क्षेत्र के अन्दर किया, लेकिन इस योजना के माध्यम से हम लोगों की स्थिति क्या है? आज हम लोगों को एक्सीडेंटल क्लेम मिल रहे है या नहीं मिल रहे हैं? उत्तर है, नहीं मिल रहे। क्या इस योजना के अन्दर हम लोगों को पीएचसी को भी शामिल करना चाहिए? उत्तर है, हां करना चाहिए। जो जांचें हैं, उन जांचों के लिए हम धकेल रहे हैं कि आप सीएचसी में जाओ, आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाओ, ये पूरी की पूरी जांचें हम लोगों को पीएचसी स्तर के अन्दर होनी चाहिए।

सभापति महोदय, मैं बायतू विधान सभा की बात करता हूं कि तमाम पीएचसी के अन्दर सीबीसी मशीन लगी हुई है। परंतु सरकारी फैसला जो पीएचसी के अन्दर कि किसी भी प्रकार

का हम शुल्क नहीं लेंगे, वह बंधन बांधता है, वहां के डाक्टर्स को कि वे सीबीसी मशीन के अन्दर केमिकल कहां से डाले। वह पूरी की पूरी मशीन, मैंने किसी और माध्यम से, सरकारी माध्यम से नहीं, वह मशीनें लगवायी और उनसे जांचें नहीं हो पा रही हैं। इन नियमों में परिवर्तन कौन करेगा? ये शिथिलता कौन लेकर आएगा? यह हम लोगों को लानी पड़ेगी।

आज कितने रुपये का क्लेम इन इंश्योरेंस कंपनियों में ड्यू है? बहुत बड़े तादाद के अन्दर ड्यू है। सिर्फ इंश्योरेंस कंपनियों में नहीं, मुख्य मंत्री दवा योजना के मार्फत से जो अस्पताल है, जोधपुर के अन्दर खबर आयी की एमडीएम के अन्दर जो भी वहां सप्लायर है, 40 करोड़ ड्यू है और उसने दवाइयां देनी बंद कर दी। क्या हम धकेलना चाहते हैं उन प्राइवेट दुकानों की तरफ? अगर धकेलना चाहते हैं तो ईमानदारी से राजस्थान में यह बात करें कि हम लोग इस व्यवस्था को वापस, कोई गलत चीज नहीं है, अपने-अपने मॉडल होते हैं। दुनिया के अन्दर कोरपोरेट मॉडल को भी कई देशों ने अपनाया है। इस मॉडल के सम्बन्ध में अगर हम लोग यह राय रखते हैं तो सदन के अन्दर सरकार को खड़े होकर हम लोगों को करना चाहिए। आज कितने क्लेम बन रहे हैं? ईमानदारी से इसका आकलन कर लीजिए। सीएचसी के अन्दर इंश्योरेंस कंपनी का, जो राजस्थान का हक है, वह क्लेम नहीं बन रहा है, क्योंकि हम लोगों के पास ऑपरेटर नहीं है, हम लोगों की प्राथमिकता नहीं है। जो करोड़ों रुपये का क्लेम बनकर इंश्योरेंस कंपनी से राजस्थान को मिलना चाहिए, उसके माध्यम से सीएचसी अच्छे ढंग से, जो भी सीएचसी के अन्दर जरूरत है, वह पूर्ति होनी चाहिए। उस क्लेम के सम्बन्ध में भी हम लोगों की प्राथमिकता नहीं है।

सभापति महोदय, जो यह योजना है, इस आरजीएचएस में क्या हुआ? आज सरकारी कर्मचारी दर-दर भटक रहे हैं। आज उसके माध्यम से दवाई लेने के लिए, कोई दवाई की दुकान में जाते हैं, मेरे पास सीजीएचएस और आरजीएचएस दोनों हैं, मेरी दवाई लेने के लिए वहां जाता हूं तो वह दुकानदार कहता है कि साहब, आरजीएचएस वाला तो साइड में रखिए, इसका तो पेमेंट का ही भरोसा नहीं है। यह हकीकत है, कोई भी जाकर देख लीजिए। एक्स एमपी के तौर पर मुझे मिलता है। यह व्यवस्था जो धरातल पर है, गलत किसी ने भी की है, उसका सुधार कौन करेगा? सुधार हम लोगों को करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, बातें बहुत हैं। मेडिकल कॉलेज के अन्दर सभी जिलो में, उन जिलों के अन्दर शायद जालौर जिला ही नहीं रहा। जोगेश्वर जी, आपका जिला, राजस्थान के अन्दर कोई न कोई परिवर्तन हो गया, इससे पहले बोले कि जालौर जिले के अन्दर...

श्री सभापतिः विराजिए।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): अंत में एक बात करके मैं कंक्लूड करना चाहूंगा कि आज मेडिकल साइंस में बहुत तब्दीली हो रही है। गूगल ने अनाउंस कर दिया कि भविष्य की मेडिकल साइंस जो आँख के रेटिना को कैप्चर करके बता दें, उसके बाद एमआरआई, सीटी स्कैन आदि किसी की आवश्यकता नहीं रहेगी, तो हम लोगों को भी आगे बढ़कर जो बदलती हुई टेक्नोलॉजी है, जो चूंकि गूगल अनाउंस कर चुका है, उसको समझकर राजस्थान को उसके

सन्दर्भ में करना है।

श्री सभापतिः धन्यवाद। श्रीमती अनिता भदेल।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): अंत में एक आंकड़ा और देना चाहता हूं जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, इस देश में 1950 के अन्दर 6.18 थी। आज 2021 के अन्दर 1.9 हो गयी।

श्री सभापतिः विराजिए। श्रीमती अनिता भदेल।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): जनसंख्या बढ़ाने की हम लोग बात करें, हकीकत में 2.1 नहीं रहेगी तो जनसंख्या घटेगी। इसको भी समझने की किसकी है? इस डिपार्टमेंट की। अगर ये डिपार्टमेंट नहीं समझेगा और नहीं बताएगा तो ये भ्रम और भ्रांति फैलती रहेगी।

श्री सभापतिः धन्यवाद।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): समय कम है। मैं लच्छेदार बात करता।

श्री सभापतिः आप बोलिए। उनका अंकित नहीं हो रहा है, आप बोलिए।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): 000

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): आपने मुझे मांग संख्या 27 व मांग संख्या 28 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): 000

श्री सभापतिः आप विराजिए प्लीज। अंकित नहीं हो रहा है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है कि अगर आप स्वस्थ है तो आप सबकुछ हासिल कर सकते हैं। इसलिए स्वास्थ्य बहुत बड़ी आवश्यकता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सरकार की। अभी बायतू से आने वाले माननीय सदस्य एनवायर्नमेंट की बात कर रहे थे। हवा, पानी, खाद्य में मिलावट की बात कर रहे थे, निश्चित रूप से आपने सही कहा कि यदि हम इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देंगे तो भला कितने ही हॉस्पिटल खोल दें, परंतु स्वास्थ्य व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकता है, उसको पूरा नहीं कर सकते। सभी सरकारें, चाहे कोई भी सरकार रही हो, माननीय वसुन्धरा जी की सरकार में मुझे याद है, 2013 से 2018 के बीच में उन्होंने भामाशाह योजना शुरू की। उसके पूर्व में मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी निःशुल्क दवा योजना लेकर आए। जब मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी बनें तो उन्होंने भामाशाह योजना के माध्यम से पूरे राजस्थान में खाद्य सुरक्षा में कवर लो और गरीब लोगों को निःशुल्क किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी उपचार की सुविधा दी। सरकारी हॉस्पिटल्स में तो उपचार की सुविधा थी ही।

(समयः बजे)

(श्री फूल सिंह मीणा, सभापति, पदासीन)

जिस तरह से हर सरकार अपनी मर्जी से नाम चेंज करती है, वह भामाशाह योजना फिर

चिरंजीवी हो गया और चिरंजीवी अब मां योजना हो गयी। जो पुराने सदस्य हैं, उनको मालूम है कि ये वही भामाशाह योजना है, जिसको वसुन्धरा जी लेकर आये थे। धीरे-धीरे इन पैकेजों में बढ़ोतरी होती गयी और अधिक से अधिक बीमारियों को इसमें कवर किया गया। माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी का धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इस पैकेज को और बढ़ाया। इस योजना को और स्ट्रेंथनिंग देने की कोशिश की और अधिक से अधिक रोगियों को हम कैसे उपचाररत कर सके, नि:शुल्क उपचार कैसे दे सके, ये सुविधा उन्होंने राजस्थान के लोगों को दी।

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि भारत के प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना पूरे देशभर में लागू की। मैंने पिछली बार भी यह बात कही थी सदन में कि जिस तरह से आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी राजस्थान से बाहर जाकर दूसरे प्रदेशों में चिकित्सा का लाभ ले सकते हैं, उपचार की सुविधा ले सकते हैं, उसी तरह से राजस्थान के बाहर रोगी भी राजस्थान आकर उपचार लें, चिकित्सा का लाभ लें, यह सुविधा राजस्थान सरकार की ओर से राजस्थान के हॉस्पिटल्स में नहीं है। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में, माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट में ये बात कही है कि राजस्थान के लोगों को बाहर भी उपचार की सुविधा मिले आयुष्मान भारत में, उसकी व्यवस्था हम करेंगे, लेकिन बाहर के रोगियों की, जो राजस्थान की सीमा के बाहर है, उन लोगों को भी यदि यहां उपचार की सुविधा मिल जाए तो निश्चित रूप से इस योजना का लाभ हम हर उस रोगी व्यक्ति को दे सकेंगे, जिसको इसकी आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, क्योंकि समय की कमी है और आप कहेंगे कि अपनी बात कंक्लूड कीजिए, इसलिए मैं अपनी अजमेर के विषय पर सीधी अपनी बात कहना चाहूंगी। अजमेर का मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल हिन्दुस्तान के आजाद होने के पहले का भवन निर्मित है और संभाग स्तर का एकमात्र मेडिकल कॉलेज उस जमाने से चल रहा है। इस मेडिकल कॉलेज के भवन के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है 50 करोड़ रुपये से भवन के नवीनीकरण के लिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये भवन के नवीनीकरण के लिए, मरम्मत के लिए नहीं होना चाहिए। ये भवन निर्माण केलिए होना चाहिए, क्योंकि बहुत लम्बे समय से मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के भवन को पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता है।

Ans/rtm 14.00 2c -6.03.2025

बहुत सारे कमरे और बहुत सारे भवन वहां बहुत पुराने है, आये दिन छत से कभी प्लास्टर निकल जाता है, कभी कुछ टूट जाता है, कभी कुछ टूट जाता है और मरीजों को इससे बहुत असुविधा होती है। इसलिए 300 करोड़ रूपये का प्लान बनाकर सरकार को भेजा गया। उस 300 करोड़ को हम नहीं मांगते कि आप एक साथ दे दीजिए, आप चरणबद्ध रूप से 300 करोड़ की राशि, जिस प्रकार से इस बजट में 50 करोड़ रूपये की राशि जारी की है

उसी तरह से अगर हर साल 50-50 करोड़ की राशि जारी होती है तो इस हॉस्पिटल की जो अलग-अलग विंग्स हैं, मेडिसिन, सर्जरी, दूसरे डिपार्टमेंट है उनकी बिल्डिंग बनाने में हमको सुविधा होगी।

सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त आपसे निवेदन करना चाहूंगी, चूंकि हॉस्पिटल में अलग-अलग स्मार्ट सिटी के तहत भी बहुत सारी बिल्डिंग्स बन रही हैं, पूरे कैम्पस में एक जगह से दूसरी जगह मरीजों को लाने ले जाने में दिक्कत होती है, इसलिए उसमें कोरिडोर बनाया जाए, उस कोरिडोर का प्लान बनाकर भी यहां भेजा हुआ है। उस कोरिडोर के लिए भी 10 करोड़ रूपये अतिरिक्त बजट की हमें आवश्यकता है1

चूंकि, पिछले बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री जी ने अजमेर में सुपर स्पेशिलिटी विंग बनाने की बात कही थी। वर्तमान में जहां टीबी हॉस्पिटल संचालित हो रहा है, उस टीबी हॉस्पिटल की बिल्डिंग को यदि शहर से दूर जनाना हॉस्पिटल है, उस जनाना हॉस्पिटल के रिक्त भू भाग पर बना दिया जाएगा तो शहर के बीच में मेडिकल कॉलेज के पास ही, मेडिकल हॉस्पिटल के पास ही सुपर स्पेशिलिटी विंग बना दी जाएगी और दूसरी जगह ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि सुपर स्पेशिलिटी विंग है उसमें स्पेशिलिटी ब्लॉक का निर्माण कराया जाना शेष है, उसके टेंडर हो गए है और आने वाले समय में एमओयू होकर शीघ्र काम प्रारम्भ हो जाएगा। उसके पहले-पहले नेफ्रोलॉजी विभाग इसके तहत लाया जा रहा है, जहां डायलिसिस यूनिट का संचालन हो रहा है। मेरी सरकार से, माननीय मंत्री महोदय से मांग है कि नेफ्रोलॉजिस्ट लगाना नितांत आवश्यक है। नेफ्रोलॉजिस्ट लगाने से किड़नी रोगियों को उचित उपचार मिल सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगी कि कैंसर विभाग के लिए ऑन्कोलॉजिस्ट और ऑन्को सर्जन लगाया जाना शेष है, आप उसकी भी तुरंत व्यवस्था करके उनको लगाये तो अजमेर संभाग के कैंसर रोगियों को अजमेर में ही सुविधा मिल जाएगी। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षण चाहूंगी हेमटोलॉजिस्ट लगाये जाने की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि ब्लड कैंसर के इलाज के लिए अजमेर मेडिकल कॉलेज स्तर पर मरीजों को उपचार मिल सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से निवेदन करना चाहूंगी, जैसा मैंने पहले कहा कि अलग-अलग विभागाध्यक्ष के लिए अलग-अलग बिल्डिंग्स बनाई जा रही है। कभी स्मार्ट सिटी के मद से, कभी एडीए के माध्यम से, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से बनाई जा रही है। ऐसे अलग-अलग विंग्स की दूरी अधिक है इसलिए 5-6 इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होटल्स में चलाए जाते हैं अगर वे इलेक्ट्रिक व्हीकल आप उपलब्ध करा देंगे तो रोगियों को सुविधा मिल जाएगी। इसी तरह से वहां एमआरआई मशीन, पीटी- सिटी स्कैन मशीन, बेस्फा स्कैन, न्यूरो माइक्रोस्कोप, ऑप्थैलमॉलाजी, ईएनटी के नवीन उपकरणों की आवश्यकता है। न्यूरोलॉजी के उपकरण जैसे ईईजी विडियो, ईईजी ईएमजी, नर्व्स कंडक्शन स्टडी, इन सभी

उपकरणों की वहां आवश्यकता है, तो आप इस वर्ष के बजट में यह व्यवस्था भी करेंगे तो हमारे मेडिकल कॉलेज में आने वाले रोगियों को और सुविधा मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां एक मेडिकल कॉलेज है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स है लेकिन प्राइवेट कॉलेज नहीं है। मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध दो हॉस्पिटल हैं, जिनमें जनाना हॉस्पिटल और सैटेलाइट हॉस्पिटल है1 यह सैटेलाइट हॉस्पिटल मेरे विधान सभा क्षेत्र में है। पिछली बार माननीय वसुन्धरा जी ने इसमे बजट देकर, पदों का सृजन करके, बहुत सारे पद क्रियेट किये। मेडिकल कॉलेज के भार को कम करने के लिए और जनाना हॉस्पिटल चूंकि शहर से दूर है, इसलिए डिलिवरी शहर के आस-पास के गाँवों की महिलाओं को शहर में मिल जाए, इस नाते से सैटेलाइट हॉस्पिटल उपयुक्त हॉस्पिटल साबित हो रहा है। मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध जेएलएन हॉस्पिटल है वह तो कोविड रोगियों के लिए ही रिजर्व कर दिया गया था, तो बाकी रोगियों के उपचार के लिए जब दिक्कत आई तो कोविड काल में सैटेलाइट हॉस्पिटल ही एक मात्र हॉस्पिटल उपलबध हो पाया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगी कि अजमेर का सैटेलाइट हॉस्पिटल जो जिला चिकित्सालय भी है, इसमें सिटी स्कैन और डी ईचीएस व यूएसजी मशीन लगाया जाना बहुत जरूरी है।

साथ ही मेडिकल ऑफिसर की वहां पोस्टिंग नहीं है। मेडिकल ऑफिसर की पोस्टिंग नहीं होने की वजह से राउंड दा क्लॉक हॉस्पिटल चलाना दिक्कत का काम होता है। मेडिकल ऑफिसर्स लगाये जाए, मेडिसिन के विशेषज्ञ लगाये जाए। स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ की वहां व्यवस्था की जाए। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, हर महीने यहां कम से कम 300-400 सीजेरियन और नोर्मल डिलिवरी होती है। शिशु रोग विशेषज्ञ का होना नितांत आवश्यक है। पहले एक मात्र शिशु रोग विशेषज्ञ मनीष शर्मा वहां लगे हुए थे, उनका ट्रांसफर बिना उनकी सिफारिश के बाहर कर दिया। वहां छोटे-छोटे माइनर ऑपरेशन भी होते हैं। इसलिये एनेस्थीसिया के डॉक्टर को भी वहां लगाना बहुत आवश्यक है। तो आप एनेस्थीसिया के डॉक्टर को वहां लगाएंगे, मेरा आपसे ऐसा निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगी कि जेएलएन संभाग का एकमात्र हॉस्पिटल है। जेएलएन हॉस्पिटल में रख-रखाव व साफ-सफाई के लिए नितांत अत्यावश्यक बजट की आवश्यकता रहती है। सब जगह से यह हॉस्पिटल टूट फूट सा गया है। तार लटक रहे हैं, रोगी उपचार के लिए जाता है, कई बार उनको करंट लग जाता है तो वह और बीमार हो जाते हैं, ऐसी स्थिति इस व्यवस्था को ठीक करें। कहीं झूलते तार हैं, कहीं नाली खुली पड़ी है, कहीं पानी ऊपर से बह रहा है, तो मेरा निवेदन है इस मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध जो हॉस्पिटल है उसकी व्यवस्था को ठीक करने का काम करेंगे।

सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि आपने जो प्रगति प्रतिवेदन दिया है उसके हिसाब से 5 हजार 971 शैक्षणिक पोस्ट स्वीकृत हैं लेकिन पूरे प्रदेश में 3 हजार 217 शैक्षणिक पोस्ट पर ही कार्यरत है, 2 हजार 754 पद अभी रिक्त है।

इसके अतिरिक्त चिकित्सालय एवं तकनीकी विशेषज्ञों में 25 हजार 927 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 18 हजार 922 कार्मिक कार्यरत हैं, 07 हजार 05 पद रिक्त हैं। अशैक्षणिक में 10 हजार 832 पद स्वीकृत हैं, 07 हजार 586 कार्मिक कार्यरत हैं। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि इन पदों को भी आप जल्दी से जल्दी भरेंगे और हॉस्पिटल की जो कमियां हैं उनको दूर करेंगे।

सभापति महोदय, इसके अलावा सैटेलाइट हॉस्पिटल के लिये निवेदन करना चाहूंगी। जैसा कि मैंने पहले कहा सिटी स्कैन मशीन के बारे में। दूसरी एमआरआई मशीन यदि सैटेलाइट हॉस्पिटल में लगा दी जाती है तो जेएलएन के भार को कम करने में आसानी होगी। डिजिटल सोनोग्राफी मशीन, ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर, गायनोलॉजिस्ट के अतिरिक्त फेब्रिकेटेड वार्ड, जो दो साल पहले बना था, उस फेब्रिकेटेड वार्ड बनने के बाद भी उसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा, वह खाली पडा है। मेरा निवेदन है कि फेब्रिकेटेड वार्ड का भी उपयोग हो। मेडिकल की एक विंग मेडिकल कॉलेज से स्थानांतरित होकर सैटेलाइट हॉस्पिटल में चली जाए तो रोगियों को सुविधा मिले, रोगियों को किसी प्रकार की दुविधा ना हो।

सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त निवेदन करना चाहूंगी कि पिछले बजट भाषण में माननीय मंत्री महोदय ने व माननीय वित्त मंत्री जी ने जीएनएम नर्सिंग कॉलेज अजमेर में खोलने की घोषणा की थी। कॉलेज को जमीन आवंटित हो गई, लेकिन जीएनएम नर्सिंग कॉलेज के लिए अभी तक भी बजट आवंटन नहीं हुआ, तो उस बजट को भी शिघ्रातिशीघ्र आवंटित करें।

माननीय सभापति महोदय, मां-योजना के लिए, जो जयपुर में नी-रिप्लेसमेंट वाले हॉस्पिटल है, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, मैं व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी आपको बताऊंगी, जो मां-योजना के पैकेज हैं उन पैकेजेज में जो हॉस्पिटल नी-रिप्लेसमेंट का काम करते हैं उन हॉस्पिटल में लोग अजमेर से भी आते हैं। एक हॉस्पिटल की इतनी शिकायत है कि वह मां-योजना में पैकेज लेने के बावजूद भी मरीजों से उसके लिए अतिरिक्त चार्ज करते हैं।

VPS-RTM-06.03.2025-14.10-2d

मैंने यह शिकायत अधिकारियों को भी की है और उसके खिलाफ आप तुरंत एक्शन करें, ऐसा मेरा निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, अंत में मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगी कि स्वास्थ्य व्यक्ति की आवश्यकता है, स्वास्थ्य सुविधाएं सरकारों को देने की जरूरत है। अधिक से अधिक लोगों को हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, वातावरण को शुद्ध करके, हम जलवायु को कैसे शुद्ध रख सकते हैं तो हम निदान तो देते ही देते हैं, लेकिन उपचारात्मक उपायों पर यदि ध्यान दिया जायेगा तो मुझे यह लगता है कि व्यक्ति अधिक बीमार नहीं पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत

धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री राजेशजी पारीक।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सभापतिजी, राजेन्द्रजी पारीक हैं।

श्री सभापतिः हां, राजेन्द्रजी पारीक।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। राज्य सरकार का एक ध्येय वाक्य है कि पहला सुख निरोगी काया। कुमारसंभव कालीदास रचित जो ग्रंथ है उससे यह सूत्र लिया गया कि- 'शरीरमाद्यं खलु धर्म साधनम्।'

माननीय सभापति महोदय, यह केवल अवधारणा नहीं है। इस अवधारणा के पीछे हमारे ऋषि, महर्षि, हमारे शास्त्र, हमारे वेद, उनमें इस बात की परिकल्पना की गयी है। भगवान भास्कर को प्रणाम करते हुए इस बात की परिकल्पना की गयी है कि सुखी कैसे रहे? शरीर निरोगी कैसे हो, उसके लिए माननीय सभापति महोदय, शास्त्र जो कहते हैं-

पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं श्रुणुयाम शरदः शतं।।

प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शत भूयश्च शरदः शतात्।।

जन्मदिवसस्य शुभाशयाः।।

सौ साल तक हम देखें, सौ साल तक हम जिएं, सौ साल तक हमारी कर्णेद्रियां, हमारे कान जो हैं, वे स्वस्थ रहे। यह परिकल्पना केवल सौ साल तक ही नहीं, उसके बाद भी हम स्वस्थ रहें, इस परिकल्पना को जब हमारे ऋषि, महर्षियों ने देखा तो मैं आपके माध्यम से हमारे माननीय मंत्री महोदय से भी एक निवेदन करना चाहूंगा, हालांकि, यह विषय उनका नहीं है लेकिन हैल्थ से रिलेटेड है और इन्होंने जो बजट घोषणा की है, उस बजट घोषणा में भी इस बात का इन्होंने जिक्र किया है कि आयुष की एक नई नीति बनाएंगे। जब हैल्थ पर और शिक्षा पर चर्चा हो रही है, खास तौर से हैल्थ पर, आयुष को इसमें शामिल किया जाना नितांत आवश्यक है। आयुष भी कोई एक छोटी-मोटी विधा नहीं है, एक सम्पूर्ण विधा है, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे यूनानी हो और आज, माननीय सभापति महोदय, विदेशों को तो छोड़िये, बल्कि अपने पूरे हिंदुस्तान में कई स्टेट ऐसे हैं जहां मेडिकल ट्यूरिज्म केवल आयुष की वजह से ही पनप रहा है तो इस चक्कर में हम क्यों इनको छोड़ देते हैं? यह एक चिंतनीय विषय है।

माननीय सभापति महोदय, जब हम स्वस्थ रहने की बात करते हैं तो सबसे पहले मेरा स्मरण आता है कोरोना काल में, माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कोरोना काल में जिस तरह से हमारी दीनता दर्शित हुई, जिस तरह से हम मजबूर हुए और उस वक्त जो कुछ भी किया गया, उससे यह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा था कि आग लगने के बाद में हम कुआं खोद रहे हैं। उस वक्त का अभी कुछ पूर्व वक्ताओं ने इस बात का जिक्र किया कि पैरामेडिकल स्टाफ ने काफी अच्छा काम किया, उनको सैल्यूट कर रहे हैं। उस व्यक्ति को हम आज भी भूल रहे हैं, कोरोना काल में जिनकी मृत्यु हो गयी, उस मृत व्यक्ति को पॉलिथीन में लपेट कर उसकी डेड-बॉडी को परिजनों तक पहुंचाना,

उस हरिजन कर्मचारी को, उस हरिजन कर्मचारी की जो पीड़ा थी, इस बात को किसी ने भी नहीं समझा। अपनी जान की परवाह किये बिना उस व्यक्ति ने उस मृत व्यक्ति को जिसके पास उसके परिजन भी नहीं जा रहे थे, उस डेड-बॉडी को लपेटकर जिस तरह से उन्होंने यह काम किया, मैं सदन के माध्यम से उन्हें भी सैल्यूट करना चाहता हूं।

खास तौर से राज्य सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया, कोरोना में जो मृत व्यक्ति थे, आज एस.एम.एस. में जो आई.पी.डी. टॉवर बन रहा है, वह आइ.पी.डी. टॉवर डेडिकेटेड है खास तौर से उन मृत डाक्टर्स के नाम पर, उनको एक तरह से श्रद्धांजलि है, उस आई.पी.डी. टॉवर के माध्यम से।

माननीय सभापति महोदय, आप भी इस बात को महसूस करें कि जब मैं ग्रामीण अंचल में या शहर में कभी गमी में जाता हूं तो वहां पर मुख्य रूप से जो बात सामने आती है कि मृत्यु कैसे हुई तो तीन कारण जो सबसे प्रमुख कारण बताये जाते हैं- कैंसर, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और एक्सीडेंट, माननीय सभापति महोदय, आज बीकानेर से जयपुर आने के लिए यदि कोई हार्ट पेशेंट है तो उसके लिए मार्ग में किसी भी तरह की सरकारी कोई सुविधा नहीं है। आज बड़े-बड़े जब एक्सीडेंट होते हैं तो मेडिकल कॉलेज, बीकानेर से लेकर जयपुर तक कोई ऐसा ट्रोम सेंटर नहीं है जहां उस गोल्डन पीरियड में उस एक्सीडेंट हुए व्यक्ति को कोई रिलीफ मिल जाये। सरकार सुविधा दे रही है। अभी पूर्ववर्ती माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि भारत सरकार ने भी इस बात की सुविधा दे रखी है, हमारी राजस्थान सरकार ने भी MAA योजना में इस बात को कर रखा है कि यदि कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसको तत्काल नजदीकी किसी हॉस्पिटल में हम ले जायें, लेकिन एक्सीडेंट पीरियड के लिए, मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आपको विशेष रूप से क्योंकि आप बहुत संजीदगी से इस बात को महसूस करते हैं कि एक्सीडेंट हुए व्यक्ति को उस गोल्डन पीरियड में कोई अच्छा ट्रोमा सेंटर मिले और वह ट्रोमा सेंटर यदि सरकारी क्षेत्र में हो, इसका आपको चिंतन और मनन करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हैल्थ के सैक्टर के बारे में आप सोचते हैं, विचार करते हैं, जिस तरह की योजनाएं आपने लागू की हैं तो मैं निश्चित रूप से इस बात को मानकर चलता हूं कि ट्रोमा सेंटर डवलप होना चाहिए।

निरोगी रहने के लिए जो खास तौर से जिन चीजों की आवश्यकता है, अभी एक पूर्व वक्ता ने काफी विस्तार से इस पर कहा, मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, दूध हो, पनीर हो, मावा हो, घी हो, ये सब चीजें हैं। आपने अपने बजट भाषण में यह भी कहा है कि इनके लिए लैबोरेटरीज बनेंगी, लैबोरेटरीज के माध्यम से हम इस पर अंकुश लगाने की कोशिश करेंगे तो मेरी इस पर एक और बात है, माननीय सभापति महोदय, केवल दूध की, पनीर की, घी की ही हम बात कर रहे हैं लेकिन जो मेडिसिन, कई बार हम अख़बार में यह पढ़ते हैं कि आपकी जो जेनेरिक मेडिसिन है, वह मेडिसिन उस गुणवत्ता की नहीं मिल रही है। किसी तरह की नकली मेडिसिन्स मिल रही हैं तो उनके बारे में हम क्या सोच रहे हैं? दूध आपने खाया, पनीर आपने खाया, उस वक्त आपको किसी बात का रिएक्शन हुआ या

कोई किसी तरह का इंफेक्शन हो गया लेकिन उस गलत दवा से जो नुकसान हो रहा है, उस गलत इंजेक्शन से जो नुकसान हो रहा है, उस गलत मेडिसिन से जो नुकसान हो रहा है तो एक तरह से यह तो मास- किलिंग जैसा मामला है, माननीय सभापति महोदय, इसके बारे में मैं माननीय मंत्री महोदय से यह आग्रह करना चाहूंगा कि खास तौर से मेडिकल के जो इश्यूज हैं, मेडिसिन्स के मामले में किसी तरह की यदि अडल्टरेशन हो तो उस पर गम्भीर से गम्भीर सज़ा का प्रावधान किया जाना चाहिए, यह बहुत गम्भीर विषय है।

माननीय सभापति महोदय, अभी आपके इस बजट भाषण में खास तौर से एक बात का यह जिक्र किया है कि- 'Prevention is better than cure', बात बिलकुल सही है लेकिन प्रिवेंशन होगा कैसे? न तो मिलावटी चीजों पर हम कोई रोक लगा रहे हैं, न किसी ओर पर हम ध्यान दे रहे हैं तो इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।

चिरंजीवी योजना का नाम बदलकर आपने MAA योजना कर दिया, किसी को कोई एतराज नहीं है MAA बड़ा अच्छा नाम है लेकिन इसमें माननीय मंत्री महोदय, पूर्व में जो व्यवस्था थी कि जो व्यक्ति 850 रुपये देकर तत्काल अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, उसको तत्काल कलक्टर के माध्यम से उसको अनुमत किया जा सकता था। अब उसमें तीन महीने का ग्रेस पीरियड दे दिया। आज आप यदि कार्ड बनाएंगे तो इसका इलाज आपको तीन महीने बाद मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, आप तो स्वयं ग्रामीण अंचल से आते हैं। बीमारी कब किसी को पूछ कर आती है? पूर्व में जब यह व्यवस्थाएं नहीं थीं, सरकार की तरफ से जब ये सुविधाएं नहीं थीं, घर बिक जाते थे, जमीनें बिक जाती थीं, गहने बिक जाते थे, कर्ज लेना पड़ता था तो बीमारी पूछकर नहीं आती और यदि किसी व्यक्ति से, कोई गलती से वह कार्ड नहीं बना पाया, यदि वह भूल गया इस बात को, वह यदि अपना 850 रुपये में यह कार्ड बना रहा है तो या तो वह कार्ड के लिए एलिजिबल है, उस स्कीम के लिए एलिजिबल है और यदि एलिजिबल नहीं है और वह 850 रुपये में अपना कार्ड बनवा रहा है तो सरकार उस कम्पनी को यह क्यों फायदा देना चाह रही है कि तीन महीने का पीरियड हम उसको दे रहे हैं कि तीन महीने बाद तुम्हारा इलाज हम अनुमत करेंगे। मेरा आपके माध्यम से यह आग्रह है मंत्री महोदय को कि इस पर तत्काल आपको चिंतन, मनन करना चाहिए। तीन महीने का जो पीरियड आप दे रहे हैं, उसको तत्काल हटाना चाहिए। पहले भी इस बात के लिए कलक्टर को एम्पावर्ड किया गया था कि जो व्यक्ति बीमार है, तत्काल उसको इलाज की आवश्यकता है तो वह तत्काल हॉस्पिटल में भर्ती होने से पहले अपना कार्ड बनवाएगा, हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद अपना कार्ड बनवायेगा। कलक्टर तक एप्रोच करेगा और कलक्टर के पास एप्रोच करके कलक्टर उसको करायेगा, कलक्टर के पास पावर है, तो कलक्टर के पास में वह पावर छोड़ रहे हैं लेकिन तीन महीने आप दे रहे हैं, मैं समझता हूं, माननीय सभापति महोदय, कई बार ऐसी परेशानी होती है कि उस वक्त आदमी जब बीमार होता है, घर में किसी तरह की परेशानी होती है तो सारी बातें वह भूल जाता है कि उसको

क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसके सामने एक ही विकल्प होता है कि सरकार की जो सुविधा मुझे मिल रही है, मैं सरकार की सुविधा से यह फायदा उठाऊं और अपना इलाज करवाऊं और अपने परिजनों की सुरक्षा का जिम्मा लूं तो मैं आपके माध्यम से यह जरूर कहना चाहूंगा।

दूसरा, माननीय सभापति महोदय, जब आपकी यह चिरंजीवी योजना, खास तौर से जिला हॉस्पिटल्स जो हैं, उनमें जब यह लागू थी तो मैं खास तौर से सीकर का जिक्र करना चाह रहा हूं कि सीकर में आर.एम.एस. की जो हमारी सोसाइटी है, उसमें चिरंजीवी योजना के माध्यम से एक बड़ा लम्बा अमाउंट जो है, चिरंजीवी योजना के माध्यम से जो रिएम्बर्स होता है, उस रिएम्बर्स से काफी बड़ा पैसा जमा हुआ।

ssy/rtm/06.03.2025/14.20/2e

आज उस पेमेंट को देने में भी कंपनियां काफी डिले कर रही हैं। कई जो हॉस्पिटल्स है पेमेंट के डिले होने की वजह से उसको अलाउ भी नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार की योजना है आरजीएचएस, इसमें लंबे समय से लोगों के पेमेंट ड्यू हो रहे हैं और इस वजह से लोगों को पेमेंट नहीं हो रहा है। लोग दवाइयां भी नहीं दे रहे हैं। आरजीएचएस को काफी सोच समझ करके राज्य सरकार द्वारा बनाया गया था। राज्य सरकार द्वारा इस योजना को जो बहुत अच्छी योजना है, सारे कर्मचारियों के लिए, बाकी जो रिटायर्ड लोग हैं उनके लिए, तो इसके माध्यम से तत्काल लोगों का पेमेंट हो, यह बहुत ज़रूरी है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी चाहूंगा कि तत्काल आप इसमें कोई न कोई व्यवस्था सोचें।

माननीय सभापति महोदय, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बारे में यहां पर काफी चर्चा हुई है। यहाँ मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज को प्योरली आपको एम्स की तर्ज पर रेफरल हॉस्पिटल बनाना चाहिए। एसएमएस हॉस्पिटल में 15-15 हजार पेशेंट्स आते हैं। उसमें न कोई रिसर्च वर्क होता है, न जो गंभीर बीमारी के लोग हैं, उनको डॉक्टर समय दे पाते हैं। भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि पेशेंट को समय देकर देखने का टाइम ही नहीं मिलता। इससे न केवल हॉस्पिटल का काम सफर होता है बल्कि हॉस्पिटल से एसोसिएटेड जो कॉलेज के प्रोफेसर साहिबान हैं उनको, अपनी कॉलेज में फैकल्टीज़ को पढ़ाने में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एसएमएस को प्योरली रेफरल हॉस्पिटल बनायें एम्स की तर्ज पर, इसमें वही पेशेंट आयेगा जो जिलों से और आसपास की जगह से रेफर होकर आयेगा, उससे उसका बोझ भी कम होगा।

उसके लिए आपको जो व्यवस्था करनी हैं, जैसे अभी वरिष्ठ माननीय सदस्य कालीचरण जी सराफ भी फरमा रहे थे कि आसपास के जो हॉस्पिटल्स हैं, वे चाहे जयपुर के हों, चाहे जिलो के हॉस्पिटल हों, जिलों के हॉस्पिटल्स को आपको स्ट्रेंथन करना चाहिए था। सभी जिलों में खास तौर से जो मेडिकल कॉलेजों की परिकल्पना माननीय प्रधान मंत्री द्वारा की गई या

माननीय अशोक जी गहलोत द्वारा भी उस पर ध्यान देकर के खोले गये, उसका अभिप्राय क्या था? कॉलेज क्यों खोले गये? कॉलेज इसलिए खोले गये थे कि हर बजट में पीएचसी खुलती हैं, हर बजट में सीएचसी खुलती हैं, छोटे-छोटे सेंटर्स में डॉक्टर्स की जरूरत पड़ रही है। उनके लिए डॉक्टर्स की अवलेबिलिटी हो, इसके लिए हमने इन मेडिकल कॉलेजेज की परिकल्पना की। मेडिकल कॉलेज हमने खोल भी दिये। लेकिन मेडिकल कॉलेज खोलने के साथ-साथ, इस बजट में भी आपने कहा है कि आप काफी पीएचसी खोल रहे हैं, काफी सीएचसी खोल रहे हैं। आपने मॉडल सीएचसी का भी जिक्र किया कि आप मॉडल सीएचसी बनायेंगे।

सभापति महोदय, मॉडल सीएचसी क्या भवन से बनती है? अच्छा भवन आपने बना दिया। अच्छी आपने रंग, पुताई करा दी, उससे तो अच्छी सीएचसी और मॉडल सीएचसी नहीं बनी। आपने हॉस्पिटल बना दिया, पीएचसी बना दी, सीएचसी बना दी, उसमें स्टाफ कैसा लग रहा है, उसमें पैरा मेडिकल स्टाफ कैसा लग रहा है? अभी बजट में एक बात कही है कि जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं, पीएचसी, सीएचसी ट्रू नॉट और सीबी नॉट मशीन आप लगायेंगे, डिजिटल एक्सरे मशीन लगायेंगे। क्या टेक्निशियन हैं आपके पास में?

माननीय सभापति महोदय, टेक्निशियंस जो जिले के हॉस्पिटल्स हैं, उनमें ही एक्सरे के लिए रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, टेक्निशियंस आपके पास में नहीं हैं और हॉस्पिटल्स आप खोल रहे हैं, पीएचसी खोल रहे हैं, सीएचसी खोल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनके साथ-साथ मशीनों को ऑपरेट करने वाले लोग और पैरा मेडिकल स्टाफ है चाहिए। आज भी कई जगह ऐसी स्थिति है कि मशीनें तो हैं, डायलेसिस मशीन है, लेकिन उसके लिए ऑपरेटर नहीं है। आपके पास एक्सरे मशीन है, लेकिन उसको ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर नहीं है। टेक्निशियन नहीं है। इसको भी साथ-साथ आपको करना है। आपने इसमें लिखा है कि करीब 1500 व्यक्तियों को आपने नौकरी देने की बात की है। खासतौर से टेक्निशियंस की भर्ती भी उतनी ही जरूरी है, जितनी बाकी के नर्सिंग स्टाफ की जरूरी है।

माननीय सभापति महोदय, एसएमएस के बाद में खासतौर से मेडिकल कॉलेज की अवधारणा थी, मेडिकल कॉलेजेज की जो वस्तु स्थिति है, वह चिंता का विषय है। मंत्री महोदय, इसको आप जितनी गंभीरता से ले सकते हैं, उतनी लें। मेडिकल कॉलेजेज की आप हालत देखें। मेडिकल कॉलेजों में एनएमसी ने हनुमानगढ़ को 12 लाख रुपये पेनल्टी लगाई, भीलवाड़ा को 3 लाख रुपये पेनल्टी, डूंगरपुर को 3 लाख, पाली को 3 लाख, अलवर को 12 लाख, सीकर को 2 लाख, बाड़मेर को 3 लाख, चूरू को 3 लाख, क्यों लगाई, एक ही फैकल्टी आज इस मेडिकल कॉलेज में और वही फैकल्टी किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज में जाकर अपनी अटेंडेंस दे रहा है। जब मेडिकल कॉलेजेज में फैकल्टी ही नहीं होगी तो वह बच्चा काहे से पढ़ेगा। बच्चों को पढ़ाने के लिए फैकल्टी हमारे पास में है नहीं।

माननीय सभापति महोदय, उसका सबसे बड़ा जो कारण है वह इनकी पॉलिसी है। राजमैस की पॉलिसी को जब पिछली बार भी सदन में चर्चा हो रही थी तो मैंने माननीय मंत्री

महोदय को इस बात के लिए विशेष आग्रह किया, मंत्री महोदय ने स्वयं भी इस बात को माना कि आज मेडिकल कॉलेजेज में राजमैस के माध्यम से और गवर्नमेंट कॉलेजेज में जो भर्तियां होती हैं, उसमें काफी बड़ा अंतर है। उन्होंने उसको लागू करने की बात भी मान ली। गवर्नमेंट के जो रुल्स हैं वह राजमैस के पर भी लागू होंगे। आज एक साल होने को आया, आज भी उस स्कीम को, राजमैस के जो कर्मचारी हैं, जो डॉक्टर साहिबान हैं, उन पर आज भी लागू नहीं किया गया है। खासतौर से जो मेडिकल कॉलेज और नये मेडिकल कॉलेज खुले हैं, उनमें 3-3 कैटेगिरीज बनी हुई हैं। डेजीग्नेटेड अलग हैं, राजमैस के अलग हैं और रेगुलर सर्विसेज गवर्नमेंट के जो डॉक्टर्स हैं वे सारे अलग हैं।

माननीय सभापति महोदय, डेजीग्नेटेड वह डॉक्टर्स हैं जो उस हॉस्पिटल से सीधे मेडिकल कॉलेज में आ गये। मेडिकल कॉलेज में आकर के वह पढ़ा रहे हैं। मैं सीकर का आपसे जिक्र करुं, सीकर में जो भी डॉक्टर साहिबान थे, जो सीनियर सर्जन थे या सीनियर मेडिसन, फिजिशियन थे, वे सारे के सारे मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। उनको डेजीग्नेटेड डॉक्टर्स के नाम पर जाना जाता है। उनके ना तो प्रमोशंस हो रहे हैं, ना उनको किसी तरह का और बेनिफिट मिल रहा है, ना उनके बारे में कोई आदमी चिंता कर रहा है। वह 5 साल तक सीकर के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाकर के आपको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, सीकर में पिछली बार भी एक बच्चा टॉपर रहा। इस बार भी जो फाइव ईयर कोर्स कंपलीट हुआ है, पूरे 5 साल का कोर्स कंपलीट हो गया, उसमें इस बार भी वह मेरिट पर है। राजस्थान में मेरिट पर आया है। ऐसे लोगों को आप डेजीग्नेटेड होने की वजह से केवल इसलिए दंडित कर रहे हैं कि वह आपके उस सिस्टम से नहीं आये हैं। जब आपने राजमैस का सिस्टम मान लिया, आपने एग्री करके राजमैस को गवर्नमेंट कॉलेज के इक्वल कर रहे हैं तो उनके बारे में आप सोच क्यों नहीं रहे हैं? उन डॉक्टर्स में क्या कमी है? कमी है तो फिर आपको दूसरे डॉक्टर्स लगाने चाहिए थे।

जब वह व्यक्ति 25-25 साल से उस हॉस्पिटल को रन कर रहे हैं, आपके मेडिकल कॉलेजेज में पढ़ा रहे हैं, अच्छी मेरिट पर बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों की अच्छी मेरिट बन रही है तो इसके बावजूद भी वह आदमी यह महसूस कर रहा है कि मैं इसलिए नहीं रख सकता कि मैं डेजिग्नेटेड हूँ। मेडिकल कॉलेजेस में आज जो वेकैंसीज हैं फैकल्टीज़ की, आप सुनकर के दंग रह जाएंगे, केवल कोई एक मेडिकल कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे पूरे मेडिकल कॉलेजों की, पाली, भीलवाड़ा, बूंदी, बाड़मेर, डुंगरपुर, सीकर, भरतपुर, चूरू, करौली, अलवर, गंगानगर, धौलपुर, चित्तौड़गढ, सिरोही, हनुमानगढ़, दौसा ये सारे मेडिकल कॉलेज है वो है जिनमें पद स्वीकृत हैं, लेकिन पद के अगेंस्ट में भर्तियां आज भी वहाँ पर नहीं हुई हैं, कौन भर्ती करेगा?

माननीय सभापति महोदय, मेडिकल कॉलेज क्या हमने इसलिए खोले थे कि अच्छे भवन बन जाए और वहाँ पर फैकल्टी नहीं हो तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? कई बच्चे मैं सीकर जाता हूँ तो मुझसे बात करते हैं कि हम तो यू ट्यूब पर पढ़ रहे हैं। हम लोगों से पूछकर पढ़ रहे है हम

यह कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। हमको यदि अच्छा टैलेंट चाहिए, अच्छे बच्चे हमको चाहिए अच्छे बच्चे पढ़कर के अच्छे बच्चे निकलें, उन बच्चों के लिए फैकल्टीज़ की व्यवस्था नितांत आवश्यक है। बिना फैकल्टी के कोई आदमी यदि यह समझे कि बिना फैकल्टी के ही वो जो है बच्चे पढ़ लिखकर के तैयार हो जाएंगे तो मैं ये समझता हूँ कि निश्चित रूप से यह हमारा भ्रम है बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छे शिक्षक चाहिए, अच्छे शिक्षक चाहिए तो आपको फैकल्टीज़ की, जो डिमांड जो है, उसको पूरी करनी पड़ेगी। फैकल्टीज की डिमांड के साथ-साथ आपको उनके कुछ जो परेशानी है उन को भी आपको सोचना चाहिए डिजिग्नेटेड डॉक्टर्स की जो परेशानी है, उसको भी आपको महसूस करना चाहिए।

राज्य सरकार इस बात को मानती है कि आरएसआर रूल्स हम लागू कर रहे हैं तो उन पर भी आरएसआर रुल्स लागू करके उनको भी सारी सुविधाएं दें। ये बहुत बड़ी कमी है। जिसको हमको कोई ठोस कदम उठा करके दूर किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, अब मैं आपसे ज़िक्र करना चाहूंगा सीकर मेडिकल कॉलेज और कल्याण हॉस्पिटल है उसमें फैकल्टीज जैसे अब सीकर में अभी आपने हर्ट स्पेशलिस्ट लगा दिया, लेकिन वहाँ पर कैथ लैब नहीं है। मैंने मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित भी किया था, मंत्री महोदय को मैं इस बात के लिए धन्यवाद भी दूंगा इस बात के लिए कि तत्काल इन्होंने सेक्रेटरी को भी इस बात के लिए अवगत कराया कि इसमें कब यह कैथ लैब खुलेगी। लेकिन आप इससे अंदाजा लगाए कि सिस्टम को कोलैप्स करने के लिए यह ठेकेदार किस तरह से उसको कोलैप्स करते हैं। पिछली गवर्नमेंट में टेंडर हुए, टेंडर को रोकने के लिए किसी ठेकेदार ने कोर्ट में अपील कर दी।

spp/rtm/06.03.2025/14.30/**2f**

कोर्ट में वो मामला अटक गया, चार साल, पांच साल वो पूरे निकल गए। कोर्ट ने जब वापस ये फैसला कर दिया कि डिपार्टमेन्ट ही स्वयं इस बात का फैसला करे। आज उन बातों को भी डेढ़ साल होने को आया। तब भी हम वहीं के वहीं हैं। यह जिम्मेदारी तय करनी चाहिए कि तत्काल ही इस तरह की चीजों को हम लागू करें। सीकर में खासतौर से मंत्री महोदय, मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा न्यूरो सर्जरी, यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी और ऑकोलॉजी, कल सदन में आपके पानी पर चर्चा थी और पानी पर चर्चा के दौरान कितने माननीय सदस्य ऐसे थे, जिन्होंने इस बात का जिक्र किया कि गंगानगर में, हनुमानगढ़ में जो रेल जो आती है, उस रेल का नाम हमने कैंसर रेल रख दिया, कैंसर ट्रेन रख दिया और यह स्थिति माननीय सभापति महोदय, जब मैं गांव में जा रहा हूँ तो मेरे सामने भी आती है।

श्री सभापतिः प्लीज समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): तीन तरह से जो डेथ हो रही है उनमें कैंसर गंभीरतम बीमारी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा आप के माध्यम से, माननीय मंत्री महोदय को, कि यदि कोई

व्यवस्था बैठ सके तो सीकर को भी आप इसमें शामिल करें। सीकर एक वो सेंटर है जो आपके जयपुर का सैटेलाइट टाउनशिप है। सीकर के आसपास की जो भौगोलिक स्थिति है और आज सबसे जो बड़ी परेशानी हमारे राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति है, भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि एक दूसरे जो अपने रिमोट एरियाज हैं बाड़मेर, सिरोही, जालौर, जैसलमेर वगैरह इनकी दूरियां इतनी ज्यादा हैं कि उन तक वह सहूलियत पहुंचना बहुत मुश्किल है। उसमें खर्चा भी बहुत ज्यादा पड़ता है, फिर भी राजस्थान एक वेलफेयर स्टेट है और ये सरकार की प्रायोरिटी बनती है कि वह तत्काल इन बातों को सोचकर और माननीय मंत्री महोदय काफी संजीदा व्यक्ति हैं। इस सारी संजीदगी को समझते हुए मेडिकल डिपार्टमेंट कैसे स्ट्रेंथन हो? इस पर माननीय सभापति महोदय, कभी आपको आसपास अपने एम एल एज की कोई कमेटी बनाकर उसके बाद उस पर भी आपको विचार करना चाहिए, ऑफिसर से भी आपको इस पर विचार करना चाहिए और ये डिपार्टमेंट कैसे स्ट्रेंथन हो, इस पर आपको गौर करना चाहिए और जो हैडक्वार्टर्स हैं, उन पर ज्यादा से ज्यादा अच्छी आप सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, इसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा।

मैं पुनः आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो कुछ सुना, निश्चित रूप से आप इस पर पूरा मनोविचार करके इनको आप लागू करेंगे और खास तौर से जो बात आप से कह रहा हूँ आयुष डिपार्टमेंट के लिए, इस पर भी माननीय मंत्री महोदय, आपके पास में डिपार्टमेंट नहीं हो, लेकिन डिपार्टमेंट जिसके पास भी है, उनसे बात करके, क्योंकि चिकित्सा पद्धति केवल मेडिकल ही नहीं है आयुष भी चिकित्सा पद्धति है और चिकित्सा की जब हम बात कर रहे हैं, चिकित्सा, चाहे मेडिकल हो, चाहे आयुष की हो, उन दोनों पर हम विचार करके राजस्थान को कैसे हम लाभान्वित कर सकें? इस पर आपको विचार करना चाहिए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री संदीप शर्मा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा पर बोलने का अवसर प्रदान किया। संपूर्ण विश्व में यदि कोई सबसे संवेदनशील विषय है तो चिकित्सा और स्वास्थ्य, क्योंकि एक रुग्ण बीमार व्यक्ति बड़ी आशा भरी उम्मीद के साथ किसी चिकित्सालय में जाता है, एक अच्छे चिकित्सक की तलाश करता है और उसका प्रयास होता है कि वह जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। जब उसे अच्छी चिकित्सा, अच्छी व्यवस्थाएँ, अच्छे संसाधन मिल जाते हैं, अच्छा वातावरण उसको मिल जाता है तो उसके मन से ही, मानसिक रूप से ही उस अनुकूल वातावरण में 50% तो यूं ही सही हो जाता है।

माननीय सभापति महोदय, आज जो बातें कह रहे थे बायतू से आने वाले माननीय हमारे विधायक जी और हमारे आदरणीय सभापतिजी पारीक साहब, तो निश्चित रूप से जैसे-जैसे आधुनिकीकरण बढ़ा है, भौतिकवाद बढ़ा है, कृषि उत्पादों में यूरिया, पेस्टिसाइड और केमिकल का उपयोग बहुत अधिक तेजी के साथ बढ़ा है। हवा, पानी, खाद्य पदार्थ ये सब बहुत तेजी के

साथ दूषित होने लगे हैं और बायतू से आने वाले हमारे विधायक महोदय की चिंता थी कि ये कौन ठीक करेगा? निश्चित रूप से इसे हम ही सही करेंगे। पूरी प्रतिबद्धता के साथ सही करेंगे और करने भी लगे हैं, क्योंकि आज जिस तरीके से तेजी के साथ मधुमेह, कैंसर, हाइपरटेंशन, हार्ट डिज़ीज़ के लोग शिकार हो रहे हैं। व्यक्ति के अंदर रोग-प्रतिरोधक क्षमता का अभाव होने लगा है और बहुत छोटा सा रोग भी बहुत बड़े रोग के रूप में उस व्यक्ति से वह ग्रसित हो जाता है। आज आवश्यकता है स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की, खान पान में सतर्कता की भी और सरकार भी इसी दिशा में काम कर रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा का, उन्होंने इस बात को समझा और सबसे पहले उन्होंने व्यक्ति की सबलता पर, उसकी स्वस्थता पर ध्यान देते हुए, जो हमारी प्राचीनतम योग पद्धति थी उसे सिर्फ भारत में ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण विश्व में उसको प्रतिपादित किया और संपूर्ण विश्व के लोगों ने उस योग की महत्ता को समझा माना और आज लोग-बाग इसके प्रति अवेयर हैं। जो बात कर रहे थे खाद्य पदार्थों में अब जो पेस्टिसाइड है, जो कैमिकल है, जो यूरिया है उसमें भी हमारी केंद्र सरकार ने नीम कोटेड यूरिया, ऑर्गनिक खेती को बढ़ावा देना, यह पहली बार यदि किसी सरकार के दिमाग में काम ये विचार आया तो हमारी केंद्र की सरकार के, माननीय प्रधान मंत्री जी के दिमाग में विचार आया, क्योंकि यदि हम व्यक्ति के जीवन में अच्छा खान-पान, अच्छी जीवन शैली दे सकेंगे तो निश्चित रूप से रोग कम रूप से आक्रमण करेंगे। मैं कोई आप लोगों की बहुत ज्यादा आरोप, या आलोचना आपकी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि यह विषय ही आरोपों और आलोचना का नहीं है, लेकिन कुछ जो आपकी कमियां रही हैं, वो तो कहनी पड़ेंगी। पर यह संवेदनशीलता का विषय है। चाहे हम हों, चाहे यह हों, सभी को मिलकर विचार करना होगा कि जो कारक हैं, जो आप भी बता रहे हो, हम भी जानते हैं उनका क्या इलाज है? कैसे उन कारकों को हम रोक सकते हैं और ये सब हमारी जिम्मेदारी भी है, दायित्व भी है, क्योंकि ढ़ाई-ढ़ाई, तीन-तीन की संख्या में लोग हमें जिताकर दिया भेजते हैं, हमसे अपेक्षा भी करते हैं और वो हमें अपना हीरो मानते हैं। कोई भी परेशानी आ जाएगी तो हमारे विधायक जी हमारे आगे खड़े रहेंगे, हमारे साथ खड़े रहेंगे। कोई सी भी जटिल परेशानी में, कोई भी दिक्कत में, यह लोगों की अपेक्षा हमसे रहती हैं। हमें अपने प्रतिनिधि के रूप में मानते हैं। जिस तरीके से आज आवश्यकता है ठीक इस आधुनिक चिकित्सा का भी पूरा सरकार ध्यान दे और साइड इफेक्ट रहित चिकित्सा भी चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़े।

इसके साथ ही साथ जैसा हमने कोरोना में देखा, कोरोना की बात कर रहे थे। कोरोना में वो स्थिति थी कि यदि माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं हों और मुझे याद है वो मंजर, वो भय उत्पन्न करने वाला दृश्य, आपके मंत्री भी तीन-तीन, चार-चार मंत्री दिल्ली जाकर माननीय लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला जी से मिले थे। ऑक्सीजन के लिए भी आपने हाथ खड़े कर दिए थे और आप सब गायब हो गए थे? मुख्य मंत्री जी भी, इस समय

आपको याद है? या भूल गए? आप भूल भी जाओ, परंतु जनता कभी इसे भूलने वाली नहीं है। वो एक दंश की तरह, घाव की तरह उनके सीने पर अमिट छाप है, जो आपने उनके साथ कोरोना में किया था। आप छिप गए थे और उस समय ऑक्सीजन कंटेनरों से, टैंकरों से राजस्थान की धरती पर आई थी, लोगों की जान बची थी। खेप की खेप रेमेडिसिवर और अन्य दवाइयां, जितनी भी संबंधित थीं, मास्क और सब ऑक्सीजन कंसंटेटर, ऑक्सीजन के सिलेंडर, सब केंद्र सरकार के माध्यम से लाये गए थे और लोगों की जान बचाने का प्रयास किया गया था। परन्तु आपने जिस तरीके से हाथ खड़े कर दिए थे, मेरा मानना है कि ये सरकार का दायित्व होता है, ऐसी स्थिति में खड़े होकर लोगों की मदद करना। केंद्र की सरकार ने देश को एम्स दिए, मेडिकल कॉलेज दिए, डायलिसिस योजना में चिकित्सा उपकरण दिए, परम्परागत चिकित्सा पद्धतियों का संरक्षण किया और आयुर्वेद में नए अनुसंधान को प्रोत्साहित किया।

jyg/rtm/06.03.25/14.40/2g

ये काम केन्द्र सरकार ने किये 2025-26 में चिकित्सा पर व्यय 1 लाख करोड़ जो कुल जीडीपी के लगभग 2 प्रतिशत के बराबर रहा। अब इसको 2.5 प्रतिशत किये जाने का लक्ष्य भी तय है। यह कार्य केन्द्र सरकार द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में महज 10 वर्षों के अन्दर हुए। चूंकि प्रधान मंत्रीजी की सोच है कि उत्तम चिकित्सा और उत्तम स्वास्थ्य से ही सबल और विकसित राष्ट्र बनेगा, अगर यह कार्य हम कर सकते हैं तो निश्चित रूप से लोगों को मजबूत बनाने का और उन्हें स्वस्थ्य रखने का काम केन्द्र सरकार का भी है और राज्य सरकार का भी है। आप काला कानून ले आये, हैल्थ के उस काले कानून की क्या आवश्यकता थी? जबर्दस्ती आपने पूरी चिकित्सा सेवा को बाधित कर दिया। आपका हमने तो यहां खड़े होकर जोरदार विरोध किया था, आपका निरोगी राजस्थान का सपना, आपका निरोगी राजस्थान का नारा और आप लादना चाहते थे उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर और प्राइवेट चिकित्सकों पर, यह ड्यूटी आपकी थी, कर्तव्य आपका था, यह आपको करना चाहिए था निरोगी राजस्थान और अगर उनसे करवाना भी था तो आपको उनको विश्वास में लेना चाहिए था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान का सरकारी चिकित्सक हो या प्राइवेट चिकित्सक हो, उसके अन्दर संवेदनशीलता है। यदि आप काला कानून नहीं लाते, दादागीरी नहीं करते, नियम और नीतियों से नहीं बांधते तो वो आपके सहयोग के लिए खड़े हो जाते। आपकी पूरी मदद करते और आपके निरोगी राजस्थान में आपका सहयोग करते। परंतु देखता हूं मैं, आज मैं यह न्यूज देख रहा था, यह कोटा की न्यूज है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं चिकित्सा मंत्रीजी का, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपकी आज जो कार्यशैली है, जो आपका कार्य प्रबंधन है, आज कालीचरणजी भी कह रहे थे कि कुछ चिकित्सकों का सम्मान करना है क्योंकि वो उत्साहित हैं, वो जोश में हैं आपकी कार्यशैली से, माननीय सभापति महोदय, यह आज की न्यूज है, 19 मेडिकल कॉलेज के हर

अस्पताल का स्टाफ क्षमता से तीन गुणा काम कर रहा है, 1947 बेड की क्षमता है लेकिन लगा रखे हैं 2831, मतलब बेड की क्षमता 1947 हैं और लगा रखे हैं 2831 और भर्ती मरीजों की संख्या इससे भी ज्यादा, इसके बावजूद पीछे नहीं हटते हमारे डॉक्टर। डॉक्टरों में उत्साह है, काम करना चाहते हैं, लेकिन काम कराने के लिए सरकार का रवैया भी उनके प्रति सकारात्मक होना चाहिए। इसलिए मैं धन्यवाद दे रहा हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी को, चिकित्सा कर्मियों को, नर्सिंग कर्मियों को, जिस तरह से आप भी मानते हैं कोरोना में जिस तरीके से उन्होंने काम किया अपनी जान हथेली पर रखकर, पूरे राजस्थान वासियों की मदद के लिए सदैव खड़े रहे, उनकी हर प्रकार से सेवा करते रहे तो ऐसे लोगों को शाबाशी देना भी आवश्यक है। निश्चित रूप से जब हम सबको साथ लेकर चलेंगे तो जिस तरीके से हम चाहते हैं कि हमारे राजस्थान के लोग पूरे तरीके से निरोगी हों, स्वस्थ रहें तो जरूर ये सारी की सारी चीजें हम पूरी कर पायेंगे। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में हमारी सरकार बड़े पैमाने पर इसी सोच के साथ काम कर रही है कि पूरे प्रदेश को कैसे स्वस्थ बनायें, हमारी संकल्पना विकसित राष्ट्र की है। यह तभी सम्भव होगा जब हम गुणवत्ता युक्त उत्तम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य युक्त राष्ट्र का निर्माण कर पायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, प्रथम बजट में जो भी घोषणाएं की गयी, वो सारी योजनाएं धरातल पर लाकर एक संकल्प के साथ, प्रबितबद्धता के साथ पूरा करने का काम किया है। आप सिर्फ घोषणाएं करके रह जाते थे।

चुनौतियां बहुत हैं इस डगर में,
पर आदत है हमें टकराने की,
तूफां की जिद है आशियाना मिटाने की,
तो हमें भी फिक्र है उनकी जिंदगियां बचाने की।

किसी परेशानी में हों, पूरी ताकत के साथ सेवा के भाव के साथ सदैव लोगों की मदद के लिए खड़े रहेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी भजन लाल जी का, जिन्होंने राजस्थान के चिकित्सा क्षेत्र में बहुत सकारात्मकता और संवेदनशीलता के साथ उत्तम चिकित्सा को दूरदराज तक सुगम बनाने के लिए कई फैसले किये। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आयुष्मान आरोग्य योजना का खाका तैयार किया। न केवल जीवन रक्षक पैकेज बढ़ाये बल्कि सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, बाहर जाकर भी व्यक्ति अपना इलाज करवा सके, यह व्यवस्था हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की। उन्होंने सत्ता में आते ही सबसे पहला काम एक-एक चिकित्सालय का निरीक्षण, उसकी मॉनिटरिंग, क्या-क्या सुविधाओं का अभाव है, किस प्रकार से इस चिकित्सा तंत्र को सुदृढ्ढ किया जाये, कैसे मजबूत हो, इन सारी चीजों का अध्ययन किया और उसके बाद बजट का निर्धारण किया, यह होता है वास्तविक और असलियत का काम, जो वास्तव में लोगों के काम आने वाला हो। कुछ भी घोषणाएं कर दो, उससे कोई लोगों को लाभ नहीं होगा, दो-तीन दिन लोग खुश हो जायेंगे, आप भी ताली बजाकर चले जाआगे लेकिन घोषणाएं करने के बाद पहले तो लोग चाहते क्या हैं, लोगों की परेशानी क्या

है, उनकी मजबूरी क्या है, किस तरीके से लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके और फिर वैसा ही बजट बनाना और उसके बाद अगले ही दिन से उस बजट के क्रियान्वयन में पूरी ताकत के साथ, क्षमता के साथ, पूरी सामर्थ्य के साथ लग जाना और अपनी टीम को भी पूरी मजबूती के साथ उस काम में लगा देना, तब जाकर बजट में जो घोषणाएं होती हैं वो शत प्रतिशत पूर्ण होती हैं, अभी हो रही हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं निश्चित रूप से हमारी जो घोषणाएं हुई हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है, चाहे वो मा योजना हो या अन्य योजना हो।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

जिस तरीके से मेरे कोटा शहर की डिमाण्ड है, उनको मैं बता दूं, आपने ट्रिंग कर दी। माननीय सभापति महोदय, खाद्य पदार्थों की बात बताना चाहता हूं। खाद्य पदार्थों में माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा ने, चिकित्सा मंत्री ने इतनी गम्भीरता से काम किया कि मिलावट को लेकर इन दो वर्षों के अन्दर अभियान की तरह पूरे राजस्थान के अन्दर लिया, 2023-24 में विभाग ने एंफोर्समेंट सैम्पल में 284 प्रतिशत लक्ष्य हासिल करते हुए देश में प्रथम स्थान हासिल किया, 1 साल में साढ़े छह लाख किलोग्राम मिलावटी सामग्री जब्त की गयी जो आपने आप में ऐतिहासिक है। बायतू से आने वाले माननीय सदस्य पूछ रहे थे, कौन करेगा, हम करेंगे। दो दिवसीय राज्य स्तरीय अभियान में 2284 वेंडर्स का निरीक्षण कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, 3915 मिलावटखोरों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। 11 करोड़ 20 लाख रुपये की पैनल्टी दर्ज हुई। मैं विभाग के मुखिया से कहना चाहूंगा कि इस लालच का कोई अंत नहीं है, यह कार्यवाही धीमी नहीं पड़नी चाहिए, पूरी ताकत के साथ इस कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाये। आज जिस तरीके से 16 मोबाइल फूड सेफ्टी लैबोरेटरी खरीदी जा रही है, इससे मौके पर ही अब जांच हो जायेगी और जिस तरीके से माननीय मुख्य मंत्रीजी चाहते हैं कि राजस्थानवासी स्वस्थ्य रहें, मिलावटी खाद्य पदार्थों से उनका बचाव कर सकें, उसी प्रतिबद्धता के साथ विभाग को काम करना होगा।

श्री सभापतिः प्लीज माननीय सदस्य।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, बहुत इम्पोर्टेण्ट बात है। माननीय सभापति महोदय, हमारे कोटा शहर में अभी बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं उनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। कांग्रेस के टाइम में, वो धारीवालजी उठकर चले गये, न्यू मेडिकल कॉलेज में एक ईंट लगी हो तो बता देना और एककार्य हुआ हो तो बता देना। परंतु मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कोटा शहर चम्बल नदी के किनारे बसा है, वहां वन हैं, प्राकृतिक वातावरण और वहां के वनों में बड़ी संख्या में दुर्लभ जड़ी-बूटियां पायी जाती हैं, चम्बल के तट पर आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा-योग एवं पंचकर्म पद्धति के मेडिकल ट्यूरिज्म की अगर स्थापना कर दी जाये तो निश्चित रूप से राजस्थान में एक बड़ा आयुर्वेदिक हब हम कोटा शहर में बना सकते हैं जहां पूरे देश से लोग अपना आयुर्वेद के माध्यम से अपना इलाज कराने आ सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी, मैं एक मिनट में अपनी मांगें जो कोटा शहर की है, एक तो हमें इंटरनेशनल रेडियो कार्डियक कैथ लैब की आवश्यकता है। 128 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन, एडवांस लाइफ सपोर्ट वाली 5 एम्बुलेंस, सिमुलेटर लैब, रोबोटिक हैंड और आदर्श सीएचसी दादाबाड़ी का उन्नयन, आदर्श सीएचसी विज्ञान नगर में पर्याप्त पदों का सृजन, कोटा शहर की बड़ा बस्ती, क्रेशर बस्ती, गोला बस्ती, दुर्गा बस्ती, श्रीनाथपुरम में नये आयुष्मान आरोग्य केन्द्र खोले जायें।

MLS/RTM/06.03.2025/14:50/2h

हमारे यहां हॉस्पिटल में नवीन तल का निर्माण पूरा हो चुका है, जिसमें 1150 बेडों की क्षमता है। वर्तमान में 340 नर्सिंग कर्मियों के पद स्वीकृत हैं। वे पर्याप्त नहीं हैं।

श्री सभापतिः डॉ. शिखा मील बराला।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): नर्सिंग स्टाफ के पद, आईसीयू के उपकरण व फर्नीचर के लिए बजट स्वीकृत किया जाये। कोटा का विस्तार होने से कोटा में एक और नर्सिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज खोलने की महती आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ. शिखा मील बराला (चोमू): सभापति महोदय, आपका आभार कि आपने मुझे मांग संख्या 27 और 28 पर मेरे विचार रखने की अनुमति दी। आपका पहले ही आभार, अगर एक-दो मिनट ऊपर हो जाएं, उसमें भी संरक्षण चाहिये। "Health is Wealth" स्वास्थ्य ही पूंजी है। आज के परिप्रेक्ष्य में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य का भी महत्त्व बढ़ गया है। बढ़ते हुए सुसाइड्स, डिप्रेशन, नशे की लत और आपराधिक प्रवृत्तियां देखते हुए हम यह समझ सकते हैं। इसे देखते हुए हमें मैंटल हैल्थ पर भी फोकस करना होगा। थॉमस फुलर ने कहा है, 'Health is not valued till sickness comes.' स्वास्थ्य का मूल्य तब तक नहीं होता, जब तक बीमारी न आ जाये।

सदन में कल जल पर चर्चा हुई। आज स्वास्थ्य और शिक्षा पर चर्चा है। दोनों ही जनता के जीवित रहने के लिए जरूरी हैं, पर सरकार के लिए आमजन का स्वास्थ्य बहुत ही सस्ता मालूम पड़ता है। स्वास्थ्य चिकित्सा बजट को देखकर जो जनता की उम्मीदें थीं सरकार से, वे सभी धराशायी होती नजर आ रही हैं। नम आंखों से परेशान जन-जन फिर से कांग्रेस की गहलोत सरकार को याद कर रहा है। आपका यह बजट राजस्थान को फिर से एक बीमारू प्रदेश की राह पर ले जाने वाला है। इस बार स्वास्थ्य चिकित्सा को 13 हजार 888 करोड़ रुपये आवण्टित किये गये, जो पिछले बजट से करीबन आधे हैं। कुल बजट में हिस्सा सिर्फ 3.7 परसेंट है, जो पिछले बजट में 8.3 परसेंट था।

ट्रांसपोर्ट में 38 परसेंट की बढ़ोतरी, रोड्स एंड ब्रिजेज में 36 परसेंट की बढ़ोतरी, बहुत बढ़िया बात है, पर राजस्थान के स्वास्थ्य को क्या आप लोग गर्त में पहुंचाना चाह रहे हैं? महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते ही जब भी विपक्ष आपको असलियत से वाकिफ कराता है,

लोक सभा में आपको नेहरू जी याद आते हैं और विधान सभा में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार याद आती है। अजी साहब, नेहरू जी ने तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आजादी के समय, जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 32 साल, उसे 1970 में अपने प्रयासों से 46, 1990 में कांग्रेस सरकार और बाकी सभी सरकारों के प्रयासों से 60 साल और आज 2024 में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 68 साल।

आधुनिक भारत के निर्माता पं. जवाहरलाल जी नेहरू के विजन से 1956 में जनता के लिए एक और मन्दिर का निर्माण किया गया, जिसे एम्स कहते हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की बात करें तो उसके लिए राजस्थान के लोगों का स्वास्थ्य हमेशा ही सर्वोपरि रहा। कोविड में जो काम किये गये, वे एक परीक्षा की तरह आये और राजस्थान को हिन्दुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व में माना गया। देश में सबसे ज्यादा 25 लाख की बीमा कवरेज देने वाली चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कांग्रेस सरकार में शुरू की गयी और लोगों में यह विश्वास कायम हुआ कि कितना भी संकट का समय क्यों न हो, सरकार आपके पीछे मजबूती से खड़ी है। चिरंजीवी योजना, जो अब मां योजना कहलाती है, उसमें कांग्रेस सरकार ने एनएफएसए, एससीसीसी कैटेगरीज को निःशुल्क बीमा प्रोवाइड कराया।

साथ ही, कोविड अनुगृहीत कैटेगरीज और संविदा कर्मियों को भी निःशुल्क बीमा दिया गया। यह इस कांग्रेस सरकार की संवेदनशीलता थी। बाकी लोगों को मात्र 850 रुपये सालाना में अपनी फैमिली के लिए बीमा का प्रावधान दिया। आज बहुत से अस्पतालों को समय पर भुगतान नहीं हो रहा है और मुझे युनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट के लोगों द्वारा अवगत कराया गया कि हाल ही में आरटीआई से पता लगा कि आयुष्मान भारत योजना की स्थिति देश में बहुत ही चिन्ताजनक है। 63 लाख कैसेज क्लैम्स से ज्यादा अटके हुए हैं और 1 लाख 21 हजार करोड़ रुपये की राशि लम्बित है, जो अस्पतालों तक नहीं पहुंच पायी है। इस वजह से आपने अस्पतालों के साथ-साथ मरीजों के स्वास्थ्य को भी संकट में डाल दिया है।

डबल इंजन की सरकार क्या सिर्फ लोगों के स्वास्थ्य को रौंदने के लिए है, सिर्फ कहने के लिए है या कोई विकास भी यहां होगा, लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान भी आप लोग रखेंगे? क्या यही है आपके लिए स्वास्थ्य क्रान्ति? मरीज लम्बी लाइनों में लगकर दवा तो लिखवा लेता है, पर मेडिकल स्टोरों पर मां योजना, एमएंडडीवाई योजना में दवाएं उपलब्ध नहीं हैं। जो दवाएं हैं, जांच सैम्पल्स उनके जो भेजे जा रहे हैं, उसमें कहीं भी वे क्वॉलिटी क्राइटीरिया को पास नहीं कर पा रहे, क्वॉलिटी चैक्स में फेल हो रहे हैं, पर सरकार द्वारा कोई भी कार्यवाही इस पर होती नजर नहीं आ रही। दवाओं की मात्रा और गुणवत्ता की कमी से नुकसान किसको है? जनता बहुत समझदार है, वह समझती है कि इससे नुकसान सिर्फ उसी के स्वास्थ्य को है।

जिस जनता ने आपको जनादेश दिया था, वह आज आपके दर पर आकर बिलकुल निराश हो चुकी है। मां वाउचर योजना शुरू की गयी, जिसमें गर्भवती महिलाओं को प्राइवेट सोनोग्राफी सेन्टर्स पर सोनोग्राफी की सुविधा दी गयी, पर देखिये, यह वाउचर माह में सिर्फ

9, 18 और 27 तारीख को जारी होता है। पूरे राजस्थान में 1248 सेन्टर्स पर यह सुविधा उपलब्ध है और आज दिन तक किसी भी सेन्टर को सरकार द्वारा पेमेंट नहीं किया गया और अभी तक तो यह भी क्लीयर नहीं है कि किस हैड द्वारा इसको पेमेंट किया जायेगा। सिर्फ नॉर्मल सोनोग्राफी इसमें है, जो आज की स्थितियों को देखते हुए एनटी-एनबी स्कैन, एनैमली स्कैन, डॉपलर स्कैन, उनकी जरूरत पड़ती है, उसका कोई प्रावधान नहीं है।

बढ़ती कॉन्जीनाइटल विकृतियों को देखते हुए मार्कर टेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है तो सरकार को इस पर भी जरूर विचार करना चाहिये। सबसे बड़ी विडम्बना देखिये, ट्रांसप्लांट्स की बात हम करते हैं, न्यूरो सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी, ऑन्को सर्जरी, बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, पर दुनिया की जननी एक प्रसूता को मां योजना में प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी का हक नहीं दिया जाता। दोगला व्यवहार सिर्फ महिलाओं के साथ यहां पर हो रहा है। जो महिला सरकारी अस्पताल में भर्ती है, वहां ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा नहीं है, इमरजेंसी में या तो उसे दूर एक सरकारी अस्पताल में जाना पड़ता है या प्राइवेट अस्पताल में जाकर खुद की जेब से खर्चा करना पड़ता है। इस तरह से हमने उन परिवारों की जो सुखद घड़ियां हैं, उनमें प्रसूताओं की जिन्दगी को अधरझूल में डाल दिया है।

आरयूएचएस की बदहालियों की तो बात ही कुछ और है। आज हमारे माननीय वरिष्ठ सदस्य सराफ जी ने भी इसका जिक्र किया। एसएमएस में हम आये दिन नये ओपीडी, आईपीडी भवन बना रहे हैं, बहुत खर्चा कर रहे हैं, वहां बहुत मरीजों का लोड है, मैं भी उसी संस्था से पढ़ी हूं और मुझे इस बात का गर्व है, पर जब आरयूएचएस में हमारे पास लाखों करोड़ का इन्फ्रास्ट्रक्चर पहले से है तो हम उसे तरीके से काम में क्यों नहीं ले पा रहे? क्यों सरकार इसके प्रति अपनी उदासीनता दिखा रही है? आये दिन न्यूज आती है कि हमने एक-एक इस डिपार्टमेंट की यूनिट को आरयूएचएस में भेज दिया। रोटेशन पर वे काम करेंगे। एक साल में क्यों आप नियुक्तियां नहीं कर पा रहे हैं?

जब आरयूएचएस की बात चली है तो अभी एक नयी पर्ची के बड़े चर्चे हैं स्वास्थ्य विभाग के गलियारों में। आरयूएचएस के वीसी पद पर महाराष्ट्र से बिलॉन्ग करने वाले फार्मासिस्ट को लगाया गया है। यह राजस्थान के सभी वरिष्ठ, योग्य और अनुभवी चिकित्सकों पर एक सवालिया निशान है। ये वही चिकित्सक हैं, जिन्होंने अपने कैरियर में अभी तक हजारों, लाखों स्पेशियलिस्ट्स और सुपर स्पेशियलिस्ट्स तैयार कर दिये हैं। क्या यहां जितने भी 200 माननीय सदस्य हैं, वे इस बात से सहमत हैं कि हमारे राजस्थान में एक भी डॉक्टर इस लायक नहीं था कि वह वीसी का पद ले सके? मेडिकल एजुकेशन की स्थिति बहुत ही चिन्तनीय है। मेडिकल कॉलेजेज में यूट्यूब से बिना प्रैक्टिकल, बिना फैकल्टी पढ़ाई हो रही है और ये डॉक्टर्स आकर हमारा इलाज करेंगे।

पराकाष्ठा है कि आरएमसी आठवीं और बारहवीं पास लोगों को फर्जी डॉक्टर्स की डिग्री दे रही है। ऐसे लोग जब फील्ड में जाकर लोगों का इलाज करेंगे और मौतें होंगी तो वे सभी सरकार के खातों में लिखी जाएंगी और हत्या के रूप में लिखी जाएंगी। राजस्थान में अभी

तक फिजियोथैरेपी काउंसिल नहीं है, जबकि बाकी स्टेट्स में है। यहां से फिजियोथैरेपी, बीपीटी करने वाले लोगों को भर्तियां नहीं मिलती हैं तो मेरी मांग है, एक राजस्थान फिजियोथैरेपी काउंसिल स्थापित की जाये। यहां पर प्राइवेट कॉलेजेज में एनएमसी के रेजीडेंट डॉक्टर्स को दिये जाने वाले स्टाइपेंड में खुलेआम नियमों का उल्लंघन हो रहा है, पर सभी सरकारें आंखें मून्दकर बैठी हैं।

राजमेस के नये कॉलेजेज, जैसे झुंझुनूं, बारां आदि में एनएमसी इंस्पेक्शन के लिए राजकीय और राजमेस कॉलेजों से चिकित्सक शिक्षकों को ट्रांसफर कर दिया गया। पीछे वाले कॉलेजेज में शिक्षकों की कमी हो गयी। अब ऐसे जुगाड़ से हम मेडिकल शिक्षा का स्तर कैसे सुधार पाएंगे?

(समय: बजे)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

राजकीय आयुर्वेद औषधालयों में करीबन 3 हजार योग प्रशिक्षक कार्यरत हैं। 2021 की नियुक्ति के बाद न उनका वेतन बढ़ा, न उनका कार्यकाल बढ़ा।

MKD/RTM/06.03.2025/15:00/2j

मेरी मांग है कि फुल टाइम नियुक्ति के साथ उनका वेतन बढ़ाया जाए। महिला स्वास्थ्य तो आपके लिए प्राथमिकता है ही नहीं, क्योंकि उड़ान योजना में पिछले 6 महीने से ज्यादा समय से सैनेटरी नैपकिन ही वितरण केन्द्रों पर नहीं पहुंच पाये। एचआईवी इंफेक्टेड महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग की बात की, पर कहीं पर भी बढ़ते हुए स्तन कैंसर स्क्रीनिंग की बात नहीं हुई। क्यों नहीं, हम सर्वाइकल वैक्सीन नि:शुल्क या रियायती दरों पर उपलब्ध कराने का विचार रखते हैं।

श्री सभापति: विराजिये। श्री जब्बर सिंह सांखला।

डॉ. शिखा मील बराला (चोमू): बहुत दिलचस्प बात तो जनवरी के तबादलों में देखने को मिली। 1 से 10 और फिर 10 से 15। सर, 15 मिनट का टाइम था।

श्री सभापति: जी नहीं, आप विराजिये, 10 मिनट।

डॉ. शिखा मील बराला (चोमू): तबादलों का उत्सव जैसा लगा। लूट की छूट दी गई। संशय में हूं कि माननीय मंत्री महोदय इससे अवगत हैं या नहीं, पर बैक डेट में तबादलों की लिस्ट ऐतिहासिक रिकॉर्डों को पार कर गई।

श्री सभापति: बहुत वक्ता हैं आपके।

डॉ. शिखा मील बराला (चोमू): हम सभी मानते हैं कि मुख्य मंत्री महोदय बहुत ही सज्जन और सौम्य स्वभाव के हैं, पर बेड़ियों में जकड़े नजर आ रहे हैं और चक्रव्यूह में फंसे नजर आ रहे हैं। उनकी हालत संयुक्त परिवार की उस गरीब बहू जैसी हो गई है, जहां परिवारजन आपस में झगड़ रहे हैं और बहू सभी को खुश रखने का भरपूर प्रयास कर रही है।

मिलावट की बात आती है तो हमें शुद्ध खाद्य पदार्थ नहीं मिल रहे हैं। आपके फूड एंड

सैफ्टी डिपार्टमेंट की एक सीनियर अधिकारी का ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें वे सुन रहे हैं कि, भैया, तुम्हारी मिठाई का सैम्पल तो पास करा दिया है, अब आगे की कार्यवाही भी करो। ऐसी चीज हमारी जनता के लिए बहुत दु:खदायी हैं। कल न्यूज देखी की दूध के 200 सैम्पलों में से सिर्फ 5 सैम्पल गुणवत्ता क्राइटेरिया पर खरे उतरे हैं।

माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, चोमू की डिमांड पर मैं बोलना चाहूंगी, कालाडेरा सीएचसी को मॉडल सीएचसी बनाया गया, पर वहां कोई भी कार्य नहीं हुआ। वहां पर हमें एक नये भवन की आवश्यकता है, जो भवन है, वह नाकाफी और जर्जर है। स्त्री रोग विशेषज्ञ के अभाव में वहां पर प्रसूताओं को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कालाडेरा गोविन्दगढ़ सीएचसी पर जनरल फिजीशियन नहीं है। सामोता सीएचसी और चोमू एसडीएच पर थ्री डी डोप्लर सोनोग्राफी मशीन की जरूरत है। बायो केमेस्ट्री लैब्स को भी वैल इक्यूप्ड करने जरूरत है। चोमू में हमें एक्स-रे मशीन की अत्यन्त आवश्यकता है। चोमू एसडीएच के लिए भूमि आवंटन।

आप आज जनता को ना साफ पानी, ना साफ खाद्य पदार्थ, दूध, बिजली आदि सुविधाएं दे सकते। आखिर में, मैं कंक्लूड करूंगी, वर्तमान सरकार की स्थितियों को देखते हुए, वह जहर देता तो सबकी निगाह में आ जाता, वह जहर देता तो सबकी निगाह में आ जाता, सो यह किया कि मुझे वक्त पर दवाएं नहीं दीं।

आपका बहुत-बहुत आभार, जय हिन्द, जय संविधान।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री जब्बर सिंह सांखला। श्री गोविन्द प्रसाद।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 27 व 28 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके तहत मनुष्य का जीवन निर्भर होता है। आज हम देखते हैं कि ईश्वर के बाद डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। डॉक्टर जीवनदान दे सकता है या किसी मनुष्य की जिन्दगी और मौत, उसके हाथ में होती है। वह उसकी जिन्दगी बचाने में रातों की नींद व नि:स्वार्थ सेवा से अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं।

एक डॉक्टर को कभी भी किसी जाति व धर्म से कोई मतलब नहीं होता है, वह सबको समान रूप से देखता है। डॉक्टर जब किसी मरीज का इलाज करते हैं तो सबसे पहले उसको मानसिक रूप से मजबूत करते हैं और जीवन से प्यार करना और शरीर को सेहतमन्द बनाये रखना डॉक्टर का मैन उद्देश्य होता है और मरीज को यही सीखाता है।

तभी तो ईश्वर सभी के जीवन के रक्षा खुद नहीं कर पाते, इसलिए इस धरती पर अपने रूप में डॉक्टर को भेजा है। इसलिए सभी डॉक्टरों को मेरा बहुत-बहुत धन्यवाद।

आज हमें आवश्यकता है चिकित्सा व्यवस्था में सुधार करने की। सरकारी अस्पतालों में स्टाफ की स्थिति, दवाओं और जांच उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त जीवन रक्षक दवाओं, वस्तुओं एवं अन्य उपकरणों पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगाना चाहिए।

केन्द्र और राज्य सरकार को मुफ्त और अनिवार्य चिकित्सा के लिए कानून बनाना चाहिए। कई गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भी नहीं होते हैं, जो होते भी हैं तो वहां स्टाफ और आवश्यक जांच उपकरण नहीं हो पाते हैं। ये तो सिर्फ झोलाछाप पर निर्भर हैं। गांवों में स्वास्थ्य केन्द्र सिर्फ कागजों में ही चलते हैं। अस्पताल में चिकित्सा और पैरामेडिकल स्टाफ की उपस्थिति सुनिश्चित करना आवश्यक है।

योजनाएं ऐसी बनें, जिसमें जो सुविधाएं देने का वादा किया जाए, वह आम आदमी को मिले। चिकित्सा को विश्वास में लेकर चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार हो और योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता हो। तभी अपनी जिम्मेदारी समझकर व्यवस्था को सुधारने में अपना योगदान दे। साथ ही, हमें कानून की आवश्यकता है। चिकित्सा व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार को निजी अस्पतालों में कीमतों के लिए नीति व कई कानून बनाने पड़ेंगे, जिससे वे मनमानी नहीं कर सकें।

आज जेनेरिक दवाइयों की खरीद और एमआरपी में बहुत अन्तर है। जैसे आई वी सैट खरीद मूल्य साढ़े नौ रुपये और एमआरपी होती है 230 रुपये। सीट्रिप टैबलेट, खरीद मूल्य साढ़े चार रुपये और एमआरपी होती है 73 रुपये। प्रेजोम डीएसआर, खरीद मूल्य 13 रुपये 75 पैसा, एमआरपी होती है 176.75 रुपये। मोतियाबिन्द में लैंस लगाने के लिए हम सरकारी अस्पतालों में 5 से 10 हजार रुपये में काम हो जाता है, लेकिन निजी अस्पताल में करीबन 60 हजार रुपये पे करना पड़ता है। ऐसी मंहगी दवाइयों के लिए मजबूर, क्यों क्या कारण है। उचित मूल्य पर दवाई उपलब्ध करवाई जाए। इस ओर सरकार को ध्यान देने की बहुत ही आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कहा है कि बहुत-सी राज्य सरकार समाज के गरीब तबके के लोगों को उचित मूल्य पर दवाइयां, खास तौर पर जरूरी दवाइयां उपलब्ध नहीं करवा रही हैं, काफी राज्यों की सरकारें इसमें विफल रही हैं। इस विफलता से निजी अस्पतालों को सुविधा प्रदान की और उन्हें बढ़ने का मौका मिला है, इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि चिकित्सा देखभाल करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है।

कोराना काल में प्राइवेट हॉस्पिटलों ने तो हद कर दी थी, मुझे कहने में भी शर्म आती है। इसलिए, आज हमारे सरकारी अस्पताल में भी डॉक्टर और दूसरे स्टाफ को पाबन्द करना होगा और योजनाओं को लागू करने में आ रही समस्याओं का त्वरित निराकरण कर, आमजन को लाभ पहुंचाने का काम करना होगा।

हमें आवश्यकता है, राजकीय चिकित्सालयों और चिकित्सा सम्बन्धी व्यवस्थाओं का निजीकरण नहीं किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा व्यवस्था पर अधिकाधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को छोटी-छोटी समस्याओं के लिए शहरों और झोलाछाप लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं और शोध कार्यों में तेजी लाई जानी चाहिए। नये डॉक्टरों के लिए कम से कम पांच साल तक की सेवा ग्रामीण क्षेत्रों में देना आवश्यक की जाए।

वर्तमान में चिकित्सा पद्धति सर्वाधिक खर्चीली है। आम आदमी को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा

मिलना मुश्किल सा हो गया है। आज की चिकित्सा सुविधा केवल अमीर और धनाढ्य लोगों की पहुंच में रह गई है। आम आदमी को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जेनेरिक दवाइयों के प्रति लोगों में विश्वास बढ़ाने के कदम उठाये जाने चाहिए। सभी तरह के स्वास्थ्यकर्मियों की संख्या में वृद्धि करने के प्रयास होने चाहिए।

निजी अस्पतालों की मनमानी, बीमारी के नाम पर लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर निजी अस्पताल मनमानी वसूली में जुटे हैं, उन पर लगाम लगानी चाहिए। सरकारें ऐसे निजी अस्पतालों का अधिग्रहण करे और साथ ही सरकारी चिकित्सा तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए। निजी अस्पतालों के लिए श्रेणीवार शुल्क तय किये जाएं।

राजस्थान में सरकार एक तरफ तो मुफ्त दवाइयों की संख्या बढ़ा रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी अस्पतालों के दवा काउंटरों पर बुखार और सर्दी, जुकाम की दवा भी नहीं मिल पा रही है। बेहतर तो यह है कि मुफ्त दवाइयों की संख्या न बढ़ाकर जरूरी दवाइयां उपलब्ध करवा दी जाएं।

चिकित्सा क्षेत्र में काम करने वालो की मानसिकता व्यावसायिक हो गई है। वे इस क्षेत्र में मिशन की तरह काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए सरकारी अस्पतालों की चिकित्सा व्यवस्था खस्ताहाल और निजी अस्पताल के मरीजों में सुधार लाना चाहिए। चिकित्साकर्मियों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी और सेवा भाव से काम करना होगा।

Bhs/Rtm/06.03.25/15.10/2k

माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा में काफी आवश्यक सुधार की जरूरत है। आज मैं एक लेख पढ़ रहा था जिसमें डॉक्टर ने बताया कि वो दिन नहीं भूल सकता जब मुझे कैंसर है, माननीय सभापति जी, तब हमें एहसास होता है स्वास्थ्य क्षेत्र में यह लड़ाई कितनी कठिन होने वाली है। मेडिकल स्कूल स्थापित करने और सीटों की सही संख्या के लिये अनुमति देने हेतु मौजूदा दिशा-निर्देशों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सकों को शिक्षण विशेषाधिकार देना और ई-लर्निंग पूल की अनुमति देना, पूरे सिस्टम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की कमी को दूर करना। साथ ही इन सुधारों से शिक्षण की गुणवत्ता से समझौता किये बिना मौजूदा चिकित्सा सीटों को दुगना किया जा सकता है। सतत शिक्षण प्रणालियों पर आधारित आवधिक पुनः प्रमाणन परिवर्तन की तीव्र गति के साथ बने रहने के लिये आवश्यक हो सकता है। छात्रों को अपने बुनियादी प्रबंधन संचार एवं नेतृत्व कौशल में सुधार करने की आवश्यकता है। डॉक्टर्स के रूप में उनकी सामाजिक प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। कक्षाओं में विषयों का एकीकरण, नवीन शिक्षण विधियों तथा अधिक प्रचलित प्रौद्योगिकी के उपयोग की आवश्यकता है। कॉलेजों में चिकित्सा अनुसंधान और नैदानिक कौशल पर कार्य करने की आवश्यकता है। पैरामेडिकल भर्ती 2023 में रिक्त रहे सहायक रेडियोग्राफर और लैब टेक्निशियन पदों पर प्रतीक्षा सूची जारी कर शीघ्र पदों को भराया जाये।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, एन.एच.एम. ने मानव संसाधनों के विस्तार, महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दों के समाधान और स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों के लिये एकीकृत उपायों को बढ़ावा देने के अपने अथक प्रयासों के माध्यम से भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पिछले तीन वर्षों में एन.एच.एम. ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य रोग उन्मूलन और स्वास्थ्य सेवा सहित कई क्षेत्रों में पर्याप्त प्रगति की है खासकर कोविड 2019 महामारी के दौरान इनके प्रयास स्वास्थ्य सुधारों के लिए अभिन्न रहे हैं।

श्री सभापतिः कृपया आपस में बातें न करें।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): और इससे पूरे देश में अतिसुलभ स्वास्थ्य सेवायें सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र में सम्माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले बजट में सैटेलाइट अस्पताल दिया अकलेरा, इसके लिये मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और कुछ आवश्यकताएं मेरे विधान सभा क्षेत्र में हैं, जो लंबे समय से सभी पद रिक्त चल रहे हैं उनको भरा जाये और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जावर व भालता को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करवाया जाये और मनोहरथाना को उप जिला चिकित्सालय बनाया जाये, ताकि क्षेत्र की जनता को 100 किलोमीटर की दूरी पर झालावाड़ न जाना पड़े। धन्यवाद, साहब।

श्री सभापतिः धन्यवाद। श्री अमीन कागजी।

श्री अमीन कागजी (किशन पोल): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27, 28 पर बोलने की अनुमति दी, उसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की डिमांड से शुरू करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक सैटेलाइट हॉस्पिटल बनकर तैयार है। मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि उसके अंदर जो पद सृजित हैं, डॉक्टर्स लगाकर उसको जल्दी से जल्दी चालू किया जाये। साथ में, उसमें जो इक्विपमेंट्स की जरूरत है उसकी भी जल्दी से खरीद की जाये ताकि वो हॉस्पिटल सुचारु रूप से चालू हो सके।

माननीय महोदय जी, इसी प्रकार मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक रामगंज में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित है, उसकी ओ.पी.डी. तकरीबन 1000 से 1100 पर डे है और वहां पर चूंकि 2016 में 50 बेडेड शहरी सामुदायिक केंद्र में क्रमोन्नत कर दिया गया था, उसका भवन पिछली सरकार में हमने 5 करोड़ 25 लाख रुपये से बना कर उसका रिनोवेशन कर दिया है। मेरा मंत्रीजी से आग्रह है कि उसके अंदर तुरंत से नवीन पद और जो शहरी सामुदायिक केंद्र में जितने पद सृजित होते हैं, नोर्म्स के हिसाब से उनकी डॉक्टर्स की नियुक्ति तुरन्त प्रभाव से कर दी जाये।

सभापति महोदय, इसी तरीके से मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक मोती कटला डिस्पेंसरी जिसको छोटे अस्पताल के नाम से जाना जाता है, उसको भी हमने 5 करोड़ 34 लाख रुपये से एक टेंडर और सरकार ने उसका 2023-24 के बजट में बजट एलोकेशन किया था, उसका

टेंडर नहीं हो पाया है। मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि उसको आगे बढ़ाते हुए उस बिल्डिंग के लिये तुरंत प्रभाव से उसका टेंडर करा जाये, क्योंकि उसकी ओ.पी.डी. 700 से 800 पर डे है।

सभापति महोदय, मेरी कुछ छोटी-मोटी डिमांड्स हैं, उस पर मैं ये सारे पेपर्स टेबल कर दूंगा। इसके बाद मैं जिस तरीके से सरकार ने पिछले साल में बजट में जो घोषणाएं की थी और पूरे बजट का करीब 8.25% बजट चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिये रिज़र्व किया था, मैं समझता हूं कि सरकार उसका 60 फीसदी बजट भी खर्च नहीं कर पाई है, उसकी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में सरकार ने घोषणा की थी कि मॉडल डिस्पेन्सरी सी.एच.सी. खोली जाएंगी। जयपुर में एक भी मॉडल सी.एच.सी. की स्थापना यह सरकार नहीं कर पाई, उसी तरीके से आर.यू.एच.एस. की अगर बात करें तो 200 करोड़ रुपये का प्रावधान सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल शुरू करने के लिये आपने किया था और मुझे अभी कल ही पता चला है कि सरकार ने आनन-फानन में, क्योंकि आप लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आपने एस.एम.एस. से कुछ सुपर स्पेशियलिटी डॉक्टर्स को उठाकर वहां पर ओ.पी.डी. 4-5 दिन पहले शुरू की है, जिसकी आपने ओ.पी.डी. के साथ आई.पी.डी. शुरू करने की बात पिछले बजट में की थी, उसका 1% भी काम आप लोग नहीं कर पाये, इसका बड़ा दुख है क्योंकि जयपुर की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जयपुर में जो साउथ ऑफ जयपुर में आर.यू.एच.एस. में हमारी तत्कालीन सरकार ने बना कर मल्टी स्पेशियलिटी सुपर स्पेशियलिटी के हिसाब से उस बिल्डिंग को बनाया था, लेकिन आप लोग उसको आज तक चालू नहीं कर पाये।

सभापति महोदय, उसी तरीके से आई.पी.डी. टॉवर की एस.एम.एस. में एक महत्वाकांक्षी योजना हमने शुरू की और आपने सरकार में आते ही उसको रोक दिया। रोकने के 1 साल बाद आपको यह होश आया, समझ आयी कि यह तो जयपुर की जनता नहीं पूरे राजस्थान की जनता के लिये एक मील का पत्थर साबित होगी, आपने उसको शुरू किया और पिछले बजट में 200 करोड़ रुपये का आपने 1200 बेडेड के लिये इसमें घोषणा की थी कि इसके अंदर हम इक्विपमेंट्स खरीदेंगे, संसाधन खरीदेंगे लेकिन बड़ी गंभीरता और चिंता के साथ में मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आपने उस 12 सौ करोड़ रुपये में से 12 रुपये भी खर्च नहीं किये, न इक्विपमेंट्स पर खर्च किये और नहीं आज तक आई.पी.डी. टॉवर की शुरुआत जो की थी, जिस मंतव्य से सरकार ने की थी, उस ओर आप अग्रसर नहीं हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि इसको गंभीरता से करें।

सभापति महोदय, इसी तरीके से पिछले बजट में जयपुर के बच्चों के लिये नोनिहाल बच्चों के लिये आपकी सरकार ने 22 करोड़ रुपये का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडिकल जेनेटिक्स की घोषणा की थी, आज तक आप उसमें कुछ कर नहीं पाये। लेटेस्ट पोज़ीशन यह है कि आप उसके अंदर न लैब की व्यवस्था के लिये जगह चिह्नित कर पाए, न उसमें कोई काम कर पाये। इसी तरीके से एस.एम.एस. अस्पताल में भी आपने पिछले बजट में घोषणा

की थी कि ई.एंड टी. विंग खोलेंगे, आपने आज तक वह ई.एंड टी. विंग भी नहीं खोली। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल और आज मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर कोई गंभीर रोगी आंख का आ जाये जिसको तुरंत प्रभाव से आंख का ऑपरेशन अगर कराना है तो वहां अगर आपको ऑपरेशन कराने के लिये डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी तो डेढ़ महीने का टाइम, सभापति जी, जिस आदमी की आंखें चली जाती हैं, जिस आदमी का मोतियाबिंद बिगड़ जाता है उसके ऑपरेशन के लिये आपकी सरकार में डेढ़-डेढ़ महीना ऑपरेशन के लिये ले रहे हैं। करोड़ों-लाखों रुपये की बजट की बात करते हैं। मैं समझता हूं कि यह भी एक चिंता का विषय है और लोगों के गंभीर रोगों के इलाज के लिये आपको इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, इसी तरीके से अगर आर.एम.एस.सी.एल. की बात करें, तो इसमें आपने पूरे तरीके से जो सत्यानाश इसका किया है, उड़ान योजना जो आप बात करके सरकार में आये थे कि महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान, और आपने क्या किया? कि डेढ़ साल से जब से आप सरकार में आये 1 रुपये का सैनेटरी नैपकिन आपने नहीं खरीदा।

Kas/rtm/06.03.2025/15.20/2l

एक टेंडर से आपने उसकी खरीद नहीं की। जितने भी सेंटर्स हैं, आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं, उनमें आज हमारी बहन-बेटियों के लिये एक भी नैपकिन अवलेबल नहीं है। बड़े शर्म की बात है कि आप महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं और आपने 14 महीने में एक भी खरीद नहीं की।

इसी तरीके से आरएमएससीएल में, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि रेट कांट्रेक्ट क्यों नहीं हो रहे? आपके कांट्रेक्ट सप्लायर्स गायब हो गये, वो आपको सप्लाई देने को तैयार नहीं है। आपने एक-एक साल से उनका पेमेंट रोक रखा है। दवाइयां आप नई खरीद नहीं पा रहे। मैं कहना चाहता हूं कि 2011 में जब हमारी सरकार थी, तो हमने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना प्रारंभ की थी और पूरे विश्व में इस योजना का प्रचार-प्रसार हुआ और पूरी दुनिया ने इसको सराहा। भारत सरकार ने भी इसको एडॉप्ट किया और कई स्टेट्स ने इसको एडॉप्ट किया। लेकिन दुःख के साथ कहना पड रहा है कि निःशुल्क दवा योजना के टेंडर की शर्तों में, जब से आप सरकार में आये हैं, आपने जो मापदंड चेंज किये है, 32 दवाइयों के लिये तो अभी तक आपके पास टेंडर में कोई पार्टिसिपेट करने नहीं आया। 141 दवाइयों के लिये सिर्फ एक कंपनी आई है और 2024 में कम से कम 121 दवाओं के सेम्पल आपके जांच में फेल हो गये। आप उन दवा मेनुफेक्चर्स पर कोई कार्यवाही नहीं कर पाये। इस पर आपको गंभीरता से विचार करना पड़ेगा।

इसी तरह से आरजीएचएस में जो पेंशनर्स हैं, बूढ़े हैं, जिनका रिटायर्मेंट है, बेड रिटर्न हैं, जो बेड पर दवाइयां लेते हैं, उनके आपने मापदंड चेंज कर दिये। दवाइयां नहीं मिल रहीं।

समाचार पत्रों में खबरें आ रही हैं। बीमा कंपनियां भुगतान नहीं कर रहीं। हैल्थ सेक्टर में जिस तरीके से आपने हालात को बदतर किया है, जनता आपको माफ नहीं करेगी। आपको सोचने की जरूरत है। ..

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

अभी मेरा टाइम बाकी है। मुझे 12 मिनट के लिये बोला गया है, अभी 8 मिनट हुए हैं।

श्री सभापति: एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री अमीन कागजी (किशन पोल): मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आपकी सरकार में जितने भी कैशलैस काम हैं, उनमें सुविधा का लाभ मिल नहीं रहा है। बीमा कंपनियां भुगतान नहीं कर पा रही हैं।

दूसरी बात, जितने भी दवाई विक्रेता हैं, क्या आपने इनके सेंटर्स को चैक किया, किस तरीके से ये नकली दवाइयां बेच रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया कि आप कोई कार्यवाही नहीं कर पाये। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस ओर आपको गंभीर होने की आवश्यकता है।

एक लेटेस्ट बात और सुनिए, आदर्श नगर विधान सभा क्षेत्र और किशन पोल विधान सभा क्षेत्र में एक तो जामडोली में सीएचसी है, एक जाजू डिस्पेंसरी है, इन दोनों में नई खरीदी हुई एक्स-रे मशीनें पड़ी हुई हैं, हमारे टाइम में खरीदी थी।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। श्री छगन सिंह जी राजपुरोहित।

श्री अमीन कागजी (किशन पोल): मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यहां टेक्निशियंस अरेंज कराएं। दो मिनट और दे दें।

श्री सभापति: विराजिए, प्लीज। बहुत वक्ता हैं।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और मांग संख्या 28- चिकित्सा शिक्षा पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय सभापति महोदय, विपक्ष के साथियों ने मेडिकल और स्वास्थ्य पर जब बोलना शुरू किया, जैसे अभी चौमूं से आने वाली विधायक ने भी महिला प्रसूति को लेकर कहा और किशन पोल विधान सभा क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कई तरह की बातें रखीं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से चौमूं से आने वाली विधायक का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, महिलाओं को प्रसूति वाला जो लाभ मिल रहा था, मुख्य मंत्री माननीय वसुन्धरा राजे जी जब थीं, तब उन्होंने भामाशाह योजना शुरू की थी। पूर्ववर्ती सरकार ने उसका नाम बदल तीन वर्षों तक इस योजना को बंद रखा और फिर तीन वर्षों के बाद उसका नाम बदल कर चिरंजीवी योजना किया और चिरंजीवी करके उसमें से जो मुफ्त में प्रसूति होती थी और बच्चेदानी का ऑपरेशन भी मुफ्त में होता था, उन दोनों को आपने उसमें से निकाल दिया। वो अगर आप सुझाव देते कि हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने यह गलती

की थी, अब आप वापस उसको शुरू करें, तो हमें लगता कि आप महिलाओं के प्रति ज्यादा गंभीर हैं। ....(व्यवधान).... मुझे समझ में आया, जब इन्होंने कहा कि सोनोग्राफी का बिल नहीं आया है। सोनोग्राफी के बिल की जब बात करी तो मैंने पता किया, तो सितम्बर में तो अभी यह लागू हुआ है, तीन महीने से ही मां योजना में सोनोग्राफी वाउचर मिल रहा है और अभी से बिल की चर्चा कैसे हो गई? तो पता चला कि खुद के हॉस्पिटल में इस तरह की योजना आस-पास में है। मैं आपसे माफी चाहूंगा, आप आपके हॉस्पिटल की समस्या न बता कर पूरे राजस्थान की समस्या बताते तो थोड़ा अच्छा लगता। ....(व्यवधान)....

माननीय सभापति महोदय, पहला सुख निरोगी काया की कल्पना के तहत मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत 35 लाख व्यक्तियों का इलाज किया गया है, इसके लिये माननीय मुख्य मंत्री महोदय का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। ....(व्यवधान)....

श्री सभापतिः विराजिए, विराजिए।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय सभापति महोदय, आगामी वर्ष में बाकी रहे ....(व्यवधान).... को निशुल्क जांच एवं दवा हेतु मां कोष गठन की जो घोषणा की है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत माननीय मुख्य मंत्री जी ने इंटर-स्टेट वाला एक बहुत बड़ा काम किया है।

श्री सभापतिः देखना कोई व्यक्तिगत आया हो तो।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो प्रवासियों की बड़ी चिंता थी कि हम बाहर के स्टेट में इलाज नहीं करवा पा रहे थे, इंटर स्टेट प्रोटेबिलिटी लागू कर प्रदेश के बाहर भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध रहेगी, इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का, चिकित्सा मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। साथ में 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन के इलाज के लिये पैकेज की घोषणा की है। हम सबकी समस्या थी, कोटा में पढ़ने वाले छात्रों द्वारा आत्म हत्या की बात होती है, उसको लेकर मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पैकेज की जो घोषणा की है, उसके लिये भी माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, इस तरह की चिंता कोई संवेदनशील सरकार ही कर सकती है।

सभापति महोदय, प्रिवेंशन इज बैटर दैन क्योर। अगर हम बीमारी से पहले ही सावधानी बरत लें..

श्री सभापतिः अगर कोई व्यक्तिगत नाम आया हो, तो उसको विलोपित कर दें।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): पिछले बजट में स्वास्थ्य शिविर लगा कर ई हैल्थ रिकार्ड बनाने का कार्य हाथ में लिया था, उसमें लगभग 92 लाख 34 हजार लोगों का ई रिकार्ड कर लिया है और शेष का भी जून, 2025 तक का करने का काम करेगी सरकार, इसके लिये मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। एक बड़ी घोषणा और की है कि प्रदेश में 70 वर्ष से अधिक उम्र वाले वृद्धजनों को आवश्यकता अनुसार घर पर ही निःशुल्क दवा उपलब्ध कराई जायेगी। इसके लिये मैं हमारी संवेदनशील सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद करूंगा। दूसरा,

टाइप फर्स्ट डायबिटीज से पीड़ित मरीजों के लिये बेहतर सुविधा के लिये प्रत्येक जिला स्तर पर डायबिटिक क्लिनिक स्थापित किये जाने की भी घोषणा की है, मैं इसका भी धन्यवाद करना चाहूंगा।

प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिये सरकार द्वारा प्रत्येक सीएचसी पर, अभी कइयों ने मांग की कि हमारे हॉस्पिटल में एक्स-रे मशीन की जरूरत है।

Msk/rtm/06.03.25/1530/2m

सरकार ने प्रत्येक सीएचसी पर डिजिटल एक्स-रे की जो घोषणा की है, साथ में ट्रू-नॉट और सीबी-नॉट मशीन उपलब्ध कराने की घोषणा की है, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री और चिकित्सा मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। वास्तव में यह सब जगह बहुत आवश्यक था, जो आपने इस प्रकार से संवेदनशील तरीके से डिजिटल एक्स-रे मशीन की जो घोषणा की है। मुझे विश्वास है कि अगले वर्ष तक, जब हम इस बजट सत्र में आये, उस समय तक सभी सीएचसी पर यह उपलब्ध हो जाये। ट्रक एवं बस ड्राइवर तथा कारीगर, दर्जी, कारपेंटर इत्यादि की आंखों की निःशुल्क जांच करे और निःशुल्क चश्में देने के काम की घोषणा की है, मां-नेत्र वाउचर के तहत। जिस प्रकार से सोनोग्राफी वाउचर के तहत मिल रहा है, उसी प्रकार से इस श्रेणी में आने वाले लोगों को मां-नेत्र वाउचर भी मिलेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं जालौर जिले से आता हूं और आहोर विधान सभा क्षेत्र से आता हूं, वहां पर वास्तव में डॉक्टरों की कमी है। आपको मैं धन्यवाद देना तो चाहूंगा कि पिछले बजट में और इस बजट में हमारे यहां पीएचसी नोरवां खोली, सीएचसी भादरजूल, सीएचसी भूती, सीएचसी पादरलीकली, उप जिला अस्पताल अब की बार आहौर में किया, इसके लिए तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और कवारडा में आपने उप स्वास्थ्य केन्द्र बजट में दिया है, इसका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि इसकी भूमि तो आवंटित हो गयी है, आने वाले समय में इसके भवन निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति मिल जाये, जिससे इनको बिल्डिंग मिलेगी और हमारा सुदूर एरिया है। यहां पर हमेशा ही विधान सभा क्षेत्र जालौर जिला, विशेषकर विधान सभा क्षेत्र आहोर स्वास्थ्य क्षेत्र में उपेक्षित रहा है।

मैं आप सभी निवेदन करूंगा, विशेष रूप से चिकित्सा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप इस ओर ध्यान देते हुए जो डॉक्टर्स की कमी है, सीएचसी में बिल्कुल डॉक्टर्स नहीं है, सियाना सीएचसी है, भादरा सीएचसी है। भादरा में जो सीएचसी है, वहां पर पद रिक्त हैं। मैं पिछले पांच-छह वर्षों से लगातार विधान सभा में डॉक्टर्स की कमी लेकर मांग कर रहा हूं, लेकिन अभी तक पूर्ति नहीं हुई है। आपने नर्सिंग ऑफिसर तो लगा दिये, सभी हॉस्पीटल में, पूरे राजस्थान प्रदेश में, इसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं चाहूंगा कि चिकित्सक के जो रिक्त पद हैं, उनको भी तत्काल रूप से आप अगर भरने की कृपा करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपको भी जनता धन्यवाद देगी। हमारे वहां भी आते रहते हैं, हमारी जो मुख्य समस्या है उस समस्या का समाधान आप दिल से करेंगे। माननीय चिकित्सा मंत्री जी, आप

का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। मैंने पहले भी कहा है कि मेरा क्षेत्र हमेशा चिकित्सा के क्षेत्र में उपेक्षित रहा है। हमारे क्षेत्र में ऐसे बड़े-बड़े कस्बे हैं, जिनकी आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार है।

श्री सभापतिः कंक्लूड करें।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): वहां पर सीएचसी एवं आसपास में पीएचसी नहीं है। ऐसे में भंवराणी, गुढा बालोतान, चांदलाई, हरजी, भोरडा में सीएचसी की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में इन बड़े कस्बों में, 15-20 हजार की आबादी तो खुद की ग्राम पंचायत की है, लेकिन आसपास में कई ऐसे बड़े कस्बे हैं, जिससे अगर इन सीएचसी की सुविधा मिल जाये तो हमारा क्षेत्र जो उपेक्षित रहा है, वहां भी बड़ी चिकित्सा सुविधा मिल जाये। देबावास, आइपुरा, अजीतपुरा, निबंला में पीएचसी की आवश्यकता है। इनको अगर आप पीएचसी करेंगे तो मुझे विश्वास है कि हमारे यहां व्यवस्था और ठीक हो जायेगी।

श्री सभापतिः विराजें।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): हमारे यहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की आवश्यकता है। उसी प्रकार से उप स्वास्थ्य केंद्र नबी, नागड़ी, रसियावास खुर्द, गुढारामा, बागुंदा, गोविंदा, पानगडा, पलासिया कलां, अलावासी में उप स्वास्थ्य केन्द्र की आवश्यकता है। माननीय चिकित्सा मंत्री जी बहुत धीर गंभीर हैं, इस ओर में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप उप स्वास्थ्य केंद्र खोलेंगे। मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री रामकेश।

श्री रामकेश (गंगापुर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27 और 28 पर मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत आभारी हूं। सभापति जी, आज का जो विषय है चिकित्सा और स्वास्थ्य से सम्बन्धित, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मुझे उम्मीद है कि आज जो सदन में सार्थक चर्चा होगी, उस चर्चा के बाद सरकार अपनी प्राथमिकता बदलेगी। अब तक सरकार ने एक साल के अन्दर जो काम किया है, उसमें हमें यह प्रतीत हो रहा है कि सरकार की प्राथमिकता में स्वास्थ्य और चिकित्सा कोई मायने नहीं रखता। हमारे ऋषि/महर्षि सबने यह कहा है कि पहला सुख निरोगी काया। आदमी अगर स्वस्थ रहेगा तो जीवन में सब काम कर सकता है। लेकिन अगर वह स्वस्थ नहीं है तो कोई काम न परिवार का कर सकता है, न गांव-तहसील का कर सकता है, न राजस्थान प्रदेश का कर सकता है, न देश का कर सकता है। इसलिए जीवन में स्वास्थ्य का बहुत महत्व है। स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, इसके लिए हमें दो तरीके से देखना पड़ेगा। एक स्वयं व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। वह अपने खान-पान में रहन-सहन, अपने व्यायाम से संयमित जीवन जीने से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है। किसी कारण से अगर वह बीमार हो जाये या उसके परिवार का कोई सदस्य अगर बीमार हो जाये, तब सरकार की जरूरत पड़ती है, अस्पताल की जरूरत पड़ती है, डॉक्टर की जरूरत पड़ती है।

माननीय सभापति महोदय, हमने वे दिन देखे हैं, परिवार में अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता था और उसको हॉस्पीटल में एडमिट कराने की जब बात आती थी तो परिवार का सारा संतुलन खराब हो जाता था। व्यक्ति आस-पड़ोस में जाता था, पैसे उधार मांगने के लिए जाता था, जब नहीं मिलता, अपने जेवर-जमीन जायदाद रखकर, क्योंकि राजस्थान के लोगों के, राजस्थान की जनता के जो संस्कार रहे हैं, वह सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन अगर परिवार में कोई आदमी बीमार हो गया, चाहे उसका सब कुछ लुट जाये, लेकिन अपने परिवार के व्यक्ति को नहीं छोड़ सकता। इसलिए बीमार होने के बाद जब अस्पतालों में खर्चा होता था, दवाई के लिए, तो इन सारी चीजों के लिए मैं हमारी पिछली सरकार और राजस्थान के लोकप्रिय पूर्व मुख्य मंत्री अशोक गहलोत साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने प्राथमिकता में सबसे पहले स्वास्थ्य को लिया। उन्होंने ऐसी-ऐसी योजनाएं चलायीं, उन्होंने बारीकी से जब देखा कि एक गरीब व्यक्ति किस तरीके से, उसके परिवार में कोई व्यक्ति बीमार हो गया तो जब वह परेशान होता है। उसकी परेशानी को समझकर सबसे पहले उन्होंने मुफ्त दवा योजना चलायी। उससे पहले महिलाओं का दर्द समझा। हमारी माता-बहनों का दर्द समझा और उनको प्रसव के टाइम जो परेशानी होती थी, उससे छुटकारा दिलाने के लिए जननी शिशु सुरक्षा योजना चलायी। इन सबसे अलग हटकर उन्होंने चिरंजीवी योजना, जिसमें 25 लाख सरकार की जिम्मेदारी पर इलाज होता था। मैं बहुत हर्ष के साथ यह कह सकता हूं कि उस योजना को हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी सराहा। पूरे देश में उसकी चर्चा हुई और पूरे देश के लोगों ने उसकी तारीफ की।

माननीय सभापति महोदय, अभी कोरोना के समय जीवन की नश्वरता से हम साक्षात परिचित हुए। उस समय हमने देखा कि किस तरीके से हमारे जो प्रियजन थे, हर परिवार में से कोई न कोई दुखद घटना हुई। उसमें हम लोगों ने जो सामना किया, उससे हमें सरकार की जरूरत पड़ी और उस समय जो सरकार ने सहयोग किया, उसके लिए मैं पूर्व मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

mdp/rtm/06.03.25/15:40/2n

उस समय सबसे ज्यादा, मंत्री महोदय, आप सदन में विराजमान हैं, अगर कोई उस समय धन्यवाद का पात्र है, आपका नर्सिंग स्टॉफ सबसे ज्यादा धन्यवाद का पात्र है। उस समय हमारे शिक्षा विभाग के जो सरकारी टीचर थे, वह धन्यवाद के पात्र हैं, छोटे कर्मचारी धन्यवाद के पात्र हैं, पुलिस के छोटे सिपाही लेवल के जो कर्मचारी हैं, वे धन्यवाद के पात्र हैं। कोरोना के टाइम कोई बाहर नहीं निकल रहा था, उस समय उन्होंने बाहर निकल कर जनता की जो सेवा की और राजस्थान प्रदेश के लोगों को बचाया, सदन के माध्यम से उनका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे सरकार के साथी बहुत बड़ी-बड़ी बातें, अपने दावे कर रहे थे। मैं आपके दावों की हकीकत बताना चाहता हूं, 'न इंतजार, न ही लंबी कतार,

आयुष्मान कार्ड से हो रहा सुलभ उपचार', यह आपका दावा है, सरकार का। माननीय सभापति महोदय, लेकिन हकीकत इसके बिलकुल विपरीत है। जो ये दावा कर रहे हैं न इंतजार, न ही लंबी कतार, आयुष्मान कार्ड से हो रहा सुलभ उपचार, हकीकत ये है कि 364 डायलिसिस मशीनें खरीदी थी। 20 करोड़ रुपये का भुगतान किया, 122 जगह भेज दी और सब की सब डिब्बाबंद हैं। एक भी काम नहीं आ रही है। आंगनबाड़ी स्कूलों में 200 करोड़ की उड़ान योजना ढेर। सैनेटरी पैड, छोटे, बेटियां ले नहीं रही, फ्री के पैड बाजार, पंचायत केन्द्रों में 30-30 रुपये में बिक रहे हैं। इसी तरीके से मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों से लेकर जिला अस्पतालों तक एलर्जी, इंफेक्शन रोकने वाली दवाएं और कफ सिरप खतम। अस्पतालों में 50 दवाएं खतम, 130 खतम होने को और आरएमएससीएल को जो सितम्बर 2024 से आर्डर करने थे रेट कांट्रेक्ट के, वह आज तक सरकार ने नहीं किये। ये सरकार की हकीकत है।

इसी तरीके से मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों ने बाजार से खरीदी 67 लाख की दवाएं। जब आप रेट कांट्रेक्ट नहीं कर रहे हैं और उसके बाद में दवाएं खरीद रहे हैं और 30 परसेंट महंगी दवाएं खरीद रहे हैं। इसी तरीके से आरजीएचएस योजना, जो कि इस योजना में कर्मचारी और पेंशनर्स का पैसा है, फिर भी ये सरकार भुगतान का रोना रो रही है। भुगतान का रोना रो रही है, जबकि इसमें सरकार का कोई लेना-देना नहीं। यह योजना सरकार की नि:शुल्क नहीं होकर कैशलेस मेडिकल क्लेम पॉलिसी की तरह वेतन में से प्रतिमाह कटौती कर संचालित की जा रही है।

माननीय सभापति महोदय, अभी जो हमारे साथी कह रहे थे, महिलाओं का मैं बताना चाहता हूं कि पाली में घटनाएं हुई एक प्रसूता को जमीन पर पटक कर, जमीन पर पड़े हुए उसका प्रसव कराया। आपके पास बेड नहीं है, आपके पास इलाज के लिए दवाई नहीं है, आपके पास डॉक्टर नहीं है और आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं हो रही हैं राजस्थान में जिससे इनका स्वास्थ्य विभाग का ढ़ांचा बिलकुल गड़बड़ा चुका है।

श्री सभापतिः विराजिए। समाप्त कीजिए। श्री हरिसिंह रावत।

श्री रामकेश (गंगापुर): माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ये सारी जो चीजें हैं।

श्री सभापतिः विराजिए। विराजिए।

श्री रामकेश (गंगापुर): सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज से संबद्ध, माननीय सभापति महोदय, एक मिनट में कहना चाहूंगा, हमारे गंगापुर सिटी में, मैं केवल एक मिनट, गंगापुर सिटी में...

श्री सभापतिः आप विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री रामकेश (गंगापुर): 000

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27 चिकित्स एवं स्वास्थ्य, मांग संख्या 28- चिकित्सा शिक्षा मांग पर मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए

मैं कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे समय दिया, समय थोड़ा ज्यादा देना इसीलिए एडवांस में आपको बताना चाह रहा हूं। माननीय, सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार द्वारा जो साहसिक कदम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पिछले बजट 2024-25 में उठाये गये, वे आगामी बजट में उठाते हुए एक मील का पत्थर साबित हुआ है। पिछले वर्ष में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के कार्यों के लिए बजट पूरी तरह से केन्द्रित था, जिसमें चिकित्सा सुविधा का अधिक विस्तार करते हुए 27 हजार 660 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, जो कि पूरे बजट का 8.26 परसेंट भाग है।

सभापति महोदय, हमारी सरकार इस बजट वर्ष 2025-26 में भी चिकित्सा सुविधा के विस्तार पर जोर देते हुए कार्य कर रही है। बजट वर्ष 2025-26 में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने पहला सुख निरोगी काया, हैल्थ इज वैल्थ को ध्यान में रखते हुए, आमजन की निःशुल्क जांच एवं दवा हेतु 3 हजार 500 करोड़ रुपये का मां कोष गठित किये जाने का एक प्रावधान रखा है, जो एक सराहनीय कदम है। गरीब आदमी को एक बहुत बड़ी सुविधा मिली है। उक्त बजट द्वारा प्रावधान से चिकित्सा सुविधा का विस्तार कर लोगों का कल्याण किया जाना, हमारी सरकार की प्रथम प्राथमिकता को दर्शाता है। हमें यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि देश का सबसे बड़ा बोनमेरो ट्रांसप्लांट सेंटर, आरयूएचएस, जयपुर में प्रारंभ होने जा रहा है। ये कैंसर रोगियों के लिए एक लाइफ लाइन साबित होगा। इसमें हर माह 50 रोगियों का इलाज किया जायेगा। मंत्री महोदय, इसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसको तत्काल प्रारम्भ किया जाए ताकि आम जन को इसकी सुविधा मिल सके।

सभापति महोदय, साथ ही साथ, इसी तरह हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी और देश के प्रधान मंत्री मोदी जी के द्वारा आयुष्मान भारत योजना लागू कर देश में आम जन को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। राजस्थान के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के वासियों केलिए गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपलब्ध कराने की दृष्टि से स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आयुष्मान मॉडल सीएचसी बनाया गया है। इसके लिए भी मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमने क्षेत्र विशेष में कोई भेदभाव नहीं रखा है। हमारे लिए सभी जनता सर्वोपरि है, न कि पार्टी। उसी अनुरूप हमारी सरकार ने काम किया है।

सभापति महोदय, मैं विपक्ष के लोगों को बताना चाहता हूं कि सरकार की कथनी व करनी में कोई फर्क नहीं है, जो हम कहते हैं, वह करके दिखाते हैं। पूर्व सरकार में सिर्फ कुर्सी को लेकर घमासान चलता रहा। पूरी सरकार केवल होटलों में ऐश करती रही, लेकिन जनता की उन्होंने कोई सुधबुध नहीं ली, जिसकी वजह से आज ये सामने बैठे हैं। आज आम जन खुश है हमारी सरकार के बजट से। ये कहते हैं कि हमने विकास के नये आयाम कायम किये हैं। कहना चाहूंगा कि इन्होंने विकास के लिए नहीं, भ्रष्टाचार करने के लिए आयाम कायम

किये थे। मैं आज अपने क्षेत्र में देखता हूं तो सिर्फ ये ही देखता हूं कि कांग्रेस सरकार के काल में जो बजट आया, सिर्फ बजट कॉपी पढ़ने तक ही सीमित रहा, धरातल पर कभी कोई काम उतारा ही नहीं गया। इनके कार्यकाल में सिर्फ शिलापट्टी पर नाम लिखवाने के अलावा और शिलान्यास करने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया।

सभापति महोदय, अब मैं मेरे क्षेत्र की कुछ बात करना चाहता हूं। साथ-साथ ही हमारी एक विशेष समस्या है। प्रदेश में चिकित्सकों का प्रथम कॉडर बनाने और चिकित्सकों को चतुर्थ एसीपी 9500 ग्रेड-पे देने की मैं बात करना चाहता हूं। इसमें मैं चाहता हूं कि सेवानिवृत्ति की आयु में विसंगतियां हैं। वर्तमान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष है, वर्तमान चिकित्सा शिक्षा में सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है। दोनों विभाग के चिकित्साकर्मियों में सेवानिवृत्ति आयु में विसंगति होने से चिकित्सकों में द्वेष भावनापूर्ण भाव होता है। अतः मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार में दोनों विभाग की विसंगतियों को दूर करने के लिए वहां के हमारे भाजपा के मुख्य मंत्री सम्माननीय मोहन लाल जी यादव ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग व चिकित्सा शिक्षा विभाग को एक समान कर चिकित्सा सुविधा का विस्तार करने का कार्य किया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी चिकित्सा सुविधा को सुदृढ़ करने के लिए, हमारे चिकित्सकों के उत्थान के लिए ये व्यवस्था हमारे यहां भी लगायी जानी चाहिए।

Ans/rtm 15.50 2o 06.03.2025

यह अत्यन्त आवश्यक है, ताकि चिकित्सकों का मनोबल बढ़ेगा।

सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की कुछ बात करना चाहूंगा। पिछले बजट 2025 में मेरी विधान सभा भीम को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देवगढ़ को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए विकास की जो मांग है, मैं आपको पटल पर रखना चाहता हूं।

उप जिला चिकित्सालय भीम के भवन का निर्माण कार्य शिघ्रातिशीघ्र करवाया जाए। चिकित्सालय मंत्रालय कर्मचारी एवं अन्य संवर्ग कार्मिकों के लिए उप जिला चिकित्सालय भीम के परिसर में आवासीय भवन का निर्माण करवाया जाए, यह अत्यंत आवश्यक है। उप जिला चिकित्सालय भीम को जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाए। उप जिला चिकित्सालय भीम जिला चिकित्सालय बनने के सारे मापदंड पूर्ण करता है।

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि लास्ट बजट पेश हुआ था तब मेरा क्वेश्चन लगा था, मेरा जिला चिकित्सालय भीम का जो भी मापदंड है वह पूर्ण करता है, मुझे उन्होंने आश्वस्त किया था कि आने वाले बजट में इसकी घोषणा करवाऊंगा। आपसे निवेदन करना चाहता हूं मेरा भीम जिला हैडक्वाटर से नहीं चार ज़िलों से, इसमें 100 किलोमीटर भीलवाड़ा पड़ता है, 100 किलोमीटर मेरा जिला पड़ता है, 100

किलोमीटर पाली पड़ता है, 100 किलोमीटर अजमेर पड़ता है, तो यह सेंटर पांइट है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसी बजट में आप वहां जिला चिकित्सालय ले लेंगे तो हमारी क्षेत्रवासियों की समस्या का समाधान होगा।

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपने देखा होगा, नागोर से 15 किमी. दूर है वहां जिला चिकित्सालय बन गया तो मेरा तो 100 किलोमीटर दूर है, तो इस पर गौर करते हुए इस पर ध्यान दें।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मुझे नर्सिंग कॉलेज की महती आवश्यकता है। नर्सिंग कॉलेज अगर प्राइवेट को भी दे दें तो मैं समझता हूं कि हमारे वहां अच्छी व्यवस्था होगी। जो पढ़े-लिखे युवा है, उनको समस्या होती है। वहां नर्सिंग कॉलेज, एएनएम, जीएनम या अदर कोई कोर्सेज वहां प्रारम्भ होंगे तो बच्चों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाएगी।

जब हर ज़िले में एक मेडीकल कॉलेज है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे ज़िले राजसमंद में भी मेडीकल कॉलेज की स्थापना की जाए, ताकि हमारे क्षेत्र के होनहार बच्चों को दूर नहीं जाना पड़े और वहीं उनको व्यवस्था मिल जाएगी।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मंत्री महोदय जी, इस पर थोड़ा सा संज्ञान ले।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): हमारी ज़िले की हैडक्वाटर की विधायक हैं, सपोर्ट कर रही है। दोनों को इंक्लूड कर दिया। इनकी घोषणा कर दें। दूसरा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भडार व क्वाथल को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाए, क्योंकि वह नेशनल स्टेट हाईवे 58 पर स्थित है, इसके आस-पास लगभग 10-12 हजार की आबादी निवासरत है। विधान सभा क्षेत्र भीम में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संचालित सभी संस्थानों में चिकित्सकों एवं नर्सिंग ऑफिसर, कार्मिकों के सृजित पद अनुसार उनको भी पूरा किया जाए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन और करना चाहता हूं कि कोरोना काल में उप जिला चिकित्सालय भीम एवं देवगढ़ में ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की गई थी। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा इसमें भंयकर घोटाला किया गया। ऑक्सीजन सिलेंडर लगाये लेकिन आज तक काम में नहीं लिए गये, तो इसकी एक जांच कराई जाए और इसका निस्तारण कराया जाये। एचडीएस हॉस्पिटल भीम व देवगढ़ में मोर्चरी में डिफ्रिज की व्यवस्था कराना अत्यन्त आवश्यक है।

श्री सभापतिः विराजिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): मेरा विधान सभा 150 किलोमीटर दूर पड़ता है। आये दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। एक्सीडेंट मृत्यु में कोई मुम्बई का होता है, कोई गुजरात का होता है, कोई दिल्ली का होता है।

श्री सभापतिः विराजिये। श्री विद्याधर सिंह।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): दो-दो, तीन-तीन दिन तक उनके परिवार वाले नहीं पहुंच पाते।

श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मेरे

विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में..

श्री हरिसिंह रावत (भीम): बहुत अच्छी सुविधा हो जाएगी।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): 000

श्री सभापति: आप बोलिये।

श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): कोविड-19 में देश और प्रदेश की क्या स्थिति रही, कोविड ने हमारी चिकित्सा व्यवस्था का पूरा खाका जनमानस के पटल पर रख दिया। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 02 लाख 61 हजार मतदाता हैं, लगभग पांच लाख की आबादी है फिर भी विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सा व्यवस्था पर्याप्त नहीं है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र कोरसीना, सिणोदिया, पचकोडिया और खण्डेल में उप स्वास्थ्य केन्द्र है। महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इन ग्राम पंचायतों की आबादी 6-7 हजार के बीच है। उप स्वास्थ्य केन्द्र कोरसीना की पंचायत मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर है जहां ग्राम पंचायत की आबादी करीबन 06 हजार है। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उच्च माध्यमिक इस ग्राम की पंचायत मुख्यालय के आस पास दस हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल एरिया है। उक्त पंचायत के चारों तरफ ग्राम पंचायत सीतारामपुरा, बड़ोती, जिनकी आबादी 30 हजार के करीब है। उप स्वास्थ्य केन्द्र जोबनेर से बुटाटी जाने वाले हाईवे संख्या 135 पर, जो सांभर उप जिला अस्पताल से लगभग 30 किलोमीटर दूर है, इस हाईवे पर यातायात का अत्यन्त दबाव रहता है, जिसके कारण यहां आये दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती है। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को जिला उप अस्पताल सांभर ले जाने के लिए बहुत ज्यादा समय लगता है, इसलिए उप स्वास्थ्य केन्द्र कोरसीना को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाए।

दूसरा, ग्राम पंचायत पचकोडीया का भी यही हाल है। हम किसको कह रहे हैं, किसको सुना रहे हैं, मंत्री जी सुन नहीं रहे, यही तो इस सदन की व्यथा है। हम इतने सदस्य चुनकर आए हैं अपनी गंभीर बात कहने के लिए और मंत्री जी सुनना नहीं चाहते कि सदस्य क्या कहना चाहते हैं। आप सभी लोग देख लीजिएगा कि क्या हाल है। मेरे ख्याल में चर्चा कम समय में कर दे या सीमित समय में कर दे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा ...(व्यवधान)...

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): हम पड़ोसी सुन रहे है ना।

श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): पडोसियों को मंत्री नहीं बनाया ना, नहीं तो मैं पड़ोसियों को भी सुना दूंगा। आज जिस पर डिमांड है, पहले पड़ोसी चिकित्सा के मंत्री बन जाए। ग्राम पंचायत सिणोदिया, जयपुर से फलौदी जाने वाले स्टेट हाईवे पर स्थित है, उसमें भी कहीं भी ऐसा नहीं है कि हमारे यहां पीएचसी की स्थापना हो, ना ही की गई है। आप बार-बार कह रहे हैं कि हमारे डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। यह जनता देख रही है, जो हम यहां बोल रहे हैं, इन सबको डबल इंजन की सरकार को जनता देख रही है। ...(व्यवधान)... जनता ने हमको तो देख लिया। हमको देखने के बाद, परखकर ही भेजा है। आपको देखने का समय अब आएगा। 2028 में आपका समय शुरू होगा कि जनता ने

आपको क्या परखा है। ...(व्यवधान)... मेरी समस्या पर कर रहे हैं या अपने भाषण की तैयारी कर रहे हैं, मैं अच्छी तरह समझता हूं कि क्या रिप्लाई के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप मुझे मत बताइये कि वह क्या तैयारी कर रहे हैं।

सभापति महोदय, दुर्भाग्य है कि हॉस्पिटल में लंबी-लंबी कतारें हैं। दवाइयों की लंबी-लंबी पर्ची लिख देते हैं। आदमी सुबह से शाम तक एक ही काम कर पाता है कि वह पर्ची लिखाकर लाया है। जब पेंशनर्स दुकान पर जाते हैं तो यह कहते हैं कि हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि सरकार ने अभी तक पैसा नहीं दिया है। सरकार के पास खजाना खाली है। डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, आप जो भी बोले, उसके बाद भी अगर खजाना खाली है तो भगवान ही मालिक है। मैं तो यह सोचता हूं कि आप लोगों से क्या व्यवस्था होगी।

दूसरी बात, आप लोगों ने अभी तक यह बना रखा है कि हमारा काम है आपकी खिलाफत करना, ऐसा नहीं है। आपका अच्छा काम होगा हम उसकी भी प्रशंसा करेंगे। मैं मंत्री जी की इस बात की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने भदाल में सीएचसी की स्थापना की है। हम कोई बुराई करने के लिए नहीं हैं, लेकिन हमारी बात को सुना जाए। आप हमारी बात ना माने यह आपका विषय है।

VPS-RTM-06.03.2025-16.00-2p

लेकिन इस सदन में अगर आये हैं तो हमारी बात को आपको मानना, नहीं मानना आपकी मर्जी है लेकिन सुनना तो होगा और नहीं सुनना होगा तो हमारे पास दूसरे तरीके हैं सुनाने के भी। हां, दूसरे तरीके भी हैं। हम संघर्ष करेंगे। संघर्ष के तरीके से करेंगे, आप उसको उलटा मत लीजिए। लट्ठ की भाषा नहीं है यह। यह भाषा है विचारधारा की।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): एम.एल.ए. साहब, आपका मोस्ट वेलकम।

श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): अब मैं तो आपसे यही चाहूंगा कि जो अब आपने एक सी.एच.सी. हमको दी है तो आपसे चार जगह पर हमारी मांग है क्योंकि हम विपक्ष में हैं तो मांगना तो हमें पड़ेगा ही। सरकार में हम नहीं हैं, सरकार में मौका नहीं मिला इसीलिए हमारी डिमांड्स कभी पूरी नहीं हुईं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: यह तो विषय ही डिमांड का है। ...(व्यवधान)...

श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): अब आपसे यह उम्मीद है कि आप इनके बारे में सोचेंगे। एक तो सिनोदिया को उप स्वास्थ्य केन्द्र से पी.एच.सी. की जाये। दूसरा, फुलेरा में आपने पिछले बजट में घोषणा की थी उप जिला अस्पताल की तो वहां पर जमीन आवंटित हो गयी है लेकिन आज सवा-डेढ़ साल से ऊपर हो गया है, वहां पर कोई कार्य चालू नहीं हुआ है, हम कब उस कार्य को पूरा करेंगे, इसके लिए भी आपसे मेरा कहना है कि उसको जल्दी से जल्दी शीघ्र ही चालू कराएं। तीसरी, उप स्वास्थ्य केन्द्र जो खण्डेल में है, उसको भी पी.एच.सी. में

क्रमोन्नत किया जाये। फुलेरा के पास पचकोडिया जो कि 25 से 30 किलोमीटर ही पड़ता है उसमें भी उप स्वास्थ्य केन्द्र से पी.एच.सी. किया जाये तो मेरी यह चार पांच मांगें हैं जिनके लिए हमारा आपसे अनुरोध है कि जनता को अगर आप देंगे तो जनता हमारे से यह होगा कि हमने आपसे मांग की और आपको भी बधाई देगी।

दूसरी बात, यह बात तय है कि सत्ता पक्ष वाले हर बात पर गुणगान करने का जो तरीका है, यह सच है कि आपको यह करना ही पड़ेगा क्योंकि आपकी कुछ मजबूरियां हैं, वह आपको करना है लेकिन इतना भी मत करो कि मंत्री हो, मुख्य मंत्री हो और वे इस भाव में ही चले कि हमारे सदस्य खुश है और सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है तो यह भी अच्छा मैसेज नहीं जायेगा, आपको कान खोलकर सुनना होगा, जनता के काम को करना होगा, जब ही आपकी सफलता का गुणगान होगा।

मैं इसके पक्ष-विपक्ष में किसी से यह बात नहीं कहता कि हम विपक्ष में हैं तो हम गलत बात करेंगे यानी हम खिलाफत ही करेंगे, लेकिन अगर आप अच्छा काम करेंगे तो मैंने पहले भी प्रशंसा की है, अब भी करेंगे, लेकिन जो सदस्य आपके साथ हैं या जो पक्ष के लोग हैं, वे सिर्फ गुणगान में ही लगे हुए हैं। क्यों बहका रहे हो इनको? इनको हकीकत दिखाओ जिससे जनता का काम हो सके और जनता का जब काम होगा तो आप दुबारा यहां आ पाओगे वरना आपने कई विधान सभाएं देख ली, मैंने तो नहीं देखी, पहली बार ही देखी है, लेकिन हां, यह जरूर है कि विधान सभाओं का अवलोकन कई बार किया है कि यह विधान सभा है, कौनसे टाइम में कौन आये, कौन गये तो यह अनुभव तो है। अब कई बार लोग कहते हैं कि आप सीनियर नहीं हो। सीनियोरिटी का क्या मतलब है? सीनियर कोई विधान सभा में ही होना जरूरी है क्या? सीनियर का मतलब है कि आपका मतलब, राजनीति में क्या हस्तक्षेप है, राजनीति को आप कितना नजदीक से देखते हैं, वह ही सीनियोरिटी है। यानी वह एक कहावत है कि हमने शादी लेट की, मान लीजिए अगर शादी सब समझते हैं राजनीति में आना, तो बारात तो देखी है हमने, बारातों में तो खूब गये हैं, फेरे खूब अटेंड किये हैं तो इसका मतलब यह थोड़े ही है कि हम नये सदस्य हैं। नये सदस्य नहीं है इसलिए मंत्रीजी, बात को गम्भीरता से लेना और हमारी बात को, विपक्ष वाले जो बात कह रहे हैं, वह कटु सत्य कह रहे हैं। उसका अगर आप अवलोकन कर लेंगे तो मैं आपको बताता हूं कि आपको अच्छी बधाइयां मिलेंगी और अच्छे आपको तमगे मिलेंगे कि खूब काम किया हमारे मंत्रीजी ने, नहीं तो वरना हम जो खड़े हैं वह ही करते रहेंगे जो आज बोल रहे हैं तो हमें आप मौका दीजिए कि हम आपके विचारों पर आपको यह कहें कि यह मंत्रीजी हैं और यह सदन है।

श्री सभापति: कंक्लूड करिये।

श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): इन्होंने यह-यह काम किये हैं और हम खुश होंगे। बुराई करने से, गहलोत सरकार ने, गहलोत सरकार ने काम नहीं किया, गहलोत सरकार ने काम नहीं किया तो काम ही नहीं किया तो आप यह बताइये कि यह योजना खतम, यह योजना खतम, यह मुफ्त वाली खतम, जब काम ही नहीं किया तो खतम किस बात का कर रहे हो?

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): यह खतम करने का मतलब है कि उन्होंने काम किया, यह साबित करता है कि पिछली सरकार ने यह काम किया जिनको आप खतम कर रहे हैं।

श्री सभापतिः श्री गोपीचन्द मीणा। आप विराजिये।

श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): धन्यवाद।

श्री सभापतिः धन्यवाद।

श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं मांग संख्या 28- चिकित्सा शिक्षा पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, विपक्ष के भाई अभी चर्चा कर रहे थे लेकिन पिछले पांच साल के कांग्रेस शासन में जितने घोटाले, जितने भ्रष्टाचार के काम हुए, आजादी के इतिहास में पहली बार पिछली सरकार ने इतने घोटाले किये हैं। मेरे जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में भीलवाड़ा जिले में इतने घोटाले किये हैं, कर्मचारियों को ट्रांसफर किये हैं और आज अच्छे कर्मचारी, अच्छे डाक्टर्स, अच्छे जी.एन.एम. स्टाफ को चुन-चुनकर उनको दूरदराज के क्षेत्रों में, अच्छे काम करने वालों को भेजा है। कोटड़ी में ब्लॉक सी.एम.एच.ओ. ने अपने राजनीतिक दबाव से, उसने कांग्रेस के नेताओं के दबाव में एक-एक कर्मचारी को वेतन बनाने में भी इतना भ्रष्टाचार किया। वेतन में आज तक किसी कर्मचारी/अधिकारी को कोई सैलरी, अपनी गाढ़ी कमाई, नौकरी करने के बाद, मेहनत करने के बाद उसको नौकरी मिलती है और वह अपनी कमाई में से भी उन्होंने वेतन-भत्ते बनाने में भी उन्होंने कर्मचारियों से ब्लॉक सी.एम.एच.ओ. ने तनख्वाह में से वे पैसे वसूलते थे, इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है। मेरे जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में उन्होंने भीलवाड़ा जिले में करोड़ों की खरीद बिना टेंडर प्रक्रिया किये ही खरीदा गया था। मशीनरी खरीद में घोटाला किया गया था और विगत कांग्रेस सरकार के भ्रष्ट आचरण के कारण खूब भ्रष्टाचार, कोरोना काल में खूब लूट-खसोट किया। भीलवाड़ा जिले में मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे पांच साल कांग्रेस के कार्यकाल में भीलवाड़ा जिले में और पूरे राजस्थान प्रदेश में इन्होंने जमकर भ्रष्टाचार किया, इसकी जांच कराने की मैं मांग करता हूं। कांग्रेस के नेताओं के दबाव में इन्होंने हमारे अच्छे अधिकारियों को बाहर कर दिया था और पांच साल तक भीलवाड़ा और राजस्थान प्रदेश की जनता को ऐसे रामभरोसे इन्होंने छोड़ दिया था, कोई सुध लेने वाला नहीं था।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे चिह्नित जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, उसमें जो लिप्त पाये गये हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे जहाजपुर में माननीय मंत्री महोदय ने इस बजट में बहुत अच्छा बजट दिया है और मैं मुख्य

मंत्रीजी का और मंत्रीजी का धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने कांग्रेस के शासन में, कोरोना काल में चपेट में आकर मरने वाले मेडिकल स्टाफ के आश्रितों को भी सरकार ने मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया है। मुआवजे के नाम पर बनाये गये बजट को भी खुर्द-बुर्द किया है।

चिकित्सा शिक्षा में बहुचर्चित अंग-प्रत्यारोपण घोटाला विगत कांग्रेस कार्यकाल की ही देन रहा है जो सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, राजस्थान के अखबारों में यह खबर विशेष रूप से बहुत चलती रही जो आये दिन अखबारों में उजागर हुई है। इसकी भी इन्होंने यहां जमकर लूट मचायी थी, लेकिन हमारे राजस्थान के लोक प्रिय मुख्य मंत्री श्री भजन लालजी के नेतृत्व में हमारी सरकार के आने के बाद और हमारे लोक प्रिय चिकित्सा मंत्रीजी, ये अनुभवी, योग्य, निष्पक्ष एवं ईमानदारी से कार्य करते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के चहुंमुखी विकास के नये आयाम स्थापित कर रहे हैं। बिना भेदभाव के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में, प्रदेश में कार्य हो रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेते हुए हमारी सरकार काम कर रही है। प्रदेश के बड़े से लेकर अन्य मध्यम राजकीय चिकित्सालयों में रोगियों का बिना लाइन के ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हुए अस्पतालों में बिना भीड़ के सुचारु रूप से उपचार प्रारंभ कर दिया गया है। इन अस्पतालों और चिकित्सालयों में प्रतिदिन पहुंचने वाले हजारों रोगियों को बिना लाइन के ही सुविधाजनक नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा सुगमता से उपलब्ध करवाने का श्रेय वर्तमान भाजपा सरकार को जाता है।

प्रदेश के कोने-कोने से, दूरदराज, सुदूर क्षेत्र के गरीब, असहाय को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो रही है। हमारे लोक प्रिय मुख्य मंत्री श्री भजन लालजी शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में और पूरे देश में माननीय प्रधान मंत्रीजी के नेतृत्व में आयुष्मान आरोग्य शिविर, गांव-गांव में राजस्थान में कैम्प लगाये जा रहे हैं, जिससे उस गांव के पंचायत मुख्यालय में जाकर कैम्प लगाने से हर गरीब का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है जिससे आमजन राहत महसूस कर रही है। दिव्यांगों को सहायता स्वरूप यू.डी. कार्ड बनाये जा रहे हैं। शिविर लगाकर मोतियाबिंद व अन्य आवश्यक ऑपरेशन भी किये जा रहे हैं। मिलावटखोरों को पकड़ा जा रहा है। जनता के स्वास्थ्य, सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में उप जिला अस्पताल 100 बेड से बढ़ाकर 200 बेड क्रमोन्नत किया गया है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को और मंत्रीजी को धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं कि जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र जो भीलवाड़ा से सौ किलोमीटर, कोटा से सौ किलोमीटर, अजमेर से 125 किलोमीटर और जयपुर से 180 किलोमीटर के बीच में है, वहां पर हमेशा सुविधाओं का अभाव रहा है। हमारे कांग्रेस के शासन में जहाजपुर को दुर्भावना से देखा गया है, विकास नहीं हुआ है, लेकिन आजादी के इतिहास में हमारे राजस्थान के लोकप्रिय यशस्वी मुख्य मंत्री भजन लालजी के नेतृत्व में और माननीय चिकित्सा मंत्रीजी के आशीर्वाद से वहां जहाजपुर में पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है, विकास कार्य हो रहे हैं।

ssy/rtm/06.03.2025/16.10/2q

कोटड़ी व जहाजपुर में आयुष्मान भारत में दो मंजिला भवन निर्माण किया जा रहा है जिसमें गुणवत्तापूर्वक कार्य हो रहा है। यह जहाजपुर ही नहीं पूरे राजस्थान की 200 विधान सभाओं में कार्य हो रहे हैं।

मैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ डिमांड्स रखना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, 2024-25 के बजट में, मेरी विधान सभा क्षेत्र के अंबरगढ़ में आपने सब सेंटर को पीएचसी से क्रमोन्नत किया, उसका शुभारंभ करवा दिया गया है, लेकिन गलती से डॉक्टर एवं जीएनएम का पदस्थापन अंबरगढ़ (मांडलगढ) कर दिया गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि बजट 2024-25 में पीएचसी मेरे जहाजपुर में स्वीकृत हुई थी और वहाँ चालू भी कर दी गई है, लेकिन पद स्वीकृत डॉक्टर्स, जीएनएम के गलती से अंबरगढ़, मांडल में स्वीकृत हो गये तो संशोधन करने का निवेदन कर रहा हूँ। उसको संशोधन जहाजपुर में करें।

पीएचसी लुहारी कला को सीएचसी में क्रमोन्नत करने की मांग करता हूँ। लुहारी कला ऐसा गांव है जहां 40 गांव 15 किलोमीटर के रेडियस में हैं, जहाँ देश की सेवा करने वाले हमारे सैनिक भाई निवास करते हैं और हर परिवार में एक-दो सैनिक हैं। मैं उन सैनिक भाइयों की सुविधा के लिए, उनके परिवारों की सुविधा के लिए, देश हित में काम करने वाले भाइयों के लिए लुहारी कला पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने की मांग करता हूँ।

पीएचसी पिपलूंद, पीएचसी रोंपा, पीएचसी बोड़ा, सीएचसी शक्करगढ़, पीएचसी अंबरवासी, इनमें भवन क्षतिग्रस्त है, इनके जीर्णोद्धार करने की मैं माननीय मंत्री महोदय जी से मांग करता हूँ कि आने वाले समय में आप इनको ठीक करेंगे, ताकि आम जनता को सुविधा मिल सके।

जहाजपुर कोटड़ी के पीएचसी, सीएचसी, उप जिला अस्पताल खजूरी, शक्करगढ़, पारोली, सवाईपुर, पंडेर सीएचसी, इनमें लंबे टाइम से डॉक्टर्स के पद रिक्त हैं, मैंने माननीय मंत्री महोदय से भी निवेदन किया है और उन्होंने आश्वस्त किया है तो मेरा आग्रह रहेगा कि वहाँ अच्छे डॉक्टर्स लगाए। दुर्भावना से, वहाँ से डॉक्टर्स को हटा दिया गया था, स्टाफ को हटा दिया गया था, आप वापस वहाँ लगाएे, ताकि हमारे वहाँ की जनता को, जहाजपुर की जनता को राहत मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाजपुर में क्षतिग्रस्त और भी जो भवन है उनको ठीक करने का प्रस्ताव मैं, आप श्रीमान के माध्यम से देना चाहता हूँ। वर्ष 2024-25 के बजट में राजस्थान के लोकप्रिय यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने 3 करोड़ एक विधान सभा में क्षतिग्रस्त भवनों को ठीक करने के लिए बजट आवंटन किया था, उनमें मेरे द्वारा प्रस्ताव दिया गया था, जिला कलेक्टर शाहपुरा ने स्वास्थ्य विभाग के जितने भी क्षतिग्रस्त, जीर्ण शीर्ण भवन थे। उनको ठीक करने के लिए 3 करोड़ का प्रस्ताव

भेजा, लेकिन एक साल होने को जा रहा है, अभी वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हुई और काम नहीं हुए। तो मेरा निवेदन है, आग्रह है कि 2024-25 के बजट में प्रत्येक विधान सभा के जो 3 करोड़ दिये गये हैं हमारे अस्पतालों के क्षतिग्रस्त भवनों को ठीक कराने के लिए वह स्वीकृति जारी करायें, ताकि भवन ठीक हो सकें।

कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक 100 किलोमीटर की दूरी में मेरे जहाजपुर से पड़ते हैं, तो मैं मांग करना चाहता हूँ कि जहाजपुर उप खण्ड मुख्यालय में उप जिला अस्पताल हो गया है और नेशनल हाइवे 148 डी सड़क निकल रही है, वहाँ आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती है तो मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि वहाँ एक ब्लड बैंक की स्थापना की जाये। वहां नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाये और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वह हमें मिलें।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं, मेरी कुछ डिमांड्स रखता हूँ, ग्राम पंचायत बावड़ी में पीएचसी खोली जाये। ग्राम पंचायत टिकड़ में एनएच 152 जयपुर से कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग निकल रहा है, वहाँ टिकड़ पंचायत मुख्यालय है, यहां भी फौजी हैं, फौजी एरिया है, यहाँ भी सैनिक भाई निवास करते हैं और उनको दूर दराज जाने में समस्या रहती है, तो मैं टिकड़ में पीएचसी क्रमोन्नत करने की मांग करता हूँ। मां घाटा रानी, जो एक शक्ति पीठ है, यहां आसपास के श्रद्धालु आते हैं और वह जहाजपुर मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर है, मां घाटा रानी में एक सब सेंटर है, उसको पीएचसी में क्रमोन्नत किया जाये।

सभापति महोदय, मैं, मेरी डिमांड निवेदन करना चाहता हूँ। हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, हमारे लोकप्रिय राजस्थान के मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में आजादी के बाद पहली बार हमारे क्षेत्र को, भीलवाड़ा जिले को, अजमेर संभाग को ऐसा बजट मिला है। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधान मंत्री कोटड़ी में विधान सभा चुनाव में आए थे, उन्होंने वादा किया था कि हर क्षेत्र में काम होगा उसी अनुरूप हमारे भीलवाड़ा जिले का, मेवाड़ का विकास हो रहा है।

सभापति महोदय, मैं आप के माध्यम से माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी को और चिकित्सा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री विनोद कुमार।

श्री विनोद कुमार (पीलीबंगा): सभापति महोदय, आपको धन्यवाद कि आपने मुझे मांग संख्या 27 और 28 पर बोलने का मौका दिया। हमारे प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली साहब, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समयः बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

इस मांग पर हमें विचार करना पड़ेगा कि लोग बीमार ही क्यों होते हैं? अच्छा वातावरण मिले, खानपान मिले, वृक्षारोपण की अच्छी व्यवस्थाएँ हो, पेस्टिसाइड के लिए एक निर्धारित मापदंड लाने की आवश्यकता है। जिस तरीके से सदन में चर्चा हुई कि हमारे खाने पीने की जो सामग्री है, उसको लेकर के सदस्यों के द्वारा अच्छे आचार विचार आदान प्रदान किए गये।

मैं भी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जब किसान पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करता

है फसलों की सुरक्षा के लिए, उसको सिक्योरिटी के रूप में हमें उन्हें विश्वास दिलाना पड़ेगा कि पेस्टिसाइड नहीं डालोगे, अगर आपकी फसल कम होती है क्योंकि पेस्टीसाइड बंद करते हैं तो 3-4 साल उतनी फसल हो नहीं पाती। किसान इतना आज थका हुआ है कि फसलें हो नहीं रही, पानी मिल नहीं रहा, उसे विश्वास दिलाना पड़ेगा किसान को कि अगर फसलें नहीं होती तो हम उसकी भरपाई करने का काम करेंगे।

चिकित्सा और स्वास्थ्य की जब बात करें तो हमारे पूर्व मुख्य मंत्री माननीय गहलोत साहब ने जो चिरंजीवी योजना चलाई, एक गरीब आदमी, एक अंतिम पंक्ति का व्यक्ति खाली जेब जब हॉस्पिटल जाने की बात सोच सकता था और इत्ते-इत्ते इलाज हुए, आज हालात क्या हैं चिरंजीवी योजना के? नाम बदल दिया, कोई बात नहीं, लेकिन आप उस योजना को सुचारु रूप से चलाने के लिए, गरीब को, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए आपको उस पर काम करने की आवश्यकता है।

कोरोना काल की जब बात आई, हमारे जो स्वास्थ्य के तंत्र थे, निचली पंक्ति के व्यक्ति को खेत, ढाणी में बैठे व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को हमारे हॉस्पिटलों की जानकारी हुई तो यह लगा कि हमारे स्वास्थ्य का जो तंत्र है वो बिलकुल बेकार है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी हमारे मुख्य मंत्री गहलोत साहब की पीठ थपथपाई कि कोरोना काल में अच्छा काम किया। हमारे सत्ता पक्ष के लोगों से कहना चाहूंगा कि कोरोना में भी हमारे लोग ट्रिपल टी, मतलब ताली, थाली और टॉर्च जला कर के इलाज करना चाह रहे थे। उस सिस्टम को सुधारना पड़ेगा, उनसे कोई इलाज होने वाला नहीं है।

माननीय मंत्री महोदय, मैं पीलीबंगा विधान सभा, जो एक ऐतिहासिक स्थल है कालीबंगा, वहाँ से आता हूँ। मैं मंत्री महोदय का धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि मेरे पीलीबंगा में 30 बेड का हॉस्पिटल था उसको 50 बेड का किया। लेकिन पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र के अंदर एसडीएम कोर्ट भी है, जनसंख्या भी ज्यादा है, नगरपालिका क्षेत्र भी है तो 30 से 70 बेड की मैं आपसे मांग करना चाहूंगा। पीलीबंगा के ही क्षेत्र रावतसर में हमारा उप खंड कार्यालय पड़ता है। उसमें हमारा ट्रोमा सेंटर बना हुआ है। डॉक्टरों का अभाव है, चाहे पीलीबंगा हो, चाहे रावतसर हो, चाहे अन्य पीएचसी बनी हो, चाहे उप स्वास्थ्य केंद्र बने हों, हर जगह स्टाफ का कहीं ना कहीं अभाव है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आप उन पदों को भरकर के आम व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का काम करें। मैं पीलीबंगा के रामपुरा को, रावतसर में सरदारपुरा खालसा उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने की आपसे मांग करना चाहूंगा। जिस तरीके से पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र के अंदर छोटे- छोटे गांव बसे हुए हैं

spp/rtm/06.03.2025/16.20/3a

और जो नॉर्म्स हैं आपके उप स्वास्थ्य केन्द्र के, वह बहुत से हमारे गांव नॉर्म्स को पूरा

करते हैं। उनको लेकर काफी जगह उप स्वास्थ्य केन्द्र कीडिमांड्स राज्य सरकार को CMHO के माध्यम से आपके पास भिजवायी गयी है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि उप स्वास्थ्य केन्द्र की भी घोषणा इसमें शामिल करें। 8 फरवरी 2024 में बजट में डोर स्टेप डिलीवरी की घोषणा की गयी, उसमें अब अखबारों में पढ़ने को मिला कि दवाइयां ही नहीं मिल रही हैं और दिव्यांगों के लिये आपके द्वारा डिस्ट्रिक्ट DDRC जिला मुख्यालय पर खोलने की बात आयी। लेकिन आज दिनांक तक एक भी इस तरीके का सुविधायुक्त मुख्य धारा में जो विकलांगों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बनाना था, आज तक आप उस पर कोई काम नहीं कर पाए। सभापति महोदय, चिकित्सा विभाग के अंदर क्रमोन्नत एवं नवीन चिकित्सा संस्थानों में प्रयोगशाला सहायक का पद स्वीकृत किया जावे एवं जिन चिकित्सा संस्थानों में प्रयोगशाला सहायक का पद विलोपित किया गया था, उन्हें अन्य चिकित्सा संस्थानों में समायोजित किया जावे। इसके साथ-साथ प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 में नियुक्त अभ्यर्थियों को, जिनका प्रोबेशन काल समाप्त हो चुका है, उनके स्थाईकरण का आदेश करवाया जावे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि चिकित्सा मंत्री जी, यहाँ एस.एम.एस. हॉस्पिटल की बात चल रही थी, हमारा जो निजी ब्लड बैंक है, उनको मान्यता अपनी सरकार देती है, उनकी जांच करती है, सब चीजें मॉनिटर करते हैं, लेकिन राजस्थान सरकार ने एक साल हो गया। एक आदेश निकाला था कि ब्लड बैंक निजी संस्थाओं से नहीं लेंगे और निजी संस्था से जब लाकर देते हैं एसएमएस हॉस्पिटल के अन्दर, तो वो मरीज को आप चढ़ाते नहीं हैं। इसकी वजह से चाहे राजस्थान हमारा जो हॉस्पिटल है एसएमएस, उसमें राजस्थान के ही नहीं, बहुत से बाहर के लोग भी इस हॉस्पिटल में इलाज के लिए आते हैं। मैं मंत्री महोदय से आप के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक से ब्लड मिलने की स्थिति में एसएमएस हॉस्पिटल स्टाफ को अब पत्र लिख कर के इस समस्या से निजात दिलाने का प्रयास करें जिससे हमारे दूरस्थ आने वाले चिकित्सा के लिए उन लोगों को लाभ मिल सके क्योंकि जब मरीज आता है तो सरकारी जो ब्लड बैंक है, आज जो 500-700 किलोमीटर दूर से आता है उसको चार यूनिट या पांच यूनिट ब्लड की आवश्यकता पड़ गई तो उसके पास चार या पांच व्यक्ति मिलते नहीं हैं। इसलिए मैं आप के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस समस्या को दूर करने का प्रयास करें।

माननीय सभापति महोदय, आपने स्वास्थ्य, चिकित्सा पर बोलने का मौका दिया, मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर जितनी भी खाली सीटें हैं, उनको भर करके आम आदमी को लाभ प्राप्त करने का काम करेंगे और मैं डॉक्टरों के लिए अच्छी व्यवस्थाओं के लिए, क्योंकि उनके लिए क्वार्टर, ठहरने की अच्छी व्यवस्था ही नहीं होतीं तो उनको दूरस्थ कहीं जाना पड़ता है। अगर उनके लिये क्वार्टर बनाया जाता है हॉस्पिटल के आस पास, तो मेरा मानना है कि अपने लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल पाएंगी। आपने मुझे इस डिमांड पर बोलने का मौका दिया, सभापति महोदय, इसके लिए आपका बहुत

बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री मनोज कुमार।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27 चिकित्सा और स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। सभापति महोदय, जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रत्येक व्यक्ति को चिकित्सा संस्थान की आवश्यकता रहती है, आज उस गंभीर विषय पर चर्चा चल रही है। मैं हमारी सरकारें चाहे, कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो, हमारे प्रदेश में वर्तमान में जो चिरंजीवी योजना, भामाशाह योजना, माननीय पूर्व मुख्य मंत्री वसुंधरा राजे ने शुरू कीं। चिरंजीवी योजना, पूर्व मुख्य मंत्री अशोक गहलोत साहब ने और ज्यादा उसकी प्रगति करने का प्रयास किया। अब सरकार ने उसका नाम मा योजना करके और ज्यादा सफल बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मुख्य रूप से बात यह है कि हमारी सरकारों की मंशा है, राजस्थान प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है, जहाँ इस तरीके की आमजन को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मिले। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम अंतिम छोर के व्यक्ति को, जो योजनाएं हम सरकार के माध्यम से शुरू करते हैं, जिनका लाभ मिलना चाहिए, इनका लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक कैसे पहुँच पाए? इसमें अड़चनें और बाधाएं क्या हैं? जो व्यक्ति इसका लाभ लेना चाहता है, उस समय इनकी बाधाओं को दूर किया जाए। इनमें सबसे बड़ी बाधा है कि चिरंजीवी योजना में या आरोग्य आयुष योजना में जो व्यक्ति भर्ती होना चाहता है, वर्तमान में सरकार ने इनके पैकेज जो निर्धारित किये हैं, प्राइवेट अस्पताल में जयपुर जैसे स्थान पर मैं जब बात करूँ तो यहाँ किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आपके पैकेज की जो रेट है, जो निर्धारित राशि आपने तय की है, सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल वाले किसी गंभीर मरीज को भर्ती नहीं करना चाहते और हमारे एसएमएस अस्पताल की बात करें तो अस्पताल की स्थिति यह है कि गंभीर मरीज ही यहाँ पहुंचता है और जब गंभीर मरीज राजस्थान के प्रदेश से आकर एस एमएस में पहुंचता है और वहाँ आने के बाद उसको बेड नहीं मिले, उसको वेंटिलेटर नहीं मिले, उसको ICU नहीं मिले, इससे बड़ी दुर्भाग्य की कोई और बात हो नहीं सकती हमारे लिए और वह व्यक्ति अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाये और उस प्राइवेट में अगर आपको चिरंजीवी में या मा योजना में शामिल करते हुए अगर भर्ती नहीं किया जाये, अगर एक रात अगर रुकना पड़ गया तो एक रात में लाखों रुपए उससे लिये जाते हैं। जब तक हमारी सरकार ने, आपने योजना ही निःशुल्क शुरू कर दी तो फिर उसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा? अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल उनको भर्ती नहीं करते तो सरकार उस पर क्या योजना बनाने की मंशा रखती है कि प्रत्येक व्यक्ति जो बीमार है, अगर इस योजना से जुड़ा हुआ है, वो उस हॉस्पिटल में जाये? उसको निश्चित रूप से उसको सुविधा मिलनी चाहिए। सरकारें 76 साल से योजना बनाती आ रही हैं। मैं सोचता हूँ कि एसएमएस अस्पताल राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, ये आजादी से पहले का हॉस्पिटल होगा। ये शासकों के समय का हॉस्पिटल है। ये सरकारें 76 वर्ष में इस राजस्थान में एक एसएमएस

अस्पताल जैसा संभाग स्तर पर भी अगर अस्पताल नहीं बना पाई तो हम कहीं बात करते हैं आगे बढ़ने, कि चाँद पर जा रहे हैं। हम बहुत कुछ आगे बढ़ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ सरकार की तरफ से हमारा एसएमएस अस्पताल है इस तरीके की संपूर्ण सुविधाओं का हर संभाग स्तर पर अस्पताल होना चाहिए। जिस पर मरीज को वेंटिलेटर या ICU की जब जरूरत पड़े तो वो मिल जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ में, माननीय सभापति महोदय, सरकार मशीनरी की बातें कर रही थीं। मैं डायलिसिस की एक बात करूँ, अभी हमारे रामकेश जी भी बात कर रहे थे, वास्तव में बड़े दुर्भाग्य की बात है 22 करोड़ की मशीनें खरीदी गईं और डेढ़ वर्ष से अगर वो मशीनें आज तक भी स्थापित होकर लोगों को लाभ नहीं दे पा रही हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। मैं कहना चाहता हूँ सरकार और सरकार के नुमाइंदों से, कि अगर मानव संसाधन जब तक आपके पास नहीं हैं, तब तक आप मशीनरी का पैसा खरीदकर मशीनरी का दुरुपयोग नहीं करें। सबसे पहले मानव संसाधन उपलब्ध कराकर आप उन मशीनरी का प्रयास करें। इसी तरीके से आप चाहे गायनिक की जब सोनोग्राफी की जरूरत है तो आपके पास डॉक्टर नहीं हैं। आपके पास अगर एक्सरे की बात करो तो एक्सरे के लिए उपलब्ध रेडियोग्राफर आपके पास नहीं हैं। इसलिए जहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमारा अंतिम छोर का है, मैं कहना चाहता हूँ सबसे छोटी मशीन है। माननीय सभापति महोदय, सीबीसी मशीन, हर डॉक्टर उसकी जांच लिखता है। अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सीबीसी मशीन नहीं है और अगर मशीन किसी भामाशाह से हम लगवा भी दें तो सभापति महोदय, उसका रिजल्ट देने के लिए गवर्नमेंट उसका पैसा नहीं देती। मैं मांग करता हूँ कि यह बहुत बड़ी समस्या है। हर व्यक्ति की जांच जाते ही डॉक्टर लिखता है लेकिन सीबीसी मशीन नहीं होने के कारण उसका रिज़ल्ट नहीं होने के कारण उसकी जांच नहीं हो पाती।

माननीय सभापति महोदय, एक और बड़ी समस्या है। हमारे नीचे के स्थान पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, वहाँ डॉक्टर्स को लगाया जाता है। वो डॉक्टर इसलिए लगते हैं कि उनको 2 साल का पीजी में जाने को उनको लाभ मिले और वो डॉक्टर वहाँ कभी भी नहीं रहते। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर अपनी हाजिरी कभी महीने में, कभी 10 दिन में, कभी 15 दिन में लगाते हैं। गवर्नमेंट इस बात की निश्चितता करें कि जो भी कर्मचारी हमारा जिस स्थान पर लगा है, उस स्थान पर निश्चित रूप से वो काम करे और उसका लाभ मिलना चाहिए। आपके सामने अभी रेफर, डॉक्टरों ने एक प्लान बना दिया कि कोई भी सीएचसी में जाइये, वहाँ डॉक्टर बैठे हैं वो इसलिए एडमिट नहीं करते कि उनको सुबह शाम उनको देखना पड़ेगा, इसका हमको इलाज करना पड़ेगा इसलिए मैं मांग करता हूँ की जो डॉक्टर रेफर करता है किसी मरीज को और जिस उच्च स्तर पर जो मरीज जाता है, उस स्थान पर क्या उसकी रेफर करने की जरूरत ठीक नहीं थी और डॉक्टर ने उसको गलत रेफर कर रहे हैं तो उन डॉक्टरों पर भी नियंत्रण किया जाए।

jyg/rtm/06.03.25/16.30/3b

जहां सामान्य रूप से उच्च स्थान पर भीड़ नहीं हो और सीएचसी पर उसका इलाज हो सके। माननीय सभापति महोदय, सीएचसी पर अगर बात करें तो सीएचसी हमारी जितनी भी हैं, वहां पर आपके डॉक्टर चार या पांच, जो भी लगते हैं, उन डॉक्टरों में ग्रामीण क्षेत्रों में जो सीएचसी है, उन सीएचसी की स्थिति यह है कि तीन से चार डॉक्टर होते हैं उनमें एक डॉक्टर रहता है और तीन या चार डॉक्टर अपने घर रहते हैं, सात-सात दिन से बारी बांध कर जाते हैं, एक डॉक्टर मिलता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं दो-चार बातें करके मेरी बात पूरी करूंगा। एक मैं कह रहा था, हमारे दवाइयों की बात है, कल-परसों मैंने एक न्यूज पढ़ी, 89 दवाइयों का सैम्पल फेल हुआ, सैम्पल फेल हुआ। उन्होंने बाहर भी कर दिया, यह बात तो ठीक है, लेकिन वो दवाइयां कब से चल रही थीं? जिस कम्पनी का सैम्पल फेल हुआ उन दवाइयों के, उनसे रिकवरी करने की सरकार की मंशा है क्या? उन्होंने दो-दो साल तक दवाई बेच दी। आपको दे दी और आपका सैम्पल फेल हुआ और उसकी जांच करके आप उनसे रिकवरी नहीं करेंगे तो फिर कितने बरसों तक बेचते रहेंगे?

माननीय सभापति महोदय, मैं मांग करता हूं मेरे विधान सभा क्षेत्र में उप जिला अस्पताल है, उसमें ट्रोमा सेंटर बन गया, लेकिन उसे बने हुए एक बरस हो गया लेकिन आज दिन तक वो सुचारू रूप से चालू नहीं हुआ, न तो उसमें उपकरण लगे और ना उसमें डॉक्टर लगे हैं। मेरे उप जिला अस्पताल में 16 डॉक्टर्स के पद खाली हैं। इसी तरीके से मेरे एचएचसी है सिद्धमुख में जिसको भामाशाह ने बहुत सुन्दर तरीके से बनाया है, दस करोड़ रुपये लगाये लेकिन एकमात्र डॉक्टर है, चार डॉक्टरों की पोस्ट वहां पर खाली है। इसी तरह से मेरे सांखू में भी आपने उसको आदर्श सीएचसी बनाया है लेकिन आदर्श के बाद अब तक उसमें कुछ किया नहीं है, डॉक्टर्स की वहां पर भारी कमी है।

श्री सभापति: श्री गोपाल लाल शर्मा।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): बजट में इन्होंने घोषणा की, हमारे एक तो संविदा कर्मचारियों की मांग है, जो ठेका प्रथा में लग गये हैं, इन्होंने बजट के पैरा नम्बर 7 में इसकी घोषणा की है कि उनको चरणबद्ध रूप से हटाने का काम करेंगे। माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ): माननीय सभापति महोदय, बजट की अनुदान मांगों पर विचार रखने का मुझे अवसर प्रदान किया, आपका बहुत-बहुत आभार।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश की माननीय उप मुख्य मंत्री महोदया ने जो कुशल बजट पेश किया, मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय भजन लाल शर्मा जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पहले कोई भी बढ़िया हॉस्पिटल नहीं था, बहुत बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद माण्डलगढ़ एक ऐतिहासिक कस्बा है, उसमें भी हॉस्पिटल नहीं था, लेकिन पहले ही बजट में राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय

भजन लाल शर्मा जी ने माण्डलगढ़ हॉस्पिटल को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किया। मेरे विधान सभा क्षेत्र में बिजोलिया एक बहुत बड़ा कस्बा है, उस हॉस्पिटल को भी पहले ही बजट में उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किया, मैं वहां की जनता की ओर से आभार प्रकट करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आपको कहना चाहता हूं कि पहले पांच साल में मैं इसी विधान सभा में था, जो मेरे सामने बैठे हैं, वो माननीय सदस्य कह रहे थे, अपनी सरकार की बड़ाई कर रहे थे पर मैं कहना चाहता हूं कि पांच साल तक कोरोना का काल भी निकला है, हम उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं, आप लोगों ने कौनसी अच्छी व्यवस्था की वो हमारे सामने है। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की व्यवस्था बिलकुल नहीं थी, दवाइयां भी बिलकुल नहीं थी, इंजेक्शन की व्यवस्था बिलकुल नहीं थी और कितने हजारों आदमी उससे मरे आपके सामने, बिलकुल उनकी कोई सुध नहीं ली। आज आप अपनी उस सरकार की बड़ाई करने में लगे हैं। मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय भजन लाल शर्मा जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो पहले ही बजट में राजस्थान की आम जनता को सुविधाएं दी, जिसमें हर तरह की राजस्थान की समस्याओं का उस बजट में निराकरण किया गया। आप आदमी देखकर तिलक निकालते थे, केवल जो कांग्रेस के विधायक थे उनका काम होता था, हम बार-बार मांग करते थे और कोई हमारी सुनने वाला नहीं था, वो सब आपके सामने है। बजट में मुख्य मंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में आम जनों को नि:शुल्क दवा व जांच की सुविधा सुनिश्चित करवाने के लिए 3,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो आपके सामने है, पहले ही बजट में है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां जीवन के सभी सुखों में पहला सुख नीरोगी काया माना गया है, इसका अर्थ है, प्राचीन समय से ही हमारे पुरखों ने स्वास्थ्य के महत्व को समय लिया था। राज्य सरकार ने आरजीएचएस योजना का दायरा बढ़ाकर इसमें महिला कर्मचारियों के आश्रित सास-ससुर व माता-पिता को भी इसमें सम्मिलित किया है। यह राजस्थान की सरकार है जिसने सबको सम्मिलित किया है क्योंकि मां-बाप बच्ची को पढ़ाते हैं और वो नौकरी लगती है और ससुराल वह चली जाती है तो मां-बाप की देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है परंतु हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय भजन लाल शर्मा जी ने ऐसा काम किया है इससे दोनों परिवार सुखी रहेंगे और बुढापे में उनका इलाज भी होगा।

माननीय सभापति महोदय, बजट में 750 चिकित्सकों व 1,500 पैरा मेडिकल स्टाफ के पदों का सृजन करने की भी घोषणा की है। आयुष्मान आदर्श ग्राम घोषित होने पर उस ग्राम को 11 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है, इससे सभी वहां के कर्मचारी मेहनत से काम करेंगे और स्वास्थ्य समस्याओं का निराकरण करेंगे। माननीय सभापति महोदय, इस युग में बदलती जीवन शैली अनियमित दिनचर्या एवं असंतुलित भोजन से उच्च रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड जैसी असाध्य बीमारियां होती हैं। बजट में फिट राजस्थान की भी घोषणा की गयी है। इसमें स्वास्थ्य एवं आहार सम्बन्धी जागरूकता का

कार्य किया जायेगा, यह अभिनव है। यदि नागरिक की जीवन शैली नियमित एवं आहार संतुलित हो तो वह अस्वस्थ्य ही क्यों हो? अस्वस्थ होने पर व्यक्ति का इलाज करना और स्वास्थ्य चेतना के माध्यम से व्यक्ति का अस्वस्थ ही न होना बहुत अच्छी बात है। किसी भी क्षेत्र में काम करने के लिए आदर्श योजना होनी चाहिए। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार देश में और प्रदेश में इसी दिशा में काम कर रही है। मुख्य मंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में दूसरे राज्यों में उपचार के लिए इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी लागू कर सरकार ने गम्भीर स्थिति में बाहर रैफर होकर चिकित्सा कराने वाले रोगियों के लिए राहत वाला कदम उठाया है। नागरिकों की जीवन सुरक्षा की दृष्टि से सरकार ने हमारे राजस्थान में 20 नये ट्रोमा सेंटर और 25 जीवन रक्षक एम्बुलेंस की सुविधा देने का निर्णय लिया है। प्रदेश को टीबी मुक्त करने का संकल्प व हर जिला अस्पताल में डायबिटिक क्लिनिक खोलने का निर्णय सरकार के आरोग्य संकल्प को स्पष्ट करता है। बजट में वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं, किशोरों, कैंसर रोगियों, एचआईवी संक्रमितों के लिए भी विभिन्न प्रावधान किये हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं पूर्ववर्ती सरकार की आलोचना नहीं करना चाहता लेकिन कुछ बातों की चर्चा जरूरी है। पूर्ववर्ती सरकार ने प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में सीएचसी खोली, घोषणा की, लेकिन उसके लिए कोई बजट प्रावधान नहीं किया और कह दिया गया कि सीएचसी का फण्ड एमएलए लैड फण्ड से देना होगा लेकिन वो घोषणा केवल घोषणा ही रह गयी, कोई काम उसमें हुआ नहीं। पिछली सरकार ने थानों में स्वागत कक्ष, खेल मैदान, आदर्श सीएचसी, ऐसी कई घोषणाएं बजट में की, लेकिन उनको पूरा करने के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं किया। यह कहकर छोड़ दिया कि विधायक मद से इसको पूरा कराया जाये। परंतु उस सरकार के काम करने की मंशा नहीं थी इसलिए ऐसी थोथी घोषणाएं की।

माननीय सभापति महोदय, कोटा के जे के लोन अस्पताल में हुई सैंकड़ों शिशुओं की अकाल मृत्यु का दृश्य याद आते ही मन शोक से भर जाता है। उससे एक वर्ष बाद ही वहीं नौ बच्चों की अकाल मृत्यु हो गयी, उस समय हो-हल्ला हुआ, बयानबाजी हुई, लीपापोती हुई। जिन परिवारों ने इन हादसों में अपना लाल, अपने घर का चिराग खोया उनके मन पर क्या बीत रही होगी, विचारणीय विषय है। मेरा निवेदन है कि ऐसी घटनाओं में लिप्त कार्मिकों पर कार्यवाही हो, जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो।

माननीय सभापति महोदय, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग चिकित्सा भारत ने पूरे विश्व को दी है। मैं यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उनकी पहल पर पूरे विश्व में 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। वर्तमान युग में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति अत्यंत सुगम व निरापद है। अन्य चिकित्सा पद्धतियां व्यक्ति के बीमार होने के बाद उनका उपचार शुरू करती है जबकि आयुर्वेद व प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति आदर्श जीवन शैली, आहार, विचार एवं दिनचर्या से हमें स्वस्थ करने का संदेश देती है। आयुर्वेद आरोग्य देता है, आयुर्वेद कहता है, व्यक्ति अस्वस्थ ही न हो। माननीय सभापति महोदय, आयुर्वेद विभाग को प्रदेश में सरकार के संरक्षण की बहुत दरकार है। विभाग की

रसायन शालाओं की स्थिति ठीक नहीं है। इनमें पहले के मुकाबले दवाइयां कम बन रही है। आयुर्वेद रसायनशालाओं पर विगत पांच वर्षों में किये गये व्यय के आंकड़ों का मैंने अध्ययन किया है, विस्तृत विवरण दूंगा तो वक्तव्य लम्बा हो जायेगा, समय की भी सीमा है। मेरा निवेदन है कि इन रसायनशालाओं में दवा निर्माण पर कम और वेतन पर अधिक खर्च हो रहा है, यह स्थिति चिंताजनक है।

MLS/RTM/06.03.2025/16:40/3c

मेरे विधान सभा क्षेत्र की भी मैं कुछ मांगों के बारे में बताना चाहता हूं। मेरे एक बडलियास कस्बा बहुत बड़ा कस्बा है, वहां पर अस्पताल की दयनीय स्थिति है। वहां बहुत पुराना हॉस्पिटल है, जिसकी जर्जर अवस्था हो चुकी है। उसे सीएचसी में क्रमोन्नत कर एक पूरी नयी बिल्डिंग बनायी जाये। हमारे विधान सभा क्षेत्र में नंदराई, बरूंदनी, जलींदरी, धामनिया को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व उप स्वास्थ्य केन्द्र खाचरोल, ककोल्या घाटी, गेऑली, खटवाड़ा, गेगाखेड़ा, जीवा का खेड़ा, सराना, खलखला, गेंदडिया, जोजवा, बोबदपुरा, किशनगढ़, रलायता को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाये। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

भैरूखेड़ा, गंदेरी, गोविंदपुरा, चोहली, धनवाड़ा, देवली, दांतड़ा छोटा, गोरधनपुरा, बीलिया, बरखेड़ी, गणेशपुरा, ऊंदरू का खेड़ा, गोउनी में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएं। सुरास, हींगवानिया, देवरिया, आजीवाज, मनगड़ी में भी नवीन स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएं। मेरे क्षेत्र में जो अस्पताल हैं, बहुत ही जर्जर अवस्था में हैं। मैं मांग करना चाहता हूं, जो-जो भी जर्जर अवस्था में हैं या जहां बिल्डिंग नहीं हैं, वहां नयी बिल्डिंग बनाने की घोषणा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में डॉक्टरों की बहुत कमी है। माण्डलगढ़ बड़ा हॉस्पिटल है। बिजोलिया में भी है। हमारे बडलियास में डॉक्टर बिलकुल नहीं हैं। वहां डॉक्टरों की नियुक्ति की जाये।

कम्पाउंडरों की कमी है। लैब हैं, पर लैब टैक्निशियन नहीं हैं। मैं मांग करता हूं कि हमारे उस क्षेत्र में कम्पाउंडर जल्दी से लगाये जाएं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मेरे विधान सभा क्षेत्र में माण्डलगढ़ बड़ा हॉस्पिटल है। वहां सोनोग्राफी की मशीन खराब है। मैं मांग करता हूं कि डिजिटल सोनोग्राफी की मशीन हमारे माण्डलगढ में दिलायी जाये। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो भी नयी-नयी पंचायतों का गठन होने जा रहा है, जो गांव हैं, बड़े कस्बे हैं, वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएं।

श्री सभापतिः श्री अनिल कटारा। (अनुपस्थित) श्री अशोक कुमार कोठारी।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ): मैं पुनः मुख्य मंत्री जी और राज्य सरकार को बधाई देता हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत आभार। जय हिन्द, जय भारत, जय-जय राजस्थान।

श्री सभापतिः श्री अशोक कोठारी। (अनुपस्थित) श्री गणेशराज बंसल।

श्री गणेशराज बंसल (हनुमानगढ़): आदरणीय सभापति महोदय, आज आपने मांग संख्या 27 व 28 पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय में संचालित महात्मा गांधी स्मृति राजकीय जिला चिकित्सालय का मुख्य भवन सन् 1980 से पूर्व का निर्मित है, जो पुराना होने के कारण जीण-शीर्ण है। पी डब्ल्यू डी विभाग हनुमानगढ़ द्वारा भी उक्त भवन के कुछ हिस्से को उपयोग योग्य नहीं पाया गया है। जिला चिकित्सालय के मुख्य भवन का नवीन निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से इस ओर भी ध्यान देने हेतु निवेदन करना चाहता हूं।

इसके अतिरिक्त जिला चिकित्सालय में वर्तमान में मुख्य भवन में 200 बैड स्वीकृत हैं और एमसीएच यूनिट में 50 बेड स्वीकृत हैं, जबकि मौके पर मुख्य भवन में 300 से अधिक बेड और एमसीएच यूनिट में 130 बेड लगे हुए हैं। जिला चिकित्सालय में 200 से 300 बैड और एमसीएच यूनिट में 50 से 100 बेड की स्वीकृति किये जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा बेड की संख्या के अनुरूप स्टाफ की भी बहुत कमी है, डॉक्टरों की कमी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से स्टाफ को पूरा करने का निवेदन करता हूं, ताकि आम आदमी को सुविधाएं मिल सकें।

वर्तमान में सरकार द्वारा चलायी जा रही मा योजना के मरीज राजकीय अस्पताल में भर्ती तो हो जाते हैं, जांच नि:शुल्क राजकीय अस्पताल से होती है, परन्तु टीआईडी जनरेट हो जाने के पश्चात मरीज प्राइवेट अस्पतालों में ऑपरेशन करवाता है, जिससे राज्य सरकार को नुकसान हो रहा है। इस पर प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। यूटीबी के माध्यम से लगे हुए अस्थायी एएनएम, जीएनएम, लैब सहायक व अन्य कार्मिकों की सेवाएं यथावत रखी जाएं एवं हो सके तो उन्हें योग्यता के आधार पर पात्र पाये जाने पर स्थायी किया जाये।

सभापति महोदय, हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर 2023 में नवनिर्मित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हनुमानगढ़ में बुनियादी फर्नीचर आज दिनांक तक उपलब्ध नहीं कराया गया है, जबकि उक्त कॉलेज में दूसरा बैच भी शुरू हो चुका है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो भी मांग अनुसार फर्नीचर है, वह उपलब्ध कराया जाये। इसके अतिरिक्त उक्त कॉलेज में एनाटमी एवं फार्माकोलॉजी विषय के प्रोफेसर्स भी उपलब्ध नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से इस ओर भी ध्यान देने हेतु निवेदन करना चाहता हूं। आज आपने मांग संख्या 27 व 28 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोरधन।

श्री गोरधन (धोद): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27 - चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और मांग संख्या 28 - चिकित्सा शिक्षा पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से इस कांग्रेस सरकार ने पांच साल में जो काम किया और जो चिकित्सा व्यवस्था की, जिस प्रकार से देखने-सुनने को मिला कि हॉस्पिटलों में स्टाफ नहीं, रोगी को देने के लिए दवाई नहीं, इस प्रकार से जैसे ही हमारी सरकार बनी, माननीय मुख्य मंत्री जी भजन लाल जी चिकित्सा और स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर हुए और इन सब व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए प्रदेश की जो गम्भीर बीमारियां हैं, असाध्य रोग हैं, उनको ठीक करने के लिए पहले ही बजट में लगभग 27 हजार 660 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, जो बजट का 8.26 परसेंट है। ...(व्यवधान)...

मोदी जी ऐसे नहीं हैं, मैं बिलकुल फैक्ट बात बता रहा हूं आपको। जिस प्रकार से, क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा इस चिकित्सा और स्वास्थ्य को ठीक कैसे किया जाये, इसके लिए हमारे माननीय भजन लाल जी काम कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मां योजना के द्वारा मैं सोचता हूं कि 35 लाख लोगों को चिकित्सा स्वास्थ्य का लाभ दिया जायेगा और इस योजना के अन्तर्गत नि:शुल्क जांच एवं दवा उपलब्ध करवायी जायेगी और इसके अन्तर्गत लगभग 3 हजार 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे बहुत सारे ऐसे काम करने वाले व्यक्ति, बहुत सारे ऐसे मजदूर या छोटा-मोटा व्यापार करने वाले लोग जो हमारे प्रदेश के बाहर भी रहते हैं, वे भी इस योजना के अन्तर्गत लाभ ले पाएंगे। ऐसी इसकी शुरुआत की गयी है।

माननीय सभापति महोदय, चूंकि हमारे जो बुजुर्ग हो गये, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिले तो 70 साल से ऊपर जो भी व्यक्ति हैं, उन्हें भी नि:शुल्क दवाइयां दी जाएंगी। माननीय सभापति महोदय, इस मां योजना के अन्तर्गत हमारे बहुत सारे ऐसे ड्राइवर होते हैं या जो बढ़ई का काम करते हैं, जो कारीगर का काम करते हैं, दर्जी का काम करते हैं और जिनकी आंखें कमजोर हो गईं, वाउचर योजना के अन्तर्गत उनकी आंखों की जांच की जायेगी और उन्हें चश्मा भी दिया जायेगा। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति माननीय मोदी जी और भारत सरकार दृढ़ संकल्पित है, फिट इंडिया की तर्ज पर माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा भी फिट राजस्थान की योजना चलायी गयी है, जिसमें 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री मोदी जी ने, जिस प्रकार से हम आज के इस समय में ज्यादा ऑयली पदार्थों का सेवन करते हैं, खाद्य पदार्थों में लिया जाता है तो किस प्रकार से दस परसेंट ऑयल हम कम करके हमारे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सकते हैं।

MKD/RTM/06.03.2025/16:50/3d

वैसे स्वास्थ्य से रिलेटेड माननीय मुख्य मंत्री जी ने आयुष नीति निर्धारित की है या आदर्श आयुष्मान ग्राम योजना के अन्तर्गत, जो भी हमारा गांव पूर्णतया निरोगी होगा, उसको बढ़ावा देने के लिए लगभग 11 लाख रुपये का पुरस्कार देने की भी घोषणा की गई है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे बहुत सारे कांग्रेस के साथियों ने इस कोरोना काल के

बारे में भी जिक्र किया। कोरोना काल में, मैं उन सभी कार्मिकों, लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, चाहे हमारे सफाई कर्मचारी हों, चाहे हमारे चिकित्साकर्मी हों, चाहे हमारे मेडिकल में काम करने वाले लोग हों, कोरोना काल में उन्होंने बहुत सराहनीय काम किया।

हम सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को, क्योंकि मोदी जी ने जिस प्रकार से कोरोनाकाल से लड़ने के लिए हमें शक्ति दी, हममें इसके प्रति जो विश्वास पैदा किया, क्योंकि कांग्रेस सरकार के मंत्री तो होटलों में ऐश कर रहे थे, होटलों में आराम कर रहे थे। लेकिन उस समय, अभी कह रहे थे, थाली बजा रहे थे, दीपक जला रहे थे, सन्देश देने के लिए, इस कोरोना से लड़ने के लिए माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से काम किया, जिस प्रकार से जनता को जागरूक किया और यही कारण रहा कि जब कोरोनाकाल का दूसरा समय आया तो हमारे जो लोग थे, वे घरों में कैद थे और इस स्वास्थ्य के प्रति या इस रोग के प्रति पूरे जागरूक हो गये थे।

माननीय सभापति महोदय, हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं, जब जनता से आग्रह करते हैं तो हमारे सभी लोग एक आवाज में घरों में कैद हो जाते हैं। आपने इसका उदाहरण कोरोनाकाल में देखा होगा।

माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से राम मन्दिर का निर्माण करवाया गया था। उस समय माननीय मोदी जी ने आह्वान किया कि आपका यह राम मन्दिर यहीं रहेगा, आप सब लोग रामलला का आराम से दर्शन कर सकते हैं, तो सब लोग राममूर्ति की स्थापना होने के बाद वहां पर गये, नहीं तो वहां पर भी करोड़ों की संख्या हो सकती थी। हमारे मोदी जी एक जनप्रिय लीडर हैं। जनता की आत्मा में निवास करते हैं, इसलिए उनकी बातों पर विश्वास करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह भी है कि जैसे हमारा कोई उद्योगपति होता है या बिजनेजमैन होता है। जब भी वे हमारे गांव में आते हैं। इस मातृभूमि के साथ में जुड़ाव रखते हैं। हमें ऐसे भामाशाहों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वे जब हॉस्पिटलों का निर्माण करवाते हैं, जब कॉलेज, स्कूल का निर्माण करवाते हैं, तो हमारे गांव के लोग हैं, हमारे जिले के लोग हैं, हमारे राजस्थान के लोग हैं, उन सबकी ड्यूटी बनती है कि ऐसे भामाशाहों का मान-सम्मान होना चाहिए, जिससे वे प्रोत्साहित होकर हमें फिर से कोई न कोई ऐसी सुविधा दे।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि हमारे बहुत सारे ऐसे रोगी होते हैं, जिनके साथ में या जिनको इलाज दिलाने के लिए उनके साथ में कोई अटेंडेंट नहीं होता। जो हमारे बड़े हॉस्पिटल होते हैं, उन बड़े हॉस्पिटलों में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वहां पर 5-10-15-20 जिस प्रकार से आवश्यकतानुसार वहां पर उनके लिए आते ही अटेंड कर लें और उनको ठीक ढंग से एडमिट करवा दे, उनकी दवाइयां चालू करवा दे तो मैं सोचता हूं कि यह एक मानव जाति की सेवा कर सकते हैं।

क्योंकि बहुत सारे ऐसे रोगी होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जो गांवों में रहते हैं, वे

एसएमएस हॉस्पिटल में जैसे ही आते हैं तो वे ऐसे ढूंढते ही रह जाते हैं।

माननीय सभापति महोदय, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की विशेषकर बात करना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र धोद में माननीय मुख्य मंत्री जी ने आते ही उप जिला अस्पताल की घोषणा की, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका साधुवाद करता हूं, मेरी जनता की ओर से उनका आभार प्रकट करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस पिछले पांच सालों में रही, लेकिन कांग्रेस के विधायक अभी भी मांग कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में ये करवा दो, वो करवा दो, लेकिन हमें तो सवा साल हुआ तो मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि हमारी दो-तीन पीएचसी हैं,हैं, जैसे खूड है, सरवड़ी है, किरड़ोली है इनको सीएचसी में क्रमोन्नत किया जाए। उप स्वास्थ्य केन्द्र को पीएचसी में क्रमोन्नत करवाने के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा खाखोली, हर्ष, सेवदबड़ी, बेराणा, सांवलोदा धायलान, सावंलोदा पुरोहितान, बोसाणा, मंडावरा, सामी, राजपुरा, चिडासरा बाडलवास ऐसे बहुत सारे उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं, इनको पीएचसी में क्रमोन्न किया जाए। हमारे दो-तीन ऐसे गांव भी हैं, जिनमें उप स्वास्थ्य केन्द्र भी खोले जाए। जैसे फतेहसिंह की ढाणी, लाड्वा और कंवरपुरा। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि ये इस बात पर जरूर ध्यान देंगे।

हमारे जो उप जिला अस्पताल है, उसमें सोनोग्राफी की मशीन, प्रोर्टेबल एक्स-रे मशीन, सीबीसी की मशीन ऐसे उपकरणों की आवश्यकता है, उन्हें उपलब्ध करवा दिया जाए तो हमारी जनता को काफी राहत मिल सकती है।

हमारी खूड और लोसल पीएचसी में एक लैब टेक्निशियन की नियुक्ति कर दी जाए तो उससे भी जनता को फायदा हो सकता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे सीकर को जो मेडिकल कॉलेज है, सीकर का जो हॉस्पिटल है, उसको भी अतिशीघ्र चालू किया जाए, जिससे एसएमएस हॉस्पिटल पर भी भार कम पड़े। हमारे क्षेत्र को लाभ मिल सके। आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। वन्दे मातरम।

श्री सभापति: श्री पूसाराम गोदारा।

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): माननीय सदस्य, आप विराजिये, मैं बोल लेता हूं। माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने मांग संख्या 27 और 28 स्वास्थ्य सेवाओं पर बोलने का मौका दिय।

पहला सुख, निरोगी काया है। तभी सब कुछ ठीक होता और तभी सब सम्भव है। इसलिए सरकार चाहे कोई भी हो, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती के साथ चुस्त और दुरुस्त किया जाना चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों में जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं, जिला हॉस्पिटल से लेकर सब-सेंटर तक, वहां बहुत कम स्टाफ उपलब्ध हैं, डॉक्टर बहुत कम उपलब्ध हैं और भवनों की स्थिति जीर्ण-शीर्ण है।

मैं यही बात कहना चाहता हूं कि एसएमएस हॉस्पिटल, जो राजस्थान का सबसे बड़ा

हॉस्पिटल है। इसमें राजस्थान से जो भी मरीज रैफर होकर आते हैं, उनको 5-5, 6-6 दिन तक इमरजेंसी के बाहर बेड नहीं मिलता, कई को वेंटीलेटर उपलब्ध नहीं होता, आइसीयू में उनको जगह नहीं मिलती। ओपीडी का विस्तार नहीं करके इस प्रकार की चीजों पर ध्यान दिया जाए। बीमार व्यक्ति को दो-चार-पांच दिन बेड नहीं मिलेगा तो बताओं वह कैसे ठीक हो सकता है? इसलिए, सबसे पहले राजस्थान लेवल पर एसएमएस हॉस्पिटल में यह व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। बहुत से ऐसे मरीज 6-6 महीने तक ऑपरेशन का इंतजार करते हैं, लेकिन उनका एसएमएस में नम्बर नहीं आता। ऐसी स्थिति में, मैं माननीय सभापति महोदय की अनुमति से कहना चाहूंगा मंत्री महोदय को और सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए और कम से कम सामान्य ऑपरेशन 15 दिन में और गम्भीर ऑपरेशन 3 दिन में होने चाहिए। ऐसी व्यवस्था, ओपीडी के अलावा ऑपरेशन थियेटर हो और एक्सपर्ट सर्जन हो, यह व्यवस्था करें। यह बात भी मैं कहना चाहता हूं।

इसके अलावा हमारी तत्कालीन कांग्रेस की सरकार, गहलोत सरकार ने कोरोना में जो शानदार मैनेजमेंट किया, अभी हमारे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य गोरधन जी कह रहे थे, मोदी जी ने बहुत शानदार मैनेंजमेंट किया। ठीक है, मोदी जी ने अच्छा सहयोग किया, वे देश के प्रधान मंत्री हैं, लेकिन थाली और दीये बहुत करवाये, उससे कभी बीमारी नहीं भगती है।

राजस्थान में मुख्य मंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने शानदार मैनेजमेंट किया, जो पूरे देश में सराहा गया और इस प्रकार की कई योजनाएं नि:शुल्क दवा योजना हमारी कांग्रेस की सरकार की देन है। जिस पर आज पूरा स्ट्रक्चर सभी सरकारों ने खड़ा रखा है। आज जो भी सरकार में बैठे हैं, हमारे नुमाइंदे, उनको भी सिस्टम को डवलप करने के लिए काम करना चाहिए। ऐसी स्थिति में कोरोना में जो मॉडल बना, उसके दौरान जो भी ओटी में कर्मचारी रखे गये, उनको कार्यमुक्त कर दिया गया, कइयों को रखा गया है, उनको स्थायी नहीं किया जा रहा है। उस समय हथेली पर जान रखकर उन लोगों ने सेवा की है। उनको वास्तव में जो कार्यमुक्त किये गये हैं, उनको वापस लिया जाना चाहिए।

Bhs/Rtm/06.03.25/17.00/3e

मैं माननीय मंत्री महोदय से, सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, इसके अलावा विशेष तौर से मुख्य मंत्री चिरंजीवी दुर्घटना योजना का इस बजट में कहीं जिक्र नहीं किया गया है भले ही उसका नाम बदल दें, लेकिन दस लाख तक का दुर्घटना बीमा क्लेम मिलना चाहिये। यह बहुत गम्भीर मामला है राजस्थान में इस प्रकार की बहुत दुर्घटनाएं होती हैं, गरीब लोगों के घर उजड़ जाते हैं तो इसमें भी यह व्यवस्था की जानी चाहिये। इसके अलावा पच्चीस लाख तक का मुख्य मंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में जो नाम बदल दिया गया मुख्य मंत्री चिरंजीवी योजना का उसमें कितने लोगों का कैशलेस इलाज

होगा, इस राशि का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। यह व्यवस्था होनी चाहिये।

सभापति महोदय, इसके अलावा मैं यह कहना चाहूंगा कि जो भी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कैम्प लगाये जाते हैं ब्लॉक स्तर पर सिर्फ फॉर्मल्टी है उस दिन बहुत से डॉक्टर उसमें आकर बैठ जाते हैं और ओ.पी.डी. खाली पड़ी रहती है, लोगों की लाइनें लगी रहती हैं और उस दिन का डॉक्टर पूरा दिन निकाल देते हैं और जांच के नाम पर ब्लड और यूरिन के अलावा कोई जांच नहीं होती। इसलिये जहां भी स्वास्थ्य सम्बन्धी आप कैम्प लगायें उसमें निश्चित तौर से सब प्रकार की जांचों की व्यवस्था होनी चाहिये, नहीं तो हॉस्पिटल्स में यह व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि वह दिन खराब न हो और उसमें जो गम्भीर रोगी हैं उनको इलाज मिल सके।

सभापति महोदय, इसके अलावा मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के जिला हॉस्पिटल जिसको चार साल हो गये क्रमोन्नत हुए उसमें रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, एनेस्थेटिस्ट नहीं है, गॉयनिक सहित स्पेशलिस्टों के 43 में से 20 पद खाली हैं आज की तारीख में। यह बहुत गम्भीर मामला है और यह सिर्फ रैफरल हॉस्पिटल बना हुआ है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें डॉक्टर्स का पदस्थापन करें। कई बार मैंने निवेदन भी किया है, नाम भी सजेस्ट किये हैं और इसके अलावा सीटी स्कैन मशीन, एम.आर.आई. की व्यवस्था भी जिला हॉस्पिटल में सुदृढ़ तरीके से की जाये क्योंकि अभी कोई नये प्रकार के उपकरण उपलब्ध नहीं कराये गये। आँख, नाक, कान की जांच के उपकरण भी बहुत कम हैं। एकाध भामाशाह ने हमें व्यवस्था जरूर करवायी है इसलिये उसमें भी जिला हॉस्पिटल लेवल के उपकरण उपलब्ध कराये जाने चाहिये।

इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि वहां जमीन मौजूद है। 2023-24 में 50 करोड़ रुपये इस बिल्डिंग के लिए मंजूर हुए, लेकिन 2024-25 के बजट में काट करके 30 करोड़ रुपये सरकार द्वारा किये गये। उसके टेंडर हो गये, स्वीकृति जारी हो गयी, आज तक माननीय मंत्री महोदय, वह काम शुरू नहीं हुआ जिला हॉस्पिटल का, जबकि वहां जमीन उपलब्ध है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि सिर्फ एक रैफरल हॉस्पिटल बना हुआ है। यहां मेडिकल कॉलेज है हमारे चूरू में, वहां हॉस्पिटल में भी ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिला स्तर पर मेडिकल कॉलेज के स्तर पर कि वहां कोई इलाज हो। वहां से उसको बीकानेर भेजा जाता है, बीकानेर से जयपुर के लिए रैफर किया जाता है, वह अपना दम तोड़ देता है। यह मरीजों के साथ एक मजाक है। इतने करोड़ों रुपये सरकार के डेली खर्च होते हैं तो ऐसी व्यवस्था में बदलाव किया जाना चाहिये। यह रैफरल हॉस्पिटल सामान्य डिलीवरी को रैफर कर देते हैं यह खेद का विषय है कि डॉक्टर नहीं है, व्यवस्था नहीं है इसलिये इन चीजों को गम्भीरता से लिया जाये।

सभापति महोदय, इसके अलावा मैं यह कहना चाहूंगा कि एक हमारे राजलदेसर तहसील है, हाईवे से जुड़ा हुआ है, नगरपालिका है, पचास गांव उसके नीचे हैं, आदर्श सी.एच.सी. है वहां 1992 में क्रमोन्नत हुई माननीय मंत्री जी, जिसमें 7 पोस्टों में से एकमात्र महिला

चिकित्सक के भरोसे है। दो लोगों के डेपुटेशन कर रखे हैं वो डेपुटेशन निरस्त करने के बाद में ज्वाइन नहीं करते। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां 18 दिन से माननीय मंत्री जी, बहुत गम्भीर बात कह रहा हूं मैं आप बात को सुनें, 18 दिन से वहां सभी पार्टियों ने, पत्रकारों ने और सर्वसमाज ने धरना दे रखा है वहां आपका कोई प्रतिनिधि बात करने वाला नहीं है। वहां पांच सौ आदमियों की ओ.पी.डी. है। इसलिये मंत्री जी, बात सुनो। आज आपके राज में वहां लोग हड़ताल पर बैठे हैं। पत्रकार हड़ताल पर बैठे हैं। वहां एक आदमी के भरोसे चल रहा है। मेरा यह निवेदन है कि वहां तत्काल कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था की जाये और डॉक्टर्स की व्यवस्था करके यह व्यवस्था की जाये। यह मंत्री जी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, इसके अलावा आज वहां अस्पताल वास्तव में 30 बैड का है, जर्जर अवस्था में वह सी.एच.सी. है। पूरी सी.एच.सी. जर्जर अवस्था में है उसका या तो जीर्णोद्धार कराया जाये या उसके पुनः निर्माण के लिए बजट दिया जाये यह भी मैं मांग करता हूं और 30 बैड से 50 बैड का हॉस्पिटल करने की भी मांग मैं आपके सामने रखता हूं। एक छापर कस्बा है जिसमें डॉक्टर की पांच पोस्ट है, दो डॉक्टर्स की पोस्ट खाली है। हालात यह है कि वहां भी पांच सौ मरीजों की ओ.पी.डी. है, लेकिन बैठने के लिए वहां फर्निचर नहीं है डॉक्टर्स के लिए वहां कुर्सी नहीं है कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि हमने एम.एल.ए. लैड से देने की बात कही लेकिन एम.एल.ए. लैड में हॉस्पिटल में फर्निचर अलाऊ नहीं हैं तो एम.एल.ए. लैड में अलाऊ कराया जाये तो हम हॉस्पिटल में फर्निचर दे देंगे। ऐसी स्थिति में विशेष तौर से मैं यह बात कहना चाहता हूं।

इसके अलावा पडियारा हमारी सी.एच.सी. है। उसमें तीन डॉक्टर हैं। अभी दो डॉक्टर ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः श्री हरलाल सहारण।

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): और एक डॉक्टर इसमें लगा हुआ है इसलिये मेरा यह निवेदन है, इसके अलावा मैं एक-दो बात और कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में ...। धन्यवाद।

श्री हरलाल सहारण (चूरू): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27 और 28 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। जिसके लिए स्वास्थ्य सेवा होनी बहुत जरूरी है और यह भी हर सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है और यह खुशी की बात भी है कि राजस्थान सरकार ने बजट 2025-26 में चिकित्सा क्षेत्र में नयी ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कई दूरदर्शी योजनाओं की घोषणा की है।

सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को, केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त करूंगा कि जिन्होंने केन्द्र के बजट में 2025-26 में करीब एक लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया। सेवायें मजबूत करने का लक्ष्य रखा है, इसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्य मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी को, माननीय चिकित्सा मंत्री जी को जिन्होंने सत्ता में आने के बाद बजट में पहले प्रदेश में सुविधा के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं, धरातल पर लागू करने का काम किया है। यह हर्ष की बात भी है कि मुख्य मंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत पैतीस लाख लोगों को चिकित्सा लाभ मिला है। सरकार ने बजट 2025-26 के पैरा संख्या 55 में आमजन को नि:शुल्क जांच, दवा हेतु 3,500 करोड़ रुपये के मुख्य मंत्री आयुष्मान आरोग्य कोष के गठन की घोषणा की, यह सराहनीय है। राज्य सरकार द्वारा बजट 2025-26 के पैरा संख्या 56 में 70 वर्ष की आयु से अधिक बुजुर्गों को घर पर नि:शुल्क दवा पहुंचाने की व्यवस्था, समस्त जिला चिकित्सालयों पर डाइबेटिक क्लिनिक खोलने की व्यवस्था, प्रदेश को टी.बी. मुक्त करने की, आंखों की जांच, नि:शुल्क चश्मे उपलब्ध कराने के लिए मां नेत्र बाऊचर योजना शुरू किये जाने की घोषणा की, निश्चित तौर यह योजना सफलतापूर्वक लागू होकर प्रदेशवासियों का जीवन बेहतर बनायेगी।

राज्य सरकार द्वारा बजट 2025-26 में पैरा संख्या 60 में 750 चिकित्सकों के, 1,500 पैरा मेडिकल कर्मियों के नये पद सृजित करने की घोषणा की है। नये चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी अस्पतालों में लगाने से स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मिलेगी।

इसी प्रकार राज्य सरकार ने बजट 2025-26 में पैरा संख्या 61 पर फिट इंडिया की तर्ज पर पचास करोड़ का प्रावधान कर फिट राजस्थान अभियान की घोषणा की है जो युवाओं, बुजुर्गों और हर आयु के लोगों को स्वास्थ्य और सक्रिय जीवन जीने की प्रेरणा करेंगे। राज्य सरकार ने बजट 2025-26 में पैरा संख्या 62 पर नवीन आयुष नीति लागू करने की घोषणा की जिसके लिए मैं राज्य सरकार को धन्यवाद दूंगा।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय को बजट घोषणा वर्ष 2025-26 में बिन्दु संख्या 63 में किये गये वित्तीय क्रम में जिलास्तर पर खाद्य सुरक्षा तथा औषधि नियंत्रक के अतिरिक्त कार्यालय खोले जाने हेतु पुराने जिले में दस तथा नये जिले में आठ में जिला स्तर पर सहायक औषधि नियंत्रक के नवीन पदों के सृजन हेतु बजट रिप्लाई में घोषणा करने का श्रम करें।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राज्य सरकार को जिन्होंने बजट 2025-26 में राज्य में खाद्य पदार्थ मिलावट रोकथाम प्रभावी नियंत्रण हेतु समस्त जिलों में चरणबद्ध रूप से प्रयोगशाला स्थापित करने की व्यवस्था की है। मैं निवेदन करूंगा कि चूरू जिले के मेडिकल कॉलेज में लाखों मरीज जीवन रेखा में हैं, प्रतिवर्ष लगभग आठ लाख मरीज आउटडोर में आते हैं जिनमें लगभग 3.5 लाख मरीज भर्ती होते हैं। इतने बड़े पैमाने पर आने वाले मरीजों की उचित जांच के लिए एम.आर.आई., डोपलर, टूडी, ईको जैसी आधुनिक मशीनें अति आवश्यक होंगी। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि रिप्लाई में चूरू में मेडिकल कॉलेज है, इसलिये घोषणा करें।

Kas/rtm/06.03.2025/17.10/3f

इसके अतिरिक्त हमारे मेडिकल कॉलेज में कुछ डाक्टरों की कमी है, वहां रिक्त पदों को भरने की भी कृपा करें।

सभापति महोदय, बजट 2025-26 पर रिप्लाई के दौरान मेरे विधान सभा क्षेत्र चूरू के आसलखेडी उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने की घोषणा के लिये मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि आपने मेरी मांग पूरी की है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को मेरे क्षेत्र की चिकित्सकीय समस्याओं से अवगत कराना चाहूंगा। हमारा चूरू मेडिकल कॉलेज 2018 में प्रारम्भ हुआ था लेकिन पिछले पांच साल कांग्रेस की सरकार ने वहां कभी ध्यान नहीं दिया कि बच्चों के साथ क्या अन्याय हो रहा है। एक कंपनी ने मेडिकल कॉलेज बनाई और आज भी वह अधूरी पड़ी है। वहां बच्चों के लिये न पंखा है, न एसी है न कूलर है। जहां राजस्थान में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, वहां तपती गर्मी में बच्चे पढ़ने जाते हैं। इसमें किसकी कमी रही, इसकी जांच कराई जाये और उस मेडिकल कॉलेज में बच्चों की व्यवस्था की जाये।

इसके साथ ही मैं मांग करता हूं कि मेरे ग्राम खासोली और जोड़ी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाये। सभापति महोदय, राज्य सरकार द्वारा और भी बहुत से अच्छे कार्य किये गये हैं। आज मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना प्रदेशवासियों के लिये वरदान साबित हो रही है। इस योजना ने सभी जरूरतमंदों को निशुल्क और बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करा कर वास्तविक रूप से जनकल्याण को प्राथमिकता दी है। अब मरीजों को गुणवत्ता का इलाज मिल रहा है। सरकारी और निजी अस्पतालों में निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिली है। मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य सरकार की जनहितैषी नीतियों के कारण कोई भी गरीब इलाज से वंचित नहीं रहेगा। डबल इंजन की सरकार में हमारा राजस्थान स्वास्थ्य सेवाओं में अग्रणी राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि चूरू मेडिकल कॉलेज जो 2018 में शुरू हुआ था, आज वह अधूरा पडा है, उसे पूरा कराने की कृपा करें और वहां जो डाक्टरों की कमी है, उसको पूरर कराएं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री सुरेश गुर्जर।

श्री सुरेश गुर्जर (खानपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे अनुदान की मांग 27, 28 चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। आज सदन में सवेरे से ही पक्ष और विपक्ष के साथी चिकित्सा और स्वास्थ्य पर सार्थक चर्चा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस चर्चा से अमृत निकले और किस तरह से पक्ष और विपक्ष के साथ चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाये, यह मेरा मानना है। यह हर आदमी के जीवन से जुड़ा विषय है। चाहे आपकी सरकार रही हो, चाहे हमारी सरकार हो, हम

सभी का फर्ज बनता है कि आम आदमी को, एक गरीब आदमी को, गांव में रहने वाले व्यक्ति को किस तरह से अच्छी चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराएं। भजन लाल जी सरकार का यह दूसरा बजट है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में अभी तक दोनों बजटों में मेरे खानपुर विधान सभा क्षेत्र का एक बार भी नाम नहीं आया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पांच सीएचसी हैं, जिसमें सबसे बड़ी सीएचसी खानपुर है। खानपुर के आस-पास 200-300 गांव आते हैं। वहां प्रतिदिन सीएचसी की ओपीडी 300-400 की है। वहां पर 50 बैड स्वीकृत हैं। अभी सरकार ने सीएचसी के लिये नये भवन के लिए दो हैक्टेयर भूमि भी आवंटित कर दी है। मंत्री महोदय, मेरी आपसे मांग है कि खानपुर मेरे विधान सभा क्षेत्र की सबसे बड़ी सीएचसी है, उसको आप उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की कृपा करें। साथ ही खानपुर में ब्लड स्टोरेज यूनिट की भी मैं आपसे मांग करता हूं। लंबे समय से चिकित्सकों के वहां पर रिक्त पद चल रहे हैं। स्त्री रोग विशेषज्ञ, जनरल फिजिशियन, शिशु रोग विशेषज्ञ के पदों को भी भरने की मैं आपसे मांग करता हूं।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र खानपुर मुख्यालय से दो मेगा हाईवे गुजरते हैं, दर्रा मेगा हाईवे और बारां-झालावाड मेगा हाईवे। वहां पर आये दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। ऐक्सीडेंट होने पर मरीज को झालावाड़ जाने में करीब एक से डेढ़ घंटा लग जाता है, 40-50 किलोमीटर की दूरी है। इसलिए खानपुर मुख्यालय पर ट्रोमा सेंटर बनाने की मैं आपसे मांग करता हूं।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र का दूसरा ब्लॉक बकानी ब्लॉक है। वहां पर 40 वर्षों से सीएचसी संचालित है। बकानी वाला ऐरिया मध्य प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है। यहां पर मध्य प्रदेश के लोग भी इलाज के लिये आते हैं और बकानी के आस-पास 100-150 गांव हैं। इसकी ओपीडी 200-300 प्रतिदिन है। वहां पर 30 बैड का हॉस्पिटल स्वीकृत है। मेरी आपसे मांग है कि बकानी को सैटेलाइट हॉस्पिटल बनाने की कृपा करें और वहां पर डायलेसिस यूनिट भी स्थापित की जाये। बकानी सीएचसी में रिक्त पडे पद, स्त्री रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन, सर्जन के पदों को भी भरे जाने की मैं आपसे मांग करता हूं।

सीएचसी रटलाई, पनवाद, सारोला में 30 बैड स्वीकृत हैं। वहां पर 30 बैड से बढ़ाकर 75 बैड करने की मैं आपसे मांग करता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र की पांचों सीएचसी में एक भी मोर्चरी नहीं है। मेरी आपसे मांग है कि पांचों सीएचसी में आप मोर्चरी की भी घोषणा करें। मेरे विधान सभा क्षेत्र के दो बड़े कस्बे, खानपुर-बकानी में जीवन रक्षक प्रणाली आधारित एम्बुलेंस की भी मैं आपसे मांग करता हूं। पीएचसी हरिगढ़, मंडावर और रीछवा को सीएचसी में क्रमोन्नत करने की मैं आपसे मांग करता हूं। हमारे पूरे ग्रामीण चिकित्सा की सबसे छोटी इकाई आशा सहयोगिनी को हम हर काम में लगाते हैं। सच्चाई तो यह है कि चाहे इंजेक्शन लगाना हो, ड्रिप लगानी हो, पर्ची बनानी हो, स्वास्थ्य कार्ड वितरण करने हो, योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना हो, अब तक जो आयुष्मान कार्ड बनाने का काम ई-मित्र से करते थे, वो

भी उनसे बनवा रहे हैं। मेरी सरकार से मांग है कि उनका मानदेय बढ़ाया जाये और चिकित्सा के रिक्त पदों को भरा जाये। सभापति महोदय, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री ताराचन्द जैन।

श्री ताराचन्द जैन (उदयपुर): सभापति महोदय, मुझे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की मांग संख्या 27, 28 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार। अभी हमारे कांग्रेस के सम्माननीय सदस्यों ने कोरोना काल को लेकर कई बातें कहीं। कोरोना काल के वो दिन आज भी याद है जब गहलोत साहब और वो, नाम भूल गया मैं, दोनों एक दूसरे को लत्थी लगाने में लगे हुए थे। कोरोना काल में जनता में विश्वास बना रहे, इसके लिये हर महीने-पन्द्रह दिन में प्रधान मंत्री जी संबोधित करते थे। हम सबने अपने जीवन में पहला ऐसा समय देखा होगा कि विदेशों से जहाजों में कंटेनर के कंटेनर आते थे। देश में जन हानि कम हो, इसके लिये पहला लॉक डाउन किया, उस दिन हमारे कांग्रेस के लोग उसमें नुक्स निकालने में लग गये कि बिना सोचे-समझे लॉकडाउन कर दिया है और उसका परिणाम यह हुआ कि 140 करोड़ की जनता में 10-20 लाख लोगों ने ही अपना जीवन समाप्त किया होगा।

Msk/rtm/05.03.25/1720/3g

अमेरिका जिसे सबसे बड़ा उन्नत देश है, उसके लिए मेरा अंदाजा है, पक्का आंकड़ा मुझे नहीं मालूम, पर 25-30 लाख से ज्यादा की हानि हुई। यह आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की सूझबूझ का परिचय है। देश में जब कोरोना वैक्सीन लग रही थी तो ये कह रहे थे कि मोदी वैक्सीन है। सब कांग्रेस वाले चुपके-चुपके वैक्सीन लगवाते थे और बाहर आकर कहते थे कि यह मोदी जी की वैक्सीन है।

(समय: बजे)

(श्री फूल सिंह मीणा, सभापति, पदासीन)

जब अमरीका जैसे देश में दो-दो ढ़ाई-ढ़ाई हजार रुपये में वैक्सीन मिलती थी। देश की 100 करोड़ जनता ने वैक्सीन लगाकर अपनी जीवन यात्रा सुनिश्चित की। यह कोरोना कालखण्ड में सूझबूझ का प्रतीक है। कोरोना काल की वजह से जैसा कि कहते हैं, हमारे भजन लाल जी ने कहा कि आप तो 25 साल तक भजन गाओ। नरेन्द्र मोदी जी की उसी सोच-समझ से जनता का विश्वास इतना प्राप्त किया है कि वास्तव में 25 वर्ष तक भजन ही गाने पड़ेंगे। ...(व्यवधान)... मैं बोल रहा हूं। थोड़ा तो सुना करो। कम से कम चार साल सुनना है।

उदयपुर संभाग का जो मुख्य चिकित्सालय है, वह महाराणा भूपालसिंह के समय से स्थित है। पिछली कांग्रेस सरकार के समय 600 बेड का एक महिला चिकित्सालय, पन्नाधाय चिकित्सालय, उस चिकित्सालय की बिना सोचे-समझे उस समय दो मंजिलें ऊपर बना दीं। 100 करोड़ से ऊपर की लागत आयी। वह बिल्डिंग उद्घाटन के पहले धराशायी और नाकाम

घोषित कर दी है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आपने पिछले बजट के अन्दर घोषणा की थी कि 60 करोड़ रुपये डीएमएफटी से देंगे और 60 करोड़ रुपये यूआईटी से दिलवायेंगे। बीच में पत्रावली चली, उस पत्रावली के पत्र मेरे पास मौजूद हैं। सरकार की सहमति बन गयी है कि हमको सौ करोड़ रुपये फिर देने हैं, कांग्रेस काल की सज़ा हमें भुगतनी है। मेरा माननीय चिकित्सा मंत्री जी से आग्रह है कि 120 करोड़ रुपये आप, राज्य सरकार के ऊपर भार नहीं आयेगा। आपको केवल निर्देश देना है, बजट के अन्दर अगर आप घोषित करेंगे तो निश्चित रूप से वह काम अतिशीघ्र होगा। 600 का जो महिला हॉस्पिटल है, उसमें आज, कभी इधर लगाते हैं, कभी उधर लगाते हैं, मेरा आग्रह है कि इस बजट में घोषित करें।

उदयपुर संभाग के 9 जिले, उसके साथ मंदसौर, नीचम, उज्जैन, मध्यप्रदेश के कई जिले हैं, वहां से उदयपुर में आते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि उदयपुर शहर में एक ही एमआरआई मशीन है, उसकी लंबी वैटिंग है। लंबी वैटिंग की इंतजार करना पड़ता है। आप दो एमआरआई मशीनों की घोषणा करें, उसके साथ-साथ यूएसजी, एड्यूल्प एनर्जी मशीन, जिसकी 50 करोड़ की लागत है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसकी भी घोषणा इसके साथ करने का कष्ट करें। बर्न वार्ड के अन्दर हालत यह है, मैं आपको सही-सही घटना बता रहा हूं। 1998 में भैरोंसिंह जी आये, उससे पहले उस वार्ड में गर्मी के अन्दर, जो मरीज 60 परसेंट से ऊपर जल जाता था, कीड़े आ जाते थे, तड़पता था। मैंने स्वयं व्यक्तिगत रूप से दो एसी दिये थे। मैंने उस समय जो एसी दिये थे, वे अब खराब हो चुके हैं। मैं सरकार की मांग करूंगा कि वे एसी लगवाये जायेंगे। अगर विधायक कोटे से भी प्रावधान का नियम है तो मैं स्वयं भी विधायक कोटे से देने का प्रयास करूंगा।

इसी तरह निवेदन करूंगा कि उदयपुर हॉस्पिटल में निर्माण की क्षमता में 35 परसेंट का नॉर्म्स है, उसमें 35 परसेंट क्षेत्र में ही निर्माण कर सकते हैं। 34.9 परसेंट में निर्माण कार्य की पूर्ति हो चुकी है। अब 0.10 परसेंट में ही निर्माण कर सकते हैं। इन हॉस्पीटलों का इतना विस्तार हो गया है। मेरे पास 25 वर्ष के भूल से। उदयपुर की जनता ने एक बार कांग्रेस कालखण्ड से, वे पत्रावलियां मेरे पास मौजूद हैं। मैं सरकार से मांग करूंगा कि पास में ही पशु चिकित्सालय है। वह शहर के मध्य है। बाहर से ट्रैक्टरों में पशुओं को लेकर आते हैं। टीबी हॉस्पिटल है, वहां 59 एकड़ जमीन उपलब्ध है। सरकार की कई पत्रावलियां मौजूद हैं, जिनमें आपसी सहमति बन गयी है। उच्च अधिकारियों को भेजकर इस पशु चिकित्सालय को आप बड़ी में शिफ्ट में करें और इस जगह को उदयपुर के जनरल हॉस्पिटल के साथ सम्मिलित करेंगे तो कम से कम आगामी 20-25 वर्षों की पूर्ति होगी। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप इसके लिए कुछ न कुछ घोषणा करें।

हमारे उदयपुर शहर के अन्दर दो सैटेलाइट चिकित्सालय हैं, एक सुंदरसिंह भण्डारी चिकित्सालय है, उसके अन्दर लगभग 200 बेड, एकदम बढ़िया हॉस्पिटल है, उसमें ओपीडी भी है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बस दो मिनट में खतम कर रहा हूं। लेकिन वहां पर इतने पद रिक्त हैं। 120 पद रिक्त हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि उन पदों की घोषणा करें। खेमराज कटाणा हॉस्पिटल नाम तो रखा है। इन दोनों हॉस्पिटलों की ओपीडी 2 हजार के लगभग है। अगर इसके अन्दर पर्याप्त स्टाफ आ गया तो निश्चित रूप से जनरल हॉस्पिटल उदयपुर की आधी समस्याओं का निदान होगा। अंत में, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उदयपुर हॉस्पिटल, यहां कैंसर के रोगी 20 हजार के लगभग हैं। इसको एसएमएस की तर्ज पर रीजनल कैंसर सेंटर की स्थापना करें। क्योंकि उसकी मात्र 90 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। मेरा आपसे आग्रह है कि संसाधनों के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है और जनता में आत्मविश्वास पैदा हुआ है। पिछले समय में, मैं फिर चर्चा करूंगा। ये कांग्रेस वाले कहते हैं। हमने तो उस समय पांच लाख फ्री किया है। मैं सत्य घटना बताकर अपनी बात खतम करूंगा। उस समय कई मरीज मेरे पास आते थे कि साहब आप गीतांजलि हॉस्पिटल में फोन कर दो, मेरे हार्ट का ऑपरेशन हो जाये। मैंने कहा, जाओ, तुम्हारा तो पांच लाख तक फ्री है। उसने कहा कि छह महीने लगेंगे। फिर मैंने मालिक से बात की। मैंने कहा कि क्या मामला है, इसका ऑपरेशन कर दो। उसने कहा, साहब कहां ऑपरेशन करेंगे। जिस दिन हमारे पास कोई नहीं होता है, उस दिन ही हम सरकारी पेशेंट का इलाज करते हैं। ऐसा ही हाल ऑर्थोपैडिक का था। इस सरकार ने घोषणा नहीं की है। आम उपभोक्ता को समुचित इलाज की गारन्टी दी है। मेरा आपसे अन्त में यही निवेदन है कि मैंने जो मांगें रखी हैं, उनकी मैं निश्चित रूप से पत्रावली माननीय मंत्री महोदय को दूंगा। उसका अवलोकन कराकर आप निश्चित रूप से इन मांगों को स्वीकार करेंगे। धन्यवाद, जय भारत, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री वीरेन्द्र जी चौधरी। पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिये।

श्री वीरेन्द्र सिंह (दांता रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27 व 28 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। जब से यह बजट की बहस चल रही है, जिसको भी देखो। उसने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने यह किया, पूर्ववर्ती सरकार ने यह नहीं किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि डबल इंजन की सरकार, सवा साल से आपने क्या किया, यह भी बताने का कष्ट करते तो ज्यादा अच्छा रहता। पिछली कांग्रेस की सरकार ने आम जनता को जो फ्री दवाइयां दी हैं। महंगी दवाइयां जो आदमी नहीं खरीद सकता था। अच्छे अस्पताल में भर्ती नहीं हो सकता था। वही पूर्ववर्ती सरकार ने उनके इलाज की व्यवस्था की। विश्व भर में जब कोरोना की फैली थी, उससे हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने डटकर मुकाबला किया और शानदार तरीके से राजस्थान की जनता को इस कोरोना बीमारी से दूर करने का प्रयास किया। आपकी मोदी सरकार ने आम आदमी से, पढ़े-लिखे आदमी, इंजीनियर से, डॉक्टर से यह अपील की कि आज के जमाने में आपको थाली बजानी है, आपको लाइट जलानी है।

mdp/rtm/06.03.25/17:30/3h

जिससे ये कोरोना भाग जाए। जो वेक्सीन आप लेकर आए हैं, अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे कि 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगायी। आज जब हम गांवों में जाते हैं, निश्चित रूप से आज जो हर्ट फेलियर हो रहा है, 15 साल के बच्चे का, 20 साल के बच्चे का, कई बार आप टी.वी. पर न्यूज़ देखते हैं कि स्टेज पर डांस करते-करते कोई गिर रहा है, निश्चित रूप से गांव में यह मानसिकता है, उसको बनाने वाली कंपनी के मालिक ने इस बात को स्वीकार किया कि जल्दी में बनाया हुआ वेक्सनी है। उसमें कुछ कमी है। उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं, जो हमें आज भुगतने पड़ रहे हैं।

आपसे एक मांग करूंगा कि मेरे रामगढ़ में जो हैडक्वार्टर है हमारी तहसील का, उसमें एक सीएचसी खुलवाने की कृपा करें। पिछली सरकार में हमारे दांता रामगढ़ क्षेत्र में काफी काम हुए। चिकित्सा को लेकर पलसाना में ट्रोमा खुला, रानोली में सीएचसी खुली, भाय में सीएचसी खुली, उप जिला अस्पताल खुला खाटू श्याम जी में, लेकिन आपकी सरकार पता नहीं दांता रामगढ़ की जनता से क्या खुंदस खाकर बैठी है, मुझे तो लगता है कि जब से भाजपा का 1980 में उदय हुआ, तब से लेकर आज तक दांता रामगढ़ में 1980 से लेकर आज तक आपका कमल नहीं खिला, शायद इसी मानसिकता से आप दांता रामगढ़ में विकास कार्य नहीं करना चाहते। धर्म और चिकित्सा को राजनीति से दूर रखना चाहिए। कुम्भ मेले में सरकार ने काफी खर्चा किया। आपने राम मन्दिर में बसें लगायीं, ट्रेनें लगायीं फ्री में लगायीं, लेकिन हमारे खाटू श्याम जी में दर्शनों के लिए आज भी अपने आप लोग आते हैं। आस्था से आते हैं। वहां पर हमने उप जिला अस्पताल खुलवाया था। वह वर्ष 2023-24 के बजट में खुला। उसका 2023-24 के अन्दर टेंडर हो गया। बजट अलॉट हो गया, लेकिन आज 2025 का मार्च चल रहा है, वह काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। वह काम नहीं शुरू होने की एकमात्र वजह, एक पत्र है जो सभापति महोदय, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये आपके मिशन डायरेक्टर है जितेन्द्र कुमार सोनी, इन्होंने एक चिट्ठी लिखी है कि श्री गजानंद जी कुमावत, भाजपा प्रत्याशी, ये चिट्ठी लिखी है इन्होंने 22/05/24 को, ये भाजपा प्रत्याशी, प्रत्याशी क्या पोस्ट होती है। प्रत्याशी सिर्फ चुनाव प्रक्रिया तक ही प्रत्याशी होता है। चुनाव के 6 महीने बाद में भी प्रत्याशी अगर कोई पोस्ट है तो कृपया मुझे बताया जावे। वे लिखते हैं उनके पत्र द्वारा उपरोक्त विषय में लेख है कि उप जिला अस्पताल, जिसमें आवंटित भूमि के साथ, आवंटित भूमि के मालिक का कब्जा है। मालिक मैं आपको बता दूं इसका मालिक नगर पालिका है।

श्री सभापति: प्लीज, बात समाप्त कीजिए।

श्री वीरेन्द्र सिंह (दांता रामगढ़): बस दो मिनट में इसी बात पर, सारी बातें मैंने शोर्ट की है, सिर्फ एक बात पर आ रहा हूं। खाटू श्याम जी की नगर पालिका ने, पूरे उसके बोर्ड में, सारे सदस्य चाहे कांग्रेस के हों, चाहे भाजपा के हों, और वह बोर्ड भाजपा का है।

श्री सभापति: श्रीमती प्रियंका जी चौधरी।

श्री वीरेन्द्र सिंह (दांता रामगढ़): सर, मैं जो कहना चाहता हूं, एक मिनट में खतम

करूंगा।

श्री सभापतिः अंकित नहीं होगा। पांच मिनट दिया है। अंकित नहीं होगा।

श्री वीरेन्द्र सिंह (दांता रामगढ़): 000

डॉ. प्रियंका चौधरी (बाड़मेर): धन्यवाद, सभापति महोदय, अपनी बात रखने के लिए मुझे समय दिया।

श्री वीरेन्द्र सिंह (दांता रामगढ़): 000

श्री सभापतिः एक मिनट पहले घंटी बजा दी थी। अंकित नहीं होगा।

श्री वीरेन्द्र सिंह (दांता रामगढ़): 000

डॉ. प्रियंका चौधरी (बाड़मेर): मैं बहुत कम समय लूंगी। मैं धन्यवाद दूंगी आदरणीय मुख्य मंत्री जी को, जिन्होंने मां योजना की शुरूआत की। 35 लाख व्यक्तियों को चिकित्सा का लाभ प्राप्त हुआ और मां कोष गठित किया 3 हजार 500 करोड़ का। फिट इंडिया की तर्ज पर फिट राजस्थान की कल्पना की है। धन्यवाद दूंगी नशा मुक्ति केन्द्र के लिए, मुख्य मंत्री बाल संबल योजना के लिए, लेकिन मेरी दुविधा आज कुछ और है, सभापति महोदय, क्योंकि आदरणीय मुख्य मंत्री जी, प्रधान मंत्री जी का, हम सब जानते हैं कि उनका संकल्प है कि स्वस्थ भारत होना चाहिए और स्वस्थ राजस्थान होना चाहिए। इसीलिए विभिन्न योजनाएं बनायी गयी हैं। इन योजनाओं की क्रियान्विति कैसे संभव है, जब न हमारे पास पूरे संसाधन हैं, न चिकित्सक हैं, न उनके नीचे नर्सिंगकर्मी हैं, न स्टॉफ है।

केवल योजनाएं बनाने से, आज मेरा मन बहुत दुःखी है, क्योंकि मैं भी एक डाक्टर हूं और मैं अगर मेरे बाड़मेर की बात करूं तो पिछले 07 सालों से जो बाड़मेर हॉस्पिटल की स्थित हुई है, मैं कई बार संज्ञान में लेकर भी आयी। बाड़मेर हॉस्पिटल की ओपीडी 3 हजार की है, जहां डेली 500 सोनोग्राफी होती है और मशीनें हैं सिर्फ 3, डाक्टर सिर्फ 200 सोनेग्राफी कर पाते हैं और 300 सोनोग्राफी को एक महीने-डेढ़ महीने की वेटिंग देनी पड़ती है, या फिर बाहर भेजना पड़ता है। सीटी स्कैन मशीनें पीपीपी मोड पर हैं जो 5 साल से पुरानी हैं, बंद पड़ी हैं। आज के दिन भी, आज भी न्यूजपेपर में हेडलाइन है कि वहां पर डेढ़ किलोमीटर दूर उस वृद्धा महिला को ले जाना पडा, उसके चोट लगी। एमआरआई मशीन की बात करूं तो 2019-20 के अन्दर एमआरआई मशीन की घोषणा की गयी थी, राजमेस के अधीन मेडिकल कॉलेज में। चार बार टेंडर हुए, निरस्त हुए, आज दिन तक एमआरआई मशीन लगी नहीं है। कैथलेब है, 2022-23 के बजट में घोषणा हुई 650 लाख की, वित्तीय स्वीकृति जारी हुई, दो बार टेंडर हुए, लेकिन कैंसिल हुए। हमारा जो बाड़मेर का मेडिकल कॉलेज है, वह इकलौता, जो 17 राजमेस के मेडिकल कॉलेज हैं, हमारा बाड़मेर का इकलौता मेडिकल कॉलेज है, जहां पर कैथलेब की सुविधा नहीं है। वहां कार्डियोलोजिस्ट है पिछले दो साल से, लेकिन मरीजों को रैफर करना पड़ता है 200 किलोमीटर दूर जोधपुर में। बाड़मेर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की हालत देखिए आप, आदरणीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी यहां पर विराजे हैं, मैं उनके ध्यान में लाना चाहूंगी कि 100 बीघा जमीन पर 191 करोड़ की

लागत से बनने वाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसका निर्माण कार्य 5 दिसम्बर, 2023 तक पूरा होना था, लेकिन आज उसकी स्थिति क्या है? मैं आपसे मांग करती हूं कि एक कमेटी बनाकर उसके निर्माण की जांच करवायी जाए। आज उस जगह की क्या हालत है, आप चैक कीजिए। वहां जो बच्चे हैं, 2019 में पहला बैच शुरू हुआ था। उन बच्चों के लिए हॉस्टल नहीं बना और जैसा हॉस्टल है, उसमें उनके लिए सुविधा नहीं है। वह नीचे गद्दा लगाकर वहां पर पढ़ाई करने के लिए मजबूर है।

नर्सिंग कॉलेज की जो स्थिति है, नर्सिंग कॉलेज के लिए भी कक्षा कक्ष नहीं है। एक दिन के अंतराल में वहां नर्सिंग ट्यूटर्स भी, डीएनएमटीसी और नर्सिंग बी.एससी. की कक्षाएं संचालित कर रहे हैं। बाड़मेर हॉस्पिटल में सिर्फ 250 बेड हैं और उसके अन्दर करीब 500 बेड की सुविधा है। एक बेड पर दो महिलाएं सोने को मजबूर है। मेरी हाथ जोड़कर करबद्ध विनती है चिकित्सा मंत्री जी से कि बाड़मेर हॉस्पिटल, बाड़मेर मेडिकल कॉलेज, एक टीम गठित कीजिए, वहां जांच केलिए भेजिए। वहां जो अनियमितताएं हो रही हैं, उनकी जांच करवाइए, क्योंकि यह जनता का पैसा है। यह हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। बाड़मेर के अन्दर इतनी दूर लोग बैठे हैं, लेकिन आज भी उनको रैफर करने की स्थिति आती है।

मैं मांग करना चाहूंगी कि आपने मैस जो पद सृजित किये हैं, चिकित्सकों के, मैं उसके लिए धन्यवाद देती हूं, लेकिन 20 साल से जो 100 चिकित्सक एडहॉक पर सेवाएं दे रहे हैं, मेरी आपसे विनती रहेगी कि नियमों में शिथिलता देकर इनको स्थायी रूप में वहां लगाना चाहिए। जो दंत चिकित्सक हैं, उनकी रिटायरमेंट एज भी अन्य सेवारत चिकित्सकों की तरह 62 साल तक करनी चाहिए। जो यूटीबी के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने बहुत मुश्किल समय में, कोविड जैसी महामारी में हमें सेवाएं दी थीं, अभी नर्सिंग ऑफिसर्स के हजारों पद खाली हैं, उनकी सेवाएं फरवरी, 2025 को समाप्त हो गयी। मेरा मान्यवर जी से निवेदन है कि यूटीबी, जीएनएम की सेवा वृद्धि मार्च 2026 तक करने की कृपा करावें ताकि आने वाले समय में वे भी अपनी नियमित सेवाएं दे पाएं। मैं विश्वास करती हूं कि आदरणीय चिकित्सा मंत्री जी, एक सीमातं जिले के ऊपर वहां जो दूर ढाणियों में बैठे लोग हैं, उनके ऊपर पूरा ध्यान देंगे।

श्री सभापति: समाप्त कीजिए।

डॉ. प्रियंका चौधरी (बाड़मेर): एक पीएचसी पर कम से कम दो डाक्टर्स होने चाहिए, क्योंकि अगर एक डाक्टर है तो प्रशासक भी वही है, क्लर्क भी वही है, कुछ लिखना है तो भी वही है।

श्री सभापति: श्री राधेश्याम बैरवा।

डॉ. प्रियंका चौधरी (बाड़मेर): मैं आपसे आग्रह करूंगी की बाड़मेर जिले पर आप प्लीज विशेष ध्यान दें। धन्यवाद।

श्री राधेश्याम बैरवा (बारां-अटरू): माननीय सभापति महोदय, आपने आज मांग संख्या 27 व 28 चिकित्सा एंव स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा पर सदन में मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। राजस्थान एक विशाल और विविधतापूर्ण राज्य है, जहां शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की अलग-अलग चुनौतियां हैं। हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री महोदय ने इस बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किया है। लेकिन हमें यह भी निश्चित करना होगा कि इन योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।

Ans/rtm 17.40 3j 06.03.2025

माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब जनता के दुख को पहचान कर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू किया। आज हम देख रहे हैं कि कैसे गरीब आदमी भी इस योजना के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं का उचित लाभ ले पा रहा है। राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के माध्यम से गरीब जनता के ऊपर पड़ने वाले बोझ को कम करने का काम किया है। माननीय वित्त मंत्री महोदया ने बजट में प्रदेश में जन-जन के लिए पहला सुख- निरोगी काया के ध्येय की पूर्ति करती मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अन्तर्गत आमजन की निःशुल्क जाँच एवं दवा हेतु 3 हजार 500 करोड़ रुपये का मां-कोष' गठित किए जाने की घोषणा की है, जो स्वागत योग्य कदम है।

हमने देखा है कि कोविड-19 महामारी के बाद स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। इस बजट में सरकार ने मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने, नए स्वास्थ्य केंद्र खोलने, अस्पतालों की बेड क्षमता में वृद्धि करने और डिजिटल हैल्थ सेवाओं को बढ़ावा देने की बात कही है। मैं इसका स्वागत करता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र बारां-अटरू की बड़ी आबादी ग्रामीण इलाक़ों में निवास करती है और किसी भी बड़ी बीमारी के लिए बारां जिला अस्पताल पर निर्भर है, बारां जिला अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट के पद सेंक्शन ना होने के कारण, हार्ट अटैक जैसी इमरजेंसी की स्थिति में ठीक से इलाज नहीं मिल पाता। इन मरीजों को तुरंत कोटा रेफर किया जाता है, जो लगभग 70 किलोमीटर है और कई बार यह मरीज कोटा पहुँचते पहुँचते रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने बजट के माध्यम से 750 चिकित्सकों और 1500 पेरा मेडिकल कार्मिकों के पद सृजित करने की घोषणा की है तथा साथ ही निवेदन करता हूं कि बारां जिला अस्पताल के लिए भी हृदय रोग और न्यूरो चिकित्सक के पद सेंक्शन किए जाएं और डॉक्टरों की नियुक्ति की जाए, इसके साथ ही बारां जिला अस्पताल में ट्रौमा सेंटर के लिए बिल्डिंग बन गई है, लेकिन उपकरण अभी उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। मेरा अनुरोध है कि जिला अस्पताल के लिए ट्रोमा सेंटर के उपकरणों के साथ-साथ एमआरई आदि उपकरण भी उपलब्ध कराए जाए। इसके साथ ही 108 एम्बुलेंस सेवाओं की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि दूरदराज के गाँवों में भी मरीजों को समय पर चिकित्सा सहायता मिल सके। मेरा यह भी अनुरोध है कि ज़िले के

अन्य मुख्य स्वास्थ्य केंद्रों अटरू और कवाई में भी डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जाए, जिससे जमीनी स्तर तक स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि हो और लोगों को जिला अस्पताल के चक्कर ना काटने पड़े। साथ ही मोटपुर के पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं, जिनकी वजह से बारां मेडिकल कालेज 100 सीटों के साथ आने वाले सत्र में प्रारंभ होने जा रहा है। साथ ही आशा भी करता हूं कि इसके लिए सरकार की ओर से प्रोफेसरों और अन्य सुविधाओं की कमी ना रहे, जिससे छात्र व ज़िले के नागरिक सभी इसका लाभ ले पाएं।

श्री सभापतिः प्लीज सदस्य, इधर होकर। इधर होकर।

श्री राधेश्याम बैरवा (बारां-अटरू): मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में योग की महत्ता को फिर से स्थापित करने का काम किया और 2014 में सरकार बनाने के बाद आयुष मंत्रालय की शुरुआत की। आज भजनलाल जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार ने भी प्रदेश में नवीन आयुष नीति लाने की घोषणा की है तथा पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से आयुष्मान आदर्श ग्राम घोषित कर 11 लाख की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है। यह सरकार की इस क्षेत्र के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

माननीय सभापति महोदय, गाय हमारी सनातन संस्कृति का सबसे अहम हिस्सा है, हम इसकी पूजा करते हैं, इसलिए मेरा अनुरोध है कि सभी जिला स्तरीय पशु चिकित्सालयों में गोवंश की देखभाल और इलाज के लिए एक अलग से इकाई की स्थापना की जाए, ताकि इलाज में देरी से बचा जा सके। बारां जिला पशु चिकित्सालय में भी सभी अत्याधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था के लिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, लगातार यह देखने में आता है कि ज़िले के वरिष्ठ अधिकारी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को जमीनी स्तर पर ठीक से प्रचारित नहीं करते और दूसरी राजनीतिक गतिविधियों में उनका ज्यादा ध्यान रहता है, इस वजह से आम नागरिकों को इन योजनाओं का ठीक से लाभ नहीं मिल पाता, मेरा सरकार से अनुरोध है कि ऐसे अधिकारियों पर सरकार ध्यान दे, ताकि आम नागरिकों को इन योजनाओं का पूरा लाभ मिल पाए।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के हर नागरिक को अच्छा स्वास्थ्य मिलना चाहिए। यह केवल सरकार की नहीं, बल्कि हम सभी जनप्रतिनिधियों की भी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए काम करें। स्वस्थ राजस्थान, समृद्ध राजस्थान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा।

मैं इस बजट में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्रालय की माँगों और अनुदानों का समर्थन करता हूँ, और सरकार से आशा करता हूँ कि हमारे क्षेत्र की ज़रूरतों को भी इसी तरह से पूरा

किया जाएगा। राजस्थान, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में विकास की और अग्रसर है और आने वाला समय राजस्थान का है।

हमारे लोकप्रिय प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने कोविड़-19 में पूरे भारत में जिस प्रकार प्रयास किया और भारत में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाई। हम आज माननीय प्रधान मंत्री जी के उच्च विचारों से यहां मौजूद है। कोविड-19 में सबके वैक्सीन लगने से हम सबको लाभ मिला।

में पुनः माननीय सभापति महोदय आपको धन्यवाद देता हूं, जिन्होने सदन में मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। धन्यवाद। जय हिन्द। जय राजस्थान।

श्री सभापति: श्री सुरेश जी मोदी।

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। पहला सुख निरोगी काया, यह कोट बिना सरकार के सहयोग से संभव नहीं है। पिछली कांग्रेस सरकार ने जनता के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो प्रयास किये वह किसी से छिपे हुए नहीं है। चिरंजीवी योजना का दायरा बढ़ाकर उसको सफलता से लागू कर, पिछली सरकार ने अच्छा काम किया। हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐतिहासिक फैसला कांग्रेस सरकार ने किया, उसके दूरगामी परिणाम आएंगे। राजस्थान में आने वाले समय में डॉक्टर्स की समस्या नहीं रहेगी।

राज्य के नागरिकों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। अतः सरकार को बिना भेदभाव किये सभी क्षेत्रों में, मंत्री जी बिना भेदभाव किये सभी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना चाहिए।

कांग्रेस कार्यकाल में मेरे विधान सभा क्षेत्र में, हर बार जब बजट आता था तो स्वास्थ्य सुधार के लिए बड़ी-बड़ी सौग़ातें मिलती थीं। कभी जिला अस्पताल मिलता था, कभी मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल मिलता था, सीएचसी, पीएचसी मिलती थी, सब सेंटर्स मिलते थे। मुझे बड़ा दुख है कि आपने स्वास्थ्य का जो बजट पेश किया, उसमें केवल एक ट्रोमा सेंटर की पुरानी घोषणा को नया रंग देकर आपने पेश किया।

पिछले कुछ समय से चारों तरफ, कोविड वेक्सीन लगने के पश्चात हार्ट अटैक औ लक़वे के काफी मामले आ रहे हैं। इसी प्रकार कैंसर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तो यह रोग युवाओं को भी चपेट में ले रहा है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इन रोगों के मरीजों की संख्या अचानक बढ़ जाने के कारण इसकी जांच के लिए डॉक्टर्स की एक कमेटी बनाई जाए जो इसकी जांच करेंं। एक उच्च स्तरीय कमेटी बनायें और आवश्यक रूप से इस ओर ध्यान दें ताकि भविष्य में इन रोगों की रोकथाम हो सके।

VPS-RTM-06.03.2025-17.50-3k

बैठे-बैठे देखते रहने से कुछ नहीं होने वाला है। हमारे परिजन यूं ही बेमौत मारे जाएंगे। 2022 में कैंसर से राज्य में लगभग 41 हजार लोगों की मौत हुई और कोविड के बाद

अचानक बढ़े हार्ट अटैक के मामलों को देखकर हमारी कांग्रेस सरकार ने पोस्ट कोविड रिसर्च के लिए आर.यू.एच.एस. में इंस्टीट्यूट बनाने के लिए 125 करोड़ रुपये का बजट दिया था परंतु नई सरकार ने इसका काम रोक दिया। अगर यह इंस्टीट्यूट बनता तो पता चलता कि ऐसे हार्ट अटैक की वजह क्या है? मेरा आपसे यह निवेदन है कि कृपया, इस ओर ध्यान दें और आर.यू.एच.एस. में इस इंस्टीट्यूट को चालू करें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र नीम का थाना में जिला अस्पताल संचालित है, लेकिन हृदय रोग और कैंसर सम्बन्धी उपचार की कोई भी व्यवस्था नहीं है और न ही इस तरह की कोई भी इकाई स्थापित है इस तरह के रोगों के इलाज के लिए न ही कोई विशेष चिकित्सक नियुक्त है और न ही कोई इन रोगों की जांच की कोई मशीन है। इस कारण इस रोग के मरीजों को जयपुर रैफर किया जाता है। रैफर के दौरान दूरी ज्यादा होने के कारण बहुत से मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं अगर उन्हें समय पर उपचार मिल जाये तो शायद उनकी जान बच सकती है।

उक्त जिला अस्पताल में ओ.पी.डी. 2200 पर डे एवरेज है और आई.पी.डी. 55 पर डे का एवरेज है और डिलीवरी 6 हजार सालाना से ऊपर है जो जिले में सबसे ज्यादा है एवं सुविधाएं अच्छी होने की वजह से दूरदराज से भी लोग इलाज के लिए इस अस्पताल में आते हैं। इन रोगों की, कैंसर और हृदय रोग, इनके मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा होती है अतः जनहित को दृष्टिगत रखते हुए मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से, स्वास्थ्य मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि जिला अस्पताल में हृदय रोग और कैंसर सम्बन्धी जांच और इलाज की मशीनें स्थापित की जायें तथा इन रोगों के विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाये। एक एम.आर.आई. मशीन शीघ्र स्थापित करने की मैं स्वास्थ्य मंत्रीजी से मांग करता हूं। दुर्भाग्य की बात है कि मुझे बजट में एक भी अस्पताल नहीं दिया गया तो कृपया, मुझे एक-एक सी.एच.सी. मावण्डा खुर्द और हसामपुर में दिलायी जायें, ये दोनों पी.एच.सी. हैं, इनकी ओ.पी.डी. बहुत ज्यादा है। पाटन एवं गुहाला की सी.एच.सी. को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करने की स्वीकृति देने की मैं मांग करता हूं। इनकी भी ओ.पी.डी. 750 प्रतिदिन से ऊपर है। इसी प्रकार दरिबा, नाथा की नांगल, नया बास एवं बासड़ीखुर्द में पी.एच.सी. की स्वीकृति प्रदान कराएं। डाबला पी.एच.सी. में डाक्टर का निवास जीर्णशीर्ण अवस्था में है, उसके लिए पुनर्निर्माण के लिए बजट दिया जाये।

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में जिला अस्पताल सहित प्रदेश के बहुत से अस्पतालों में सोनोग्राफी मशीनें बेकार पड़ी हैं, क्योंकि सोनोग्राफी करने वाले नहीं हैं। यह एक पूरे राजस्थान की समस्या है अतः इस समस्या का भी समाधान आवश्यक रूप से ध्यान देकर कराएं। स्वास्थ्य विभाग में आपने बड़ी संख्या में दूरस्थ स्थान पर तबादले किये हैं, रिकार्ड बनाया है आपने इस बार ट्रांसफर का और यह आपने तबादले प्रशासनिक दृष्टि से नहीं बल्कि राजनीतिक दृष्टि से किये हैं। आपने मेरे यहां एक एस.सी. की विकलांग महिला, महिला एस.सी. की और विकलांग, उसका आपने बाड़मेर-जैसलमेर ट्रांसफर किया है। पाटन में जो

बड़ा अस्पताल है, मेरे विधान सभा क्षेत्र का दूसरा बड़ा अस्पताल है, वहां पर डॉक्टर और कम्पाउंडर बिलकुल कम संख्या में है। मरीज आते हैं और बिना इलाज के ही चले जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं।

आपने जिन कर्मचारियों को हटाया है, उनकी जगह पर कर्मचारी भी नहीं लगाये हैं। कम से कम उनकी जगह पर कर्मचारी तो लगा देते तो अस्पतालों का काम तो चलता रहता। ग्रामीण क्षेत्र में कर्मचारी जाने के इच्छुक नहीं होते हैं, लोकल के अलावा। मेरा आपसे यह निवेदन है कि ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टरों को या तो सैलरी ज्यादा दी जाये या उनको रूरल अलाउंस के नाम से कुछ मदद की जाये जिससे कि उनका इंटरेस्ट उस ग्रामीण क्षेत्र में जाने में हो।

आपने नीम का थाना से तो बहुत ही दुर्भावनापूर्वक व्यवहार किया है। जिला समाप्त करके आपने उसकी स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर रोक लगाने का काम किया है। हम मेडिकल कॉलेज की मांग कर रहे थे, नर्सिंग कॉलेज की मांग कर रहे थे एवं यहां की परिस्थितियों को देखकर ये मांगें जायज थीं तो मेरा यह निवेदन है कि मंत्रीजी हमारी इन मांगों पर विचार करें एवं हमें यह सौगात दें।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत सारे डॉक्टरों, कम्पाउंडरों, ए.एन.एम. व अन्य कर्मचारियों के पद खाली हैं कृपया, उन पर शीघ्र नियुक्ति करने का कष्ट करें। मेरे क्षेत्र में एम.सी.एच. अस्पताल बनकर तैयार है। उसमें आप मशीनें और उपकरण दिलायें एवं स्टाफ की नियुक्ति कर इसे शीघ्र चालू करायें ताकि जनता को इसका लाभ मिल सके। हमारी सरकार ने आर.टी.एच., राइट टू हैल्थ कानून बनाया था, मेरा आपसे यह निवेदन है कि इसके नियम बनाकर इसे समयबद्ध तरीके से लागू करें। सवा साल निकलने के बाद भी आपने अभी तक नियम नहीं बनाये हैं।

टेलीमेडिसिन, दूरदराज के लोगों तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। वर्ष 2024-25 में 619 करोड़ रुपये का बजट अनुमोदित भी किया गया परंतु दिसम्बर तक केवल 13.71 करोड़, 619 में से 13.71 करोड़ रुपया ही खर्च किया गया है तो मेरी राय में इस ओर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य सेवाएं जहां सुदूर इलाके हैं, वहां इससे बढ़िया कोई तरीका है नहीं। 01 अप्रैल से 21 दिसम्बर, 2024 तक दवा योजना के जो 90 दवाओं के सैम्पल फेल किये हैं, आपने एक भी फर्म को अभी तक डिबार नहीं किया है। हमारे कार्यकाल में नि:शुल्क दवा योजना पर सरकार का पूरा फोकस था, इसके लिए हर साल पूरा बजट खर्च होता था। 2024-25 में 2411 करोड़ का बजट प्राप्त हुआ लेकिन इसमें आधा भी बजट दिसम्बर तक खर्च नहीं हुआ, 1190 करोड़ रुपया आपने दिसम्बर तक खर्च किया है।

प्राइवेट अस्पतालों के क्लैम जो हैं चिरंजीवी के, आज आपने जिसका नाम MAA कर दिया है, उसके अस्पतालों के क्लैम समय पर पास नहीं हो रहे हैं इसलिए प्राइवेट अस्पताल इलाज करने से मना कर रहे हैं।

श्री सभापति: प्लीज, अपनी बात को समाप्त कीजिए।

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): मेरा आपसे यह निवेदन है कि स्वास्थ्य सेवाओं को विशेष ध्यान रखते हुए हर इलाके में, चाहे वहां पर कांग्रेस का विधायक हैं या चाहे वहां बी.जे.पी. का विधायक हैं, हर जगह पर आप इस दृष्टिकोण से काम करें कि जनता को सुविधा मुहैया हो। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री लालारामजी बैरवा।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची समाप्त होने तक के लिए बढ़ाया जाये।

श्री सभापति: क्या सदन की सहमति है?

(स्वीकृत)

सदन का समय आज की कार्य सूची समाप्त होने तक बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 27- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व

मांग संख्या 28- चिकित्सा शिक्षा पर विचार

श्री लालाराम बैरवा (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27 एवं 28 पर आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। एक श्लोक के साथ में मैं अपनी बात को प्रारंभ करना चाहता हूं-

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।।

अर्थात, सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त रहें, सभी का जीवन मंगलमय बने और कोई भी दु:ख का भागी न बने, ऐसी भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। बेशक आज के आधुनिक दौर में कई बीमारियों का पता आसानी से लगाया जा सकता है, क्योंकि अब ऐसे आधुनिक उपकरण, आधुनिक मशीनें इन सबका आविष्कार भारत के अन्दर हो गया है। कई बीमारियों से निजात दिलाने वाली दवाइयां भी मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध हैं, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में भारत का गौरवशाली इतिहास सृष्टि के शुरूआत से ही चला आ रहा है। हमारे पौराणिक साहित्य में देवताओं के चिकित्सक अश्वनी कुमारों का पर्याप्त जिक्र भी है। धार्मिक ग्रंथों में महर्षि शुक्राचार्य, सुषेण वैद्य तथा हर्ष मित्र जो दुर्योधन के राज वैद्य जैसे संजीवनी बूटी के पारंगत महान चिकित्सकों का व्यापक वर्णन हमको मिलता है। मृत शरीर को पुन: स्वस्थ करने में भी सक्षम थे। सदियों से भारत में आयुर्वेद तथा शल्य चिकित्सा पद्धति का समृद्ध इतिहास हमारा रहा है।

.... आगे जारी....

ssy/rtm/06.03.2025/18.00/3I

भारत के लिए गौरव का विषय है कि ऑस्ट्रेलिया के मेलबॉर्न में रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन तथा अमेरिका में कोलंबिया इरविंग मेडिकल सेंटर में भारतीय महर्षि सुश्रुत की प्रतिमा लगाई गई है। उन कॉलेजों में डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले कई देशों के छात्रों को बताया जाता है कि महर्षि सुश्रुत फादर ऑफ सर्जरी थे। कई देश स्वीकार कर चुके हैं कि प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत हजारों वर्ष पूर्व भारत में हुई थी। हम सब भी अच्छी तरह जानते हैं कि भगवान शिव ने क्रोध में आकर गणेशजी का सिर काटा था और उसकी भी सर्जरी हमारे भारत के इतिहास में हुई है। ऐसे ही रावण के युद्ध में रावण को जब राम पराजित करने के लिए गए, तब लक्ष्मण को बाण लगा तो संजीवनी बूटी हनुमान लेकर आये और उससे उनको जीवित किया। ऐसे सर्जरी के पितामह व शिक्षक महर्षि सुश्रुत द्वारा शल्य चिकित्सा और संस्कृत भाषा में रचित सबसे प्राचीनतम ग्रंथ सुश्रुत संहिता का अरबी भाषा की किताब ए सुश्रत नामा पुस्तक के रूप में भी अनुवाद हो चुका है।

आयुर्वेद के महर्षि चरक भारतीय औषधि विज्ञान के मूल प्रवर्तक थे। आयुर्वेद का अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ चरक संहिता महर्षि चरक की रचना है, इसलिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन भी कहा जाता है।

आज के युग में मैं आप सबको यह कहना चाहता हूँ कि स्वस्थ रहने के लिए एक श्लोक के साथ बात करता हूं,

'व्यायामात् लभते स्वास्थ्यं दीर्घायुष्यं बलं सुखं,
आरोग्यं परमं भाग्यं स्वास्थ्यं सर्वार्थसाधनम्।'

व्यायाम से स्वास्थ्य, लंबी आयु, बल और सुख की प्राप्ति होती है। निरोगी होना परम भाग्य है और स्वास्थ्य से अन्य सभी कार्य सिद्ध होते हैं। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अगर स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ शरीर रहता है तो भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक भारत के लिए भी अच्छे रूप में काम करेगा।

सभापति महोदय, यहाँ हमारे चिकित्सा मंत्री जी बैठे हैं, उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि मेरे शाहपुरा जिले में, शाहपुरा विधान सभा में कार्डियोलॉजी की यूनिट नहीं होने के कारण मेरी शाहपुरा विधान सभा की देवतुल्य जनता को आये दिन घटनाओं का सामना करना पड़ता है। कार्डियोलॉजी की यूनिट हमारे भीलवाड़ा जिले में है और शाहपुर वहां से 50 किलोमीटर दूर पड़ता है, उसके कारण अगर हृदय रोग किसी व्यक्ति के होता है तो उसको शाहपुरा हॉस्पिटल से रैफर करके भीलवाड़ा भेजते हैं, रास्ते में जाते-जाते ऐसे कई व्यक्तियों की जान चली जाती है। माननीय सभापति जी, आप के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि शाहपुरा हाल ही में जिला था और आस पास के एरिये का सबसे बड़ा अस्पताल भी है, वहाँ पर पीएचसी और सीएचसी भी है, वहाँ की जनता को इसका लाभ मिले और जन हानि ना हो, इसलिए शाहपुरा के जिला अस्पताल के अंदर कार्डियोलॉजी की एक यूनिट

खोलनी चाहिए।

माननीय सभापति जी, मैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि पूर्व बजट के अंदर हमारी देवतुल्य जनता की डिमांड पर वहाँ ट्रोमा सेंटर दिया, लेकिन किसी प्रकार की बिल्डिंग निर्माण की वित्तीय स्वीकृति, फंड नहीं आया तो आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ कि वहाँ बिल्डिंग की, उपकरणों की और उसके साथ में स्टाफ की अति आवश्यकता है, उसको पूरी कराएंगे तो निश्चित तौर पर जो ट्रोमा सेंटर की पूर्व बजट में घोषणा हुई है, उसका लाभ शाहपुरा की देवतुल्य जनता को मिलेगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि शाहपुरा में जिला अस्पताल होने के बावजूद भी वहाँ पर ब्लड बैंक नहीं है। छोटे-मोटे किसी भी प्रकार के ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है तो ब्लड लेने के लिए भीलवाड़ा जाना पड़ता है। शाहपुरा में बहुत पुराना जिला अस्पताल है, उसके बावजूद भी यहाँ पर ब्लड बैंक जैसी सुविधा नहीं है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी को और सरकार को कहना चाहता हूँ कि ब्लड बैंक अगर आप खोलते हैं तो शाहपुरा की देवतुल्य जनता को लाभ मिलेगा। वहां दुर्घटनाओं में जो जान जाती है उनसे बचा जा सकता है।

माननीय सभापति जी, मैंने पूर्व में भी मंत्री महोदय को ध्यान दिलाया कि जिला अस्पताल में और उसके आस पास की जितनी भी पीएचसी, सीएचसी है, वहाँ पर जितने पद स्वीकृत हैं, उन पर ना तो डॉक्टर हैं, ना नर्सिंग ऑफिसर हैं, ना वहाँ गांव के अंदर डॉक्टर हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इतना बड़ा जिला अस्पताल होने के बावजूद भी केवल मात्र वहाँ पर छह डॉक्टरों की नियुक्ति है, वहां पर नर्सिंग ऑफिसरों के पूरे पद नहीं भरे हुए हैं, इस कारण से मरीजों की वहाँ पर लाइन लगी रहती है। रात भर बाहर खड़े-खड़े वह अपना इलाज कराते हैं, वहाँ पर डॉक्टरों की व्यवस्था, नर्सिंग ऑफिसरों की व्यवस्था, स्टाफ की व्यवस्था अगर आप कराते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा अस्पताल वहाँ पर अच्छा चलेगा।

सभापति महोदय, आयुष्मान केंद्र, जो वर्तमान में हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से चल रहे हैं, आज वह बंद पड़े हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रयासों से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को मान्यता प्राप्त कराई और आज पूरा विश्व योग कर रहा है।

श्री सभापतिः समाप्त करिये। श्रीमती गीता बरवड़।

श्री लालाराम बैरवा (शाहपुरा): इसी कड़ी में हमारे राज्य के अधिकांश केन्द्र जो संचालित हैं उनको तुरंत प्रभाव से चालू कराना चाहिए।

श्री सभापतिः समाप्त कीजिये।

श्री लालाराम बैरवा (शाहपुरा): सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती गीता बरवड़ (भोपालगढ़): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27 और 28 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार।

पहला सुख निरोगी काया, क्योंकि शरीर स्वस्थ है तो सब सही है। स्वास्थ्य ही सर्वोपरि है।

सभापति महोदय, मैं सिर्फ अपने विधान सभा की बात करना चाहूंगी। भोपालगढ़ अस्पताल उप जिला अस्पताल हैं जहां पर संसाधनों की कमी है, आपने मोबाइल हेल्थ यूनिट का झांसा देकर जनता को सिर्फ गुमराह किया। गहलोत सरकार द्वारा यहाँ पर ट्रोमा सेंटर का भवन निर्माण करवाया गया, लेकिन अभी तक कोई भी इक्विपमेंट वहाँ पर नहीं आया, पिछले सदन में भी मैंने यह मांग की थी कि वहाँ पर कोई इक्विपमेंट नहीं है, तो सारे इक्विपमेंट उपलब्ध कराए जायें, लेकिन अभी तक भी वहाँ पर कोई संसाधन उपलब्ध नहीं कराया गया।

भोपालगढ़ के अस्पताल में कुल 28 पद डॉक्टरों के स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 9 का स्टाफ है, 19 पद रिक्त हैं, नर्सिंग ऑफिसर के कुल 52 पद है, कार्यरत सिर्फ 24 हैं तथा 28 पद रिक्त हैं, ये रिक्त पद भरवाने की मैं मांग करती हूँ, इसके लिए मैंने पिछले सदन में भी मांग की थी और मंत्री जी से भी मिलकर बोला था, लेकिन आज तक कोई पद नहीं भरे गये।

इसी प्रकार आसू बावड़ी सीएचसी का भी यही हाल है, वहाँ पर भी पद रिक्त पड़े हैं, इनको भरवाने का निवेदन करती हूँ और आपसे उम्मीद करती हूँ की ये रिक्त पद आप भरवायेंगे।

spp/rtm/06.03.2025/18.10/3m

सफाई कर्मचारी, वार्ड ब्वॉय, इनकी भी कमी है। अस्पतालों में सफाई नहीं हो पा रही है, जिससे यह रोगों को दूर तो नहीं कर पा रहे हैं, रोगों को बनाने का काम चल रहा है। हॉस्पिटल में जो ठेके के कर्मचारी हैं, उनको भी मैं परमानेंट करने की आपसे मांग करती हूँ।

माननीय सभापति महोदय, कोरोना काल में माननीय गहलोत सरकार ने 50 लाख की लागत से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया गया था, जो वर्तमान में बंद पड़ा है। इसको सुचारू रूप से शुरू करवाने की मैं मांग करती हूं। निवेदन करती हूं कोरोना काल में गहलोत साहब ने जो काम किया, उसके लिए सबने सराहा। जो बहुत शानदार कोशिश रही मरीजों को बचाने की, नि:शुल्क दवा योजना गहलोत सरकार की रही। चिरंजीवी योजना को बदलकर मा योजना में बदल दिया गया, जिसका 25 लाख रुपये दिया जाता था। बावड़ी और आसोज सीएचसी अस्पतालों में ट्रोमा सेंटर की मैं मांग करती हूं। बावड़ी आसोज में गायनिक डॉक्टर भी नहीं हैं। गर्भवती महिलाओं को वहां से जोधपुर रेफर किया जाता है, जिसमें 2 घंटे का टाइम लगता है और रास्ते इतने खराब हैं कि उनको आने में बहुत परेशानी होती है, तब तक मरीज की हालत खराब हो जाती है। ट्रोमा सेंटर नहीं होने से परेशानियां तो आती भी हैं और अचानक वहां पर आजकल एक्सीडेंट बहुत होते हैं तो वहाँ से जोधपुर आने में बहुत टाइम लगता है और अभी भी पिछले महीने भर पहले भी एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें तीन जनों की वहीं पर ही डैथ हो गई और पांच-सात महीने पहले एक और एक्सीडेंट हुआ, जिसमें सात जने

थे और उनको जोधपुर लाते एक जने की एक वही पर ही डैथ हो गयी। आसोज से खींवसर नागौर, बनार से कुचेरा, रातड़ी से मेड़ता तीन हाईवे लगते हैं, जो सेंटर बिंदु पर हैं। ये कृषि और औद्योगिक क्षेत्र भी पड़ता है। इसी प्रकार बावड़ी अस्पताल जोधपुर से नागौर हाईवे मुख्य बिंदु पर है। वहां पर ट्रोमा सेंटर की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैंने मंत्रीजी से पिछली बार भी मिलकर बोला, पिछले सदन में भी बोला, यहां पर ट्रोमा सेंटर की जरूरत है, क्योंकि ये अस्पताल हाईवे पर पड़ता है और यहा पर एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं और मरीज भी बहुत ज्यादा आते हैं तो यहां से इनको रेफर या तो नागौर कर दिया जाता है या हॉस्पिटल किया जाता है तो बहुत लम्बा टाइम लग जाता है उनको पहुंचने में।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की बनार पंचायत में सैटेलाइट अस्पताल क्रमोन्नत किया, जिसको करीब-साल डेढ़ साल हो गया, लेकिन अभी भी उसके भवन निर्माण का ना तो कोई बजट आया है, न वहां पर कोई स्टाफ लगाया गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री से कहना चाहूंगी कि भवन निर्माण का बजट और वहां पर स्टाफ लगाया जाए।

सभापति महोदय, पीएचसी, सीएचसी की मैं बात करूं तो अपग्रेड करने की मांग करती हूँ। आप के माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस ग्राम पंचायत के परिधि क्षेत्र की जनसंख्या 20 हजार के करीब है। वर्तमान में पीएचसी पर 200 से 300 ओपीडी प्रतिदिन होने के कारण इस क्षेत्र में जनता को सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके इसीलिए सालवा कलां, खवासपुरा, सोहेला पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने एवं पीएचसी गजसिंहपुरा, बुड़किया, अरटियाखुर्द, कुड़ी में सारे डॉक्टरों के रिक्त पद भरने की मैं मांग करती हूं।

माननीय सभापति महोदय, विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के उप स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता है। वर्तमान में रामड़ावास कला, पालड़ी रणावत, सियारा, बूचेटी एवं हीरादेसर ग्राम पंचायतों की जनसंख्या 7 हजार से 8 हजार करीब है। ये सारी ग्राम पंचायतें मुख्य मार्ग पर स्थित हैं। इन ग्राम पंचायतों के आसपास राजस्व गांव दूरदराज की ढाणियों सहित परिधि क्षेत्र, जिनकी कुल आबादी लगभग 25 हजार से 26 हजार हैं। सभापति महोदय, रामड़ावास कला, पालड़ी राणावता, सियारा, बूचेटी एवं हीरादेसर उप स्वास्थ्य केंद्र को पीएचसी में क्रमोन्नत करवाने एवं रिक्त पद भरने की मैं आपसे मांग करती हूं।

सभापति महोदय, साथ ही नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की आवश्यकता देखते हुए भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र में दूर दराज की ढाणियों, ग्रामों एवं औद्योगिक क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि ग्राम, ढाणियों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाने में काफी दूरी होती है और रोगियों का उपचार नहीं होता इसीलिए ग्राम पंचायत डंडोरा, बुरछा, नागलवास उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मैं मांग करती

हूं।

सभापति महोदय, भीमराव अंबेडकर राज्य के बालिका और बालक आवासीय विद्यालय में जीएनएम का पद स्वीकृत करवाने की आवश्यकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राज्य के बालिका और बालक आवासीय विद्यालय राजस्थान में काफी संख्या में हैं। हर विद्यालय में करीब 400 से 600 बालिकाएं रहकर पढ़ाई करती हैं। कक्षा छह से 12 वीं तक पूर्ण आवासीय विद्यालय होने के कारण बालिकाओं के स्वास्थ्य को लेकर सरकार का किसी प्रकार कोई उचित प्रबंध नहीं है।

सभापति महोदय, इस सन्दर्भ में मेरा आपसे माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है की आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं को स्वास्थ्य की देखभाल के लिए हर विद्यालय में जीएनएम महिला स्वास्थ्यकर्मी की स्थायी व्यवस्था करवाने की मांग करती हूँ। हर विद्यालय में जीएनएम का क्वार्टर बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर जीएनएम नहीं है।

उप जिला अस्पताल भोपालगढ़ के लिए प्राप्त भवन उपलब्ध होने से ही एएनएम प्रशिक्षण केंद्र खोलने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र में आसपास के परिधि में महिला व स्वास्थ्यकर्मियों को लाभ मिल सके। उप जिला अस्पताल भोपालगढ़ में पर्याप्त भवन उपलब्ध है, इसमें जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने की मैं आपसे मांग करती हूं और उपखंड बावड़ी में नर्सिंग कॉलेज खोलने की मैं आपसे मांग करती हूँ। सैनेटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट को अस्पतालों में हटा दिया गया है, लेकिन आप इनकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं।

श्री सभापति: समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्रीमती गीता बरवड़ (भोपालगढ़): एक मिनट और। राजस्थान स्वायत शासन संस्था में आप इसकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं लेकिन इसकी कोई भी पोस्ट नहीं रखी जा रही है। आखिर में हमने आपको यही कहना चाहती हूं-

राजस्थान सरकार है बीमार, मंत्री हैं लाचार,
मुख्यमंत्री हेलिकॉप्टर में है सवार।
जनता हैं बेहाल कुछ तो करो राजस्थान सरकार,
नहीं तो 2028 में जनता करेगी आप सबका इलाज। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हसंराज पटेल। (अनुपस्थित) श्री कंवरलाल।

श्री कंवरलाल (अंता): माननीय सभापति महोदय, आपने मान संख्या 27 एवं 28 पर मुझे आज इस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर से, धरती के भगवान और धरती के मंदिर की बात करने का मुझे अवसर दिया है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय का ध्यान एक अत्यंत गंभीर विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो केवल इस देश के समस्त चिकित्सकों, बल्कि विशेष रूप से राजस्थान के सभी डॉक्टरों के लिए अत्यंत आवश्यक है।

माननीय सभापति महोदय, पश्चिम बंगाल में अगस्त माह में एक महिला रेजीडेंट डॉक्टर

के साथ जो भयावह घटना घटी, उसने सरकार की सभी सुरक्षा संबंधी खामियों को उजागर कर दिया। ये घटना केवल एक राज्य तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे देश भर के चिकित्सा संस्थानों में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर गंभीर प्रश्न खड़ा कर गई। इस गंभीर विषय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार एक कार्यबल नेशनल टास्क फोर्स का गठन हुआ, जिसमें देश के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों के विशेषज्ञ चिकित्सकों को शामिल किया गया। राजस्थान के गर्व की बात है एम्स जोधपुर के निदेशक प्रोफेसर जी.डी.पुरी को इस टास्क फोर्स का हिस्सा बनाया। मैं आगे आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्री महोदय को ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस राष्ट्रीय कार्यबल में राजस्थान की सरकारी अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों के लिए क्या सिफारिश प्रस्तुत की? उन सभी सिफारिशों में से अभी तक कितनी सिफारिशों को लागू किया गया? उनकी स्थिति क्या है? तीसरा, भविष्य में इन सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार का मन और माननीय मंत्री महोदय का मन क्या है? सभापति महोदय, ये आपको जानना आवश्यक है और मेरा बताना आवश्यक है कि एम्स जोधपुर के निदेशक ने अपने संस्थान में रजिस्टर्ड डॉक्टरों के कल्याण और सुरक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो बाकी सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बन सकता है? हम सभी जानते हैं कि चिकित्सक विशेष रूप से रेजीडेंट डॉक्टर 24 घंटे मरीजों की सेवा में लगे रहते हैं। यदि अस्पताल में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जाये तो न केवल चिकित्सा समुदाय के लिए बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए एक गंभीर संकट पैदा कर सकती है। अतः आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को आग्रह करना चाहूंगा कि राजस्थान में सभी सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा उपाय को सख्ती से लागू किया जाए। इसके साथ ही राजस्थान रेजीडेंट डॉक्टरों के लिए सुरक्षित कार्य सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक नीति तुरंत लागू किया जाए। एम्स जोधपुर के कार्यप्रणाली का अध्ययन करें और उसे अन्य अस्पतालों में भी लागू कर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, ये केवल डॉक्टरों की सुरक्षा का विषय नहीं है बल्कि पूरे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, आमजन के हितों का जुड़ा हुआ मुद्दा है।

jyg/rtm/06.03.25/18.20/3n

यदि डॉक्टर सुरक्षित होंगे तो निश्चित रूप से मरीजों की सेवा कर सकेंगे जिससे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था अधिक सुदृढ़ हो सकेगी। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस विषय पर उचित कदम उठाकर प्रदेश के समस्त चिकित्सकों को आश्वासित करें।

माननीय सभापति महोदय, इस सम्माननीय सदन के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान, अंग प्रत्यारोपण, डॉक्टरों की सुरक्षा, आपात कालीन सेवाओं की स्थिति में देश में चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधा, ऐतिहासिक विस्तार जैसे विषयों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। यह विषय न केवल प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था अति अावश्यक है बल्कि आम नागरिकों के

जीवन-मृत्यु के अंतर को तय करता है।

मानीनीय सभापति महोदय, मैं एक घटना की ओर आपको ले जाना चाहता हूं। 2013-18 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में माननीय हमारे गृह मंत्रीजी अमित जी शाह एक मीटिंग ले रहे थे, उस समय हमारे स्वर्गीय सांवरमल जी जाट, जो मंत्री थे, अपनी किसानों की बात रख रहे थे, अचानक उनका कार्डियक अरेस्ट हुआ और वे गिर गये। डॉक्टर विश्वनाथ जी भी उस समय साथ थे, उस समय उनका सीपीआर किया, मुंह से उनको सांस दिया, मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर उस समय एम्बुलेंस और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, ऑक्सीजन सिलेण्डर अगर पास होता तो मैं कहता हूं कि आज हमारा किसान नेता 15 दिन अस्पताल में जूझने के बाद मृत्यु की ओर अग्रसर नहीं होता।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको एक गम्भीर विषय, जीवन-मृत्यु से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि स्वस्थ जीवन के लिए सभी को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो जिससे जीवन बच सकता है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गम्भीर रूप से बीमार को अंग के प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है। जब तक उन्हें उपयुक्त दाता नहीं मिलता तब तक उनकी जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। राजस्थान में अंगदान और प्रत्यारोपण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। इस बारे में मैं बताना चाहता हूं कि राजस्थान के राज्य अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण के माध्यम से अब तक 48 परिवारों ने मस्तिष्क की मृत्यु के बाद, ब्रेन डेड घोषित करने के बाद अपने परिजनों का अंगदान किया है, जिसमें 110 परिजनों को नया जीवन मिला है। सवाई मानसिंह अस्पताल में जयपुर में अंग प्रत्यारोपण की सुविधाओं को बढ़ावा दिया गया है जिससे कई गम्भीर रोगियों को जीवनदान मिला है। उदयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर में नये अंगदान केन्द्र स्थापित किये हैं, जिससे अंगदान और अंग प्रत्यारोपण की प्रक्रिया को और बढ़ावा मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि इस प्रक्रिया को और सरल बनाने की आवश्यकता है। जोधपुर में मथुरादास माथुर अस्पताल में अंग प्रत्यारोपण केन्द्र आपने घोषित किया है, ये लोगों के लिए फायदे की बात है। एसएमएस अस्पताल में लीवर ट्रांसप्लांट सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है, जिससे लीवर सम्बन्धी गम्भीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को राहत मिलेगी। माननीय सभापति महोदय, ये सभी प्रयास नीरोगी राजस्थान योजना के अंतर्गत किये जा रहे हैं जिसके तहत राजस्थान सरकार ने 14 हजार 533 करोड़ रुपये का बजट स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आवंटित किया है। इसलिए मैं सरकार को, यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय भजन लाल शर्मा जी को और माननीय मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, हम यह नहीं भूल सकते कि अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में अभी भी कई सुधारों की आवश्यकता है। अंगदान करने के प्रति जागरूक करने के प्रयासों को बहुत तेज किया जाये तभी जाकर यह पूरा काम हो सकता है। हर जिले में एक समर्पित अंग

प्रत्यारोपण केन्द्र स्थापित किया जाये और लोगों को जागरूक किया जाये। मरीजों के परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए एक विशेष कोष की स्थापना की जाये ताकि लोगों में और विश्वास पैदा हो जाये। डॉक्टरों की सुरक्षा और कार्य स्थल पर सुधार के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि डॉक्टर केवल पेशेवर नहीं है, बल्कि वो समाज के लिए सेवाभावी योद्धा होते हैं, लेकिन असुरक्षित महसूस करने लगते हैं तो पूरे समाज में चिंता का विषय बन जाता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि डॉक्टर धरती का भगवान है, उन्होंने कोरोना काल में परिवार की चिंता छोड़कर अपने मरीजों को बचाने में अपनी जान की बाजी लगायी है। यह सही बात है कि उनकी प्रतिज्ञा में कहते हैं, मेरा जीविकोपार्जन, मेरा परिवार मरीजों के बीमार होने से चलता है लेकिन वो भगवान से यह भी प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मेरे में इतनी ताकत देना, इतना ज्ञान देना, इतनी शक्ति देना कि मेरे पास आने वाले मरीज को मैं समय पर ठीक कर सकूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में उन्होंने अभूतपूर्व परिवर्तन किया है। मेरी बहन शिखा मील जी ने अभी बताया था कि नेहरू जी ने दिल्ली में एक एम्स खोला है, मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि आपने 70 वर्षों में 7 एम्स खोले थे, माननीय मोदीजी ने अभी 23 एम्स कर दिये हैं। 1947 से 2014 तक 70 वर्षों में देश में मात्र 387 मेडिकल कॉलेज बने थे लेकिन हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी ने मात्र 10 वर्षों में इनकी संख्या बढ़ाकर 706 कर दी है। 2014 से पहले देश में केवल 51 हजार एमबीबीएस की सीटें थीं लेकिन माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से और मेहनत से इनकी संख्या 1 लाख 7 हजार कर दी है जो जस्ट संख्या की डबल है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में कई नये मेडिकल कॉलेज स्थापित किये हैं जिससे प्रदेश के युवाओं को मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने के अवसर बढ़ेगे और रोजगार बढ़ेंगे।

श्री सभापतिः समाप्त कीजिये।

श्री कंवरलाल (अंता): माननीय सभापति महोदय, एक बात कहकर मेरी बात को समाप्त करूंगा। माननीय वसुन्धरा जी जब हमारी पूर्व मुख्य मंत्री थी तो भामाशाह योजना के माध्यम से निःशुल्क प्राइवेट अस्पतालों में और सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा की बात की गयी थी। अब मुख्य मंत्री चिरंजीवी योजना के माध्यम से ... ।

श्री सभापतिः श्रीमती शोभारानी कुशवाह।

श्री कंवरलाल (अंता): बोल बा द्यो साहब।

श्री सभापतिः मेरा सभी वक्ताओं से करबद्ध निवेदन है कि संख्या अभी 21 वक्ता बोलना बाकी है। हर व्यक्ति को समय का आपके संगठन ने बता रखा है। अपने समय में अपनी बात को पूरी करने से पहले जो भी डिमाण्ड है वो पहले रख दें, मेरी घंटी बजेगी, पांच मिनट हैं उसके एक मिनट पहले और आठ मिनट हैं उसके दो मिनट पहले, उसमें अपनी बात समाप्त

करें ताकि सभी अपनी-अपनी बात रख सके। ...(व्यवधान)... श्रीमती शोभारानी कुशवाह।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): जो टेबल करना चाहें कर सकते हैं?

श्री सभापति: हां, टेबल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ...(व्यवधान)... प्लीज सदस्य।

श्रीमती शोभारानी कुशवाह (धौलपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार।

माननीय सभापति महोदय, धौलपुर विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सा विभाग से सम्बन्धित समस्याओं के बारे में अवगत कराना चाहती हूं कि वर्ष 2023 में विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में पीएचसी एक ग्राम जमालपुर दूसरी मसूद स्वीकृत की गयी थी जिसकी अभी तक भूमि आवंटित नहीं हुई है। इसी वजह से अभी तक किराये के भवनों में संचालित की जा रही है तथा जिसमें न कोई डॉक्टर है न ही पूर्ण रूप से स्टाफ जिसके कारण से ग्रामीणों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि जल्द से जल्द इनके लिए भूमि आवंटित की जाये और नवीन भवन निर्माण कार्य करवाया जाये जिससे सुचारू रूप से पीएचसी चलायी जा सके। जिला चिकित्सालय धौलपुर में मशीनरी एवं स्टाफ के रिक्त पदों को भरा जाये जिससे मरीजों एवं आम जन को सही समय पर उचित इलाज मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में सर्वे कराकर नई पीएचसी और सीएचसी स्वीकृत कराने का श्रम करें जिससे चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में धौलपुर जिला अग्रणी बन सके। इसी प्रकार से जिला चिकित्सालय धौलपुर में भी मशीनरी एवं स्टाफ की भी कमी है, सोनोग्राफी के लिए मरीजों को करीब एक महीने में नम्बर आता है जिसके कारण मरीजों को बाहर प्राइवेट सोनीग्राफी करानी पड़ती है।

MLS/RTM/06.03.2025/18:30/3o

जिससे गरीबों को बड़ी भारी समस्या का सामना करना पड़ता है और मजदूर गरीब लोग कर्ज लेकर भी सोनोग्राफी करवाते हैं, जिसके चलते मरीजों को सही समय पर उचित उपचार नहीं मिल पाता है। अतः सभापति जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस महती आवश्यकता जिला चिकित्सालय, पीएचसी और सीएचसी, धौलपुर में मशीनरी एवं स्टाफ की कमी को दूर करें और संसाधन उपलब्ध कराने की कृपा करें। जय हिन्द, जय भारत, जय-जय राजस्थान।

श्री सभापति: श्री हंसराज मीना।

श्री हंसराज मीना (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद कि आपने मुझे मांग संख्या 27 - चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और मांग संख्या 28 - चिकित्सा शिक्षा पर बोलने का अवसर दिया। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व में

प्रदेश में ''पहला सुख नीरोगी काया'' के ध्येय को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में और अधिक सुधार तथा नागरिकों के स्वास्थ्य स्तर को बढ़ाने के लिए महत्त्वपूर्ण कदम उठाये और उसी कड़ी में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अन्तर्गत लगभग 35 लाख व्यक्तियों को चिकित्सकीय लाभ प्राप्त हुआ है।

इसी कड़ी में माननीय वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने इस वर्ष मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के साथ ही नि:शुल्क जांच एवं दवा हेतु 3 हजार 500 करोड़ रुपये का महाकोष गठित किये जाने की जो घोषणा की है, वह निश्चित रूप से एक स्वागत योग्य कदम है। माननीय सभापति महोदय, साथ ही मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मां योजना के माध्यम से आमजन को और अधिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए माननीय वित्त मंत्री महोदया ने बजट 2025-26 में इंटर-स्टेट पोर्टेबिलिटी लागू कर प्रदेश के बाहर भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने की जो घोषणा की है, इससे निश्चित रूप से प्रत्येक राजस्थानवासी, जो राजस्थान के अलावा बाहर अपने व्यवसाय के लिए, अपने धन्धों के लिए काम करता है, उसको निश्चित रूप से इस मा योजना का फायदा मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, यह विषय मानव जीवन के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। इसी विषय पर आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जब कोई भी व्यक्ति, चाहे बीमार व्यक्ति हो या पीड़ित व्यक्ति हो, जब उस पर दु:ख आता है, कष्ट आता है तो शायद सबसे पहले जिसको वह याद करता है, उसका नाम सबसे पहले उसकी जुबान पर आता है। वह नाम है 'मां' का। मां की पनाह में, मां की गोद में उसको जो सुकून मिलता है, निश्चित रूप से वह व्यक्ति पूरे संकटों को, पूरे दु:खों को भूल जाता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी का कि उन्होंने राजस्थानवासियों के लिए इस मा योजना के तहत जो 3 हजार 500 करोड़ का कोष गठित किया है, इससे निश्चित रूप से राजस्थान के प्रत्येक गरीब को, अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को लाभ मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की कुछ मांगें रखना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, सपोटरा विधान सभा क्षेत्र, जो करौली जिले में आता है, भौगोलिक रूप से उसका अधिकांश हिस्सा डांग क्षेत्र में आता है और डांग क्षेत्र चूंकि पहाड़ी इलाका है, वन्य क्षेत्र का काफी हिस्सा आता है, जिसके कारण भौगोलिक रूप से रोडों की कनेक्टिविटी एवं अन्य सुविधाएं प्रॉपर नहीं हैं। ऐसा दूरस्थ इलाका, जिसमें करणपुर, मंडरायल या हमारा महाराजपुरा, वे ऐसे इलाके हैं जहां पर रोड की सही सुविधा नहीं होने के कारण आज भी लोगों को चिकित्सा सुविधाओं, सरकार के द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं, उनका प्रॉपर लाभ नहीं मिल पा रहा है।

लोगों को छोटी-छोटी बीमारियों के लिए, वहां से वे लोग करौली या सपोटरा के लिए आते हैं तो रास्ते में आते हुए ही काफी लोगों की गम्भीर बीमारियों से या तो मृत्यु हो जाती है या उन्हें उचित स्वास्थ्य का लाभ नहीं मिल पाता है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं चिकित्सा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती क्षेत्र,

विशेषकर वन क्षेत्र एवं पहाड़ी इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण यहां रहने वाले नागरिकों को छोटी-छोटी बीमारियों के इलाज के लिए मीलों पैदल चलकर या महंगे निजी वाहनों का सहारा लेकर शहरों की ओर जाना पड़ता है। कई बार समय पर उपचार नहीं मिलने के कारण रोगी की स्थिति गम्भीर हो जाती है, उसकी जान तक चली जाती है। गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह स्थिति और भी चिन्ताजनक हो जाती है।

अतः, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय चिकित्सा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के ब्लॉक सपोटरा के गांव अड्डदा, बैरूंडा, भूत्यापुरा, निसाणा, सूरतपुरा एवं ब्लॉक मंडरायल के गांव बांसोली, आमरेकी, दाबर, अमरापुर, लाला का पुरा, कोंडरी में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की अति महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि उप स्वास्थ्य केन्द्र बालोती, चोलागांव, खेड़ला, निवेरा, महाराजपुरा, कल्याणी, बीजलपुर को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने के साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नारोली डांग, जो बड़ा कस्बा है, घनी आबादी है, उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी का भी धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने गत वर्ष सपोटरा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को जो उप जिला अस्पताल का दर्जा दिया, क्रमोन्नत किया, उसके लिए भूमि चिह्निकरण का सारा कार्य हो चुका है, लेकिन अभी तक उसकी वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हो पायी है, इसलिए सपोटरा उप जिला चिकित्सालय के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी करवाने के साथ ही उप जिला चिकित्सालय सपोटरा में मातृ एवं शिशु चिकित्सा इकाई खोलने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुड़गांव, जो उप खण्ड सपोटरा का बड़ा कस्बा है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 23 पर करौली-गंगापुर के मध्य स्थित है, कुड़गांव से करौली, गंगापुर सिटी एवं सपोटरा की दूरी लगभग 30 से 35 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर आये दिन घटित होने वाली गम्भीर दुर्घटनाओं में घायलों को तत्काल उपचार की आवश्यकता होती है, जिससे उनकी जान बचायी जा सके, इसलिए माननीय सभापति महोदय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुड़गांव में ट्रॉमा सैंटर खोले जाने की आवश्यकता है। साथ ही, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 50 बैड में क्रमोन्नत किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि क्षेत्र में पहले से मौजूद स्वास्थ्य केन्द्रों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाये। जिला चिकित्सालयों सहित जिले के सभी चिकित्सा संस्थानों में डॉक्टरों एवं स्टाफ के रिक्त पदों को भरा जाये। साथ में ही विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की जाये, आवश्यक दवाओं की निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित की जाये, जिससे मरीजों को इलाज के लिए महंगी दवाइयां नहीं खरीदनी पड़ें।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि चिकित्सालय भवन राजकीय आवासों में जांच हेतु मशीनों, जैसे सीबीसी सैमी ऑटो एनेलाइजर, एक्स-रे मशीन, सोनोग्राफी एवं अन्य आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि करौली जिले को बने लगभग 28 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जिले में जिला औषधि नियंत्रक का कार्यालय स्थापित नहीं हो पाया है, जिसके कारण दवा विक्रेताओं को अनुज्ञा पत्र सम्बन्धी कार्य हेतु 125 किलोमीटर दूर सवाई माधोपुर जाना पड़ता है। नकली एवं नशीली दवाइयों की बिक्री की प्रभावी रोकथाम की दृष्टि से भी करौली में जिला औषधि नियंत्रक कार्यालय सृजित किये जाने हेतु मेरा आपसे निवेदन है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा एक और निवेदन है और यह मेरा नहीं, मैं मानता हूं, सभी माननीय सदस्य यहां विराजमान हैं, इनके क्षेत्र में भी, एक हमारी कॉमन समस्या है कि मान लो, कोई घटना कहीं हो जाती है और हार्ट अटैक या ब्रेन हैमरेज या कोई क्रिटिकल केस है,

MKD/RTM/06.03.2025/18:40/3p

उसको जब सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ले जाते हैं और वहां से उसको जयपुर के एसएमएस के लिए रैफर किया जाता है तो वहां जो एम्बुलैंस है, उसको सम्बन्धित जिला चिकित्सालय में लेकर जाती है और वहां से टाइम है, आने-जाने का जो टाइम है, उसको जयपुर नहीं ले जाकर उसको जिला अस्पताल में ले जाती है, उस टाइम के कारण पेशेंट को जो उचित उपचार में विलम्ब होता हैं। माननीय चिकित्सा मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि 108 एम्बुलैंस सुविधा को मुहैया कराने का श्रम करें, जिससे रोगी को कम समय में बेहतर उपचार मिले सके।

साथ में, मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि 2025-26 के बजट में इन मांगों को शामिल किया जाए।

श्री सभापतिः अपनी बात समाप्त कीजिये।

श्री हंसराज मीना (सपोटरा): जिससे राजस्थान का हर नागरिक स्वस्थ एवं सशक्त जीवन जी सके। धन्यवाद, राम-राम सा।

श्री सभापतिः श्री विकास जी चौधरी। अपनी बात सात मिनट में समाप्त कीजिये।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): राम-राम, सभापति महोदय।

श्री सभापतिः राम-राम।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): आपने मांग संख्या 27- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं मांग संख्या 28- चिकित्सा शिक्षा पर मुझे अपनी बात रखने का जो मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

सभापति महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य न केवल हमारे नागरिकों के मौलिक अधिकार

से सम्बन्धित है, बल्कि राज्य के मानव संसाधन के समग्र विकास एवं राज्य के निवासियों को सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पिछले दशकों में हमारी कांग्रेस की सरकार ने राज्य में कई सकारात्मक पहल की है। मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष, चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, आरजीएचएस तथा अन्य कई सामाजिक योजनाएं, ये हमारे नागरिकों को न केवल आकस्मिक आये खर्चे से बचाने, बल्कि नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में भी सहायक रही है।

आदरणीय सभापति महोदय, यह दुर्भाग्य है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसकी देश और विदेश में बड़ी प्रशंसा की गई, जो प्रदेश के हर परिवार को 25 लाख तक कैश लेस इलाज सुविधा देती थी, बदलकर इसको आपने कम करने का काम किया, जिसे जनता आपके राज में आने के बाद भुगत रही है। आपने इसका नाम चैंज किया। नाम तो आप लगातार चैंज कर रहे हैं। मुझे तो अभी हम बैठे थे, एक साथी हमारा उधर चला गया था चुनावों में, मुझे लगा उसका नाम कहीं आप बदल न दें, तो कम से कम ये तो आप वो करना। मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने..। आदरणीय मंत्री महोदय, मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की, गहलोत साहब की सरकार ने, पर ऊपर वाले ने आवाज ऐसी दी है, जोगाराम जी...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आत्मा दूसरी है, आत्मा हमारी तरफ है।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): आज गरीब केवल अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। मुझे याद है, जब हम छात्र राजनीति करते-करते इस राजनीति में आए, जब हम अस्पतालों में लोगों से मिलने जाते थे, लेकिन 2018 से 2023 के बीच में कांग्रेस की सरकार में गरीब को अपनी जेब पर नजर डालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने एक गरीब परिवार को हिम्मत दी है, उसको चिरंजीवी जैसी योजना दी है।

आदरणीय सभापति महोदय, आजकल अखबारों की सुर्खियां बन गईं, स्वास्थ्य सरकार की कोई प्राथमिकता नहीं रही है। आपकी इस योजना में लगातार जटिलताएं हैं, भुगतान की समस्या है, गरीब आदमी अस्पतालों के चक्कर काटता फिर रहा है।

हमने राइट टू हैल्थ का कानून दिया, आज उस कानून की क्या स्थिति है, आप और हमसे छिपी हुई नहीं है। ये कानून आज भी लम्बित है, जनता को इसका लाभ नहीं मिल रहा है।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि कई दशकों से हम देख रहे हैं कि राजस्थान राज्य का एसएमएस मेडिकल कॉलेज सहित हमारे अजमेर का जेएलएन मेडिकल कॉलेज भारी प्रशासनिक अव्यवस्थाओं का शिकार इसलिए हो रहा है कि वहां डॉक्टरों को प्रशासकों के तौर पर लगाया गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यहां एक कैडर की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि हमारे बहुमूल्य चिकित्सकों को राहत मिल सके और वे मरीजों की ओर ध्यान दे सके।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बजट में डॉक्टरों और स्टाफ भर्ती की घोषणा की गई, स्वागत

है, लेकिन इतनी-सी की गई है, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): ऊंट के मुंह में सीरा।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): ऊंट के मुंह में सीरा। वो अख़बार वालों ने माफी मांग ली। उनसे गलती से हो गया, जीरा की जगह सीरा लिखा गया।

मैं, मंत्री महोदय, आज आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, पूरे राजस्थान में खाद्य सुरक्षा के नाम पर पूरे प्रदेश की जनता को जहर परोसा जा रहा है। आज मेरे जैसे नौजवान, अभी एक नौजवान का वीडियो आया कि घोड़ी पर तौरण मारने जा रहा है, उससे पहले अटैक आकर वह खत्म हो गया। नाचते-नाचते लोग गिर रहे हैं, जिम में वर्क ऑउट करते हुए गिर रहे हैं, इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कैम्प लगे, नौजवानों में आखिर क्या कमी आ गई, लेकिन पूरे राजस्थान में एक परसेप्शन बना हुआ है कि देश में कोरोनाकाल खंड में एक तरफ देश के प्रधान मंत्री जनता से ताली और थाली बजवा रहे थे, दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की अशोक गहलोत की सरकार ने भीलवाड़ा मॉडल पेश किया। जिसकी राजस्थान में ही नहीं, देश में नहीं, विदेशों में भी प्रशंसा की गई।

मैं चाहता हूं कि इस ओर आपका ध्यान जाए। हमारी नौजवान पीढ़ी को सुरक्षित रखने का काम आप कर सकें। (समय समाप्ति सूचक घंटी)।

आदरणीय सभापति महोदय, मुझे कम समय दिया है, क्योंकि आज बोलने वाले, अभी तो आपने 5 मिनट में ही घंटी बजा दी आपने।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): लगातार दूसरा बजट आपका असफल रहा है। जनता के आंसू आ रहे हैं। एक कवि ने कहा कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंसुओं का समुन्दर होना। आदरणीय, कृपलानी जी।

इसलिए, मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं सीधे मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ पर आना चाहता हूं। यह अख़बार की सुर्खी बता रही है कि 14 महीने में आपकी सरकार आने के बाद हमारे किशनगढ़ जैसी औद्योगिक नगरी में एक भी रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। आपने लगाया, लेकिन उसने आपकी बात नहीं मानी, जॉइन नहीं किया। किशनगढ़ जैसी जगह अगर सोनोग्राफी नहीं हो रही है तो इससे बड़ी विडम्बना इस सरकार के लिए, इस प्रदेश के लिए हो नहीं सकती है।

आदरणीय सभापति महोदय, किशनगढ़ का जिला अस्पताल है, जिसमें पूर्ववर्ती सरकार ने 42 करोड़ पास किए। आपने उस बजट को बढाया, 30 करोड़ से बढ़ाकर 72 करोड़ कर दिया। मैं स्वागत करता हूं, लेकिन 70 करोड़ पास करने के बाद आज भी नींव का पत्थर वहां नहीं लगा। जिला अस्पताल में 44 डॉक्टर होने चाहिए, आज भी दर्जन भर पद खाली है। हमारे हरमाड़ा में 4 पद सीएचसी में स्वीकृत हैं, एक डॉक्टर है। बोराड़ा में 5 हैं, वहां भी पद खाली हैं। अराई जैसी उपखंड में 8 डॉक्टर हैं, 4 पद खाली हैं, 3 हैं, जिसमें से 2 आ नहीं रहे हैं। क्षेत्र में 12 पीएचसी हैं, सुरसुरा में एक भी डॉक्टर नहीं है। बांदरसिंदरी में एक भी डॉक्टर नहीं

है, कई जगह डॉक्टरों का यह आलम है। खंडाज में एक भी डॉक्टर नहीं है, दायिदा में एक डॉक्टर नहीं है, डसूक में एक डॉक्टर नहीं है, गोटियाणा में एक डॉक्टर नहीं है। बेरोजगार लगातार नौकरी के लिए दर-दर भटक रहे हैं, उनको जॉब दो, ताकि हमारे राजस्थान और विशेषकर किशनगढ़ और अजमेर के क्षेत्र के लोगों के साथ कुठाराघात नहीं हो। स्वास्थ्य से बड़ी कोई पूंजी नहीं है। पहला सुख निरोगी काया है, लेकिन सरकार ने पहला सुख निरोगी काया नहीं, ये दूसरे सुख पर आ गये हैं।

श्री सभापतिः समाप्त कीजिये। श्री आदू राम जी मेघवाल।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): इसलिए ज्यादा समय यह सुख चलने वाला नहीं है। आदरणीय सभापति महोदय, ये गंगानगर की एक खबर, अब लास्ट, बस।

श्री सभापतिः अंकित नहीं होगा।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): 000

श्री आदू राम मेघवाल (चौहटन): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2025-26 की अनुदान मांग संख्या 27 व 28 पर सदन में बोलने का सुअवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आज के इस सारगर्भित, अतिमहत्वपूर्ण आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं के लोकहितकारी विषय, एक दूसरे से सीधे धरातल पर पारस्परिक जुड़े हुए हैं। साथ ही, सुसंगठित भी है।

माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम अपने विचार रखने से पूर्व प्रदेश की सम्पूर्ण जनता जनार्दन से कहना चाहूंगा कि राजस्थान प्रदेश अब उन्नति और प्रगति की राह पर अग्रसर है। प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा के कुशल नेतृत्व, दूर दृष्टि सोच एवं डबल इंजन की भाजपा सरकार बहुआयामी सफल कार्यशैली से प्रदेश में चहुंमुखी सर्वांगीण विकास की मझदार प्रबल गति से चलायमान है।

वास्तव में, राजस्थान प्रदेश अब अपनी अद्भुत, अलौकिक एवं विश्वसनीय छवि से सम्पूर्ण भारतवर्ष में पूर्णिमा की चांदनी की तरह से प्रकाशमय है।

Bhs/Rtm/06.03.25/18.50/3q

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि मैं जिस सीमावर्ती विधान सभा क्षेत्र चौहटन की देवतुल्य जनता के असीम आशीर्वाद, प्रेम तथा स्नेह को प्राप्त कर लोकतंत्र के पवित्र सदन में प्रतिनिधि के रूप में लोक तथा प्रदेश हित की अतिमहत्वपूर्ण मांगों को सदन में रखने हेतु उपस्थित हुआ हूं जो सीमावर्ती राजस्थान के सुदूर रेतीले धोरों की धरती, सीमांत तथा पिछड़ा क्षेत्र, भारत-पाक सीमा का अंतिम छोर है।

माननीय सभापति महोदय, हमारी भाजपा सरकार प्रदेश के सीमांत क्षेत्र में अंतिम छोर पर बैठे प्रत्येक भारतीय नागरिक के बेहतरीन भविष्य एवं जन-जन के कल्याण के उत्थान के

प्रति सदैव समर्पित एवं संकल्पित है।

प्रदेश की भजन लाल जी सरकार ने अपने 01 वर्ष के स्वर्णिम कार्यकाल में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा गठित भ्रष्टाचार, कुशासन व जंगलराज के स्तंभ को ध्वस्त कर सुशासन, आपणो अग्रणी राजस्थान एवं विकसित राजस्थान के बेहतरीन भविष्य की नींव रखी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुदान की मांग संख्या 27 -चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विषय पर मेरे निर्वाचित विधान सभा क्षेत्र चौहटन की अति आवश्यक मांगों को माननीय मुख्य मंत्री महोदय एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी के समक्ष रखता हूं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेड़वा को उप जिला अस्पताल में एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भूणिया को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने की अति आवश्यकता है, जिससे विस्तृत सीमावर्ती क्षेत्र में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का आमजन को उचित लाभ प्राप्त हो सके।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र चौहटन में वर्तमान में संचालित उप स्वास्थ्य केंद्र केकड़, जूना लखवारा, गिड़ा, नेहरो की नाडी, रोहिला, आलमसर, नवातला राठौड़ान, सावां, इशरोल, शोभाला दर्शान, नवापुरा, पुराणियों का तला, आलमसर, सणाऊ आदि को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो सकें एवं चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हो सके।

माननीय सभापति महोदय, चौहटन विधान सभा क्षेत्र में चौहटन पंचायत समिति के अंतर्गत नाइयों की ढाणी, साकरिया तला, देवाणियों का तला, जाटों की बस्ती, रूगपुरा बाछड़ाऊ, सुरते का तला, रावते का तला तारातरा मठ, गोदारों का तला लीलसर, सऊओ का तला, अणदोणी खोथो की ढाणी पोकरासर में धानाऊ पंचायत समिति के अंतर्गत ढाकों का तला, वसिये का तला, शशीबेरी में सेड़वा पंचायत समिति के अंतर्गत मोती की बेरी, भांभुओं का तला, चंपाबेरी शेरपुरा, रते का तला, नवातला, बाखासर, डोब की बेरी, आदर्श केकड़, बाबा रामदेव जी नगर भंवार, रणछोड़पुरा, नवातला, बाखासर में फागलिया पंचायत समिति के अंतर्गत अंबावा, रड़वा, मोगावा, खारी, खारतलाई बावरवाला, वेरडी मीठड़ी, छोटा हाथला, पांचरला, वांकलसर सांवलासी, खाराडेर ओगाला, श्रीयादे नगर गंगासरा, आदर्श चितरडी, पनोरिया आदि नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने की अति महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जिससे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हो सके एवं आम ग्रामीणजनों को चिकित्सा सुविधाओं के अनेकों लाभ प्राप्त हो सकें।

माननीय सभापति महोदय, विधान सभा क्षेत्र चौहटन में धनाऊ तहसील एवं पंचायत समिति मुख्यालय के समीप संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, धनाऊ में मौसमी बीमारियों एवं रोगियों की बढ़ती संख्या के कारण 30 बेड से 50 बेड में क्रमोन्नत करने या अभिवृद्धि करने की अति आवश्यकता है, जिससे आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो सके।

साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धनाऊ में एक्स-रे तथा ईसीजी मशीन उपलब्ध करवाई

जाये। जिससे पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता से आमजन को बेहतर चिकित्सा सेवाएं मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा कि विधान सभा क्षेत्र चौहटन के अंतर्गत जिला चिकित्सालय चौहटन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेड़वा तथा धनाऊ में 104 जननी एक्सप्रेस एवं 108 एंबुलेंस सेवा भी उपलब्ध करवाये जाने की अति महत्वपूर्ण आवश्यकता है, ताकि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के बीमारीग्रस्त रोगियों एवं घायलों-पीड़ितों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 2024-25 बजट घोषणा में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री जी भजन लाल जी शर्मा जी को और हमारी उप मुख्य मंत्री दिया कुमारी जी को और हमारे चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह जी खींवसर को, आपने बाड़मेर जिला मुख्यालय पर जिला अस्पताल के बाद में बाड़मेर जिले के अन्दर कोई जिला अस्पताल दिया है वह चौहटन विधान सक्षा क्षेत्र में दिया है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी से मेरा निवेदन रहेगा कि राजकीय जिला चिकित्सालय, चौहटन में बहुत से विशेषज्ञों चिकित्सकों मेडिसिन, सर्जरी, चर्म रोग, फोरेंसिक मेडिसिन आदि तमाम पद लम्बे समय से रिक्त पड़े हैं जिससे आमजन को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है। अतः इन समस्त रिक्त पदों को अति शीघ्र भरा जाए, जिससे आमजन को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के लाभ मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से अनुदान की मांग संख्या 28 चिकित्सा - शिक्षा विषय पर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्य मंत्री जी व माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष अति महत्वपूर्ण मांग को रखना चाहता हूं कि पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र बाड़मेर जिले में न होकर बालोतरा जिला मुख्यालय पर स्वीकृत एवं संचालित है। बाड़मेर जिले से अलग होकर बालोतरा नवीन जिला बन चुका है।

इस प्रकार बाड़मेर जिले में नवीन ए.एन.एम. प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने की नितान्त आवश्यकता है। इस हेतु मेरे निर्वाचित विधासभा क्षेत्र चौहटन में उपखंड मुख्यालय चौहटन पर 50 बेड का फील्ड हॉस्पिटल का नवीन भवन निर्मित है, यह भवन वर्तमान में खाली पड़ा है। ए.एन.एम. प्रशिक्षण केंद्र को प्रारंभ करने हेतु इस भवन को उपयोग में लिया जा सकता है। साथ ही यह भवन नवीन निर्माणाधीन जिला अस्पताल भवन के बिल्कुल नजदीक भी है, जिससे ए.एन.एम. प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण सुविधा नजदीकी से ही मिल सकेगी।

माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा मंत्री महोदय से मेरा निवेदन रहेगा कि विधान सभा क्षेत्र चौहटन में चौहटन उपखण्ड मुख्यालय पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने की स्वीकृति प्रदान करावें, जिससे सीमावर्ती क्षेत्र की महिला वर्ग को स्वास्थ्य

सेवाओं का उचित लाभ प्राप्त हो सके।

माननीय सभापति महोदय, विधान समा क्षेत्र चौहटन में राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय खोले जाने की मांग सीमावर्ती क्षेत्र के छात्र-छात्राओं द्वारा लम्बे समय से की जा रही है। इस हेतु माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा कि छात्र हित की जायज मांग के अनुसार विधान सभा क्षेत्र चौहटन में एक राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय की स्थापना की जाए ताकि चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में नये आयाम स्थापित हो सके। छात्र- छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

श्री आदू राम मेघवाल (चौहटन): माननीय सभापति महोदय, मैं आज के दिन हमारे यशस्वी देश के प्रधान मंत्री, विश्व के सबसे बडे नेता नरेन्द्र मोदी जी को भी इस सदन के अन्दर याद करूंगा, जिन्होंने कोरोना काल के अन्दर जहां राजस्थान की उस समय की सरकार होटलों के अन्दर बन्द थी उस समय हमारे यदि दवा, एक जमाना वह भी था कि मलेरिया की दवा ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: समाप्त कीजिये। श्री मोतीराम। पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिये।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): सभापति महोदय, टेबल करना है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर जिले के अन्दर एक सीटी स्कैन और हमारी जो एम.आर.आई मशीन्स हैं, ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप टेबल कीजिये।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): वो लम्बे समय से खराब चल रही है। साथ ही साथ गडरा को जिला अस्पताल बनाने के सम्बन्ध में और यूटीबी की लम्बे समय से काफी बड़ी मांग है।

श्री सभापति: टेबल कर दीजिये आप।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): मेरा निवेदन है कि यूटीबी के जो कर्मचारी हैं नर्सिंग इनकी आप कार्य अवधि बढायें। साथ ही साथ बाकी जो मैटेरियल है मैं टेबल कर रहा हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मोतीराम जी।

श्री मोतीराम (रेवदर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इस हेतु धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र वर्तमान में आधुनिक चिकित्सा से वंचित है। इस विधान सभा क्षेत्र के उप जिला चिकित्सालय आबू रोड व अधिकांश सी.एच.सी., पी.एच.सी. व उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों के अन्य पैरामेडिकल स्टाफ के पद रिक्त हैं इससे परेशान होकर क्षेत्र की गरीब जनता को मजबूरी में निकटवर्ती गुजरात राज्य के प्राइवेट चिकित्सालयों में महंगा इलाज करवाना पड़ता है।

माननीय सभापति महोदय, सी.एच.सी. रेवदर का वर्तमान भवन जर्जर अवस्था में है...

Kas/rtm/06.03.2025/19.00/4a

तथा यहां पर वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए जगह भी अपर्याप्त है। अतः इस सी.एच.सी. भवन को राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित ग्राम पंचायत लूणोल के गांव राजगढ़ में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा आवंटित ट्रोमा सेन्टर की भूमि पर स्थानान्तरित किया जाये, क्योंकि यह जगह आवागमन की दृष्टि से उपयुक्त है और यहां भवन निर्माण व अन्य सुविधाओं हेतु भामाशाह, दानदाता पैसा देने के लिए तैयार हैं। हाईवे पर सी.एच.सी. स्थानान्तरित होने से सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल लोगों को त्वरित रूप से इलाज भी मिल सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, सी.एच.सी. रेवदर पर अस्थि रोग विशेषज्ञ, मेडिसन व सर्जरी विशेषज्ञों के पद भी रिक्त हैं। इन तीनों विशेषज्ञ चिकित्सकों का यहां होना अति आवश्यक है। अतः मेरा सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र आबू रोड की चिकित्सा संबंधी उक्त समस्याओं का यथाशीघ्र समाधान कर क्षेत्र की आम जनता को राहत प्रदान कर मुझे अनुगृहीत करावें। धन्यवाद।

श्री सभापतिः ललित जी, हमेशा इधर से जाना है, बीच में से होकर नहीं जाना। श्री विरेन्द्र सिंह जी मसूदा।

श्री विरेन्द्र सिंह (मसूदा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27 और 28 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, एक कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया। करो योग, रहो निरोग, इसी सन्दर्भ में हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया और उस दिन पूरी दुनिया योग करती है और बीमारी को दूर भगाती है।

माननीय सभापति महोदय, आज के समय में एलोपैथी के डाक्टर चाहे भारत के हो या विदेशी हो, वो भी एलोपैथी के साथ योग और प्राणायाम का निर्देश देते हैं कि दवाई तो लो, लेकिन योग करना भी आवश्यक है। योग और प्राणायाम में वह शक्ति है, जिससे कैंसर जैसा गंभीर और असाध्य रोग भी ठीक हो रहा है। उसका गवाह है बाबा रामदेव का पतंजलि योग पीठ। विदेशी डाक्टर जो कैंसर से पीड़ित है, वो ऑपरेशन न करवा कर वहां पतंजलि योग पीठ में आकर योग और प्राणायाम कर रहे हैं, उससे कैंसर जैसी बीमारी भी ठीक हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी ने कोरोना में देश को बचाया और देश ही नहीं विदेश में भी वैक्सीन भिजवाई। ....(व्यवधान).... जान नहीं गई है, जान बचाई है। आज ये दीपक जलाने, थाली बजाने, शंख बजाने का विरोध कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, शंख बजाने से हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन की क्षमता बढ़ती है, यह एक वैज्ञानिक कारण है और आज आप लोग भी जब चुनावों के समय मंदिरों में जाते हो, तो वहां खूब थाली बजाते हो, खूब दीपक जलाते हो और शंख बजाते हो कि भगवान मुझे इस चुनाव में विजयश्री प्रदान करें। देश को बचाने के लिये देश के माननीय प्रधान मंत्री जी ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया। कोरोना में जो वैक्सीन लगी, हमारे विपक्ष के साथी आज उसको हार्ट

अटैक से जोड़ रहे हैं। हार्ट अटैक की बीमारी कोई नई नहीं है। आज के समय में हमारे एलोपैथी के चिकित्सक भी सलाह देते हैं कि आप रोज घूमने जाओ और रोजाना योग और प्राणायाम करो, जिससे शरीर में कॉलेस्ट्रोल की मात्रा कम हो।

(समय: बजे)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, इनके राज में इनके बजट में इन्होंने जो घोषणाएं कीं, उनमें से 70-80 परसेंट काम नहीं हुए, केवल 20-25 परसेंट काम हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, इनके समय में केकड़ी से जो चिकित्सा मंत्री थे, वो हमारे विधान सभा क्षेत्र से भी पोस्टें तोड़कर केकड़ी ले गये जैसे कि वो सिर्फ केकड़ी के ही चिकित्सा मंत्री थे। सभापति महोदय, यह कहते हैं कि वोटों की राजनीति करते हैं। वोटों की राजनीति करने का मैं आपको एक उदाहरण दूं। हमारे लूलवा ग्राम पंचायत है श्री सीमेंट के पास, वहां ग्राम पंचायत के केवल दो वार्ड हैं, जो एक सब सेंटर के लायक है, वहां इनके शासन में इन्होंने एक सीएचसी खुलवा दी। सरकार के पैसे का दुरुपयोग हुआ और आज वहां डाक्टर बैठे रहते हैं, कोई पेशेंट वहां नहीं पहुंचते हैं, कांग्रेस की सरकार ने ये काम किये हैं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे इस बजट में महत्वपूर्ण काम किये हैं। केन्द्र प्रवर्तित योजना में नवीन मेडिकल कॉलेज खोला जाना तथा जिला चिकित्सालयों के उन्नयन के प्रथम चरण में भरतपुर, भीलवाड़ा, चूरू, पाली, डूंगरपुर, बाड़मेर एवं सीकर। द्वितीय चरण में धोलपुर तथा तृतीय चरण में श्रीगंगानगर, चित्तोडगढ़, सिरोही, अलवर, दौसा, करोली, बूंदी, बारां, इत्यादि में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किये गये हैं।

माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण की मेडिकल कॉलेजों में परियोजना लागत राशि 179 करोड़, द्वितीय चरण में 250 करोड़ तथा तृतीय चरण में 325 करोड़ निर्धारित की गई है। भारत सरकार से 31 मार्च, 2024 तक इन तीन चरणों में कुल 2613 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है, जिसके विरुद्ध 2,156.23 करोड़ रुपये की राशि 15 फरवरी, 2025 तक व्यय की जा चुकी है। भारत सरकार से प्राप्त अग्रिम के विरुद्ध देय राज्यांश 1,742 करोड़ के विरुद्ध 2,160.19 करोड़ की राशि व्यय की जा चुकी है। इन 23 मेडिकल कॉलेजों के विरुद्ध 21 कॉलेज अभी तक प्रारंभ किये जा चुके हैं तथा टोंक व जैसलमेर में आगामी शैक्षणिक सत्र में कॉलेज प्रारंभ करने के लिये राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली को आवेदन कर दिया गया है। भारत सरकार द्वारा आरंभ हो चुके 21 कॉलेजों के लिये 2,380 एमबीबीएस सीट्स तथा 94 पीजी सीट्स स्वीकृत की जा चुकी हैं। आज हमारे विपक्ष के साथी कहते हैं कि डाक्टरों की कमी है। अगर राजस्थान में समय पर मेडिकल कॉलेज खुलते, डाक्टर ट्रेनिंग करके आते तो आज डाक्टरों की कमी नहीं रहती।

माननीय सभापति महोदय, केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 23 मेडिकल कॉलेजों के साथ भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 23 नये नर्सिंग कॉलेज खोले जाने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के अंतर्गत 60 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार तथा 40

प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी। यह प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्य मंत्री भजन लाल जी की चिकित्सा के क्षेत्र में गारंटी है।

माननीय सभापति महोदय, नर्सिंग कॉलेज हेतु परियोजना लागत राशि 230 करोड़ रुपये भारत सरकार एवं 92 करोड़ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। इन सभी 23 नर्सिंग महाविद्यालयों में बी एससी नर्सिंग पाठ्यक्रम विगत वर्षों के दौरान तीन शैक्षणिक सत्रों में आरंभ हो चुके हैं। प्रति कॉलेज 60 बी एससी सीट के हिसाब से 1,380 छात्र प्रति वर्ष प्रवेश प्राप्त कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, राज्य में तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा प्रति जिला एक नर्सिंग कॉलेज प्रारंभ करने के नीतिगत निर्णय के तहत तीन वर्ष की बजट घोषणाओं में कुल 29 नर्सिंग कॉलेज आरंभ करने की घोषणा की गई है।

Msk/rtm/05.03.25/1910/4b

सिविल निर्माण लागत राशि 21.03 करोड़ रुपये प्रति कॉलेज निर्धारित की गयी है। इस प्रकार का कुल योजना 610.03 करोड़ रुपये निर्धारित हुई, जिसके विरूद्ध भारत सरकार की हिस्सा राशि 138 करोड़ तथा राज्य सरकार की हिस्सा राशि 472.03 करोड़ रुपये है। माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार की यू जी, पी जी सीट अभिवृद्धि योजना फेज-2 के अन्तर्गत राज्य को कुल 1,170 पी जी सीट तथा 750 यू जी सीट की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी है। इस योजना के अंतर्गत प्रति सीट 1.20 करोड़ रुपये की राशि में से 7 प्रतिशत राशि अर्थात 72 लाख रुपये भारत सरकार द्वारा तथा शेष 40 प्रतिशत राशि अर्थात 48 लाख रुपये राज्य सरकार द्वारा वहन किये जायेंगे। माननीय सभापति महोदय, राज्य के लिए कुल स्वीकृत 1,170 पीजी सीटों में से 643 सीटें प्रारंभ हो चुकी हैं तथा 527 सीट प्रारंभ करने के लिए एन एम सी को आवेदन प्रक्रियाधीन है। राज्य के लिए कुल स्वीकृत 750 यू जी सीटों में से 730 सीटें प्रारंभ हो चुकी हैं तथा 20 सीट प्रारंभ करने के लिए एन एम सी को आवेदन प्रक्रियाधीन है।

श्री सभापतिः समाप्त करें।

श्री विरेन्द्र सिंह (मसूदा): मेरे विधान सभा क्षेत्र में प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री जी, वित्त मंत्री जी और चिकित्सा मंत्री जी ने बहुत कुछ दिया है। मसूदा में उप जिला चिकित्सालय दिया है, भिनाय में 50 बेड की सी एच सी की घोषणा की है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापतिः विराजें। श्री अमित चाचाण।

श्री विरेन्द्र सिंह (मसूदा): लेकिन फिर भी मेरे उप जिला चिकित्सालय मसूदा में जो पिछले बजट में हुआ, उसके लिए निर्माण स्वीकृति। उप जिला चिकित्सालय मसूदा में डॉक्टर लगवाने।

श्री सभापतिः विराजें। प्लीज विराजें।

श्री अमित चाचाण (नोहर): सभापति महोदय, आपने मुझे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत आभार। भूखे को रोटी, मरीज

को दवा सबसे बड़ी सेवा है। कांग्रेस का शासन जब-जब आया, चिकित्सा के क्षेत्र में अनेकों-अनेक क्रान्तिकारी कदम रखे गये। अनेकों-अनेक योजनाएं आमजन किसान, मजदूरों के लिए लेकर आये, चाहे वह नि:शुल्क दवा योजना हो, नि:शुल्क जांच योजना हो, मुख्य मंत्री चिरंजीवी बीमा योजना हो, हर योजना से पंक्ति के अंतिम छोर तक के व्यक्ति को लाभान्वितकरने का काम किया। जब कोरोना काल आया, पूरे देश और विश्व के अन्दर राजस्थान की तारीफ की गयी। मुख्य मंत्री अशोक गहलोत की तारीफ की गयी कि उन्होंने एक शब्द कहा था कि चाहे मेरी सरकार का पूरा खजाना क्यों न खाली हो जाये, मैं मेरे राजस्थान की जनता को तड़पता हुआ नहीं देखा सकता। यह राजस्थान एकमात्र राज्य था, जहां कोरोना मरीजों का नि:शुल्क इलाज किया जा रहा था। जो रेमडेसिविर इंजेक्शन 50-50 हजार रुपये ब्लैक में बिक रहे थे, वे सी एच सी लेवल पर भी मुख्य मंत्री ने नि:शुल्क उपलब्ध कराने का काम किया। माननीय मंत्री महोदय का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में उप जिला चिकित्सालय है, उसके भवन का निर्माण दस करोड़ रुपये की लागत से चल रहा है। अभी 30 करोड़ रुपये की और आवश्यकता है। जुलाई के सत्र में मंत्री महोदय आपने मुझे कहा था कि एक टीम का गठन करके आपके क्षेत्र में मैं भेजूंगा, लेकिन आज तक छह महीने गुजरने के बाद भी वहां कोई टीम नहीं पहुंची। इसके साथ ही, मैं आपसे कहूंगा कि उसको जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने का आप काम करें। 100 बेड से 150 बेड में क्रमोन्नत करने का काम करें, क्योंकि रोगी भार को देखते हुए, वहां 1500 से 2000 की ओपीडी है। महीने की 300-300 डिलीवरियां उस हॉस्पिटल के अन्दर हो रही हैं। अल्ट्रा साउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, जांच मशीनों की वहां आवश्यकता है।

माननीय मंत्री महोदय, वहां ट्रोमा सेंटर का उद्घाटन हमने डेढ़ साल पहले कर दिया था। तीन करोड़ से शानदार भवन का निर्माण भी हो चुका था, लेकिन आज दिनांक तक वहां छह के छह डॉक्टरों के पद रिक्त हैं। ट्रोमा सेंटर का कोई भी सामान उस बिल्डिंग में नहीं पहुंचा है, जांच मशीनें भीं। आपके कार्यकाल का भी सवा साल गुजर चुका है, इसलिए आपसे निवेदन है किइस ट्रोमा सेंटर में डॉक्टरों के पद भरे जायें और वह सामान पहुंचाया जाए। उप जिला चिकित्सालय में ऑर्थो का पद भी रिक्त है, वह भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरे शहर में फकीरचंद-लालचंद कणदोई शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है, जो दानदाता के द्वारा करोड़ों रुपये की भूमि में एक शानदार बिल्डिंग का निर्माण कार्य करवाया गया था, लेकिन आज उस दानदाता को पीड़ा व दर्द होता है। वह हॉस्पिटल मात्र टीकाकरण का रह गया है।

मेरा आपसे निवेदन है कि चाहे आप शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करें, चाहे उसको सैटेलाइट हॉस्पिटल में क्रमोन्नत करें, जिससे कि दानदाताओं का भी हौसला बढ़े। मेरे गांव धानसिया, कुइयां, मंदरपुर जो पीएचसी है, उसको सीएचसी में क्रमोन्नत करने का काम करें। दलपतपुरा, जबरासर, मालासर, रतनपुरा, पांडुसर और थालड़का के उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने का करें। जिले का सबसे बड़ा गांव

मानगढ़, फेफड़ा जो उप तहसील है, जिसमें सीएचसी का भवन जर्जर हो चुका है, उस भवन का आप निर्माण करें और उस गांव की आबादी 20 हजार है, उसको भी 30 बेड से बढ़ाकर 50 बेड करने का आप करें।

माननीय सभापति महोदय, पिछले दो-तीन वर्षों में हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक की बहुत ही घटनाएं घट रही हैं। यह शहरी क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। किसान के छोटे-छोटे युवा, जवान भी इस हार्ट कोलैप्स से जा रहे हैं। हमें प्रयास करना होगा कि उप जिला स्तर पर हार्ट केयर यूनिट की हम स्थापना करें, जिससे कि हम आने वाले समय में जानों को बचा सकें। एक कैंसर रोग दिन-प्रतिदिन हर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में पैर पसार रहा है, इसके लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए कि जिला स्तर पर भी कोई कैंसर यूनिट बने, जिससे कि कैंसर के मरीजों को संभाग स्तर पर नहीं आना पड़े।

हमारे कई युवाओं की मांग लंबे समय से चल रही है। चाहे वह प्रयोगशाला सहायक हो, जिसकी भर्ती अगस्त, 2022 में की गयी थी, उनको नियुक्ति दी गयी थी और अगस्त 2004 में उनका परिवीक्षाकाल भी पूरा हो चुका है। छह माह गुजरने के बाद भी उनकी फिक्सेशन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पायी है। माननीय अधिकारी गण भी यहां बैठे हैं तो उनसे भी कहना चाहूंगा कि अल्प वेतनभोगियों को ज्यादा चक्कर न कटायें। उनकी समस्याओं का समय पर समाधान करें। हमारे जो योग शिक्षक लगे हुए हैं, उनकी भी लंबी-चौड़ी मांग है कि योग सत्र के दिन 10 दिन से बढ़ाकर उनका पूरा महीना किया जाए। पूर्व में महिला योग शिक्षकों की वेतन विसंगतियों को दूर करके उनके मानदेय को बढ़ाया जाये, जिससे अन्य राज्यों में जिनके मानदेय काफी ज्यादा हैं और राजस्थान में उनको नाममात्र का मानदेय दिया जा रहा है। पार्ट टाइम योग शिक्षकों की भर्ती को राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स, 2022 में शामिल करते हुए उन्हें स्थायी पद सृजित किये जाएं और एनएचएम में जो संविदाकर्मी हैं, उनको संविदा रूल 2022 के तहत एनएचएम के कार्यरत संविदाकर्मियों को नियमित करने के लिए 4,518 पद सृजित किये गये थे। वित्त विभाग ने वह एसओपी भी जारी कर दी, लेकिन आज दिनांक तक उनको नियुक्ति नहीं दी गयी है, यह भी मंत्री महोदय से मेरी मांग है। अधिकारियों से मैं कहना चाहूंगा कि समय पर काम करें, जिससे कि उनको चक्कर न काटने पड़े। दूरदराज के जो हमारे युवा साथी हैं, वे राजधानी में आते हैं, उनका खर्चा भी लगता है और बार-बार आपसे मिलने का निवेदन करते हैं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके अलावा एक हमारे जो सीएचओ की मांग है कि उनको भी जो 25 हजार रुपये दिये जा रहे हैं, उनको भी हम परमानेंट करने का काम करें। इसके अलावा जो प्रति माह 15 हजार रुपये इंसेटिव की राशि को भी फिक्स मानदेय में, जैसा बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखण्ड में दिया जाता है, उसी तरह ही उनको भी दिया जाये। यह भी मेरी आपसे मांग है। एक प्रयोगशाला भर्ती का तो मैंने आपको बता दिया। माननीय मंत्री महोदय, मेरा आपसे विशेष अनुरोध रहेगा कि चिकित्सा के मामले में राजनीति न करते हुए पक्ष व विपक्ष के जिन-जिन

विधायकों की मांग है और जो जायज मांग है, उनको आप समय पर पूर्ण करायें।

श्री सभापतिः आपस में बात नहीं। माननीय सदस्य, आपस में बातें मत करो। ललित मीणा। माननीय ललित मीणा जी।

श्री अमित चाचाण (नोहर): आपके सवा साल गुजरने के बाद भी पूर्ववर्ती सरकार के जो भी काम थे। आज वे भवनों के निर्माण के बाद उद्घाटन की बात हो, चाहे वह भवनों के शिलान्यास की बात हो, आप उन्हीं कार्यों को करते जा रहे हैं। सवा साल में भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार के द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में कोई भी नया कदम नहीं उठाया गया है। मेरा आपसे आग्रह है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी पिछले पांच वर्षों में 13 सब-सेंटर दिये गये। चार पी एच सी दी गयी, एक सी एच सी दी गयी, एक सब-डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दिया और एक ब्लड बैंक की बिल्डिंग भी बन चुकी है। उसका भी आप संचालन करने का काम करें, जिससे कि रक्तदाताओं के कैम्प भी लगते रहते हैं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) अगर उसी ब्लड बैंक उसका रक्त संधारण किया जायेगा तो समय पर मरीजों को ब्लड मिलेगा, जिससे गंभीर एक्सीडेंट होते हैं या किसी भी तरह की सर्जरी में वह ब्लड काम आयेगा। तो हम उसमें दुर्घटना को रोकने का काम कर सकें। यह भी मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है।

मंत्री महोदय, जिस तरह से आपने मुझे इस सदन के अन्दर जुलाई सत्र के दौरान आश्वस्त किया था कि आपके विधान सभा क्षेत्र में टीम आयेगी, लेकिन आज दिनांक तक टीम नहीं आयी। अगर सदन में हम कोई बात कहते हैं, सदन में हम किसी तरह का आश्वासन देते हैं तो यह आठ करोड़ की जनता की भावनाओं का सदन है। इसको गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन मंत्री महोदय शायद आपकी बातों को अधिकारियों ने गंभीरता से नहीं लिया होगा। इसलिए एक बार पुनः मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसमें विचार करें, अधिकारियों को निर्देश दें और मेरे विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सा के क्षेत्र में जो-जो समस्याएं आ रही हैं, चाहे वह भवन निर्माण के कार्यों की आ रही है, चाहे वह किसी तरह के इक्विपमेंट की आ रही है, चाहे वह बेड वृद्धि की आ ही है, चाहे वह नये शिक्षा संस्थान खोलने की आ रही है, आप उनको समय पर करायें, जिससे कि मेरे क्षेत्र की तमाम जनता को लाभ मिल सके। गरीब, मरीज को लाभ मिल सके, गरीब व्यक्ति को लाभ मिल सके, यह मैं आपसे निवेदन और अपील करता हूं। आपने मुझे दिया, आपका बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापतिः श्री अनिल कुमार कटारा। अपन ऐसे आपस में बातें करने लगते हैं, जैसे यह वार्तालाप गृह हो। सामने वाले सदस्य बहुत इम्पोर्टेंट कहते हैं, उनकी बातें सुनी जाये। अपनी बातें लॉबी में बैठकर भी की जा सकती हैं।

mdp/rtm/06.03.25/19:20/4c

श्री अनिल कुमार कटारा (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, मुझे चिकित्सा एंव स्वास्थ्य पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद व आभार।

सभापति महोदय, मैं आज इस सदन में चौरासी विधान सभा की उस मां का दर्द बयां करने खड़ा हुआ हूं, जिसकी तकलीफ ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। जिसकी ममता का अपमान हमारे चिकित्सा तंत्र ने खुलेआम किया। दिनांक 2 दिसम्बर, 2024, ये तारीख राजस्थान केलिए काला धब्बा बनकर दर्ज हुई। जब डूंगरपुर जिले की पीठ पीएचसी के आँगन में एक बेबस मां दर्द से तड़पती रही, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मगर वहां बैठे चिकित्साकर्मियों ने उसका प्रसव कराने से इंकार कर दिया। न कोई डाक्टर आया, न कोई नर्स, न कोई सहारा देने वाला हाथ। वहीं खुले आम आसमान के नीचे अस्पताल के दरवाजे पर उस मां ने अपने लाल को जन्म दिया। अगले दिन उसी पीएचसी के बाहर एक बोर्ड टांग दिया गया, यहां आपातकालीन प्रसव सुविधा उपलब्ध नहीं है। वाह री सरकार, वाह री चिकित्सा व्यवस्था, जब जिंदा मां बच्चों की चीखों को सुनकर भी आपकी आत्मा नहीं कांपी तो फिर उस बोर्ड पर लिखने की जरूरत क्या थी? ये बोर्ड आपकी संवेदनहीनता का प्रमाण पत्र है। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि आदिवासी इलाके में अस्पताल सिर्फ इमारतें हैं। वहां संवेदनाएं नहीं, वहां डाक्टर नहीं, वहां सिर्फ सिस्टम की लाशें पड़ी हैं।

माननीय सभापति महोदय, अब बात करें सिकल सेल एनिमिया की। केन्द्र सरकार ने 2047 तक सिकल सेल एनिमिया मुक्त भारत का सपना देखा। मगर हकीकत यह है कि राजस्थान के 9 आदिवासी जिलों में सरकारी आंकडे यह बताते हैं कि 10 हजार 746 लोग सिकल सेल एनिमिया से पीड़ित है। यह आंकडे तब के हैं, जब स्क्रीनिंग नाममात्र की हुई है। अगर ईमानदारी से हर गांव, हर फले, हर घर पर जाकर स्क्रीनिंग की जाए तो ये आंकडे लाखों में निकलेंगे। जब स्क्रीनिंग ही नहीं करेंगे तो बीमारी को कैसे पकड़ेंगे? जब बीमारी ही नहीं पकड़ेंगे तो इलाज कैसे करेंगे? वर्ष 2047 में सिकल सेल मुक्त भारत बनाने का सपना महज चुनावी वादा है।

हम तो मरते आ रहे हैं सदियों से,
सरकारी वादों की चादर ओढ़कर,
कभी मलेरिया, कभी टीबी, कभी सिकल सेल,
हमारी जिंदगी बन गयी है लाइलाज कैंसर।

माननीय सभापति महोदय, आदिवासी इलाके की चिकित्सा व्यवस्था सिर्फ रिपोर्ट्स में चमक रही हैं। धरातल पर सिर्फ अँधेरा है, लाचारी है, बेबसी है। हम सरकार से कहना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं, अगर इन मुद्दों पर तुरंत कार्यवाही नहीं हुई तो हम सड़कों पर उतरकर अन्याय के खिलाफ आरपार की लड़ाई लड़ेंगे। अगर इंसानियत बचानी है तो हमें न्याय दीजिए। अगर आदिवासी की ममता की कद्र है तो हमें इंसाफ दो। वरना हर गांव, हर चौपाल से एक ही आवाज आयेगा, भील प्रदेश बनाना ही आखिरी हल है।

माननीय सभापति महोदय, चौरासी विधान सभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं की बात करें तो मेरे क्षेत्र में अस्पतालों की स्थिति बेहद ही गंभीर है। कई अस्पतालों में डाक्टर्स की कमी है, तो कई जगहों पर स्टॉफ की कमी नजर आती है। वहां पर चिकित्सा सुविधाएं

ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। ऐसे में आम जनता का इलाज कैसे संभव है? सरकारी अस्पतालों में जरूरी दवाइयों की कमी के कारण मरीजों को गोलियां व कुछ प्राथमिक दवाइयां देकर संतुष्ट किया जाता है। इसी कारण वहां गरीब मरीज को प्राइवेट मेडिकल पर दवाइयां खरीदनी पड़ती है। कई सारे केसेज ऐसे हैं, डिलीवरी व एक्सीडेंटल केसेजों को रैफर कर दिया जाता है। सबसे बड़ी दुविधा यह है कि आम नागरिकों को अच्छी सुविधाएं नहीं मिलने के कारण अपनी जमीनें गिरवी रखनी पड़ती है, अपने गहने गिरवी रखने पड़ते हैं या फिर किसी से ब्याज पर पैसे लेकर अच्छे इलाज के लिए गुजरात जाते हैं। इस कारण आम नागरिक की आर्थिक कमर टूटती जा रही है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पी एच सी व सी एच सी के भवन तो हैं, लेकिन उनकी हालत बहुत ही खराब व जर्जर अवस्था में है। वहां पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इस पर काम करने की जरूरत है। माननीय मंत्री महोदय को विशेषकर दक्षिणी राजस्थान के अंतिम छोर पर बसे आदिवासी इलाके को स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी अंचल के गांवों में कई झोलाछाप बंगाली 10वीं, 12वीं पास करके खुले आम क्लिनिक खोल लेते हैं। ऐसे लोगों को किसकी शह पर क्लिनिक खोलने का अधिकार दिया गया? चिकित्सा विभाग के बड़े अधिकारियों का साया उन पर है, ऐसा लग रहा है। फिर भी ऐसा अगर नहीं है तो अधिकारी लोग इन पर कार्यवाही करें। सी एच सी व पी एच सी में जांचों के नाम पर लिस्ट बड़ी है।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री अनिल कुमार कटारा (चौरासी): कुछ बीमारी की जांचें हो रही हैं और कुछ की नहीं। मशीनें वहां पर खराब पड़ी हैं।

श्री सभापति: विराजिए। श्री मांगेलाल जी।

श्री अनिल कुमार कटारा (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, कुछ डाक्टर्स ने खुद के निजी अस्पताल खोल रखे हैं।

श्री सभापति: बैठिए।

श्री अनिल कुमार कटारा (चौरासी): पी एच सी व सी एच सी पर सुविधाएं नहीं मिल रही और मजबूरन डाक्टर्स के निजी अस्पतालों में जाना पड़ता है।

श्री मांगेलाल मीना (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, मांग संख्या 27 और 28 पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपको और हमारी पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता को बहुत-बहुत धन्यवाद। गहलोत सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने राइट-टू-हेल्थ कानून बनाया था, लेकिन इस सरकार को नियम बनाकर, इसको इम्प्लीमेंट करना था। सवा साल में आज तक नियम नहीं बनाए, इसको लागू नहीं किया। इसको लागू करवाना चाहिए सरकार को। यह मेरी सरकार से अपेक्षा है।

वर्ष 2024-25 में एनआरएचएम में 20.27 करोड़ रुपये का बजट आवंटित हुआ और

खर्चा केवल 3.49 करोड़ का हुआ। ये आपकी सरकार की उपलब्धि है। दिसम्बर तक 2024-25 में नि:शुल्क दवा योजना में 90 दवाओं के सैम्पल फेल किये और सरकार ने एक भी फर्म को न तो ब्लैकलिस्ट किया, न कोई डिबार किया। कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। जबकि कांग्रेस सरकार में शत-प्रतिशत बजट का यूटिलाइजेशन होता था। जनता को दवाओं का लाभ मिलता था। सही दवाएं मिलती थीं। आपने आयुष्मान आरोग्य मन्दिर के नाम से सीएचसी/पीएचसी के नाम के आगे केवल पेंट से लिखने का काम किया है और कोई काम नहीं किया है। जनता आपकी कार्यशैली और जिस तरह से काम कर रहे हैं, बजट खोखला है, ढोल की तरह खाली है, आवाज ही आवाज है। कुछ काम करके दिखाइए। जनता आपका रिपोर्ट कार्ड बना रही है। नहीं तो आप इसके परिणाम भुगतेंगे। जनता गहलोत सरकार को, कांग्रेस सरकार को याद करती है। उसकी उपलब्धियों के पीछे याद करती है। कहती है-

गहलोत इश्यो कांई जादू करगो रै,
जनता कूं आवै याद,
कांग्रेस इश्यो कांई जादू करगी रै,
जनता कूं आवै याद।

श्री सभापतिः पूरा तो सुनाओ।

श्री मांगेलाल मीना (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): आरटीएच कानून बनाया था। चिरंजीवी बीमा योजना में 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा था, जिसको आपने 5 लाख किया, घटाने का काम किया, जो भी लाभ नहीं मिल रहा है। 10 लाख दुर्घटना बीमा योजना कवर थी। कांग्रेस राज में 5 वर्ष में 1674 सब-सेंटर खोले गये थे, 710 पी एच सी खोली गयी थी, 325 सी एच सी खोली गयी थी, 67 उप जिला अस्पताल बनाये गये थे, 70 जिला अस्पताल बनाये गये थे, 10 सैटेलाइट अस्पताल बनाये गये थे और एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी। सभापति महोदय, आपसे मैं निवेदन करूंगा कि भारत सरकार के निर्धारित नॉर्म्स के अनुसार सी एच सी की संख्या राजस्थान में 2022 में 313 अधिक थी, जिसके कारण राजस्थान देश में अग्रणी रहा था। इसका श्रेय कांग्रेस सरकार को ही जाता है।

सभापति महोदय, मैं अब मेरी विधान सभा पर आता हूं। माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपसे निवेदन किया था कि हमारे पिनान और राजगढ़ सीएचसी पर ट्रोमा सेंटर होने चाहिए। उसकी स्वीकृति निकाली है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। कुछ मांगों के लिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 2010 में 75 बेड का क्रमोन्नत हुआ था सी एच सी, राजगढ़, जो कि जिला अस्पताल और उप जिला अस्पताल के निर्धारित मापदंडों से ज्यादा रखता है, उसके बाद भी आज भी सी एच सी है। आउटडोर 3 लाख 82 हजार 249, पर-ईयर की। आई पी डी 19 हजार 604 और शल्य क्रिया 4 हजार 224, प्रसव 2767, लेब जांच 1 लाख 6 हजार से ज्यादा है। जिला अस्पताल की दूरी 40 किलोमीटर, मेगा हाइवे 2 किलोमीटर दूर है, दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस 18 किलोमीटर दूर है, नेशनल हाइवे 3 किलोमीटर दूर है। इन सभी मापदंडों को देखते हुए

और चार विधान सभा के लोग आते हैं वहां पर। अलवर ग्रामीण, थानागाजी, बांदीकुई और राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ के लोग आते हैं। ये निर्धारित मापदंडों से ऊपर है। आपने बहुत सारे जिला अस्पताल बना रखे हैं। माननीय मंत्री जी, आपसे निवेदन है कि जनता को लाभ देने के लिए और जनता को राहत देने के लिए गुहार है आपसे कि इसको जिला अस्पताल/उप जिला अस्पताल में घोषणा करने का कष्ट करें। जनता आपकी आभारी रहेगी।

Ans/rtm 19.30 4d 06.03.2025

मैं और वहां की जनता आपका तहेदिल से आभार व्यक्त करेंगे।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री मांगेलाल मीना (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): कुछ करेंगे तो राजगढ़ में आपका स्वागत कराएंगे।

श्री सभापति: गीत पूरा नहीं गाते यह, बैठो आप। श्रीमती सुशीला।

श्री मांगेलाल मीना (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): साहब, अभी तो मेरा टाइम है।

श्री सभापति: बैठो-बैठो। अंकित नहीं होगा।

श्रीमती सुशीला रामेश्वर डूडी (नोखा): माननीय सभापति महोदय, आज आपने मुझे सांकेतिक कटौती प्रस्ताव की मांग संख्या 21 - चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूं।

आदरणीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र नोखा में जिला चिकित्सालय के भवन निर्माण की स्वीकृति सितम्बर, 2023 में जारी हो चुकी थी, लेकिन खेद का विषय है कि जिला चिकित्सालय की स्वीकृति जारी होने के डेढ़ वर्ष बाद भी जिला चिकित्सालय का भवन निर्माण नहीं होने से नोखा की जनता आज भी वांछित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तरस रही है।

विगत विधान सभा सत्र में मेरे द्वारा जिला चिकित्सालय नोखा के भवन निर्माण के सम्बन्ध में सदन में पूछे गये प्रश्न के उत्तर में मुझे बताया गया कि चिकित्सालय के भवन निर्माण से सम्बन्धित प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। माननीय न्यायालय के निर्णय के पश्चात ही भवन निर्माण किया जाएगा। माननीय सभापति महोदय, मैं इस सम्बन्ध में सदन के सामने खुलासा करना चाहती हूं कि जिला चिकित्सालय के भवन निर्माण पर माननीय न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं है। जिला चिकित्सालय नोखा के भवन निर्माण हेतु सितम्बर, 2023 में जारी प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसरण में भवन निर्माण की निविदा भी फरवरी, 2024 में जारी कर दी गई थी। दानदाता द्वारा करोड़ों की बेशकीमती भूमि राज्य सरकार को जिला चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु दान की गई। राज्य सरकार ने दान स्वरूप भेंट की गई भूमि को स्वीकार कर लिया। दानदाताओं ने दान नियमों के तहत अपने हिस्से का भवन निर्माण कार्य कराना भी स्वीकारा, बावजूद इसके बिना माननीय न्यायालय के किसी स्थगन आदेश, नोखा की जनता से राजनीतिक द्वेषता रखने वाले कुछ

लोगों द्वारा शासन एवं प्रशासन को लिखे गये महज शिकायती पत्र के आधार, जिला चिकित्सालय नोखा के निर्माण की टेंडर प्रक्रिया को अपरिहार्य कारणों का हवाला देकर मार्च, 2024 में निरस्त कर दिया गया था। साथ ही पत्र क्रमांक 134 दिनांक 14 मार्च,2024 द्वारा जिला चिकित्सालय नोखा हेतु पुनः भूमि के चयन बाबत जिला कलेक्टर बीकानेर को लिखकर दिया गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के इस कदम से क्षुब्ध होकर पत्र क्रमांक 134 दिनांक 14.03.2024 के क्रियान्वयन पर दानदाताओं ने माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन ले लिया। पूर्व से स्वीकृत दानदाता द्वारा दान की गई भूमि पर जिला चिकित्सालय का भवन निर्माण करवाने पर माननीय न्यायालय का कोई स्थगन नहीं है। ऐसे में पूर्व से स्वीकृत भूमि पर राज्य सरकार जिला चिकित्सालय का भवन निर्माण..

श्री सभापतिः आप विराजे।

श्रीमती सुशीला रामेश्वर डूडी (नोखा): ऐसे में पूर्व से स्वीकृत भूमि पर राज्य सरकार जिला चिकित्सालय का भवन निर्माण..

श्री सभापतिः आप विराजें। आप कॉपी टेबल कर दें।

श्रीमती सुशीला रामेश्वर डूडी (नोखा): बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया।

श्री सभापतिः आप टेबल कर दें। श्री ललित यादव।

(श्रीमती सुशीला रामेश्वर डूडी (नोखा) द्वारा कॉपी टेबल की गई।)

श्री ललित यादव (मुण्डावर): सभापति महोदय, मांग संख्या 27 व 28 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर बोलने का मौका दिया मैं आपका व मेरी पार्टी के नेता का धन्यवाद करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कोई राजनीति का विषय तो है नहीं, सेवा का विषय है। चाहे सरकार उधर की है या हमारी सरकार रही, सब लोगों को यह प्रयास करना चाहिए कि हम लोग जनता को कैसे सहूलियत दे सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की राजनीति किये बगैर, स्वास्थ्य जो जनता का मौलिक अधिकार है उसको उपलब्ध कराना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, तो सरकार इस ओर जरूर ध्यान देने का काम करें।

परमात्मा करे प्रदेश में कोई बीमार नहीं हो। आपको इस विभाग में कलम भी नहीं चलाना पड़े, लेकिन हारी-बीमारी कहकर नहीं आती है। जब भी हमारी सरकार रही तो बहुत अच्छे कदम सरकार ने उठाये। मैं समझता हूं कि आप भी इसमें सही प्रयास करे और सही कदम उठाएंगे तो जनता को लाभ मिलेगा।

सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की चर्चा करूँ। बजट में मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर सीएचसी का जिक्र हुआ। आपने बेड बढ़ाने की बात कही, 30 से 50 बेड करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, कम से कम 100 बेड का आप लोग प्रावधान करें, जिससे वहां के लोगों को फायदा मिल सके। वहां हर वर्ष 01 लाख 51 हजार 487 ओपीडी हो रही है। बिना गायनिक डॉक्टर के 200 डिलिवरी हर महीने हो रही है। कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा वहां स्टाफ की कमी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां स्टाफ भरने का काम करें।

शाहजहापुर सीएचसी एन.एच.48 पर लगती है, मैंने पहले भी वहां ट्रोमा सेंटर की मांग की थी। मेरा निवेदन है कि वहां ट्रोमा सेंटर बनाया जाये। वहां मरीज आते हैं लेकिन सुविधा के अभाव में वहां से वापस चले जाते हैं। पी एच सी, सी एच सी क्रमोन्नत होने के बाद भी नर्सिंग कर्मचारियों के 06 पद स्वीकृत होते हैं सी एच सी में, लेकिन पी एच सी के तीन पद चल रहे हैं। इसमें तो हम लोग कम से कम सुधार करने का काम करें जिससे वहां के लोगों को राहत मिल सके। मेरे विधान सभा क्षेत्र में तमाम सी एच सी व पी एच सी है उन पर सैकड़ों की संख्या में स्टाफ की कमी है, सरकार उनको भरने का काम करें।

पिछली सरकार में 25 लाख तक का फ्री इलाज देने का काम किया। आपने उसको बंद करने का काम किया। उस योजना को बंद कर दिया जो कैशलेस योजना थी। आयुष्मान भारत योजना लाए जिसमें 40 परसेंट लोगों को ही फायदा हो रहा है। आप नाम बदल रहे हो, नाम तो भले ही कुछ भी कर लो, लेकिन जनता को सहूलियत देने का काम करो। आप लोग केवल इधर-उधर की बात करके जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हो, जनता को राहत देने का काम करो, नहीं तो वह समय दूर नहीं है जैसे हम लोग इधर बैठे है वैसे आप लोग सारे के सारे तो नहीं लेकिन कुछ लोगों का इधर बैठने का काम हो जाएगा, इसलिए जनता के लिए सही ढंग से काम करो। आज प्रदेश के हालत बहुत बुरे बने हुए हैं। सरकार है बीमार, मंत्री है लाचार, मुख्य मंत्री जी है हेलीकॉप्टर में सवार, अब तो सरकार जी कुछ करो, नहीं तो 2028 में जनता करेगी आपका मजबूत ईलाज, अगर जनता के लिए काम नहीं किया तो। आपको जनता के लिए काम करने की आवश्यकता है।

चिरंजीवी योजना, मुख्य मंत्री आयुष्मान योजना, मां आप लोग लेकर आये हो लेकिन आप उसमें कुछ काम नहीं करना चाहते। आप उसमें कुछ काम करिये जिससे जनता को फ्री इलाज मिल सके। गरीब आदमी प्राइवेट अस्पताल जो फाइव स्टार अस्पताल है, जहां अच्छा इलाज होता है, वहां जाकर इलाज कराने का मौका दिया तो पिछली सरकार में अशोक जी गहलोत ने दिया। गरीब आदमी बिना पैसे के भी अस्पताल जाकर अपना इलाज करवा रहा था। आपने उन सबको बंद करने का काम कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आरजीएचएस में कर्मचारी का पैसा भी कट रहा है, लेकिन कर्मचारी को लाभ नहीं मिल रहा, उसके परिवार को लाभ नहीं मिल रहा। आपने इसमें इतनी जटिल प्रक्रिया कर दी, जिससे वह लोग परेशान हो रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि आप इसमें सही करने का काम करेंगे। नि:शुल्क दवा योजना की तो आपने हवा निकाल रखी है। आपकी 121-121 दवाइयों के सेम्पल फेल हो रहे हैं। आप लोग जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर आपने जनता के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया तो बहुत जल्दी वह समय आयेगा कि आप लोगों को इस बात को समझने की आवश्ययकता पड़ेगी कि हमने गलती की है। आप घंटी थोड़ा लेट, मुझे एक मिनट देना। सबके हित की बात कह रहा हूं।

मैंने पिछली बार मिलावटखोरी पर चर्चा की। मंत्री जी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। माननीय सभापति महोदय, यह आपकी भी समस्या है, प्रदेश में मिलावाट खोरी इतनी हो रही है..

श्री सभापति: श्री गणेश घोगरा।

श्री ललित यादव (मुण्डावर): कुछ लोगों की जान जा रही है।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री ललित यादव (मुण्डावर):000

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27 व 28 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, हमारे टीएसपी क्षेत्र की बात करुंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में डॉक्टर के सभी पद रिक्त है। सबसे पहले बिछीवाड़ा की बात करुंगा जो हाइवे पर पड़ता है, सी एच सी है और यहां सात पर स्वीकृत हैं और सात के सात पद रिक्त है। हमारी पिछली सरकार ने ट्रोमा सेंटर खोला था, स्वीकृत किया था, बजट भी अलॉट हो गया लेकिन आज तक उस ट्रोमा सेंटर का कोई अता-पता नहीं है।

VPS-RTM-06.03.2025-19.40-4e

उस सी.एच.सी. में रात को तो ठीक है, दिन में भी डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं तो वहां की आम जनता परेशान है। यह डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है? हमारे एक इंजन की सरकार ही अच्छा काम कर रही थी यह खाली डबल इंजन की नाम की सरकार रह गयी है। हर हॉस्पिटल में सब रिक्त पद पड़े हुए हैं, वह भरे जाये। इसी तरह से सी.एच.सी. पालदेवल में छह पद स्वीकृत हैं और दो पद ही वहां पर भरे हुए हैं, चार पद रिक्त हैं। इसी तरह से सी.एच.सी. गामड़ी अहाड़ा, इसमें पांच पद स्वीकृत हैं, पांचों के पांच पद रिक्त हैं। माननीय मंत्री महोदय, आप जवाब दें तब यह बतायें कि ये रिक्त पद कब तक भरेंगे? इसी तरह से कनिष्ठ विशेषज्ञ, सामान्य चिकित्सालय, डूंगरपुर में 71 पद स्वीकृत हैं और भरे कितने? केवल पांच, 66 पद खाली है। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, 30 पद स्वीकृत हैं इनमें से दस भरे हुए हैं और बीस पद खाली हैं। चिकित्सा अधिकारी 143 पद, भरे कितने हैं? 83 भरे हुए हैं और 60 पद खाली है। चिकित्सा अधिकारी दंत के 5 पद स्वीकृत हैं और एक ही पद भरा हुआ है, चार पद खाली हैं। इसी तरह से माननीय सभापति महोदय, हमारे टी.एस.पी. एरिया में, जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, गरीब है, पिछड़ा है, आदिवासी वहां पर रहते हैं और इनको आज सही ढंग से सरकार की योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा है। कांग्रेस सरकार में 25 लाख तक का नि:शुल्क इलाज फ्री मिल रहा था, लेकिन आज वह ही स्थिति आ गयी है कि वापस उनको गुजरात पलायन करना पड़ता है। छोटी सी बीमारी के लिए, एक्सीडेंट हो जाये, हाथ में फ्रैक्चर हो जाए, पैर में फ्रैक्चर हो जाये तो हमें उदयपुर जाना पड़ता है, वह भी प्राइवेट में पैसे देने पड़ते हैं तो यह डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है?

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टर ज्यादा हो गये हैं। वे गरीबों को लूट रहे हैं लेकिन अधिकारियों को कमीशन मिल रहा है इसलिए वह झोला छाप डॉक्टरों पर कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, मंत्रीजी, उन झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ आप कार्यवाही करें और जो रिक्त पद हैं उनको भरा जाये। इसी तरीके से माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)...

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): भूल गये क्या? बैटरी लेट उठ रही है।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): भूल नहीं गया हूं। नहीं-नहीं, बैटरी कोई लेट नहीं उठ रही है।

माननीय सभापति महोदय, ट्रोमा सेंटर की बात, पी.एच.सी., सी.एच.सी. जो खोली है हमारी सरकार ने लेकिन इनकी सरकार ने तो खाली नाम बदलने का काम किया है। यहां पर मोदीजी जो थालियां बजवा रहे थे, मोमबत्ती लगवा रहे थे, ढोल बजवा रहे थे लेकिन कांग्रेस सरकार ने, गहलोत सरकार ने रात-दिन एक करके भीलवाड़ा मॉडल बनाया, किसी को भूखा नहीं सोने दिया, यह काम किया है तो कांग्रेस ने किया है। आज सोनोग्राफी की स्थिति क्या है? सोनोग्राफी में लोग वहां इलाज करवाने जाते हैं, सोनोग्राफी करवाने जाते हैं तो लाइन में कतार लगती है और उस मरीज की सोनोग्राफी सात-सात दिन बाद हो रही है और डॉक्टर भी समय पर नहीं मिल रहे हैं। डॉक्टर आज अपने जो पर्सनल क्लिनिक खोले हुए हैं, वहां पर बैठते हैं। मरीजों को नहीं देखते हैं तो मैं माननीय मंत्री महोदय, यह कहना चाहता हूं कि उन डॉक्टर्स के खिलाफ भी कार्यवाही करें, जिससे गरीब को सही समय पर उनका इलाज मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे कोरोना काल में गहलोत सरकार ने ऑक्सीजन की जब जरूरत थी, तब ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था की थी और हमारे वहां पर प्रसूता को आज भी रास्ते में भी डिलीवरी हो जाती है, समय पर वहां पर डॉक्टर नहीं मिलता है और जो क्वार्टर बने हुए हैं सी.एच.सी., पी.एच.सी. के अन्दर, वहां पर रात को डॉक्टर रहते ही नहीं हैं तो वह क्वार्टर किस बात के बने हुए हैं? आप यह आदेश करें कि वहां पर वे रहें जिससे गरीबों को सही समय पर इलाज मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से घाटी में डूंगरपुर शहर में हमारी सरकार ने पी.एच.सी. खोली थी। एक प्राइवेट भवन में वह चल रही है लेकिन मंत्री महोदयजी, उस भवन का बजट भी हमने दे दिया था लेकिन आज तक वह पी.एच.सी. नहीं बनी है तो आप हमसे ऐसा बैर क्यों रखना चाहते हैं? आप यह बतायें कि यह आप कब तक बनाएंगे घाटी की पी.एच.सी.? वहां के लोग तरस रहे हैं। यह बहुत पुराना अस्पताल है, इसमें भी कोई व्यवस्था नहीं है। किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है और ये बात कर रहे हैं जय जय राजस्थान की, जय जय राजस्थान की।

माननीय सभापति महोदय, हमारे वहां पर डॉक्टर्स के, नर्सिंग कर्मियों के जो पद रिक्त हैं उनको जल्दी से जल्दी भरा जाये और हमारे यहां पर कई इलाज नहीं हो रहे हैं। जैसे हमारे

यहां पर न्यूरोलॉजी का डॉक्टर नहीं है, फेफड़ों का डॉक्टर नहीं है तो ऐसी गम्भीर बीमारियों के लिए हमें पलायन करना पड़ता है गुजरात तो ऐसे में गरीब नहीं जा सकता है तो माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी न्यूरोलॉजी डॉक्टर की हमारे वहां पर भर्ती करें जिससे वहां पर गरीब आदिवासियों को फायदा मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि जो मिलावटखोरी कर रहे हैं, आज यह कह रहे हैं कि पनीर आ रहा है, मावा आ रहा है, यह कहां से आ रहा है? पशुधन तो बचा ही नहीं है तो यह सब नकली आ रहा है, इनके खिलाफ कार्यवाही करें। फूड इंस्पेक्टर की उन दुकानों से सेटिंग रहती है, वे पैसा लेते हैं और सैम्पल पास कर देते हैं तो मैं आपसे यह आग्रह करना चाहूंगा, सदन के माध्यम से यह आग्रह करना चाहूंगा कि जो मिलावटखोरी कर रहे हैं, इससे सबका नुकसान हो रहा है तो उसके लिए कम से कम दो साल की सज़ा का प्रावधान रखें तो मिलावटखोरी बंद होगी और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरीके से मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि हमारे मंझोला सी.एच.सी. में, वहां पर भी पद खाली हैं, वे पद भी भरे जायें और प्लेसमेंट एजेंसी पर, माननीय मंत्री महोदय, आपके जो ठेकेदार हैं प्लेसमेंट एजेंसी पर, जो नर्सिंग कर्मियों की भर्ती करते हैं तो अब उनको मानदेय आप कितना देते हैं, यह आप बतायें? वह ठेकेदार उनको अपनी मर्जी से लगाता है, मर्जी से निकाल देता है, ऐसी दुर्भावना रखता है। जो कांग्रेस की सरकार में लगे हुए हैं, उनको तो बिना किसी कारण से निकाल दिया। आप कारण तो बताओ कि उस कर्मचारी को, उस नर्सिंगकर्मी को आप क्यों निकाल रहे हैं? लेकिन इस दुर्भावना के साथ आप जो काम कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार, मोदी सरकार और जय जय राजस्थान का नारा लगा रहे हैं तो मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र की जो मांग है, डॉक्टर्स नहीं हैं, नर्सिंगकर्मी नहीं हैं, उनको जल्दी से जल्दी भरा जाये। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।

श्री सभापतिः श्री अशोक कुमार कोठारी।

श्री अशोक कुमार कोठारी (भीलवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आपने हमें बजट की अनुदान की मांग संख्या 27- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं मांग संख्या 28- चिकित्सा शिक्षा पर समय प्रदान किया, उसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।

माननीय सभापति महोदय, हमारे शास्त्र में यह लिखा है कि पहला सुख निरोगी काया पर अभी हम स्वस्थ कहां है? न शरीर से और न मन से क्योंकि हमारा आहार, विहार सब अशुद्ध हो गया। अभी थोड़ी देर पहले बायतू से आने वाले माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि वर्तमान में दूध, दही, घी, सब्जियां व अन्य पदार्थों में पेस्टिसाइड जहर मिल गया है, वे सही कह रहे हैं तो इसके समाधान हेतु हमें वापस अपनी संस्कृति की तरफ लौटना होगा।

हमारे देश के प्रधान मंत्रीजी अपने मन की बात में हमेशा कृषि, जैविक कृषि एवं गौमाता की तरफ लौटने की बात करते हैं, वह ही सही समाधान होगा। हमारे देश के ऋषि-मुनियों ने हमेशा स्वस्थ एवं निरोगी रहने हेतु योग का अमूल्य उपहार हमें दिया है जिसको हमारे

प्रधान मंत्रीजी द्वारा विश्व पटल पर योगा दिवस के रूप में स्थापित करवाया है। भारत की भूमि देव भूमि है और ऋषि मुनियों का देश है। भारत की संस्कृति, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। यहां पर ही सर्वप्रथम चिकित्सा विज्ञान की खोज हुई थी। महर्षि सुश्रुत जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी कहते हैं, उनसे लेकर आयुर्वेद के जनक महर्षि चरक एवं उनके शिष्य ऋषि वाग्भट्ट द्वारा व्यक्ति को स्वस्थ और निरोगी रहने हेतु ज्ञान दिया। तब यह कहा गया कि एक स्वस्थ व्यक्ति सुदृढ़ राज्य का निर्माण कर सकता है क्योंकि स्वस्थ नागरिक ही किसी भी देश की सबसे बड़ी सम्पत्ति है।

माननीय सभापति महोदय, पहले जब एक आदमी बीमार होता था तब उसके परिवार वाले उसकी बीमारी से ज्यादा बीमारी पर खर्च होने वाले रुपयों की व्यवस्था में चिंतित रहते थे। हमने कई बार बीमारी पर घर और खेत नीलाम होते हुए सुना है और देखा है। यहां हम हमारी पूर्व मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धराजी राजे सिंधिया को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने एक दूरगामी सोच रखते हुए, संसाधनों की कमी होते हुए भी आप द्वारा सर्वप्रथम भामाशाह योजना लाकर राजस्थान में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी जिससे हरेक गरीब का इलाज बिना खर्च की चिंता के सम्भव हो पाया। वही चिकित्सा क्षेत्र में पिछली सरकार द्वारा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और जेनेरिक दवा योजना लाकर आमजन हेतु राहत का कार्य किया। आज किसी भी व्यक्ति को नि:शुल्क चिकित्सा के साथ नि:शुल्क दवा पूर्णरूप से दिलवाकर इलाज की गारंटी है। आज वही योजना हमारे यशस्वी प्रधान मंत्रीजी के मार्गदर्शन में राजस्थान में मुख्य मंत्री आयुष्मान योजना के नाम से चल रही है। इस योजना के अंतर्गत पिछले वर्ष 35 लाख व्यक्तियों को चिकित्सा लाभ और 3,500 करोड़ रुपये का महाकोष का गठन, सरकार का प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य के प्रति गम्भीरता को दर्शाता है, जिससे प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं आने वाले दिनों में और बेहतर होंगी।

माननीय सभापति महोदय, हम हमारे स्वास्थ्य मंत्रीजी का भी धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे कि आपने प्रदेश में नवीन नर्सिंग कॉलेज खोलने हेतु पुन: विज्ञप्ति निकाल कर आवेदन आमंत्रण किये, जिससे नर्सिंगकर्मियों में आ रही कमी को भी दूर किया गया। माननीय सभापति महोदय, हम हमारे विधान सभा क्षेत्र की बात करते हैं। भीलवाड़ा एक औद्योगिक नगरी है, शहर की जनसंख्या लगभग पांच से छह लाख है पर शहर केन्द्र में होने के कारण आस-पास के सौ किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र और गांवों के मरीजों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाता है।

ssy/rtm/06.03.2025/19.50/4f

शहर में महात्मा गाँधी राजकीय चिकित्सालय के नाम से 550 बेड की क्षमता का जिला स्तरीय चिकित्सालय है, वर्तमान में उक्त हॉस्पिटल में 750 बेड चल रहे हैं। प्रतिदिन यहाँ 4 हजार से 5 हजार लोगों की ओपीडी होती है, सभी बेड फुल रहते हैं। कई बार मरीजों को बेड के अभाव में इंतजार भी करना पड़ता है।

वर्तमान में भी चिकित्सालय में गैस्ट्रो, हार्ट, न्यूरो सर्जरी, यूरोलॉजी, कार्डियक सर्जरी और कैंसर केयर यूनिट की कमी है, जिससे मरीजों को जिले से बाहर या निजी चिकित्सालय में जाना पड़ रहा है। हॉस्पिटल परिसर में किसी भी नए भवन की जगह नहीं होने से अब हॉस्पिटल में कोई गुंजाइश नहीं बची है। भीलवाड़ा का भौगोलिक क्षेत्र रेलवे पटरी के पूर्व और पश्चिम में बसा होने के कारण पटरी के उस पार रहने वाले शहरवासियों हेतु कोई भी मेडिकल सुविधा नहीं होने के कारण भीलवाड़ा में मेडिसिटी के नाम से न्यास की 4 लाख 50 हजार स्क्वायर फीट भूमि राजकीय चिकित्सालय हेतु आरक्षित करवा दी गयी। सभापति महोदय, हम आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में यह बात रखना चाहेंगे कि अगर उक्त भूमि पर राज्य सरकार द्वारा कैंसर सेंटर मय पद सृजन की घोषणा की जाये तो भीलवाड़ा की जनता पूर्ण सहयोग करते हुए शहर के भामाशाहों और पीपीपी के माध्यम से बिल्डिंग निर्माण करवा दिया जायेगा। यह भीलवाड़ा ही नहीं, आसपास के जिलों के रोगियों हेतु वरदान साबित होगा। इस हेतु मैं सरकार से भीलवाड़ा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और कैंसर केयर सेंटर स्थापना की मांग करता हूँ।

एमजी हॉस्पिटल में नर्सिंगकर्मियों के बहुत से पद रिक्त हैं। वर्तमान में हॉस्पिटल में केवल 433 बेड के हिसाब से ही नर्सिंगकर्मी दिये हैं, जिससे मरीजों की देखभाल में बहुत दिक्कत आ रही है। हॉस्पिटल में मेडिकल उपकरणों की भी कमी है, जिससे मरीजों को एक रिपोर्ट हेतु कई दिन इंतजार करना पड़ता है। स्थिति को देखते हुए मेरी यह मांग है कि जांच हेतु वर्तमान में उपलब्ध मशीनों के अतिरिक्त एक-एक नवीन सीटी स्कैन, सोनोग्राफी मशीन, एमआरआई मशीन उपलब्ध कराई जाये। साथ ही इस हेतु पद सृजन भी किये जायें। सीटी स्कैन मशीन तो हॉस्पिटल को उपलब्ध करवाना था।

श्री सभापति: विराजें।

श्री अशोक कुमार कोठारी (भीलवाड़ा): पर यह अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई।

श्री सभापति: श्री शंकर लाल डेचा।

श्री अशोक कुमार कोठारी (भीलवाड़ा): जिला मुख्यालय स्थित महात्मा गाँधी राजकीय चिकित्सालय में आधुनिक कैथ लेब की सुविधा नहीं है, जिस कारण मरीजों को निजी चिकित्सालय में हृदय संबंधी ऑपरेशन कराने पड़ रहे हैं।

श्री सभापति: बैठिये। बोलिये, समय प्रारंभ हो गया आपका।

श्री शंकरलाल डेचा (सागवाड़ा): सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 27 और 28 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं, आपको और सदन को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

आदरणीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में चिकित्सा सुविधाओं का काफी अभाव है, यहाँ के गरीब आमजन को हॉस्पिटल के लिए 5 से 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, दवाई करवानी पड़ती है, मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर में निम्न चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने हेतु सांकेतिक कटौती के लिए कटौती प्रस्ताव मांग संख्या 27 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर अपनी बात रखना

चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में सबसे बड़ा जिला अस्पताल पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय सागवाड़ा है, जिसकी काफी समस्याएं हैं, जिसमें विशेष कर वहाँ के कुछ डॉक्टर हैं जो लापरवाह हैं, प्रशासनिक कमजोरी होने से जनता काफी परेशान हैं। वहाँ के डॉक्टर चिकित्सालय में बराबर ड्यूटी ना दे करके अपने निजी चिकित्सालय में सेवा देते हैं, जिससे वहाँ के गरीब लोगों को हमारी सरकार की मंशानुसार प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। वहाँ के पीएमओ और कुछ उनके साथ में डॉक्टर हैं, वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हुए काम नहीं कर रहे हैं। जो डॉक्टर हैं वह एनपीए ले रहे हैं फिर भी बाद में निजी प्रैक्टिस करते हैं, उन डॉक्टरों के खिलाफ़ भी विभागीय जांच कर कार्रवाई करनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, पंडित दीनदयाल जिला अस्पताल सागवाड़ा में ट्रोमा सेंटर एवं ब्लड बैंक कई वर्षों पूर्व खोल दिया है, परंतु पद स्वीकृत नहीं होने एवं पद रिक्त होने से जनता को सुविधाएं नहीं मिल रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से इस अस्पताल में ट्रोमा सेंटर, ब्लड बैंक के लिए पर्याप्त पदों की स्वीकृति जारी कर पदों को भरने का निवेदन करता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ओबरी को 100 बेड का करने, मोर्चरी खोलने, तहसील ओबरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोला गया है, जिसे अपग्रेड कर 100 बेड का करने तथा मोर्चरी की स्वीकृति प्रदान करने की महती आवश्यकता है। इस क्षेत्र में यही एकमात्र चिकित्सालय है जहाँ पुलिस थाना है, तहसील कार्यालय होने के बावजूद भी मोर्चरी की सुविधा नहीं है, जिससे दुर्घटना होने पर पोस्टमॉर्टम के लिए 25 से 30 किलोमीटर दूर सरकारी सागवाड़ा हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। साथ ही ओबरी क्षेत्र 25 ग्राम पंचायतों का सेंटर है।

पंडित दीनदयाल जिला अस्पताल सागवाड़ा को 300 बेड का करने, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पाडवा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चितरी एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घाटा का गांव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव रखता हूँ, ताकि यहाँ की जनता को सही सुविधाएं मिल सके।

नवीन सेंटर खोलने, विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में कई जगह पर 1 हजार से अधिक आबादी है परंतु चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है, अतः निम्न स्थानों पर नवीन सब सेंटर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने की स्वीकृति प्रदान करावें, साथ ही यहाँ नवीन भवन को भी बजट घोषणा में सम्मिलित कराने का श्रम करें:-

डेबरिया, बिजोला, दाहला, जादेला, नया तालाब, डोला, दाहेला, नेनसावा, नवाटाबरा, डामोरवाड़ा, राजपुर, हड़माला, ठाकरड़ा, वन खंड काठल, शिवराजपुर, सुन्दरपुर, पादड़ी छोटी, उदयपुरा, माविता, छतरपुरा। यह सब सेंटर नवीन भवन की स्वीकृति कराने में।

मेरे विधान सभा में कई सब सेंटर तो खोल दिए गए, परंतु पिछले पांच वर्षों से भवन की

स्वीकृति नहीं मिली है, जिससे यहाँ सभी सब सेंटर किराये के भवन में संचालित हो रहे हैं या फिर किसी सरकारी भवन में, जिससे उक्त सब सेंटर पर प्राप्त होने वाले दवाइयां खराब हो रही है या फिर जनता को सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। इस हेतु निम्न सब सेंटरों के भवन की स्वीकृति प्रदान करानी अति आवश्यक है, ताकि जनता को सही सुविधाएं मिल सकें:-

जूतेलाई, रामसौर, गड़ा, जसराजपुर, पारड़ा, विष्णु जी सीलोई, मोदरा, बेसरा, पारड़ा मेहता, फावटा, बोरखेड़ा, अखेपुर, सेमलिया, घोंटा, काहेला, वमासा, गड़ा वैजनिया, नंदौड़ और ठाकरड़ा।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कोविड के समय यूटीबी कार्मिकों का चयन हुआ था और इस विभीषिका में इन लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर जिस समय मनुष्य, मनुष्य से दूर भागता था, उस समय उन्होंने जनता की सेवा की और उनका कार्यकाल 31 मार्च 2025 को पूरा हो रहा है, इनका कार्यकाल बढ़ाया जाये एवं इनका स्थाई समाधान कर इन्हें नर्सिंग ऑफिसर, पीएसओ या चिकित्सा विभाग में अन्य पदों पर सीधा नियोजन किया जावे, ताकि इनका स्थायी समाधान हो सके।

साथ ही पिछले समय नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती हुई थी, जिसमें टीएसपी क्षेत्र के पद नहीं होने से चयनित अभ्यर्थियों का अपने गृह जिले से 300 से 500 किलोमीटर दूर तक पदस्थापन हुआ है, जिसमें अधिकांश आदिवासी समाज के अभ्यर्थी हैं। मेरा निवेदन है कि टीएसपी क्षेत्र के पद सृजित कर इनका पदस्थापन गृह जिले में कराया जावे।

सभापति महोदय, हमारे सामने वाले विपक्ष के भाई बंधु यह कह रहे थे कि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही थी, जादूगर की सरकार थी, लेकिन हमारी सरकार देशभक्तों की सरकार है, हमारी सरकार कामदारों की सरकार है, नामदारों की नहीं।

spp/rtm/06.03.2025/20.00/4g

और इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कहते थे मैं देश का चौकीदार हूँ और मोदी जी यह भी कहते थे कि एक अकेला सब पर भारी। ऐसा हमारा मोदी जी का जो विजन है। हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी, इन्होंने जो कहा वो किया है। आज मेरे विधान सभा क्षेत्र में और डूंगरपुर जिले में भी शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में कई सारा बजट पेयजल के लिए, किसानों के लिए दिया है। मैं राजस्थान की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए हमारे देश के आदरणीय प्रधान मंत्री मोदीजी, जिन्होंने कोविड में थाली बजाई, ताली बजाई, घंटी बजाई और शंख बजाया और इसके माध्यम से कोरोना को भगाने वाले हमारे देश के आदरणीय प्रधान मंत्री, जिन्होंने आज देश में भी या विदेश में भी जाते हैं तो विदेश के लोग भी प्रणाम करते हैं जबकि वो कभी प्रणाम नहीं करते हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति भी कहते हैं कि मोदी जी कुछ बड़ा करने वाले हैं तो हमारे देश के ऐसे प्रधान मंत्री हैं। आदरणीय, मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर दिया, इसके

लिए मैं सदन को और आदरणीय सभापति जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।

श्री सभापति: श्रीमती रमीला खड़ीया।

श्रीमती रमीला खड़ीया (कुशलगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 27 और 28 के ऊपर मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका आभार। आज चिकित्सा और स्वास्थ्य पर मैं बात करती हूँ। आज मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात रखना चाहती हूँ। सब आज इस सरकार की बडाइयां कर रहे थे। मैं यह कहना चाहती हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जब पिछली सरकार ने 75 बैड से 150 बैड का हॉस्पिटल दिया उस हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन गयी, बन के तैयार हो गई, शिलान्यास हो गया, उद्घाटन कर दिया। बाद में हमारी सरकार ने 30 करोड़ रुपये दिए फिर उप जिला अस्पताल के लिए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में उप जिला अस्पताल जिस तरह से कुशलगढ़ में उप जिला अस्पताल है, उसमें डॉक्टरों के रिक्त पद हैं। रिक्त पदों में इस सरकार ने आनन-फानन में बिना सोचे और बिना समझे, मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि मंत्रीजी, विशेष करके इसका ध्यान दें। दिन की ओपीडी 500 ओपीडी आती है, इसके बाद में उप जिला अस्पताल से डॉक्टरों को ट्रांसफर कर दिया गया। मैं मंत्री जी से ये कहना चाहती हूँ कि टीएसपी क्षेत्र है, हमारे आदिवासी इलाका है, हमारा गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा से लगता हुआ है और हमारा क्षेत्र से बांसवाड़ा जाने के लिए 70 किलोमीटर, गुजरात जाने के लिए 70 किलोमीटर, तो वहां पर जो रिक्त पद हैं, उनको भरा जाए। मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूँ और अधिकारी भी बैठे हुए हैं, उनसे भी मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र कसारवाड़ी में सीएचसी है और 30 बेड का हॉस्पिटल है, उसमें दो डॉक्टर थे। मंत्री महोदय बैठे हुए हैं, जोगा राम जी, आप ध्यान से उसको सुनना और सब उधर बातें कर रहे हैं, बताना। मैं ये कहना चाहती हूँ।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): बुरा मत मानना। गैलरी में बैठे अधिकारियों को संबोधित नहीं करते, इतनी मेरी रिक्वेस्ट है। आप हमको, अध्यक्षजी को जरूर सम्बोधित करो।

श्रीमती रमीला खड़ीया (कुशलगढ़): मेरा ये कहना है कि दो डॉक्टर थे, दोनों के रिक्त पद कर दिए। आप इस सीएचसी को बंद करना चाहते हैं क्या? मैं यह कहना चाहती हूँ की वो एरिया कांग्रेसी है, पर अभी दो सरपंच आपके बीजेपी के जीते हुए हैं, वो उस हॉस्पिटल में दवाई लेने नहीं जाएंगे क्या? किस मकसद से और किस विचार से इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया और डॉक्टरों के कैसे रिक्त पद कर दिया गया है? उन रिक्त पदों को भरने की आप मंशा रखते हैं या नहीं? जिन्होंने ये सूची बना कर दी, ये बहुत गलत है। आप मंत्री जी, बहुत अच्छे हैं, भले हैं और मैं यह कहना चाहती हूँ पर मंत्री जी ने उनकी लिस्ट ही नहीं मंगाई और आनन-फानन में यह ट्रांसफर जिस तरह से कुशलगढ़ और कसारवाड़ी के जो रिक्त पद हैं, छोटे नर्सों के भी ट्रांसफर कर दिए और चपरासियों के भी ट्रांसफर कर दिये, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? ये मैं कहना चाहती हूँ। जिस तरह से आज एक चपरासी का ट्रांसफर करके आज मेरे छोटी सरवा में 26 पद हैं, उनमें से नौ पद रिक्त हैं। मखुमपुरा में

26 पद हैं, उनमें से 15 पद रिक्त हैं। इसी तरह से मैं पढ़ने लग जाऊंगी तो काफी लम्बा होगा। मैं यह कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमारे पिछली सरकार ने करोड़ों की बिल्डिंग और भवनों के लिये पैसे दिए, भवन बन के तैयार हो गए। पर इस सरकार ने तो कुछ भी नहीं किया। जब पिछली सरकार ने भवन दिए और पैसे दिए उनमें नाम मंढवाने का काम किया, इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? टीएडी मंत्री आए थे, सरकार ने दिया होता एक भी तो आप उसके बाद लोकार्पण करो, शिलान्यास करो तो हम कहें। मुझे भी नहीं बुलाया। मेरी होम पंचायत है, मेरी गृह पंचायत में लोकार्पण करने के लिए, शिलान्यास करने के लिए पहुंचे थे। इसके बाद में वहाँ विरोध हुआ टीएडी मंत्री का। हमारे टीएसपी के हमारे आदिवासी का पैसा तो मंत्रीजी ने हमको दिया नहीं है। ये दोनों बातें करने में मस्त हैं। इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि पिछली सरकार ने आए दिन हमारे कुशलगढ़ विधान सभा में इधर गुजरात, उधर मध्य प्रदेश की सीमा से लगता हुआ एरिया है, आज भी घटना बहुत दुखद घटना घट गई है। दोनों टीचरों की भिड़ंत होने में दोनों की मौत हो गई। वहां पर ट्रॉमा सेंटर पिछली सरकार ने दिया था, आपने उसको निरस्त कर दिया। ये रिप्लाई में जरूर मंत्रीजी बताएं और यह बात हमारी रखें कि ट्रोमा सेंटर खुलवाने की बात आप करेंगे? जिस तरह से आज आदिवासी क्षेत्र है, इस आदिवासी क्षेत्र के इलाके में हमारे जो रिक्त पद खाली पड़े हैं, नर्सों के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भी ट्रांसफर किया गया है और आपने जो स्थानांतरण किये हैं, उनको यथावत करने का काम करें। जय हिंद। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सुखवंत सिंह।

श्री सुखवंत सिंह (रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27 एवं 28 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। सबसे पहले मैं मेरे विधान सभा रामगढ़ के क्षेत्रवासियों के साथ शीर्ष नेतृत्व को भी आप के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया। मैं पहली बार इस सदन में आया हूँ और ये बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा बनाये गये संविधान की ताकत है कि हम जैसे गांव, गरीब, किसान के बेटे को विधान सभा में पहुंचने का अवसर मिला। इसके लिए बाबा साहब का नमन करता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार के ऐतिहासिक बजट पेश करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्रीजी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। अब मैं हमारे सदन के नेता और माननीय मुख्य मंत्री जी के बारे में एक उदाहरण देकर छोटी सी बात आपको कहता हूँ1 जब किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य की जानकारी करनी हो तो उसकी हार्टबीट चैक करते है, उसका शुगर लेवल चैक करते है, देखते है कैसा है? उसमें कैल्शियम और प्रोटीन की मात्रा कितनी है? इसका पता करते हैं। इसी प्रकार अगर किसी देश या प्रदेश की आर्थिक स्तिथि देखनी हो तो उसकी महंगाई दर देखते हैं। सेंसेक्स ऊपर चढ़ रहा है या नीचे गिर रहा है यह देखते है? फिस्कल डेफिसिट देखते है, करेंट डेफिसिट देखते हैं। इससे इकोनॉमी का पता चलता है।

jyg/rtm/06.03.25/20.10/4h

इसी प्रकार किसी नेता की स्थिति देखनी हो तो उसका चरित्र कैसा है और वह व्यावहारिक दृष्टि से कितनी पकड़ है, शीर्ष नेतृत्व से सम्बन्ध कैसे हैं, ईमानदार कितना है, यह जानकारी लेनी होती है। हमारे सदन के नेता यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय भजन लाल शर्मा जी उपरोक्त सभी बिंदुओं पर खरे उतरे हैं, उन्होंने जिस तरह सबका साथ सबका विकास के मंत्र से काम किया है, हमें उन पर गर्व है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में इस ऐतिहासिक बजट में करीब 100 करोड़ के काम स्वीकृत हुए हैं, रामगढ़ सीएचसी को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किया गया है, गोविन्दगढ़ सीएचसी को 30 बेड से 50 बेड, खेड़ा महमूद और चिड़वाई को पीएचसी में क्रमोन्नत, खूंटेटा कलां में जीएसएस, 35 करोड़ की सड़कें, 10 करोड़ की नोन पेचेबल सड़कें, इन सभी कार्यों को स्वीकृत करने के लिए मैं यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय भजन लाल शर्मा जी और उनके मंत्रिमण्डल के साथीगण और हमारे अलवर सांसद और केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव जी को धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि हम सबको कम से कम हॉस्पिटलों पर, स्वास्थ्य पर, चिकित्सा पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमें सुझाव देने होंगे कि व्यवस्थाएं कैसे सुधरें। यह किसी एक राजनीतिक दल का काम नहीं है, यह हम सबका काम है। हमें पेस्टिसाइड और खाद के प्रभावों से अवेयर रहना होगा। अधिक पैदावार के फेर में हम इनके दुष्प्रभावों को भूल गये हैं। आज हम सब गम्भीर बीमारियों से ग्रस्त होते जा रहे हैं, इन सबका कारण पेस्टिसाइड युक्त फल, सब्जियां, दूध, अनाजों का सेवन करना है। हमें ऑर्गेनिक खेती की ओर जाना होगा जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। जैसा पहले भी सभी लोग बता चुके हैं, पहला सुख निरोगी काया।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ की कुछ मांगें आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र के गांव ढाढोली में नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग पिछले चार-पांच साल से बनकर तैयार है, उसको संचालित करने की अनुमति प्रदान करें। हमारे बूटोली और पाटा में पीएचसी स्वीकृत करने की मांग है। बड़ौदा में जो कि दिल्ली एक्सप्रेस वे के बिलकुल एक किलोमीटर नजदीक है, इंटरचेंज है वहां पर ट्रोमा सेंटर की मैं मांग करता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के सीएचसी, हॉस्पिटलों में महिला चिकित्सकों के साथ-साथ विशेषज्ञ चिकित्सकों को भी लगाने की कृपा करें। भांभोली पीएचसी है, उसको सीएचसी में क्रमोन्नत करने की मैं मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे विपक्ष के साथ इस तरह पूरी बातें कह रहे थे कि जैसे 2018 से 2023 तक तो राजस्थान में दूध की नदियां बह रही हो और हमने उनको आकर रोक दिया हो। आपको भी सब पता है, आपने क्या किया, जनता ने आपको बता दिया, आप ज्यादा गुणगान न करें तो ज्यादा ही अच्छा होगा।

माननीय सभापति महोदय, अंत में मैं जो हमेशा कहता हूं, रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं,

अगर अपनों के साथ अपने खड़े हो जाते हैं। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री नाना लाल निनामा।

श्री नाना लाल निनामा (घाटोल): माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने मांग संख्या 27 व 28 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत क्षेत्र ब्लॉक घाटोल और पीपलखूंट का क्षेत्र आता है जिसमें करीब 80 प्रतिशत जनसंख्या जनजाति वर्ग की रहती है। आज भी यह क्षेत्र चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी उपेक्षित है, आज भी दूरदराज के स्थानों पर एक्सीडेंट केस एवं महिलाओं के प्रसव जैसी समस्याओं के लिए बांसवाडा मुख्यालय, प्रतापगढ़ मुख्यालय की ओर जाना पड़ता है। दोनों तरफ की दूरी 50 किलोमीटर है, जिसके कारण कभी-कभी जो मरीज होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। चिकित्सा क्षेत्र के नाम से पीएचसी और सीएचसी खोल दिये गये लेकिन आज भी कई जगह वरिष्ठ और कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, मेडिकल ऑफिसर के काफी पद रिक्त हैं, जिसके कारण मरीजों को इलाज हेतु अन्य जगह जाना पड़ता है। अगर घाटोल की बात की जाये तो इस ब्लॉक में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या तीन है, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की संख्या 11 है, उप स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 76 है। यहां पर पदों का विवरण इस प्रकार है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को अवगत कराना चाहूंगा कि ब्लॉक सीएमएचओ का पद 1 है, 1 कार्यरत है, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के 2 पद हैं, 2 रिक्त हैं, कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के 2 पद हैं, 2 रिक्त हैं, मेडिकल ऑफिसर के 22 पद हैं, 18 कार्यरत हैं, 4 रिक्त हैं, नर्स ग्रेड प्रथम 13 स्वीकृत है, 12 कार्यरत हैं, 1 रिक्त है। नर्स ग्रेड द्वितीय 27 स्वीकृत हैं, 24 कार्यरत हैं, 3 रिक्त हैं। एएनएम के 183 पद स्वीकृत हैं, 140 कार्यरत हैं, 43 रिक्त हैं। फार्मासिस्ट के 6 पद हैं, 1 कार्यरत है, 5 खाली हैं। लैब टेक्निशियन के 12 हैं, 5 कार्यरत हैं, 7 खाली हैं। रेडियोग्राफर का 1 पद है, 1 खाली है। महिला स्वास्थ्य दर्शिका 13 हैं, 4 कार्यरत हैं, 9 खाली हैं।

माननीय सभापति महोदय, घाटोल के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की ओपीडी कभी-कभी 400 से 500 के आसपास हो जाती है। वर्तमान में घाटोल कस्बे की संख्या करीब 3 हजार है। माननीय मंत्रीजी, इस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की मैं मांग करता हूं। मेरे क्षेत्र के अन्दर खमेरा जो ब्लॉक घाटोल के अंतर्गत आता है, इस पीएचसी में सबसे अधिक प्रसव होते हैं लेकिन गायनिक विशेषज्ञ नहीं होने के कारण काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर गायनिक विशेषज्ञ की पद स्थापना की जावे। ताकि जनजाति क्षेत्र को स्वास्थ्य सेवा सुलभ हो सके और इस पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत किया जावे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि खमेरा की 20789 जनसंख्या है, आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए जमीन उपलब्ध है, भूमि का पट्टा संलग्न है, इसको सीएचसी में क्रमोन्नत करने की कृपा

करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, संज्ञान में लाना चाहता हूं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डूंगरिया जो उप स्वास्थ्य केन्द्र से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया गया है, वो आज भी उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन में चल रहा है। मैं माननीय मंत्रीजी को कहना चाहूंगा कि इसका बजट भी 2023-24 में पास हो गया है, मैं आपसे मांग करता हूं कि इस पीएचसी भवन का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ करें ताकि उस क्षेत्र की जनता को लाभ मिल सके। जहां तक मैं बात करूं पीपलखूंट पंचायत समिति के ब्लॉक सामुदायिक केन्द्र जो संख्या 2 पर हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 2 हैं, उप स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 34 है। यहां के भी पदों का विवरण इस प्रकार है। मेडिकल ऑफिसर 6 पद स्वीकृत, मात्र 3 कार्यरत हैं, एमओ के 2 पद स्वीकृत हैं, जिन पर मात्र 1 कार्यरत है, बाकी जनरल मेडिसन, जनरल सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग विशेषज्ञ, सभी पद रिक्त हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह क्षेत्र पूर्णतः पिछड़ा क्षेत्र है। ऐसी स्थिति में यदि स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधा नहीं मिल पाये तो सरकार से हम क्या आशा करेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि ये भी पद भरे जायें। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पीपलखूंट और घाटोल में डॉक्टरों के जितने पद रिक्त हैं, उन पर तुरंत प्रभाव से पद स्थापना कर जनता को चिकित्सा सुविधा सुलभ करायी जाये। इस क्षेत्र के प्रतापगढ़ जिले का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र घण्टाली है उसको भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने की मांग करता हूं। मैं जो डूंगरिया की बात कर रहा था, उसमें भी जमीन का पट्टा और सब चीज वहां उपलब्ध है।

MLS/RTM/06.03.2025/20:20/4j

आपको सरकार की तरफ से माननीय मंत्री महोदय, जमीन भी अलॉट हो गयी, उसका पट्टा भी मिल गया और जमीन की कोई कमी नहीं है। इस डूंगरिया पीएचसी का भवन बहुत जल्दी बनाने की आप कृपा करें ताकि उस क्षेत्र की जनता को लाभ मिल सके। आप सभी का धन्यवाद देते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूं।

श्री सभापतिः डॉ. शैलेश सिंह।

डॉ. शैलेश सिंह (डीग-कुम्हेर): सभापति महोदय, धन्यवाद, आपने मांग संख्या 27 और 28 पर मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज हमारे विपक्ष के साथी पारीक साहब ने एक बड़ी चिन्ता व्यक्त की थी। उनकी चिन्ता बड़ी वाजिब है। प्रदेश और देश में जो डॉक्टर्स की कमी है, उसको लेकर उन्होंने अपनी चिन्ता व्यक्त की थी। आपके माध्यम से मैं पारीक साहब से कहना चाहूंगा कि इनकी जो केन्द्र में सरकारें रहीं, अगर वे सही समय रहते इनकी तरह चिन्ता कर लेतीं तो हो सकता है आज हमारे देश और प्रदेश में डॉक्टर्स की कमी नहीं होती।

2014 में देश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आयी। उससे पहले कई वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, और दलों की भी सरकार रही, कांग्रेस का समर्थन रहा, ...(व्यवधान)... विकास भाई, सुनो, आप भी यहीं थे हमारी जगह कुछ दिन पहले तक। 2014 से पहले पूरे देश में केवल 6 एम्स मेडिकल कॉलेज, सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज जिसको हम कह सकते हैं, वे केवल 6 हुआ करते थे। 2014 के बाद मात्र 10 साल में माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश में 15 एम्स खोलने का काम किया है। 15 तो शुरुआत हो गयी है, उसके बाद 6 की घोषणा हो चुकी है, जिनकी बहुत जल्दी शुरुआत होगी। इसे कहते हैं देश की जनता के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील होना, न कि केवल बातें करना।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि आजादी से 2014 तक देश के अन्दर 380 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे और 2014 से 10 साल के अन्तर में 300 मेडिकल कॉलेज खोलने का काम नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया है। माननीय सभापति महोदय, अगर आप राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में करीब 43 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 6 राजकीय, 1 आरयूएचएस, 22 राजमेस, 1 ईएसआई और 12 निजी क्षेत्र में हैं। 5 नये मेडिकल कॉलेज 2024-25 में राजमेस सोसाइटी के अन्तर्गत प्रारम्भ किये गये हैं राजस्थान में। वर्तमान में कुल 6505 एमबीबीएस की सीटें राजस्थान में हैं, 3183 पीजी एवं 436 सुपर स्पेशियलाइजेशन की सीटें राजस्थान में आज की तारीख में मौजूद हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि डॉक्टर्स की राजस्थान में कमी जरूर है, लेकिन जैसा आज एक हमारे माननीय सदस्य एक अख़बार की खबर दिखा रहे थे, डॉक्टर्स की कमी तो है, लेकिन हमारे डॉक्टर्स जिस मेहनत और लगन के साथ राजस्थान में काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे चिकित्सा मंत्री जी को, माननीय मुख्य मंत्री जी को।

सभापति महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान चिकित्सा शिक्षा विभाग में कुल 128 बजट घोषणाएं कीं। उनमें से मात्र 39 का क्रियान्वयन आप लोग कर पाये और आप लोग बात करते हैं राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य की? 128 में से मात्र 39 ही आप पूर्ण कर पाये? माननीय भजन लाल जी की सरकार के बजट 2024-25 में चिकित्सा शिक्षा विभाग में कुल 24 घोषणाएं हुईं, जिनमें 34 कार्य किये जाने थे। इनमें से 3 घोषणाएं पूर्ण हो चुकी हैं, 20 की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है और 11 वित्तीय स्वीकृति के लिए वित्त विभाग में प्रक्रियाधीन हैं।

माननीय सभापति महोदय, जो हमारे होनहार स्टूडेंट्स मेडिकल में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनको पहले किसी जमाने में अलग-अलग प्रदेशों में परीक्षाएं देने जाना पड़ता था। हर प्रदेश की परीक्षा का फॉरमैट भी अलग होता था, उसके कारण उनको काफी दिक्कतें आती थीं। हमारी सरकार ने पूरे देश में एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसको हम नीट के नाम से जानते हैं, मेडिकल एंट्रेस के लिए एक प्रणाली चालू की। उससे हमारे मेडिकल एस्पिरेंट स्टूडेंट्स को बहुत सहूलियत मिली है।

माननीय सभापति महोदय, अभी कुछ देर पहले हमारे विपक्ष के साथी कह रहे थे, हमारी सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि आपने नाम बदलने का काम किया। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, हमारी भारतीय जनता पार्टी की वसुन्धरा जी की सरकार ने राजस्थान में एक योजना शुरू की ''भामाशाह राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना'' और उसके तहत लाखों राजस्थानियों ने स्वास्थ्य लाभ लिया और फिर कांग्रेस की सरकार आयी। कांग्रेस की सरकार ने आते ही उस योजना को बन्द करने का काम किया और 3 साल राजस्थान की जनता को ऐसी महत्त्वपूर्ण योजना के लाभ से वंचित करने का काम किया। 3 साल बाद उसी का नाम ''चिरंजीवी योजना'' परिवर्तित करके राजस्थान में लागू कर दिया।

ये कहते हैं कि हमने उस योजना को बन्द किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने उस योजना को बन्द नहीं किया। उस योजना में हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने सुधार किया है। उसमें काफी और चीजें जोड़कर उसे ''मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना'' के नाम से संचालित किया। सभापति महोदय, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे राजस्थान के जो लोग दूसरे राज्यों में रह रहे हैं, चाहे वे नौकरी कर रहे हैं या अपना कोई काम कर रहे हैं, अगर उन्हें जरूरत पड़ती थी इलाज की तो वे दूसरे राज्य में जब इलाज कराते थे तो उनको इस योजना का लाभ पहले नहीं मिल पाता था। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी की फैसिलिटी दी। राजस्थान के लोग अब अगर किसी दूसरे प्रदेश में जाकर अपना इलाज करवाते हैं तो वह पैसा राजस्थान की सरकार खर्च करेगी।

माननीय सभापति महोदय, वर्तमान में हमारी भजन लाल सरकार ने प्रदेश में गम्भीर और असाध्य बीमारी, जिसको हम टर्शरी केयर भी बोलते हैं, उस टर्शरी केयर के लिए 13 सौ करोड़ रुपये की इस बजट में घोषणा की है। उसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय सभापति महोदय, सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर का एक ऐसा नामी अस्पताल है, जो राजस्थान ही नहीं, हमारे पड़ोसी राज्य, चाहे वह हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो, सब जगह के लोग एसएमएस हॉस्पिटल में इलाज के लिए आते हैं। हमारी सरकार एसएमएस हॉस्पिटल में बढ़ती भीड़ को देखते हुए आईपीडी टावर सहित भवन उन्नयन...। ...(व्यवधान)...

MKD/RTM/06.03.2025/20:30/4k

माननीय सभापति महोदय, मुझे याद आता है, वह भयानक समय, जब पूरा विश्व कोरोना की महामारी में त्राहिमाम-त्राहिमाम कर रहा था। हमारे विपक्ष के साथी अभी बड़ी बड़ाई कर रहे थे, कोविड मैंनेजमेंट में।

सभापति महोदय मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब राजस्थान की जनता त्राहि-त्राहि कर रही थी, उस समय में राजस्थान के मुख्य मंत्री और माननीय मंत्री महोदय और राजस्थान के कांग्रेस के विधायक, ये सब लोग पांच सितारा होटल में बन्द होकर, पांच

सितारा होटल के मजे मार रहे थे।

श्री सभापतिः श्री चेतन पटेल। आप बैठें।

डॉ. शैलेश सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय, एक बहुत अर्जेंट बात मैं आपसे कहना चाहूंगा।

श्री सभापतिः अंकित नहीं होगा। आप बोलिये।

डॉ. शैलेश सिंह (डीग-कुम्हेर): 000

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): माननीय सभापति जी, आज इस अहम मुद्दे पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, पहली-पहली बार आये हो, सदन में। इससे कोई अच्छी छवि थोड़े ही हो जाती है।

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): समय की कमी को देखते, मैं सीधे मंत्री जी को अवगत करवाऊंगा कि आपके विभाग ने हमारे पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में जो भेदभाव किया, उसके बारे में आपको अवगत करवा रहा हूं।

मैं पहले भी पर्ची के माध्यम से अवगत करवा चुका हूं, पर आज डिमांड्स है तो मैं एक बार दोबारा आपको अवगत करवा रहा हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में बड़ौद पीएचसी पड़ती है। बड़ौद पीएचसी में 108 एम्बुलैंस थी, जिसे गत सरकार ने हमें दी थी, जिसका नम्बर आरजे-14-पीई-8188 है। पूर्व में पास ही विधान सभा क्षेत्र सांगोद है। सांगोद में माननीय मंत्री जी हीरालाल जी ने एक सुनवाई की थी। उस जनसुनवाई में उन्होंने बीसीएमएचओ को एक नई एम्बुलैंस उनके विधान सभा क्षेत्र दीगोद पीएचसी पर लगाने के लिए बोला। सत्ता के भय से और सत्ता के डर से बीसीएमएचओ ने हमारी जो बड़ौद पीएचसी की एम्बुलैंस थी, उसको वहां से दीगोद शिफ्ट कर दिया। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे बड़ौद में भी दुर्घटनाएं होती हैं, भगवान करे न हो, पर होती हैं। वहां पर भी मरीज हैं। उन्हें भी एम्बुलैंस की जरूरत पड़ती है। मानवता और नैतिकता के नाते आप इस बड़ौद पीएचसी की जो एम्बुलैंस है, जो दीगोद पीएचसी भेज दी गई है, उसको आप पुनः बड़ौद पीएचसी पर संचालित करने का कष्ट करें।

चाहे मंत्री हीरालाल जी अपने विधान सभा क्षेत्र सांगोद में कितनी ही एम्बुलैंस लगायें, हमें उससे मतलब नहीं है, पर जो हमारी एम्बुलैंस थी, उसको आप दोबारा मानवता और नैतिकता के नाते बड़ौद पीएचसी में लगाने का कष्ट करें। मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा, क्योंकि एक-एक जो भी दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसके लिए सरकार में बैठे आप, मैं और सभी अधिकारी पाप के भागीदार बनेंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उस बड़ौद पीएचसी में दोबारा एम्बुलैंस को भेजने का कष्ट करें।

हमारे विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में पिछले बजट में उप जिला अस्पताल स्वीकृत किया गया। अभी तक उसमें कोई काम नहीं हो पाया है। उसका एस्टीमेंट जयपुर भिजवा दिया गया, मगर बजट नहीं मिला, बजट आने पर ही उसका काम आरम्भ होगा तो आप इस पर भी थोड़ा ध्यान दें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र की सीएचसी इटावा में संविदा स्टाफ कार्यरत हैं। यह स्टाफ ठेकेदार के माध्यम से कार्यरत है। संविदा स्टाफ के वेतन का भुगतान ठेकेदार द्वारा उठा लिया गया। मगर संविदा स्टाफ को कई महीनों से भुगतान नहीं किया गया। संविदा स्टाफ को मात्र 5 से 6 हजार रुपये राशि मिलती है। उसके बाद भी वह भी अगर उनको न मिले तो वे अपने परिवार का पालन-पोषण कैसे करेंगे, यह सोचने का बहुत बड़ा विषय है। आप कार्यवाही करें।

माननीय मंत्री जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मेरे विधान सभा क्षेत्र में एएनएम के पूरे रिक्त पद भर दिये, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, पर अभी भी समस्याएं काफी हैं। पूरे विधान सभा क्षेत्र किसानी, खेती बाड़ी पर निर्भर है। गरीब क्षेत्र है और सरकारी अस्पतालों पर ही पूरा विधान सभा क्षेत्र निर्भर है। पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में डॉक्टर्स के 21 और दूसरे कार्मिकों की 48 की पोस्टें खाली हैं। हमारी गत सरकार ने बहुत सारी पीएचसी, सब-सेंटर, नई-नई बिल्डिंग आवंटित की, बनकर पूरी भी हो गईं, पर बिना स्टाफ के खोलना सम्भव नहीं है। इसलिए आप सहयोग करें, क्योंकि मुख्य-मुख्य काम गत सरकार ने कर दिया। आपको तो केवल और केवल बेरोजगारों को रोजगार देना है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप यह कष्ट करें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में सुल्तानपुर सीएचसी है, जिसकी ओपीडी वर्तमान में 800 पार है। यह सीएचसी मेडिकल कॉलेज, कोटा के अधीन आती है। इसके बावजूद भी सुल्तानपुर सीएचसी में सुविधाओं का विस्तार नहीं हो पा रहा है। मेडिकल कॉलेज, कोटा हमारे सीएचसी सुल्तानपुर को बिलकुल भी मदद नहीं कर रहा है। स्थिति यह है कि पांच में से चार स्पेशिलिस्ट के पद खाली हैं। पिछले पांच महीने से सोनोलॉजिस्ट नहीं होने के कारण सीएचसी में सोनोग्राफी मशीन धूल खा रही है।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसी सीएचसी सुल्तानपुर में महीने में करीब 60 डिलीवरी केस आते हैं और करीब 10 को कोटा रैफर करना पड़ता है। बिना गायनी चिकित्साकर्मियों के डिलीवरी केस में समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

माननीय मंत्री जी, इसके अलावा सर्जन डॉक्टर नहीं होने से करोड़ों रुपयों के उपकरण धूल खा रहे हैं। इसके अलावा लैब टेक्निशियन, कनिष्ठ लेखाकार, कनिष्ठ सहायक, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी व स्वीपर के पद खाली हैं। इसके साथ ही सर्जरी, मेडिसिन, गायनी व शिशु रोग विशेषज्ञ के स्थान पर अन्य डॉक्टरों को लगा रखा है, जो केवल चिकित्सा अधिकारी हैं।

इसलिए, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेडिकल कॉलेज, कोटा को निर्देशित करें कि वह इसमें पूरा सहयोग करे। मैं यह भी निवेदन करता हूं कि सीएचसी सुल्तानपुर की स्थापना सन 1990 के करीब हुई थी, तब से लेकर अब तक तीस साल गुजर जाने के बाद भी अभी तक अस्पताल क्रमोन्नत नहीं हो पाया है, जबकि यह कई (..व्यवधान..) गांवों का मुख्यालय है, तो आप सीएचसी सुल्तानपुर को भी क्रमोन्नत कराने का कष्ट करें।

श्री सभापतिः विराजिये। श्री अर्जुन लाल।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आज मुझे मांग संख्या 27 और 28 पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। कहा है:

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।।

स्वास्थ्य इस जीवन में सबके लिए जरूरी होता है। हमारे मुख्य मंत्री जी ने अबकी बार पूरे राजस्थान को बहुत अच्छी सौगातें दी हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे मुख्य मंत्री जी भजन लाल जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने मेरे विधान सभा क्षेत्र में जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल और कई सारी सौगातें चिकित्सा के क्षेत्र में दी हैं। इसके अलावा मैं पिछली सरकार की कुछ कमियां हैं, वह बताना चाहूंगा। विगत सरकार के कार्यकाल के दौरान चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बन्धित कुल 128 बजट घोषणाएं की गई थीं, उनमें मात्र 39 का ही क्रियान्वयन पूर्ण हुआ और वर्तमान में 73 बजट घोषणाओं के कार्य विभिन्न स्थानों पर प्रगतिरत हैं। 15 बजट घोषणाएं ऐसी हैं, जिनकी स्वीकृतियां तो जारी हो गईं, लेकिन धनराशि उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं कर सके। प्राथमिक स्तर के कार्य सम्पन्न होने के बाद कार्य अवरूद्ध है और एक बजट घोषणा तो ऐसी भी है, जिनकी आज तक स्वीकृति जारी नहीं हुई है।

वर्ष 2023-24 के दौरान 6 बजट घोषणाएं ऐसी थीं, जिनके लिए बजट प्रावधान नहीं किया जाकर राजमेस की आय या आरएमएससीएल के द्वारा ऋण लिया जाकर कार्य सम्पन्न करवाये जाने थे। मेरा अभी वर्तमान में जो हमारी सरकार ने जो घोषणाएं की हैं, जिसमें 34 बजट घोषणाएं की गईं, 34 बजट घोषणाओं में 34 कार्य सम्पन्न किये जाने थे, इनमें से 3 बजट घोषणाओं की क्रियान्विति पूर्ण हो चुकी है और 20 कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं और उनमें से 6 कार्य प्रगतिरत हैं और शेष 11 कार्यों की पत्रावली वित्त विभाग के पास पैंडिंग है। हमारे और आपके कार्य करने में, हमारी सरकार में जो कार्य होते हैं, हमारे मुख्य मंत्री जी ने जो कहा है, कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के पीपाड़ शहर, जिसे पूर्व मुख्य मंत्री जी, अशोक गहलोत जी अपना दूसरा घर मानते थे, उन्होंने उनके साथ भी जादूगरी कर दी। वहां पर उन्होंने एक जिला चिकित्सालय भवन की घोषणा की थी। गत सरकार ने 2021-22 में पीपाड़ शहर में जिला अस्पताल की घोषणा की गई, लेकिन 2023 तक एक रुपये का कार्य नहीं किया गया तथा न ही वहां पर तकनीकी स्वीकृति या कार्यादेश या वित्तीय स्वीकृति जारी की। आज तक भूमि का चयन नहीं हुआ है। जनता को गुमराह किया गया।

मेरा निवेदन है कि पीपाड़ शहर में माननीय मंत्री महोदय, पीपाड़ शहर में जो पूर्व में सीएचसी चल रही थी।

Bhs/Rtm/06.03.25/20.40/4I

और उसमें जो डॉक्टर्स क्वार्टर और पैरा मेडिकल स्टॉफ के जो क्वार्टर्स बने हुए हैं वो नाकारा उनको घोषित कर दिया गया है तो उन्हें ध्वस्त करके वहां पर सी.एच.सी. के अन्दर ही जिला अस्पताल बनाने की मैं आपसे मांग करता हूं कि उसी जगह क्योंकि इन्होंने तो चार साल हो गये, बना नहीं रहे हैं और वह पैसा लैप्स नहीं हो जाये, हमारे पीपाड़ शहर में जिला अस्पताल जहां पर सी.एच.सी. चल रही है वहीं पर बनायें और इसके लिए शीघ्रातिशीघ्र आप कार्यवाही करवायें।

दूसरा, मैं मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत आभारी हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं भजन लाल जी शर्मा को मेरे बिलाड़ा शहर में जो सी.एच.सी. थी, उसको उन्होंने क्रमोन्नत करके उप जिला अस्पताल बनाया। माननीय मंत्री महोदय, मेरे बिलाड़ा में भी सी.एच.सी. भवन इन्टेक्ट है और उसके पास दो हैक्टेयर भूमि खाली पड़ी है और एक एकड़ जमीन पास में अपनी कीमती करीब पांच करोड़ की जमीन उन्होंने सुपुर्द कर दी है विभाग को तो वहां भी उप जिला अस्पताल के भवन के निर्माण के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं और मेरे विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में जो ट्रॉमा सेन्टर हमारे माननीय पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी ने घोषणा की थी और उसमें दानदाताओं के द्वारा तीन करोड़ रुपये लगा कर वो ट्रॉमा सेन्टर बनाया गया और आज भी दानदाताओं के माध्यम से वह चल रहा है, पूरे राजस्थान में यदि आप ट्रॉमा सेन्टर पूरी जगह से रिपोर्ट मंगवा लें तो बिलाड़ा जैसा ट्रॉमा सेन्टर कहीं नहीं चल रहा है तो मेरा आपसे आग्रह है कि वहां पर अभी जो स्टॉफ था उसको हटा कर वो कोई ट्रेनिंग में चले गये हैं तो वहां पर हकीकत है कि ट्रॉमा सेन्टर और सी.एच.सी. दोनों दूर-दूर हैं और रात्रिकालीन ट्रॉमा में डॉक्टर्स की अति आवश्यकता रहती है तो उनको चार किलोमीटर दूर आने-जाने में रात्रि समय में बड़ी दिक्कत रहती है तो मेरा आपसे आग्रह है कि ट्रॉमा को जो अलग यूनिट है सी.एच.सी. से उसका कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन सी.एच.सी. के सारे स्टॉफ को वहां भेजा जाता है तो मेरा आपसे आग्रह है कि सी.एच.सी. के स्टॉफ को तो सी.एच.सी. में रहने दें और ट्रॉमा सेन्टर का जो स्टॉफ है उनको लगा कर उनको निश्चित रूप से आप ट्रॉमा जो राजस्थान में नम्बर वन चल रहा है उसको नम्बर वन पर रखेंगे।

इसके साथ ही साथ हमारे पी.एच.सीज में करीब सत्तर प्रतिशत डॉक्टर्स के पद खाली पड़े हैं। हमारे दो ब्लॉक हैं दोनों ब्लाक्स में बी.सी.एम.ओ. नहीं है। वहीं के डॉक्टरों के माध्यम से उनसे कार्य करवाया जा रहा है तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप बी.सी.एम.ओ. और पी.एच.सी. के जो रिक्त पद हैं उनको भरेंगे और नगरपालिका क्षेत्र बिलाड़ा और पीपाड़ शहर में जो पहले जनता क्लिनिक और फिर आयुष्मान आरोग्य मन्दिर के नाम से केन्द्र सरकार की योजना के अनुसार वहां पर पांच-पांच क्लिनिक मुख्य मंत्री आयुष्मान आरोग्य मन्दिर बनाने का जो आपने निर्णय लिया था वो वहां पर खोले जायें और इसके अलावा जो निर्धारित मापदंड हैं उनके अनुसार सी.एच.सी., उप जिला अस्पताल, जिला अस्पताल, पी.एच.सी. में जो

जांचें हो रही हैं, उन जांचों के लिए भी वहां पर हमारे लैब टेक्निशियन और ग्रेड फर्स्ट, सेकंड फार्मासिस्ट की जो वेकेंसीज़ हैं, उनको भी आप जल्दी भरेंगे। विधानसभा क्षेत्र बिलाड़ा में, बिलाड़ा शहर नगरपालिका पीपाड़ शहर इनमें पैरामेडिकल स्टाफ, फार्मेसिस्ट, लैब टेक्निशियन, नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग के लिए कोई भी ऐसी शिक्षण संस्थान नहीं है तो मेरा आपसे आग्रह है कि वहां पर या तो राजकीय या निजी शिक्षण कॉलेज या संस्थान खोलने की आवश्यकता है और प्रदेश में चिकित्सकों की कमी को देखते हुए जोधपुर स्थित एस.एन. मेडिकल कॉलेज, मारवाड़ मेडिकल विश्वविद्यालय में एम.बी.बी.एस. हेतु सीटों को बढ़ाने की मैं आपसे मांग करता हूं कि आप वहां पर निश्चित रूप से सीटें बढ़ाएंगे, तो हमारे जो डॉक्टर्स की कमी है, कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ विशेषज्ञ की जो कमी है उनसे पूर्ति हो जाएगी।

श्री सभापति: विराजें, माननीय सदस्य।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): एक सेकंड, एक बात कहनी है। मॉडल सी.एच.सी. बोरूंदा में आपने घोषणा की थी कि बोरूंदा के अन्दर हम मॉडल सी.एच.सी. बनायेंगे तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में मॉडल सी.एच.सी. बोरूंदा को घोषित तो कर दी लेकिन सी.एच.सी. बोरूंदा की वर्तमान में इतनी व्यवस्था चरमराई हुई है एवं वहां पर स्टॉफ, डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने की मैं मांग करता हूं। साथ के साथ आपसे मैं यह निवेदन करता हूं कि जो भी मेरे करीब पूरे विधान सभा क्षेत्र की पी.एच.सी., सी.एच.सी. और उप जिला अस्पताल, जिला अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी है उनको पूरा करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत। जय-जय राजस्थान।

श्री सभापति: श्री मनीष यादव।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): धन्यवाद सभापति महोदय, चिकित्सा व्यवस्था और जो चिकित्सा शिक्षा का आज विषय है, उस पर मुझे भी बोलने का अवसर मिला है इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, किसी भी प्रदेश की अगर आगे बढ़ने को और उसके विकसित बनने की अगर हम उसकी तरफ देखेंगे तो शिक्षा, चिकित्सा ये जो दो विषय हैं वो ऐसे विषय हैं जो किसी भी बढ़ते हुए राज्य की रीढ़ की हड्डी है कि वहां पर कैसी चिकित्सा व्यवस्था है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं आज आये दिन अस्पतालों में जाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज हर घर में देखो बीमार व्यक्ति की संख्या बढ़ती जा रही है प्रदेश में जो मैं कहना चाहूंगा कि धीरे-धीरे जिस प्रकार का खानपान हमारा है, उससे हमारा प्रदेश यह कहना चाहूंगा कि अस्पतालों की तरफ बहुत सारे परिवारों को रुख करना पड़ता है। मेरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सदन में जो लोग हम बैठे हैं, भले ही वो पक्ष में हों, विपक्ष में हों, लेकिन एक बात पर चर्चा हम जरूर करायें कि राजस्थान में जो शुद्ध के युद्ध की बात होती है क्या वह सही रूप से जमीन पर होती है? हम सब लोगों को निर्णय करना पड़ेगा कि अस्पताल में व्यक्ति को क्यों जाना पड़ता है, उसकी क्या जरूरत है? सबसे पहले हम को इस बात पर चर्चा करानी चाहिए कि बीमारियां कैसे पनपती हैं। आज पेस्टिसाइड का उपयोग किस प्रकार से बढ़

गया है, किस प्रकार से आज कोई भी अन्न हो या सब्जी हो, जिसमें बिना पेस्टिसाइड के वो अन्न और सब्जी हमको नहीं मिल पाती। इस बात पर भी विशेष गौर करने की आवश्यकता है। मैं प्रदेश के सबसे बड़े हमारे अस्पताल एस.एम.एस. हॉस्पिटल, जिसमें मैं कहूंगा कि आये दिन जो प्रतिदिन कम से कम 10 से 15 हजार लोगों की ओ.पी.डी. रहती है, मैं कल का समाचार पत्र पढ़ रहा था और कल के समाचार पत्र में ये खबर छपी कि ओ.पी.डी. में दवाओं का टोटा है, गंभीर मरीज भटक रहे हैं तो यह हमारे प्रदेश की ऐसी व्यवस्था को दिखाता है कि हम किस प्रकार की व्यवस्था हमने चला रखी है, कैसा चिकित्सा सिस्टम हमने डवलप कर रखा है और निशुल्क दवा योजना में 1 साल में 89 सैंपल जो हैं वह फेल हो चुके हैं।

सभापति महोदय, यह इस बात की गवाह है कि हम कितनी चिंता करते हैं, कैसी सरकार चलाते हैं, कैसे चिकित्सा व्यवस्था चलाते हैं या फिर केवल आंकड़ों का मायाजाल दिखा कर के हम इस प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। हम सब लोगों को तय करना पड़ेगा कि जहां पर हम बैठे हैं, जिस सदन में हम चर्चा कर रहे हैं, इस प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था मजबूत बनें। आज गांव में जाकर के हम देखते हैं। आज हम लोग जितने जनप्रतिनिधि हैं, मरने वालों की संख्या जो हमारे नौजवान साथी हैं कि कोरोना की वैक्सीन के इफेक्ट की वजह से या किस वजह से आज मरने वाले नौजवानों की संख्या बढ़ रही है। हमें चर्चा करनी चाहिए, आंकड़े सार्वजनिक करने चाहिए, समिति बनाकर के, जो पिछली पूर्ववर्ती सरकार ने जो समिति बनायी उसकी रिपोर्ट आपको सार्वजनिक करनी चाहिए कि किस वजह से आज प्रदेश में नौजवान मौतें ज्यादा हो रही हैं। आज हर घर में जा करके देखेंगे एक-एक गांव में 10-10 से ज्यादा एक समय में 15-15 से ज्यादा कैंसर के मरीज हैं। अगर इन बातों पर हम चर्चा नहीं करेंगे तो ये बेमानी होगा इस सदन में बैठकर के कि हम प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं। हमें तय करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और चर्चा करनी पड़ेगी, रिसर्च करना पड़ेगा कि प्रदेश में ये चिकित्सा व्यवस्था कैसे चरमराई हुई है, कैसे घर-घर में लोग परेशान हैं, बीमार हैं।

सभापति महोदय, आज जो व्यक्ति अपनी आय का 70% से अधिक केवल चिकित्सा व्यवस्था पर अपने परिवार का इलाज कराने पर खर्च करता है, कोई शिक्षा पर खर्च करता है, लेकिन हम को तय करना पड़ेगा माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमें प्रदेश में ऐसा सिस्टम डवलप करना पड़ेगा, ऐसा मॉडल बनाना पड़ेगा, जिससे सबको सुलभ चिकित्सा व्यवस्था मिल सके, सस्ती चिकित्सा व्यवस्था मिल सके और जो मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना है, गरीब व्यक्ति को इलाज के लिए दर-दर नहीं भटकना पड़े, उसके लिए हम सब लोगों को प्रयास करना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र से जुड़ी हुई चर्चा मैं आपके बीच में करना चाहूंगा। हमारे विधानसभा क्षेत्र में 2023-24 की बजट घोषणा में ट्रॉमा सेंटर की जो हमारे घोषणा हुई, उसमें 3 करोड़ 7 लाख की राशि भी स्वीकृत हो चुकी है

Kas/Rtm/06.03.2025/20.50/4m

और उप जिला अस्पताल के लिये 1.53 हैक्टेयर भूमि का आवंटन हो चुका है, लेकिन अभी तक उस अस्पताल का भूमि पूजन भी नहीं हो पाया है। इस अस्पताल का नामकरण हमारे संत श्री नारायण दास जी महाराज के नाम से होने जा रहा है। सभापति महोदय, हमारे विधान सभा क्षेत्र में जो हमारा उप जिला अस्पताल है, उसमें ब्लड स्टोरेज की जगह ब्लड बैंक में क्रमोन्नत किया जाये। मेरे विधान सभा क्षेत्र की सीएचसी अमरसर, खेदरोली, मनोहरपुर को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किया जाये।

श्री सभापतिः कृपया सभी अपने-अपने स्थान पर बैठें। विराजिए। श्री लादु लाल पितलिया। विराजिए, अंकित नहीं होगा।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): 000

श्री सभापतिः माननीय मंत्री महोदय, ये सब आपसे डिमांड मांग लेंगे, आप तो आपके स्थान पर विराजो।

श्री लादु लाल पितलिया (सहाड़ा): माननीय सभापति महोदय मुझे मांग संख्या 27 व 28 पर बोलने का मौका दिया उसके, लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र सहाड़ा में बजट 2025-26 में खांखला और कारोई को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करने पर मैं माननीय मुख्य मंत्री जी, वित्त मंत्री जी और चिकित्सा मंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं आपका ध्यान मेरे विधानसभा क्षेत्र सहाड़ा के वर्तमान में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उप खण्ड मुख्यालय रायपुर, जिला भीलवाड़ा को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत करवाने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, उप खण्ड रायपुर का क्षेत्रफल लगभग 70 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसके अंतर्गत 21 ग्राम पंचायत हैं। उक्त ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत लगभग 150 गाँव, कस्बे व छोटी ढाणियां हैं, जिसके अन्तर्गत कुल लगभग 1 लाख से अधिक की आबादी निवासरत है एवं उप खण्ड क्षेत्र रायपुर नगरपालिका क्षेत्र है एवं नगरपालिका रायपुर की कुल जनसंख्या 15,000 के आस-पास है। वर्तमान रायपुर उप खण्ड में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय चिकित्सालय है, जहां पर 50 बैड स्वीकृत हैं एवं कुल 10 चिकित्सकों के पद स्वीकृत है तथा 17 नर्सिंग कार्मिकों के पद स्वीकृत हैं, जिनमें से केवल 5 चिकित्सक कार्यरत हैं, बाकी रिक्त पद पड़े हैं। उप खण्ड रायपुर की निवासरत आबादी को मद्देनजर रखते हुए उक्त चिकित्सालय छोटा है तथा चिकित्सालय की क्षमता काफी कम है। इस कारण उप खण्ड रायपुर के व्यक्तियों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं से वंचित होना पंड रहा है। उप खण्ड रायपुर का जिला अस्पताल भीलवाड़ा स्थित है एवं जिला चिकित्सालय उप खण्ड रायपुर से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भीलवाड़ा जिले के समस्त उप खण्डों के अनुरूप सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उप खण्ड मुख्यालय रायपुर को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाना निश्चित रूप से जनता की सुविधाओं के लिए एक अच्छा कदम रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन रहेगा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उप खण्ड मुख्यालय रायपुर को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्न्त कर विधानसभा क्षेत्र रायपुर की जनता को सौगात प्रदान करने की मांग करता हूँ।

सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र सहाडा के रायपुर ब्लॉक के लड़की, गोविन्दपुरा तथा ब्लॉक सहाड़ा के उल्लाई, कांगनी, शिवरती तथा सुरावास में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की मैं मांग करता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र साहड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंगापुर, साहड़ा कोशीथल, पोटला रायपुर, मोखुन्दा तथा ट्रोमा हॉस्पिटल गंगापुर और साहड़ा चिकित्सालय पर विशेषज्ञ चिकित्सकों, जैसे ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, जनरल सृजन, एनेसिथिसिया, ENT आदि के पद रिक्त होने के कारण मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सभापति महोदय, निवेदन है कि अतिशीघ्र इन रिक्त पदों को भरा जाये, ताकि चिकित्सालय में मरीजों को राहत मिल सके।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र साहड़ा के गंगापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को आदेश क्रमांक 103/2022-23 सैटेलाइट हॉस्पिटल क्रमोन्नत किया गया था, परन्तु अब तक चिकित्सा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पद सृजन की स्वीकृति जारी नहीं की गई। अतः निवेदन है कि सैटेलाइट चिकित्सालय गंगापुर में मानक अनुसार चिकित्सा अधिकारी एवं कर्मचारियों के पद एवं जांचों की संख्या में वृद्धि किए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान करने के निर्देश प्रदान करें।

श्री सभापतिः विराजिए।

श्री लादु लाल पितलिया (सहाड़ा): एक मिनट।माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा में लगभग 8 उप स्वास्थ्य केन्द्र ...

श्री सभापतिः श्री रोहित बोहरा।

श्री लादु लाल पितलिया (सहाड़ा): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट।

श्री सभापतिः आप टेबल कर दो।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27, 28 पर बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं आरएमआरसीएल की बात करना चाहूंगा। मंत्री महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मंत्री महोदय, मंत्री महोदय।

श्री सभापतिः सुन रहे हैं, आप तो बताओ।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): मंत्री महोदय आरएमआरसीएल में 1800 आइटम का रेट कांट्रेक्ट है, and you have not done rate contract for 550 items. That mean's one third. और यह एक साल पुराना हो चुका है। मेरे हिसाब से आपको इसमें करेक्टिव एक्शन लेना चाहिये। आपके यहां हॉस्पिटल में दवाइयां नहीं हैं, that is the basic reason, कि वो दवाइयां नहीं हैं। आपके इक्युप्मेंट्स की इंक्वायरी हो रही है। मेरे ख्याल से आपको आरएमआरसीएल की वर्किंग पर एक मीटिंग लेनी चाहिये और कहना चाहिये कि किस तरह से वहां काम चल रहा है। आपके एनएचएम में लास्ट सवा साल से 22453 पद

खाली हैं, आपने उनको भरने का क्या किया, वह बता दें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में आपको 8377 करोड़ खर्च करना था, आपने 2806 करोड़ रुपये आपने खर्च किये, that means' you have just spent one third of the total amount. मेडिकल मोबाइल, जो आपने कहा कि हम घर-घर जाकर करेंगे, आपने यह बजट एनाउंसमेंट किया है। लास्ट ईयर जब हमारी सरकार थी, तब हमने 48239 शिविर लगाये थे। आपने इस साल दिसम्बर तक सिर्फ 27266 शिविर लगाये हैं। That mean's you are down by almost 20 per cent. If you calculate it, you are down by 20 per cent. आपको टोटल बजट एनएचएम में मिला है 5323 करोड़ रुपया, आपने अभी तक 580 करोड़ खर्च किया है। आपके पास पैसा नहीं है, आपके हॉस्पिटल बन रहे हैं, ठेकेदारों ने काम बंद कर दिया, क्योंकि आप एनएचएम का पेमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं। मंत्री महोदय, थोड़ा सा आप यह देखो, ऑल हॉस्पिटल जो हमारी सरकार ने शुरू किये थे, उन सबके काम बंद हैं, क्योंकि एनएचएम का पेमेंट नहीं हो रहा है। Over a period of time, लोगों की इतनी डिमांड है कि पेमेंट हो भी नहीं रहा है।

दूसरा, Fifteenth Finance Commission में आपको 2031 करोड़ रुपया खर्च करना था, आपने अभी 330 करोड़ रुपये खर्च किया। इसी तरह से आप जो औरतों को घी बांटते हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट्स में आप 5 किलो घी बांटते हैं, before delivery - 2 Kgs and, after delivery - 3 Kgs. 2023-24 में 19,761 लोगों को आपने घी बांटा था। आज की डेट में दिसम्बर तक आपने सिर्फ 12,533 लोगों को बांटा है, that mean's you are still down by 20 per cent. आपने अभी भी 20 परसेंट कम बांटा है। आप बच्चों के लिये जो निशुल्क गाडियां भेजते हो, 2023-24 में 7.25 lakh people were carried from their houses to the Hospital. 2024-25 में यह टोटल फिगर 4.8 आया है, that mean's you are still down by 12 per cent. इस साल जो आपका फिगर है, you are down by 12 per cent. उजाला क्लिनिक में आपका बजट था 27 करोड़ रुपया, आपने 2.64 करोड़ रुपये खर्च किये, इतना ही खर्च हुआ है। 25 करोड़ रुपये का कोई खर्चा नहीं हुआ है।

Msk/Rtm/06.03.25/2100/4n

बालिका संबल योजना, जिसमें हम 30 हजार रुपये जमा करते हैं, कोई भी म्यूचुअल फंड या यूटीआई में आप जमा करते हैं, वह 30 हजार रुपये जब तक वह 21 साल की महिला होती है, वह डेढ़ लाख रुपये हो जाता है। आपका बजट 60 लाख रुपये का था। आपने क्या खर्च किया, सिर्फ 12 लाख रुपये। That means, you have just spent 20 per cent of your money, till December. I am giving you all these figures till December. इसको आप थोड़ा-सा देखें।

मैं आपका ध्यान आकर्षण धौलपुर की तरफ करना चाहता हूं। मेडिकल कॉलेज खोल दिये, टीचर्स नहीं हैं। आपके नेशनल मेडिकल काउंसिल ने यह लिखकर भेज दिया कि जहां आपने मेडिकल कॉलेज खोले हैं, वहां टीचर्स नहीं है तो क्यों नहीं इन मेडिकल कॉलेजेज को

बन्द कर दिया जाये। यह आपको भी पता है, यह हमको भी पता है। धौलपुर में लड़कों ने प्रैक्टिकल नहीं किये। Are we creating doctors on Youtube? वे डॉक्टर्स क्या करेंगे? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं है। आप बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी नहीं दे रहे हैं, you don't have teachers. क्या करेंगे, फैकल्टी नहीं है। फैकल्टी की सख्त कमी है। इसको आप थोड़ा-सा देखें। हम क्या कर रहे हैं, हम हर मेडिकल कॉलेजेज हर डिस्ट्रिक्ट में खोलते जा रहे हैं। अच्छा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा दिया है, हमारी सरकार ने भी पैसा दिया, Without realising the fact, मैं दोनों पार्टियों को ब्लेम कर रहा हूं। I am not trying to blame you. मैं दोनों पार्टियों को ब्लेम कर रहा हूं। आपने डिविजनल हैडक्वाटर्स पर कैथ लैब नहीं खोलीं, क्या करेंगे? एसएमएस हॉस्पिटल पर पूरा जोर आ रहा है, वह आपके लिए भी दिक्कत है। Everybody comes to SMS Hospital, क्योंकि डिविजनल हैडक्वाटर पर न तो कैथ लैब है, न न्यूरो का कोई आदमी बैठा है, न वहां पर आपके पास कोई डॉक्टर है, न सीटी स्कैन मशीन है। सीटी स्कैन मशीन तो आपने जिलों में लगा दी। न एमआरआई मशीन है, उसको जयपुर भागकर आना पड़ता है। What is the fun? आपने मेडिकल कॉलेजेज खोले हैं, आप कम से कम डिविजनल हैडक्वार्टर के मेडिकल कॉलेजेज को एम्पॉवर कर दो, यह मेरा आपसे कहना है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दूसरा, आपने सब सीएचसी पर सोनोग्राफी मशीन कर दी, एक पर भी डॉक्टर नहीं है। What is the fun? हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप कर दिया। आपने दे दिया, हमारी सरकार ने दे दिया, उससे कोई फर्क नहीं है। डाक्टर्स ही नहीं हैं, सोनोग्राफी हो ही नहीं रही है। What is the fun? मेरे को आप बताओ कि या तो हम इसी में खुश हैं कि एक-दूसरे की बुराई कर लें और यहां भाषण दे दें। पब्लिक-एट-लार्ज का क्या फायदा हो रहा है? पब्लिक-एट-लार्ज का तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। राजाखेड़ा में सोनोग्राफी मशीन 5 साल से बंद है। न हमारी सरकार ने कोई डॉक्टर दिया, न डेढ़ साल से आपकी सरकार ने कोई डॉक्टर दिया। है ही नहीं। आपने सीएचसी पर मेरे यहां पर ट्रांसफर किये। मेरे सीएचसी पर एक डॉक्टर, मरेना सीएचसी पर एक डॉक्टर है। हमारी दो पीएचसी, without realising the fact, मेरी दोनों पीएचसी खाली कर दी। डॉक्टर्स का ट्रांसफर कर दिया। जहां तक आप ट्रांसफर करते हो, वह आपका पैरोगेटिव है, कम से कम दूसरे तो लगायें। पीएचसी वह आदमी क्या करेगा? He has to run 60 Kms, उसको इलाज कराने के लिए 60 किलोमीटर जाना पड़ता है। इसी तरह से सरमथरा में पीएचसी गोलारी और बागथर खोल दें। 60-60 किलोमीटर पर एक पीएचसी नहीं है। यह नोट कर लें। पीएचसी सरमथरा में गोलारी और बागथर पर यदि आप खोल दें, बसेड़ी में within 25-30 Kms आपको पीएचसी मिल जायेगी।

अब मैं आपका ध्यान और दिलाना चाह रहा हूं। धौलपुर में मेडिकल कॉलेज धौलपुर शहर से करीब 15 किलोमीटर चला गया। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) साहब, एक सेकण्ड। हमारे पास बिल्डिंग पड़ी हुई। हमारे पास वहां पर एक डॉक्टर नहीं रहता है। जहां शहर की पोपुलेशन 75 हजार है, वहां डॉक्टर्स नहीं लगा रखे हैं।

श्री सभापतिः श्री फूल सिंह मीणा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): हमने चार बार रिक्वेस्ट कर ली कि वहां पर डॉक्टर्स लगा दें, नर्सिंग स्टॉफ लगा दें तो कम से कम जनता क्लीनिक जैसा तो काम हो जायेगा। मेरा आपसे सिर्फ इतना-सा निवेदन है कि वहां पर..

श्री सभापतिः अंकित नहीं होगा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): 000

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्चया 27- चिकित्सा व स्वास्थ्य और मांग संख्या 28 - चिकित्सा शिक्षा पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मेरे संगठन व आपका बहुत-बहुत आभार। मेरे से पहले विपक्षी भाई बोल रहे थे कि मोदी जी ने थाली बजाई, मोदी जी ने दीपक जलाया, इनको वह तकलीफ नहीं है। इनको वह तकलीफ है कि उन्होंने थाली बजाने का ऐलान किया है, पूरा हिन्दुस्तान इकट्ठा हुआ। सबने, चाहे वह विपक्ष हो, चाहे पक्ष हो, चाहे वह कैसा भी आदमी थी, उन्होंने सब ने थाली बजायी और मोदी जी का सहयोग किया, वही इनको तकलीफ है। सभापति महोदय, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मेरे पड़ोसी रात-दिन, हम आमने-सामने लड़ते थे, कांग्रेस परिवार के, मेरे घर पर दीपक नहीं थे, उससे ज्यादा दीपक कांग्रेस भाइयों और बहनों ने जलाये। इनको यह तकलीफ है कि मोदी जी के साथ में सारे इकट्ठा कैसे हो गये? थाली कैसे बजा दी? यह तकलीफ है। अगर ये नहीं करते तो वास्तव इस कोरोना की भट्टी के अन्दर सब जल जाते और उनको काबू नहीं कर पाते। इन सबको एक करने के लिए मोदी जी से हो सकता हैकि भगवान से परमिशन लेकर यह काम किया। इस वजह से हम बच गये। ये तो होटलों में बैठे थे। हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता ने मिलकर, मैं तो यह कहता हूं कि पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे चिकित्सा डिपार्टमेंट हो, रात-दिन अपने बच्चे-बच्चियों की परवाह किये बिना उन्होंने सेवा की। यह तकलीफ है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा।

सभापति महोदय, आपने मुझे कम समय दिया। मैं तो मेरी डिमांड रखना चाहता हूं। मेरे उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्दर हिरण मगरी सेक्टर-6 में सैटेलाइट हॉस्पिटल है, उसके अन्दर मरीजों की संख्या इतनी है कि 3500 का ऑउटडोर होता है। वहां पर सुविधा की कमी है।

श्री सभापतिः शांत रहें। सभापति जी को बोलने दें, बाकी तो फिर चक्कर पड़ जायेगा। वे सब नोट कर रहे हैं।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): मैं मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहता हूं कि उस हॉस्पिटल में 100 बेड ही हैं, उसमें 200 बेड और भवन बनाने की अनुमति दें। सभापति महोदय, गोरधन बिलास एरिया उदयपुर का एक मिनी उदयपुर है। उसमें पीएचसी हॉस्पिटल चल रहा है, उसको सीएचसी कराने के लिए आग्रह कर रहा हूं। क्योंकि वहां दस किलोमीटर दूर जनरल हॉस्पिटल है और कोई प्राइवेट हॉस्पिटल भी नहीं है। उसको पीएचसी से सीएचसी

कराने के लिए मैं आग्रह कर रहा हूं। रामपुरा, अंबाबाड़ी एरिया में भी सीचीसी नहीं तो कम से कम पीएचसी खोलकर आम जनता को राहत प्रदान करें। सभापति महोदय, मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हाकम अली खां।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27 व 28 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे से पहले राजाखेड़ा से आने वाले माननीय साथी ने जो बताया कि पक्ष और विपक्ष के एक-दूसरे पर आरोप लगाकर चले जाते हैं, लेकिन जनता को क्या मिला? सभापति महोदय, मेरे खयाल से पूरे राजस्थान में हो रहा है और शायद पूरे भारत में भी हो रहा होगा। कोरोना काल की जो महामारी आयी थी, उसके बाद मौत का जो आंकड़ा बढ़ा है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हार्ट अटैक और पैरालाइसिस की बीमारी ने बहुत ज्यादा गंभीर रूप ले रखा है। डॉक्टरों के पास जाते हैं तो वे भी यह बात मानते हैं कि हार्ट अटैक के केस बहुत ज्यादा बढ़े हैं। हार्ट की सर्जरी बहुत ज्यादा करनी पड़ रही है। बहुत सारे पेशेंट मर रहे हैं। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप इसके ऊपर कोई विशेष ध्यान देकर कोई जांच करायें। राजस्थान के हर नागरिक की जांच करायें, वह मौत के आगोश में न जाये, वह पहले ही सचेत हो जाये।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): मोदी जी से बोलकर एक बार थाली बजवा लो।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): थाली बजाने से हार्ट अटैक की बीमारी ठीक नहीं होगी। हार्ट अटैक की बीमार तो इलाज से ठीक होगी। आरजीएसएच के बारे में मैं आपको बताऊं। सभापति महोदय, अभी मैं अन्दर आ रहा था तो यह पर्ची बाहर के एक सुरक्षा गार्ड ने दी है। उन्होंने यह कहा कि हमारी तनख्वाह से आरजीएचएस के पैसे तो काट लिये जाते हैं, लेकिन आरजीएचएस का इलाज नहीं मिल रहा है। मेडिकलों पर दवाई नहीं मिल रही हैं।

mdp/rtm/06.03.25/21:10/4o

मेडिकल स्टोर पर जाते हैं तो मेडिकल वाले बोलते हैं कि पेमेंट नहीं है हमारा 7 महीने, 8 महीने, एक साल से तो क्यों उन कर्मचारियों के पैसे काटे जा रहे हैं? कर्मचारी ही नहीं, मेरे ख्याल से यहां हम 200 आदमी बैठे हैं, इनमें से भी किसी को आरजीएचएस में इलाज नहीं मिल रहा, आरजीएचएस में दवाई नहीं मिल रही है। मंत्री जी, आप इसकी तरफ ध्यान दें। कर्मचारियों का पैसा काट रहे हैं और उनको दवाई दे नहीं रहे हैं। चिरंजीवी योजना के अन्दर आपने एक भी प्राइवेट हॉस्पिटल को पैसा नहीं दिया है। सारे प्राइवेट हॉस्पिटल कह देते हैं कि हमारे पास इलाज के लिए पैसा नहीं आ रहा है। चिरंजीवी का आपने नाम बदल दिया, 'मा', अच्छी बात है 'मा' अच्छा नाम रखा है, कोई इसका विरोध नहीं है, लेकिन कम से कम इस योजना में फंड तो दीजिए। गरीब को इलाज तो मिले। गरीब का एक सपना पूरा हो रहा था कि मैं भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर इलाज कराऊं, उसको आपने चकनाचूर कर दिया।

(समयः बजे)

(श्री फूल सिंह मीणा, सभापति, पदासीन)

एक जो आपने स्थानांतरण किए, स्थानांतरण करो, कोई बात नहीं, सरकार की प्रक्रिया है, लेकिन कम से कम जहां से आपने स्थानांतरण किया, वहां कम से कम डॉक्टर, कम्पाउंडर लगाओ तो सही। जैसे अभी माननीय राजाखेड़ा से आने वाले सदस्य कह रहे थे कि डॉक्टर हटा दिया, पीएचसी खाली कर दी, वहां इलाज कौन करेगा? इसलिए आपने जहां ट्रांसफर किये, वहां कम से कम डॉक्टर तो लगाइए।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पिछली बार जब आपने बजट रखा था, उस समय भी मैंने कहा था कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक बीबीपुर गांव है, उसमें सीएचसी की बिल्डिंग का काम, दिसम्बर, 2023 में शिलान्यास हुआ था और उसका काम जब स्टार्ट हुआ, गांव वालों ने जागरूकता दिखाकर जिस फर्म ने काम किया, उस फर्म ने घटिया काम किया, इसलिए गांव वालों ने जाकर उसकी जांच करायी। एनएचएम के अधिकारी वहां गये, इंजीनियर वहां गये और उन्होंने कहा कि ये काम गलत है, आप इस काम को तोड़ो, वह काम दोबारा स्टार्ट तो कराइए। वह वहां की वहां पड़ी है। एक मेरे उप जिला अस्पताल का, जो फतेहपुर के अन्दर है, दिसम्बर, 2023 में उसका शिलान्यास हुआ था, उसका काम रुका हुआ है। मैंने पहले भी बजट में कहा था कि आप जो काम हमें दें बहुत अच्छी बात है, नहीं दें तो कम से कम जो काम चालू हैं, उनको तो पुरा कराइए। एक मेरे यहां ट्रोमा सेंटर है, 2009-10 में खुला हुआ है, आज भी उस ट्रोमा सेंटर में डाक्टर्स की सिर्फ 2 ही पोस्ट हैं, जबकि तीन नेशनल हाईवे लगते हैं। रोज आये दिन एक्सीडेंट होते हैं, ट्रोमा में आते हैं और ट्रोमा वाले क्या करते हैं कि रैफर की पर्ची भरी हुई रखते हैं। सिर्फ पेशेंट का नाम लिखते हैं और रैफर कर देते हैं। नॉर्म्स के अनुसार आप उसमें पद देने की मेहरबानी करें।

श्री सभापतिः समाप्त कीजिए।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): मेरे विधान सभा क्षेत्र में मैं आपसे मांग करता हूं कि दो पीएचसी खुली हुई हैं, कायमसर और असावाबड़ा, उसमें भवन का अभाव है। भवन का बजट दीजिए।

श्री सभापतिः श्री कुलदीप जी।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): एक सब-सेंटर की मैं मांग करता हूं कि आलमास, उदनसिरी इसमें आप भवन के लिए बजट अलॉटमेंट करें।

श्री सभापतिः बात समाप्त कीजिए।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): एक मिनट, माननीय सभापति जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र के बड़े गांव हैं....

श्री सभापतिः अंकित नहीं होगा।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): 000

श्री कुलदीप (विराटनगर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27 पर बोलने का अवसर दिया, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। आजादी के 75 साल बाद भी कई बार मन को तकलीफ होती है जब व्यक्ति यह बोलता है कि मेरी जान जा रही है, मेरी जान बचा लो। कभी पीने का पानी मांगता है, कभी चलने के लिए सड़कें मांगता है। बहुत-सारे हमारे विपक्ष के साथियों ने कई बातें रखी हैं। मैं सीधा विपक्ष की बात ही कर रहा हूं, आपके सुनने में थोड़ा-सा फर्क हो गया। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि केवल भाषणबाजी से काम चलने वाला नहीं है। देश की जनता, प्रदेश की जनता..

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): कुलदीप जी, आज टीवी पर क्या चल रहा है, वह बता देना।

श्री कुलदीप (विराटनगर): अच्छा, विकास भाई, बैठर बात कर ल्यागा आपा। लेकिन मैं सीधा-सीधा मेरे विधान सभा विराटनगर पर आना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि मेरा ऐसा क्षेत्र है जहां पर कई प्रकार का ऐसा पार्ट है कहीं समतल है, कहीं पहाड़ी है, भिन्न-भिन्न प्रकार का क्षेत्र मेरा बना हुआ है। मैं सबसे पहले तो प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री महोदय भजन लाल शर्मा जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरे क्षेत्र में अस्पतालों को लेकर, दो-दो उप जिला अस्पताल आपने दिये हैं। सीएचसी, पीएचसी मेरे यहां दी है। साथ ही, आपके माध्यम से सरकार के मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे लगभग 16 पीएचसी विराट नगर विधान सभा क्षेत्र में हैं, पीएचसी में एक भी डॉक्टर नहीं है और उनको बहुत दूरी तय करके जाना पड़ता है। मैं आग्रह करूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि मेरे सभी पीएचसी में डॉक्टर लगाएं। इनमें भाकरी पीएचसी है, पाचूडाला है, भाभरू है, करौली है, प्रागपुरा है, जवाहरपुरा है, लोहाकदा खुर्द है, खातोलाई है, बाड़ीजोड़ी है। सारे पीएचसी पर, बहुत बड़े गांव हैं।

साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, साईवाड़ में एक भी डॉक्टर नहीं है। मैं यह भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यदि 5 साल में जो हमारे विपक्ष के साथी बोल रहे हैं, अगर आपने डॉक्टर्स की भर्ती कर दी होती, पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती कर दी होती, आपने नर्सिंग स्टाफ की भर्ती कर दी होती तो आज हमारे सामने हालात ऐसे पैदा नहीं होते। ...(व्यवधान)...

मैं जिक्र आप पर भी करना चाहता हूं, आपने एक विषय रखा कि हमने कोविड के समय में, वेक्सीन की बात आप कर रहे थे मनीष जी, हम पड़ोसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि आपने भी उस समय वैक्सीन लगवाया या नहीं लगवाया? वह वैक्सीन भी मोदी जी का ही था और आज आप जो दौड़-दौड़ कर चल रहे हैं, उसका कारण भी मोदी जी ही है, जिसके कारण से आप स्वस्थ हो बिलकुल।

इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि साईवाड़ जो हमारी सीएचसी है, इसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, वहां यूटीबी पर लगा रखा है एक डाक्टर। मेरी इस विषय पर अधिकारियों से बातचीत भी हुई है। यहां इश्यू कोई आ रखा है, इसलिए, मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करूंगा

कि इस प्रॉब्लम को सोर्ट आउट आप कीजिए।

मेरे पूरे विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में 479 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से मात्र 301 पद पर हमारे कर्मचारी, अधिकारी लगे हुए हैं, 178 अभी पद हमारे खाली हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप यहां तत्काल प्रभाव से क्षेत्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर डाक्टर्स लगाने के साथ-साथ पैरा मेडिकल कर्मचारियों को लगाने का काम करें। दो-तीन ऐसे क्षेत्र हैं हमारे विराटनगर में जो मेरे बड़े प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, जैसे भाकरी गांव है, बड़नगर गांव है, बीलवाड़ी गांव है, यहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सीएचसी के रूप में क्रमोन्नत किया जाए, जिससे हमारी जनता को लाभ मिल सके।

विषय तो बहुत सारे थे, लेकिन आपने समय कम दिया। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अपनी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय।

श्री सभापति: डॉक्टर सुभाष जी गर्ग।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): धन्यवाद, सभापति महोदय, विशेष रूप से समय देने के लिए। मैं केवल अपनी बातों पर आता हूं भरतपुर के सन्दर्भ में। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि भरतपुर संभागीय मुख्यालय का जो आरबीएम हॉस्पिटल है और मेडिकल कॉलेज, संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है और आप लोग जानते हैं पूरे राजस्थान की जो प्रॉब्लम है, कैंसर, ब्रेन स्ट्रोक, कार्डिएक प्रॉब्लम, नेफ्रोलोजी और लंग्स रिलेटेड जो कैंसर हो रहे हैं, ये पांच चीज ऐसी हैं, जिन पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। आपके माध्यम से मेरा स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध है कि वह इन 5-6 चीजों को लेकर संभागीय स्तर पर सारी सुविधाएं डवलप कर दें, जिनकी जरूरत है।

दूसरा, मैं कहना चाहूंगा कि मेडिकल कॉलेज, भरतपुर में पीजी कोर्सेज शुरू करने की जरूरत है। तीसरा, मैं कहना चाहूंगा कि जो मेडिकल शिक्षक हैं, मेडिकल कॉलेज और राजमेस के शिक्षक हैं, उनको वेतन-भत्ते की जो घोषणा की गयी थी, राजकीय मेडिकल कॉलेज के समान किए जाएं। चौथा, एक जनाना हॉस्पिटल की भरतपुर में बहुत जरूरत है। पांचवां, सैटेलाइट हॉस्पिटल में बिल्डिंग नहीं है, उसको बनवाया जाए।

एक जो महत्वपूर्ण है, आज बहुत सारे मीडिया के लोग यहां आए थे। आप बहुत सारे लोगों से भी कह कर गये होंगे कि सरकार के निर्णय के बावजूद भी, बजट घोषणा की थी और फाइनेंस ने सेंक्शन भी दे दी है कि राजस्थान जर्नलिस्ट हैल्थ गारंटी जो स्कीम है, उसके नियम बनाकर राहत दी जाए। आप जानते हैं कि ये जो पत्रकार जिस स्तर के हैं, रोजाना कुआं खोदते हैं और पानी भरते हैं। मेरा आग्रह है कि उनकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए राजस्थान जर्नलिस्ट हैल्थ गारंटी स्कीम को लागू किया जाए।

अंत में कहना चाहूंगा कि भरतपुर विधान सभा क्षेत्र में बरसो, घुसियारी, उदरा में पीएचसी खुलवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री टीकाराम जी जूली।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): धन्यवाद, सभापति महोदय। आज आपने जो अनुदान

की मांग 27 व 28 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

Ans/rtm 21.20 4p 06.03.2025

संसदीय मंत्री महोदय, आप आगे आ जाओ। मंत्री जी को बुलाओ, कहां है। हां भई, मंत्री जी को बुलाओ। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): कभी-कभी नजरें इधर भी इनायत कर दो ना।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अपने तो तैयार है।

तुम्हारे पांव के नीचे काई जमीन नहीं,
कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं
मैं बेपनाह अँधेरों को सुबह कैसे कहूं,
मैं इन नज़ारों को अंधा तमाशबीन नहीं।

अब यह तो किस्मत है कौन आकर लपक रहा है, आपने ले लिया तो अच्छा है। माननीय सभापति महोदय, आज मेडिकल पर चर्चा कर रहे हैं। मंत्री जी का मेज बजाकर स्वागत करो, हद हो गई, सबसे सीनियर है ...(व्यवधान)...

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): तुमने पुकारा और हम चले आये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): और जान हथेली पर ले आए।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आपने पुकारा हम दौड़े चले आये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): पर, हुजूर, आते-आते बड़ी देर कर दी।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान पूरे हिन्दुस्तान में पहला ऐसा राज्य बना जहां राइट टू हेल्थ जैसा कानून हम लोगों ने बनाया। राजस्थान पूरे हिन्दुस्तान में पहला ऐसा प्रदेश बना जहां 25 लाख तक का इलाज हमने राजस्थान की जनता को दिया। आप लोगों ने खूब कहा कि 25 लाख से कितने लोगों का इलाज हुआ। इसके अन्दर जनता को एक संतुष्टि थी, एक भरोसा था। चाहे आज 05 लाख का इलाज हो रहा हो, सबका 05 लाख का भी नहीं हो रहा, जिसको जितनी जरूरत है उतना इलाज कराता है। लेकिन एक भरोसा था कि 25 लाख तक का इलाज पूरे परिवार का मिलेगा। कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होना है वह होगा। इस बात की तो पूर्व चिकित्सा मंत्री जी भी ताकीद करेंगे कि इतना अच्छा हेल्थ का मॉडल राजस्थान में बना। चाहे पीएचसी हो, सीएचसी हो, मेडिकल कॉलेज हो, सारी स्ट्रेन्थ हो, डॉक्टर्स की सैलरी बढ़ाने की बात हो, नर्सिंग स्टाफ की बात हो, यूटीबी की बात हो। जितने नवाचार पिछले पांच साल में हुए, वह नहीं हो सकते। अब हालात यह हो गई है, काफी दिनों तक तो यह रहा कि स्कीम बंद कर दी, लेकिन स्कीम को बंद नहीं किया आपने उसकी मां योजना बना दी। मां योजना की स्थिति यह है कि अगर आप अख़बार देखेंगे तो मेडिकल के लिए रोजाना कोई ना कोई न्यूज आती है। चाहे गलत ब्लड ग्रुप का खून चढ़ने से मौत की बात हो, चाहे अस्पताल में चूहों के कुतरनें से बच्चों की मौत होने की बात हो, एम्बुलेंस में डीज़ल खतम होने से मरीज की मौत होने की बात हो, यह तीन चीज मैं आपको बता रहा हूं, ऐसी

सैकड़ों अख़बारों की कटिंग आप देख सकते हैं।

यूटीबी में जो लोग लगे हुए हैं, आप यूटीबी को हटाकर वापस संविदा पर लगाने की तैयारी कर रहे हो, यह कौनसा व किस हिसाब से आप काम कर रहे हो? हम इतनी शानदार स्कीम आरजीएचएस राजस्थान के लोगों के लिए, कर्मचारियों के लिये लेकर आए, माननीय सदस्यों के लिए भी है लेकिन आपने क्या कर दिया कि बुजुर्ग आदमी भी वहां फोटो खिंचवाने जाएगा। फोटो खिंचवाए तो लाइन लग रही है, बैठने की जगह नहीं है। ...(व्यवधान)... आप पता करवा लेना, ऐसे करने से नहीं होगा। झाडू लग रही है ऐसे। इधर आने की तैयारी है, स्वागत है आपका, आपका स्वागत करेंगे।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आपको मुबारक हो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): दोनों ही चीज़ें है, ना तो लोगों को अच्छा इलाज मिल पा रहा है, ना मेडिकल स्टोर्स के पेमेंट का भुगतान हो पा रहा है, यह स्थिति है। मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसमें अच्छा काम कीजिए, इस स्कीम को और मजबूत कीजिए। हमारे किसी सहयोग की आपको आवश्यकता हो तो हम जरूर करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, चिरंजीवी बीमा योजना जब राजस्थान के अन्दर चली तो राजस्थान का इंश्योरेंस कवरेज 93 परसेंट था, जो कि भारत का राष्ट्रीय औसत 42 परसेंट था, दुगुने से भी ज्यादा, क्योंकि पूरे देश में ऐसी कोई स्कीम नहीं है जो इतना कवरेज देती हो। यूपी के अन्दर 16 परसेंट है। महाराष्ट्र में 22 परसेंट है। पंजाब में 25 परसेंट है। हरियाणा में 26 परसेंट है। एमपी में 38 परसेंट है। एक मॉडल और चल रहा है गुजरात मॉडल, उसमें 44 परसेंट है। आप देखिये, राजस्थान का हेल्थ कवरेज। आप चाहे कितना भी नकारें लेकिन यह हकीकत है।

चिकित्सा सुविधाओं का हमारे समय का यह परिणाम है कि एम.एम.आर. पिछले दो वर्षों में 28 अंक की गिरावट आई है जो कि राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। आई.एम.आर. 30.3 रह गई है, जबकि राष्ट्रीय औसत 35.2 है। प्रदेश में 95 परसेंट प्रसव संस्थागत हो रहे हैं जो राष्ट्रीय औसत से 07 परसेंट अधिक है। 2015-16 में टीकाकरण की एवरेज कवरेज 54.8 परसेंट थी, अब 81 परसेंट हो गई। यह हमारा पांच साल का काम था, जिसकी वजह से हम लोग यहां तक पहुंचे। ...(व्यवधान)... भगवान भरोसे थाली बजवा रहे थे, वह था भगवान भरोसे। यह काम करने के आधार पर था।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): इतना अच्छा काम किया तो वहां क्यों?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): वह अलग कारण है, मैं आपको कभी अलग बताऊंगा। इस चीज से उसका कोई तालमेल नहीं है, वह अलग बात थी। ...(व्यवधान)...

सभी ज़िलों के अन्दर मेडिकल कॉलेज खोले जाए यह स्कीम मनमोहन सिंह जी लेकर आए, 75-25 का रेश्यो था और पूरे देश के अन्दर उन्होंने शुरूआत की। आप लोगों ने उसी स्कीम को अडॉप्ट करते हुए, जैसी आपकी आदत है नाम तो बदल ही दिये, 60-40 का रेश्यो करके कह दिया हैं कि हम इसको करवा रहे हैं। आपकी सरकार 2013-2018 थी, जहां सिर्फ

छह मेडिकल कॉलेज और तीन नर्सिंग कॉलेज खोले। हमने 12 मेडिकल कॉलेज और 29 नर्सिंग कॉलेज खोले, अंतर है। यही नहीं तीन मेडिकल कॉलेज ऐसे थे, राजसंमद, जालौर व प्रतापगढ़, जो भारत सरकार की गाइड लाइन पूरी नहीं कर पा रहे थे, इनके लिए राजस्थान सरकार ने अपने पास से इनको खोलने की घोषणा की, बजट स्वीकृत किया, जमीन अलॉट हो गई और आप लोगों ने उसको कैंसिल कर दिया। तो चीज बननी चाहिए या बिगड़नी चाहिए, यह मैंने पहली बार यहीं पर देखा है।

आपको एनएचएम में 2024-25 में जो पैसा मिला वह 20 करोड़ 27 लाख, माननीय मंत्री जी आप केवल साढ़े तीन करोड़ ही खर्च कर पाए, दिसम्बर तक। आप जो कह रहे हो ना कि आपने महात्मा गांधी अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल खोल दिये, हमने तो कुछ तो सोचकर किया होगा, जो बच्चों को वहां एडमीशन लेने के लिए लॉटरी लगानी पड़ रही है। लेकिन आपने तो 250 रुपये का पेंट करवाया और आयुष्मान आरोग्य मन्दिर खोल दिया। उस मन्दिर के अन्दर आपने कितना बजट दिया है, कितना पैसा दिया है, वह भी आप जवाब दें, तब बता देना।

VPS-RTM-06.03.2025-21.30-4q

आपको प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हैल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत वर्ष 2024-25 में 181 शहरी आयुष्मान आरोग्य मन्दिर, जो अभी अपन शहरी जनता के लिए कह रहे थे, आप लोगों ने इसको भी आयुष्मान कर दिया शहरी, कोई बात नहीं। 181 मिले, आपने मात्र अभी 26 ही पूरे किये हैं यानी, यहां तो आप यह कह रहे हो कि मोदीजी के नाम पर ताली-थाली बजाएंगे और यहां मोदीजी की योजना की आप लोगों ने तो जो बैंड बजा रखी है, रेड पीट रखी है, वह आपके सामने ही है।

फिर आपको टेलीमेडिसिन के लिए, दूरदराज के इलाके के अन्दर हैल्थ की सुविधाएं पहुंचे उसके लिए 2024-25 में 619 करोड़ रुपये के बजट का अनुमोदन हुआ लेकिन दिसम्बर तक मात्र 2.2 परसेंट, बेढ़म साहब, दो ही परसेंट है। दो ही परसेंट पैसा आप खर्च कर पाये और तो और पूरे एक साल के अन्दर अप्रैल से लेकर दिसम्बर तक आपकी नि:शुल्क दवा योजनाओं के 90 सैम्पल फेल हो गये 90, क्या कार्यवाही की आपने? क्या कार्यवाही की?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): वे आप वाले ही थे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हमारे समय में हम पूरा ध्यान रखते थे। अभी आपको 2024-25 में 2411 करोड़ रुपये का यह बजट मिला लेकिन आपने दिसम्बर तक 1190 करोड़ रुपये ही, माननीय सभापति महोदय, खर्च किये। हमने 2022-23 में चिरंजीवी के लिए 1850 करोड़ का बजट रखा, पूरा खर्च किया। 2023-24 में 2300 करोड़ का बजट रखा, पूरा खर्च किया। 2024-25 में आपने 2500 करोड़ का बजट रखा और जो दिसम्बर तक मात्र 1675 करोड़ रुपये ही खर्च हुआ है। तो यह बचाकर कहां ले जाओगे आप? इसके कारण हॉस्पिटल्स के अन्दर समय पर क्लेम पास नहीं हो रहे हैं, वह लोगों को मना कर रहे

हैं, लोगों को परेशानियां आ रही हैं, यह बात मैं आपसे कहना चाहूंगा।

हमारे समय में जब इंश्योरेंस कम्पनी क्लेम के पैसे का भुगतान करती थी, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल को, ऐसे ही सरकारी हॉस्पिटल को भी देती थी और सरकारी हॉस्पिटल्स के अन्दर इससे अच्छी उनकी निजी आय हो गयी थी और बहुत अच्छा काम वे कर सकते थे, लेकिन आज स्थिति क्या है? आज स्थिति यह है कि अगर हम मथुरादास माथुर, एम.डी.एम. हॉस्पिटल की ही बात करें तो उस पर 40 करोड़ रुपये का कर्जा हो गया है, वह मेडिकल उपकरण, मेडिकल सामग्री, वेंडर्स का पैसा नहीं दे पा रहे हैं, यह स्थिति हो गयी है और इसमें जरूरत पड़े तो आप विधि विभाग से भी दे देना, आप इसकी लड़ाई लड़े, कानूनी लड़ाई लड़े, विधि मंत्रीजी, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा और यही स्थिति लगभग सब जगह पूरे राजस्थान में है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यह पेपर आपको किसने बनाकर दिया है?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह वह पेपर नहीं है जो आप सोच रहे हो।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह लीक हो गया है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): 2022-23 में आर.जी.एच.एस. के 1 करोड़ 39 लाख 20 हजार 347 क्लेम आये हमारे समय में और हमने सबको दे दिया, सिर्फ 12 हजार ही लंबित थे। 2023-24 में 1 करोड़ 66 लाख 90 हजार 184 क्लेम आये, हमने सबको दे दिया, मात्र 80 हजार 171 ही लंबित थे लेकिन 2024-25 में दिसम्बर तक 1 करोड़ 36 लाख 34 हजार 904 क्लेम आये और 14 लाख 41 हजार 463 क्लेम आज भी पेंडिंग हैं, यह स्थिति है, तो इन लोगों का भुगतान नहीं करोगे तो आगे यह इलाज नहीं करेंगे, इलाज नहीं होगा तो पब्लिक परेशान होगी और पब्लिक परेशान हो तो आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो पड़ता है। मानवता के नाते जब आदमी इलाज करवाने के लिए जाता है, जब उसकी स्थिति मैंने कई बार देखी है, कई बार मैं खुद भी गया हूं, किसी के साथ भी गया हूं, जब आदमी हॉस्पिटल के अन्दर जाता है तो उसको कुछ नहीं दिखता। डॉक्टर उसको भगवान दिखता है और यह लगता है कि ये मेरे को बचा लेंगे, यह सुविधाएं यहां पर मिल जाये तो मेरा बचाव हो जायेगा। मेरे परिवार का व्यक्ति बच जायेगा, यह कोशिश रहती है लेकिन उस समय भी अगर हम इस ओर ध्यान नहीं देंगे तो फिर कौन ध्यान देगा? जनता ने तो हमें चुनकर यहां भेज दिया, जिम्मेदारी हमारी है।

इसी प्रकार से अभी आर.यू.एच.एस. के अन्दर आपने वी.सी. लगाया है। फार्मासिस्ट को ही लगा दिया। फार्मासिस्ट यानी कि नॉन डॉक्टर को आप लोगों ने वी.सी. बना दिया और वह भी महाराष्ट्र से, तो पूरे राजस्थान में आपको कोई आर.यू.एच.एस. के लिए वी.सी. नहीं मिला? सहारण साहब, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। देखिये, वी.सी. तो आप पूरे राजस्थान के डॉक्टर और आपके सामने वाली सीट पर जो माननीय सदस्य हैं, वे भी यह चाहते हैं कि राजस्थान का ही कोई अच्छा डॉक्टर इसका वी.सी. बनता तो आर.यू.एच.एस. जो है, उस चीज का फायदा राजस्थान की जनता को और अच्छा मिलता, यह बात मैं कहना चाहता हूं।

मेडिकल काउंसिल में जिस व्यक्ति को दूसरे डॉक्टर्स के लाइसेंस जारी करने का अधिकार रजिस्ट्रार बनाकर दिया था, उसके खुद सात सालों तक का लाइसेंस ही रिन्यू नहीं हुआ, उनको आप बना रहे हो। हमने 2023-24 में सी.एच.ए. के लिए, हैल्थ वालंटियर्स फोर्स बनाने की घोषणा की थी, आप इसको लागू कीजिए, उन्होंने बहुत मदद की है कोविड के समय में सी.एच.ए. ने, उनका आप ध्यान रखिये।

माननीय मंत्रीजी, मैं यह कहना चाहूंगा कि कैंसर एक ऐसा विषय है जो इस राजस्थान में ही नहीं हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के अन्दर एक इस प्रकार की बीमारी बन गयी है। जहां भी हम गांवों में जाते हैं या तो कैंसर या हार्ट अटैक या एक्सीडेंट यह तीन डेथ ज्यादा हो रही हैं, बाकी तो जो नॉर्मल डैथ होती है, वह कम हो गयी, यह ज्यादा हो गयी जो असमय डैथ हो रही है। इसके लिए मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहूंगा कि इसमें 60-70 परसेंट मरीज तो लॉस्ट स्टेज, थर्ड या फोर्थ स्टेज पर ही आते हैं और उसके बाद कोई ज्यादा बचता नहीं, यह काबू से बाहर रहती है। 2020 में यह 39 हजार और 2022 में 41 हजार लोगों की मृत्यु कैंसर से हुई है। हमने इसी वजह से आर.यू.एच.एस. में जो, सॉरी, हार्ट अटैक से हुई है। हार्ट अटैक से, रिसर्च करने के लिए कोविड के बाद में, आफ्टर कोविड रिसर्च के लिए, कोविड रिसर्च सेंटर के लिए 125 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था पर सरकार बदल गयी, आपने रोक दिया। आपने रोक दिया तो इसका खामियाजा प्रदेश को भुगतना पड़ रहा है, इसका भी आप नाम बदलकर इसको भी शुरू कीजिए ताकि इस पर रिसर्च हो और आफ्टर कोविड जो इफेक्ट जनता पर पड़ रहे हैं उसका समाधान हो सके।

मैं MAA योजना के लिए कुछ सुझाव आपको देना चाहूंगा कि इसके अन्दर कैंसर बायोप्सी जो है, उसको आप पुनः शामिल करें। मुंह की, जबड़े की, चेहरे की जो कैंसर की बायोप्सी है। आर.सी.टी. को रेगुलर पैकेज में आप जोड़ें, जनता को इसकी जरूरत है। फेशियल फ्रैक्चर के लिए पूर्व में उपलब्ध पैकेज, Open reduction and internal fixation को पुनः जोड़ें। जनरल डेंटिस्ट्री के पैकेज को पुनः जोड़ें। इम्प्लांट रिमूवल पैकेज को पुनः जोड़ें। यह हटा दिये हैं, यह पहले थे। इसी प्रकार से यू.टी.बी. कर्मचारी, नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, ए.एन.एम. लैब टेक्निशियन, लैब सहायक, इनको आप कार्य मुक्त कर रहे हैं, ये लोग मेरे से भी मिले हैं, आपसे भी मिले होंगे, लगातार जगह-जगह ये लोग चक्कर काट रहे हैं, तो इनका आप ध्यान रखें और इनको आप हटाये नहीं। क्यों किसी के पेट पर लात मार रहे हैं? नौकरी बड़ी मुश्किल से तो मिलती है, उसको हम हटा रहे हैं, उसका हम ध्यान रखें। यह निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा।

इसी प्रकार से आयुष मिशन के तहत राजकीय आयुर्वेद औषधालयों में फुल टाइम योग शिक्षक आप लगायें। राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा अधीनस्थ नियम, 2023 में पैरामेडिकल स्टाफ के पद जोड़कर कैडर सेवा नियम बनाकर आप भर्ती करें। MAA योजना के अन्दर फिजियोथेरेपी की सुविधा शुरू की जाये और फिजियोथेरेपी छात्र-छात्राओं की इंटर्नशिप के समय न्यूनतम 7500 स्टाइपेंड दिया जाये और प्रदेश में राजकीय फिजियोथेरेपी का

महाविद्यालय खोलने का काम किया जाये। यही बात मैं माननीय मंत्रीजी, आपसे निवदेन करना चाहूंगा क्योंकि मेरा समय हो गया।

माननीय सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।

श्री सभापतिः अनुदान की मांगों पर श्री गजेन्द्र सिंहजी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री।

ssy/rtm/06.03.2025/21.40/5a

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, जितने भी यहां पर हमारे वक्ता जो आज इस डिमांड पर बोले थे, उनके सुझावों का स्वागत करता हूं, उनका जो क्रिटिसिज्म रहा है, उसकी मैं जांच कराऊंगा। 402 कटौती प्रस्तावों का जवाब हमारे डिपार्टमेंट से ऑलरेडी बन चुका है और आज रात को माननीय सदस्यों को डिस्पैच हो जायेगा।

आज जो भी मेरा वर्जन प्रस्तुत करूंगा, मैं बिलकुल फैक्ट्स और फिगर्स के साथ करूंगा, या तो आप यह कह सकेंगे कि मेरे फिगर्स सही नहीं हैं, अगर वह फिगर्स सही हैं तो फिर आपको मेरे फैक्ट्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे।

हमारी सरकार जबसे आई, हमने इस विभाग के अन्दर जो भी काम किया, हमने इसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष नहीं सोचकर, हमारे डिपार्टमेंट में जो नये कर्मचारी लिये हैं, जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, उसमें हमने जैसे सूर्य अपनी रोशनी में किसी से भेदभाव नहीं करता है, उसी तरीके से काम किया है।

कुछ एमएलएज ने इश्यू रेज किये थे, कई तो चले गये, मैं डॉ. शिखा जी के बारे में बात करूंगा कि आपने जो फिगर्स प्रस्तुत किये, मां बाउचर योजना है, उसके अन्दर पैसा नहीं मिल रहा है। हकीकत यह है कि यह योजना 17.09.2024 को शुरू हुई थी और 76,642 बाउचर फ्री सोनोग्राफी के लिए 318.38 लाख के दिये थे, जिसमें से 70,753, आउट ऑफ 76,642 का भुगतान हो गया है। आपको कुछ डाउट है कि आपके हॉस्पिटल का नहीं हुआ है। उसके अन्दर मुझे पता है कि बैंक अकाउंट के अन्दर, आपके कोई नंबर्स के अन्दर प्रोब्लम था।

डॉ. शिखा मील बराला (चोमू): I want to raise my issues here, यहां पर मेरे हॉस्पिटल की बात नहीं है, यहां मैं मेरे एरिये की बात करती हूं, प्रदेश की बात करतीहूं ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): प्लीज, आप विराजें।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं आपके पर्सनल इश्यू की बात नहीं कर रहा हूं, आप जो इश्यू रेज कर रहे हैं वह कह रहे हैं कि जो मा वाउचर्स, जिन लेडीज ने जाकर के अपनी सोनोग्राफी कराई थी, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपका कोई पर्टीकूलर वेस्टेड इंट्रेस्ट है। लेकिन जो आपने बोला कि वाउचर्स के भुगतान नहीं हो रहे हैं, हमारी जो ऑडिटेड रिपोर्ट्स है, हमारे पास जो भी है, उसका मैं आपको बता रहा हूं कि 70,753 आउट ऑफ 76,642 वाउचर्स जो हैं, उनका हो चुका है। अब चूंकि आपका हॉस्पिटल है, आप भी

इंपैनल्ड हो, तो मैंने कहा शायद हो सकता है कि आपके कोई परेशानी हो, उसमें उन्होंने कहा कि आपका थोड़ा अमाउंट ड्यू है, मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, there is a small amount due. उसका कारण था कि आपके बैंक खाते का जो नंबर था उसके अन्दर जहां 0 होना चाहिए वहां उन्होंने 8 लिख दिया, यह आपकी जो भी रकम है, वह आपकी करा देंगे।

हमारे माननीय सराफ साहब ने कई रिकमंडेशंस दिये थे, आप 5 साल मंत्री रहे हैं, आपको तजुरबा है, हमें तो सवा साल ही हुआ है, और आपने जो इशूज़ रेज किये थे कि ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए, आपने रेज किया था कि बॉन्ड होना चाहिए 5 साल का, आपने रूरल एरियाज में जो जाते हैं, उनको थोड़ा भत्ता ज्यादा मिलना चाहिए, इन्सेंटिव मिलने चाहिए, आपने विलेज पोस्टिंग के अंदर जो दूर-दराज एरिया है उनका बोला, आपका स्वागत है। आपने एक और इश्यू रेज किया था कि आरयूएचएस का नाम भैरोसिंह जी के नाम से होना चाहिए तो हम इसके अंदर रिकमंड करेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी से, बीजेपी पार्टी से सबसे कद्दावर नेता जो इतनी बार मुख्यमंत्री बने और उपराष्ट्रपति बने।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सर्वमान्य हैं।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मेरे ख्याल में राजस्थान में कोई भी पॉलिटिशियन उस हाइट तक नहीं पहुंच पाया, तो यह सुझाव हमारे मंत्री और हम सब मुख्य मंत्री जी को पेश करेंगे। मुझे आशा है कि आप का जो एक्सपीरियंस है, आप हमें गाइड करें और हम सब साथ मिलकर इस डिपार्टमेंट का जितना भला कर सकते हैं, हम करेंगे।

कई माननीय सदस्यों ने इशूज रेज किये थे और मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि अभी विधान सभा चल रही है, आपके जो भी समस्याएं हैं, अब कई चीज़ हैं, इतना बड़ा राजस्थान है, इतने हॉस्पिटल्स हैं, कई चीज़ हम चूक जाते हैं, तो आपसे यह निवेदन है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स खास करके जो वैकेंसीज़ हैं आपके हॉस्पिटल्स में वह लाकर के हाइलाइट करें, हमें कम से कम पहले फेज के अंदर 66 पर्सेंट जो भी वैकेंसीज हैं, कम से कम करनी हैं चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, तो आप जाकर, मिलकर के हमें बताना।

माननीय सभापति महोदय, इसके अंदर ऐसा है कि पिछली सरकार की जो सीरियसनेस और कमिटमेंट था इस विभाग के प्रति, उसके बारे में मैं थोड़ा आप के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि कांग्रेस का 2023-24, जो लास्ट बजट था उसमें आपने 22,572 करोड़ रुपये मेडिकल और चिकित्सा विभाग को दिये, जो कि आपके पूरे बजट का 4.73 पर्सेंट था ओनली और हमारा 2024-25 का जो था, उसमें 27,660 करोड़ मतलब 5 हजार करोड़ देकर 8.26 पर्सेंट हमारे बजट का था। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सीरियसनेस इस विभाग के प्रति है, वह प्रमाणित करती हैं कि उनकी प्रायोरिटी इस विभाग की थी।

इसके अलावा अभी जो 2025-26 का बजट है 28,865 करोड़ है, 27,660 से लेकर 28,865 करोड़, और भी इजाफा करके इस बजट में हमने दिया। हमारी जो सीरियसनेस है, डिपार्टमेंट पैसे से चलता है, इक्विपमेंट पैसे से आता है, सैलरीज पैसे से देते हैं तो यह पैसा

जो अलॉट किया गया यह हमारी सरकार की सीरियसनेस बताती है, our commitment to medical health or well-being of Rajasthan.

अब मैं आपको बताऊं कि आप कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दो जो सबसे क्रिटिकल इश्यू होता है मेडिकल ऐंड हेल्थ के अंदर वह हॉस्पिटल है, यह है, वह है, लेकिन उसके अंदर आपके पास स्टाफ नहीं है और यह जो लेगेसी आप छोड़कर गए, मुझे अचंभा है कि 5 साल के अंदर आपने भर्ती ही नहीं की। मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर बताता हूं, आपके जो 5 साल हैं, सभापति महोदय, आप गौर से सुनिए, इन्होंने 27,490 मेडिकल के अंदर 5 साल में कर्मचारी लिए, जो की हम 01 साल के अंदर ही ले चुके हैं। जितने आपने 5 साल में लिए, उनको अपॉइंटमेंट मिलकर उन्होंने जोइन भी कर लिया। आपका फर्स्ट ईयर के अंदर जो था, आपने 8,107 एम्प्लॉइज लिए और लगभग 25 हजार एंप्लॉयीज फर्स्ट ईयर में हम भर्ती कर चुके हैं।

spp/rtm/06.03.2025/21.50/5b

मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी वर्तमान में जो फील्ड में हम लगा चुके हैं चिकित्सा अधिकारी (दंत) 208, नर्सिंग आफिसर 7,674, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 4,755, लैब टैक्नीशियन 1917, सहायक रेडियोग्राफर 883, ईसीजी टैक्नीशियन 157, नेत्र सहायक 112, डेंटल टैक्नीशियन 86, हॉस्पिटल केयर टेकर 32, ऑक्यूपेशनल थैरेपिस्ट 26, खाद्य सुरक्षा अधिकारी 200, संविदा नर्स 2,338 और CHP हमने 5,261 और चिकित्सक शिक्षा 665, 24,314 लोगों को हम ले चुके हैं। इसके अलावा 2025 के अन्दर हम 26,501 और लोगों को नियुक्तियां दे देंगे। फार्मासिस्ट 3,067 मार्च, 2025 तक आ जाएंगे। मार्च तो आ ही गया, मार्च में आ जाएंगे। चिकित्सा अधिकारी 1700, यह तीन महीने में आ जाएंगे। संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 3,058 यह मार्च एण्ड तक आ जाएंगे। इसी महीने में आ जाएंगे। विभिन्न संवर्गों के 10,888 दिसम्बर में आ जाएंगे। नर्सिंग एवं पैरा-मेडिकल संविदा 5,142 इनकी परीक्षा जून में हैं, 2025 में आ जाएंगे और यह भी इस साल आ जाएंगे। चिकित्सा शिक्षक 2,296 और अन्य 350 इस तरह 26,501 हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह बताना चाहूंगा कि यह पहली बार ही राजस्थान में हुआ है और यह हमारी सरकार का एटीट्यूट बताता है कि हम जितने भी लोगों को नौकरी देंगे, डॉक्टर्स हैं, नोन गजिटेड हैं, हमारा एक ही लक्ष्य रहेगा कि हम पदों को भरें और इसके लिये राजस्थान पोर्टल पर हमने जितने भी नये अधिकारी आये हैं, उनको बिलकुल ट्रांसपेरेंट तरीके से हमने फिल्टर्स डाले। महिला, डायवर्स महिला, विडो महिला, विकलांग लोग हैं, यह सब करके हमने फिल्टर्स डाले हैं और फिल्टर्स डालने के बाद में हमने उनको सब जिले का च्वाइस लिया और मैरिट जो था, वो तो इम्पोर्टेंट था ही। कम्प्यूटर ने जहां-जहां रिक्त पद थे, माननीय सभापति महोदय, चाहे वह आपके विधान सभा क्षेत्र में हो, बाड़मेर में आप देख लीजिएगा, चौधरी जी, आप देखना तो सही। मैं आपको बताऊंगा हरीशजी आपको बताऊंगा

कि जब आपकी सरकार गयी थी तो बाड़मेर में कितने लोग थे और 2025 के अंत में कितने आ जाएंगे। आप भी बैठे हो, मैं भी बैठा हूं।

माननीय सभापति महोदय, सबसे गंभीर हालत राजस्थान के अन्दर है, जिनको हमने रेड जोन बनाया है, वह है आपका गंगानगर, बीकानेर, आपके डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर जैसलमेर, जोधपुर आ गया और फिर जितने ट्राइबल एरिया हैं प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, यह जितने भी 10 डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनके अन्दर हमने पोर्टल के ऊपर जोर लगाया कि इनको भरो, क्योंकि वहां पर कोई है ही नहीं। बिलकुल खाली है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): खाली किसने छोड़ा?

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इनकी रिसायत में यही हुआ। माननीय सभापति महोदय, जब मैं मंत्री बनकर आया था पिछले साल, पहली गर्मी आयी थी, 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्प्रेचर था और जैसलमेर के अन्दर आप्थोलमोजिस्ट, आंख का डॉक्टर एक भी नहीं था पूरे जिले के अन्दर। यह जो पोर्टल है, आपके जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यह जो इतने गंभीर हालत में हैं, इन डिस्ट्रिक्ट्स को चाहे वहां पर आपके एम एल एज ज्यादा हों, चाहे हमारे एम एल एज ज्यादा हों, इन डिस्ट्रिक्ट्स को मैं पूरा विधिपूर्वक मेरी प्रायोरिटी है कि इन एरियाज को मैं भर दूंगा आकर।

जूली साहब, भर्तियों के अन्दर आप लोगों ने क्या किया? आपके पांच साल का हमने एक साल में ले लिया है। आप फैक्ट्स वैरीफाई कर लेना और हरीश जी, आप प्लीज 2025 के एण्ड में, मैं आपसे मिलकर बात करूंगा।

अब आगे अपने First Referral Units (FRUs) हमारे राजस्थान के अन्दर 2,065 हॉस्पिटल और यूनिट्स हैं, जहां हमारी 99 प्रतिशत डिलिवरीज होती हैं। उसके लिये 160 CHC को चुना गया है, जिनको कहते हैं FRU, जहां पर कोम्प्लिकेटेड डिलिवरी होती है। आपको, 50-60 किलोमीटर में उस लेडी को हम वहां पर पहुंचा सकते हैं और वह FRU चलने के लिये हमें उसके अन्दर एक पीडियाट्रेशन चाहिए, एक हमें एनेस्थेटिस्ट चाहिए। तीन तो हमारे स्पेशलिस्ट हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ती है, तो उसके अन्दर जब हम आये थे तो आपके 162 FRUs हैं, उनमें से खाली 87 वर्किंग में थे, बाकी नहीं चल सकते जब तक यह तीनें स्पेशलिस्ट आपके पीडियाट्रिशन, एनेस्थेटिस्ट और गायनिक का, जब तक तीनों का ग्रुप नहीं बनता तो वह नहीं चलता है। आपके खाली 87 ऑपरेटिव थे और, माननीय सभापति महोदय, हमने प्रायोरिटी से 129 चालू करवाये। 87 से हमने 129 चालू करवाये। अब वर्किंग आपका टोटल 129 हो गया।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा जो आपके ट्रोमा सेंटर्स हैं, माननीय सभापति महोदय, ट्रोमा सेंटर्स के अन्दर भी हमने बहुत सारे चालू कर दिये। वहां पर स्पेशलिस्ट ओरथो, एनेस्थटिस्ट, यह सब होना जरूरी है। उनको भी हम भर देंगे।

अब हमारी मा योजना आ गयी।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने ट्रोमा सेंटर

चालू किया था। उसकी स्वीकृति हो गयी थी..(व्यवधान)..

श्री सभापति: प्लीज सदस्य, बीच में नहीं। ..(व्यवधान)..

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपके सारे ट्रोमा सेंटर चालू हो जाएंगे। पहला उपचार वहां पर आपको दे देंगे। अब, माननीय सभापति महोदय, मा-योजना आ गयी। अब इनको यह भी जलन है कि चिरंजीवी योजना का नाम हमने मां-योजना क्यों कर दिया? जूली जी, सुनो। मां तो मां होती है what a great word. फिर आप मां के ऊपर भी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यह मां, दादी शब्द पर एतराज करते हैं। मां हो, दादी हो एतराज करते हैं।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपने चिरंजीवी योजना के नाम से शुरू किया, यह बहुत अच्छी योजना थी। लेकिन आप लोगों ने जो इतने ढोल पीटे, 25 लाख, 25 लाख, माननीय सभापति महोदय, खाली दो लोगों को दिये थे 13 लाख और 9 लाख दो या तीन लोगों को मिले थे, बाकी जितने भी मिले थे, वह 3 लाख से बिलो था। पर आपने फाल्स प्रोप्रेगेंडा किया कि हम इस योजना में 25 लाख दे रहे हैं। अच्छी योजना थी। ..(व्यवधान)..

श्री सभापति: प्लीज सदस्य, बिराजिये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): बीच में नहीं बोलें। माननीय सभापति महोदय, मेरा विरोध है। थोड़ा बहुत तो चलता है, पर हर बार खड़े नहीं होवें। यह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। इनको समझाओ, अक्ल ही नहीं है। ..(व्यवधान)..

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मा-योजना एक बहुत इम्पोर्टेंट योजना इसलिए है कि केवल सरकारी हॉस्पिटल इतनी बड़ी पापुलेशन के लिये हर चीज सरकार नहीं कर सकती है और आज आप विदेश में देखिए, बड़े-बड़े एडवांस देशों में, वहां पर एक सिम्पल इक्विशन होता है। पेशेंट, हॉस्पिटल और एजेंसी इंश्योरेंस की, सिम्पल और मां-योजना के तहत आप देखिए कि आपका लास्ट ईयर था 2023, 2023 के अन्दर 2,200 करोड़ आपने खर्च किय मा योजना के अन्दर। हमने अगले साल 3,200 करोड़ रुपये खर्च कर दिये। एक हजार करोड़ ज्यादा खर्च किये हैं। हॉस्पिटल इम-पैनल थे 832, अब एक साल में हो गये 945, सत्तर साल प्लस के जितने लोग हैं, वह 8 लाख फैमेलिज को बैनिफिट मिला, उपचार मिला है।

jyg/rtm/06.03.25/22.00/5c

(समय: बजे)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

यह आपके टाइम में था नहीं क्योंकि माननीय मोदीजी ने 70 साल के लोगों को बेनिफिट देने के लिए यह पहली बार ही किया तो इसको हम आपसे कम्पेयर नहीं करेंगे।

पैकेज आपके टाइम थे 1806, एक साल बाद हमने उनको कर दिये 2370, स्पेशलिस्ट जो थे, स्पेशलिटीज आपके थी 31 और हमने कर दिये 36, इसमें बच्चों का, कैंसर का, गेस्ट्रो

का हमने कर दिया। 1.34 करोड़ जो फैमिलीज हैं उनको इसके अन्दर बैनिफिट मिला। जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं, उनकी बड़ी-बड़ी जो हैं जैसे कैंसर इंस्टीट्यूट हैं, उनकी 70 प्रतिशत इनकम जो है वो मा योजना से आती है, 70 परसेंट, आप बड़े हॉस्पिटल से पूछ लीजिये, 70 प्रतिशत फुटफाल इसके थ्रू आता है। इसके अन्दर एम्पैनलमेंट के रूल्स से अपने हॉस्पिटल्स के उनको हमने रिलेक्स कर दिये। Shikha Ji, please confirm. Now the rules are relaxed for the hospitals. माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अगले 2 महीने के अन्दर अभी तो आप राजस्थान में ही करा सकते हैं, दो महीने के बाद में आयुष्मान पोर्टल की कम्पेटिबिलिटी के तहत बाहर से कोई भी स्टेट से हमारे स्टेट में इस योजना के थ्रू इस योजना में इलाज करवा सकते हैं। अब आप इमेजिन करो कि हमारे हॉस्पिटल्स को इनकम कितनी बढ़ेगी? इसके पश्चात् 6 महीने के बाद में हमारे भी लोग दूसरे स्टेट्स में जाकर इस पोर्टल के थ्रू अपना इलाज करवा सकेंगे, अगर आप चाहते हो कि हम गुड़गांव में जाकर मेदांता से कराये, दिल्ली के हॉस्पिटल में करायें, 6 महीने में हमारी यह पोर्टेबिलिटी हो जायेगी। मैं सोचता हूं कि जब ये दोनों चीजें हो जायेंगी, इसके अन्दर मा योजना एक बहुत बड़ी योजना बनेगी और हमारे हॉस्पिटल्स का प्रेशर भी रिलेक्स होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट के अन्दर हमने 3,500 करोड़ रुपये इस बार मा योजना के लिए बढ़ाकर पहले हमारे 3,200 करोड़ रुपये खर्च हुए, आपके टाइम 2,220 थे, अब 3,500 करोड़ रुपये माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसके लिए दे दिये हैं। हमारे डेली 8,200 मरीज आते हैं और 9.42 करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन मा योजना के थ्रू डेली होता है, एवरीडे होता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब आ गया आपके आयुष्मान आरोग्य मन्दिर। हमारे 70 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं और गांवों के अन्दर जो सबसे छोटा हेल्थ यूनिट है वह है सब हेल्थ सेंटर और सब हेल्थ सेंटर के अन्दर पहले खाली एक नर्स होती थी। हम उसको स्ट्रोंग बना रहे हैं, हमारे ग्रामीण लोग जो ज्यादा क्योंकि वहां गांव में रहते हैं तो उनके पंचायत के पास या नियरेस्ट, क्योंकि सब सेंटर्स तो बहुत ज्यादा खुले हुए हैं, हम चाहते हैं हमारे राजस्थान में 20,348 सब सेंटर्स हैं, इनके अन्दर एक सीएचओ, सेमी डॉक्टर जिसकी सैलरी होगी 30-35 हजार, एक एएनएम होगी जो थोड़ी हाईली पेड होगी, बेटर क्वालिटी की और एक आपकी आशा वर्कर होगी। वहां पर वाई-फाई के साथ हम वहां पर एलसीडी स्क्रीन देंगे, एक कम्प्यूटर देंगे, एक प्रिंटर देंगे, मोबाइल देंगे और इलाज वहां पर जो होगा, आप मोबाइल से कोई लेडी है, वो फोन पर, आजकल गांव की जो लेडीज वो मोबाइल अपन लोगों से भी ज्यादा जानती है, they are more aware with this thing. हमें फंक्शन नहीं मालूम लेकिन उनको मालूम है, वो लेडी धूप के अन्दर एक वीडियो ले सकती है कि मेरे हाथ में ये छाले हो रहे हैं या फोड़े हो रहे हैं और वो वहां पर सीएचओ को भेज सकती है और कह सकती है, उसको दिखेगी यह कॉमन बरसाती या कोई मौसम की बीमारी है तो आप जाकर फलां, फलां सफाखाना या कैमिस्ट की दुकान पर जाकर या ट्यूब ले आ, यह टेली कांफ्रेंसिंग

से होगा और वहां जो सेमी डॉक्टर अवेलेबल होगा, मैं यह सोचता हूं कि एक बहुत स्ट्रॉंग हमें गांव के अन्दर ग्रास रूट के अन्दर यह मेडिकल हम इसको ले जायेंगे। अभी हमारे 20,348 सब सेंटर्स हैं, उनके अन्दर 11,655 लोग सी एच ओ जाने शुरू हो गये हैं और वहां पर आपके योगा, एनसीडी स्क्रीनिंग, बीपी, शुगर, इस तरह की 12 सेवाएं हैं, टेली मेडिसन, फ्री मेडिसन, फैमिली प्लानिंग, ये जितनी भी चीजें हैं, ये वहां पर आपके सब सेंटर जो हमारा लोएस्ट लेवल है वो इनको उपलब्ध करायेगा, यह मैं सोचता हूं कि हमारे गांवों के लिए बहुत बड़ी चीज होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैंने प्रश्न भी आंसर किया था, गहलोत साहब ने जनता क्लीनिक खोली थी, 2019-20 में, वो जनता क्लीनिक वो आपने पूरे राजस्थान में इतनी भारी उपलब्धि थी कि आपने खाली 15 ही खोली और पूरे राजस्थान में मोहल्ला क्लीनिक आपने दिल्ली में देखी उसको आपने कॉपी कर लिया, यहां 15 ही खोली, ...(व्यवधान)... ओनली 15, इनकी लिस्ट भी है मेरे पास में, मैं दे दूंगा और उसके अन्दर क्या था कि दानदाता और सी एस आर फण्ड से पैसा आता, सी एस आर और दानदाता, Government was not paying. ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): कुछ नहीं।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नो, निल बटा निल। ...(व्यवधान)... जूली साहब, प्लीज सुनो। आप मेरे फैक्टस कम्पेयर कर लेना। अब सुनिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मैं तो इतना-सा कह रहा हूं कि हेल्थ का मामला इतना सीरियस है और जोगारामजी इसको डाइवर्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा सीरियस रहना चाहिए, गम्भीरता। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: ये शायद आपको हंसा रहे हैं, ताकि आप स्वस्थ रहें। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): ये नाराज हैं कि अध्यक्षजी जोधपुर गये और मेरे को जोधपुर नहीं लेकर गये, इसलिए नाराज हैं।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि उसके बाद जनता क्लीनिक का उद्देश्य यह था....

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): नाराज तो हूं लेकिन कारण बता दूं? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: नहीं बताना, राज को राज रहने दो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): राज को राज रहने दो।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां पर कस्बे हैं, जहां डिस्टेंस ज्यादा है, गरीबों के लिए तो यह जो इन्होंने जनता क्लीनिक इन्होंने खोली इसके बाद इन्होंने 2021-22 में उसका नाम लिख दिया शहरी स्वास्थ्य कल्याण केन्द्र, ठीक है जी, उसके बाद क्या हुआ 2020 और 2021 हमारे हिन्दुस्तान के शेर मोदीजी ने युवाम शुरू कर दी, युवाम के अन्दर इन्होंने सबसे पहले 2020-21 में, 2021-22 में 122 पी एच

सी, सी एच सी जो भी नजदीक हो, खोले, 2022-23 में 142 दुबारा। उसके बाद में इन्होंने 2023-24 में 143 और 2024-25 में 181, इसके अन्दर पूरा फण्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया का 7 लाख रुपये प्रति महीने, ये तीन के सेट में चलाते थे, जनता क्लीनिक और हमारे आज है 357, अरबन आयुष्मान आरोग्य मन्दिर। उसमें सैलरी, रेंट, माइनर रिपेयर, ऑल्टरेशन, फर्नीचर, स्टाफ प्लेसमेंट और एक डॉक्टर, दो जीएनएम, एक एएनएम और एक लैब टेक्नीशियन, एक फार्मा, एक हेल्पर और एक स्वीपर, 125 जांचें, मेडिसंस और 8 टेस्ट जिसमें एक कार्ड से है, यह जो था, यह बड़ा मोदीजी की उपलब्धि थी जो इन्होंने 357 अरबन आयुष्मान आरोग्य मन्दिर बनाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आयुष्मान टावर, नींवें आपने लगायी, बहुत बढ़िया, बजट घोषणा के अन्दर 1100 करोड़ का बनेगा, आपका आयुष्मान टावर अगले साल चालू हो जायेयगा, इसके अन्दर सब सुपर स्पेशलिटी, स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनेगा, कार्यकारी एजेंसी इसकी जेडीए है, 1100 करोड़ रुपये का यह प्रोजेक्ट है, 1,243 बेड होंगे, ऑपरेशन थियेटर 20 होंगे, कैथ लैब 4 होंगे, ओपीडी पंजीकरण काउण्टर 100 होंगे, और 1 चिकित्सा, अपने कोविड के जो डॉक्टर्स जो फाइटर्स थे उनका एक स्मारक बनेगा वहां पर, उन्होंने अपना जो योगदान दिया।

MLS/RTM/06.03.2025/22:10/5d

और एक होगा हेलीपैड, मरीजों के लिए। सरकार जब भी बदले, जूली जी, उसको यूज मत कर लेना हैलीपैड को कॉन्स्टीट्यूएंसी में जाने के लिए। Only for medical reasons. ...(व्यवधान)... कार्डियोवेस्क्यूलर टावर, जो इस साल तैयार हो जायेगा, वह भी एक स्टेट ऑफ द आर्ट, ये दोनों जो चीजें बनेंगी, राजस्थान के लिए गौरव की चीजें होंगी। आप लोगों ने उनकी नींवें लगायी हैं, आप लोगों को भी धन्यवाद, पर हम इसको कैरी फॉरवर्ड करके अच्छी बढ़िया फिनिशिंग करेंगे। उसमें हृदय रोग सुविधाएं, बेड क्षमता 212, ऑपरेशन थियेटर्स 5, कैथलैब्स 5, ओपीडी पंजीकरण काउंटर्स 4, और इनका सिविल कार्य ऑलमोस्ट कम्प्लीट होने को आ रहा है। इस साल हमें आशा है कि इसको भी हम खोल लेंगे।

भौगोलिक दृष्टि से देखा जाये, एसएमएस 4 हजार बेड का हॅस्पिटल है, शहर बहुत बड़ा हो गया है, एक साइड से दूसरी साइड जाने में 40-40 मिनट भी लग जाते हैं तो भौगोलिक दृष्टि से देखते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने आर यू एच एस को एम्स के तौर पर 'रिम्स' बनाने की घोषणा की है। वहां पर मेडिकल एजुकेशन भी होगी, रिसर्च भी होगा और ट्रीटमेंट भी होगा। इसके अन्दर अभी 700 करोड़ रुपये हमें दो बजट्स में मिल चुके हैं और इसको हम बिलकुल एम्स की तर्ज पर रन करेंगे और एसएमएस का जो डेली का 15 हजार रोगियों का फुटफॉल है, उसे वह कट करेगा। एसएमएस हॉस्पिटल का ढांचा जब बना था, उस टाइम जयपुर की आबादी ढाई लाख थी और अब हो गयी है 42 लाख। एसएमएस के ऊपर बहुत प्रेशर है। एसएमएस की बराबर टक्कर से इसको हम आगे, सुपर स्पेशियलिटी है, अभी वहां

गैस्ट्रो, कार्डियो, नेफ्रो हैं, वहां पर न्यूरो, न्यूरो सर्जरी, यूरोलॉजी, एंड्रोक्रोनोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, ऑन्कोलॉजी और ऑन्कोलॉजी सर्जरी।

वहां पर राजस्थान की बेस्ट मशीनें लगी हुई हैं। ...(व्यवधान)... 25 करोड़ और 10 करोड़ का लीनियर एक्सीलरेटर लगा है, जिससे कैंसर के ऑपरेशंस हो सकें। स्टेट ऑफ द आर्ट, मेरे ख्याल से राजस्थान में ऐसी मशीनें नहीं हैं, जो आपके आरयूएचएस में हैं तो इससे भी पूरे राजस्थान को बहुत लाभ मिलेगा। कैंसर सैंटर, इसके अन्दर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 119 करोड़ दिया है, राजस्थान गवर्नमेंट 121 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसके अन्दर मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, रेडियो थैरेपी, पैलेटिव मेडिसिंस, पैथोलॉजी, ब्लड बैंक, ये सब आपके आरयूएचएस के अन्दर आएंगे और लीनियर एक्सीलरेटर वहां पर ऑलरेडी है।

राइजिंग राजस्थान में हमारे लिए बहुत एनकरेजिंग था कि लगभग 16 हजार 276 करोड़ के एमओयूज खाली न्यू मेडिकल कॉलेजेज के लिए हुए हैं। ये एमओयूज अगर ग्राउंड पर आ जाएं तो हमारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज को बहुत तगड़ा बूस्ट मिलेगा। ...(व्यवधान)... आ जायेगा जी। वे लोग जो साइन करने आये हैं, वे जयपुर भ्रमण करने, चने खाने तो नहीं आये हैं, वे काम करने आये हैं। एम्बुलेंस जो हैं अभी, 1778 एम्बुलेंसेज आयी हैं, 800 जननी की, 836 बेसिक लाइफ सपोर्ट की, 197 एडवांस लाइफ सपोर्ट की और मैंने तय यह किया है कि नेशनल हाइवेज, स्टेट हाइवेज के लोग, पीडब्ल्यूडी को बैठाकर जो-जो हाइवेज के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ये एम्बुलेंसेज, जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम करोड़ रुपये से ऊपर की एम्बुलेंसेज हैं, आपके भी कोई सुझाव होंगे, हम उन एम्बुलेंसेज को सही हाइवेज पर लगाएंगे ताकि वह जो एक्सीडेंट से एक घण्टे पहले का क्रिटिकल आवर होता है, उसके अन्दर लोगों की जान बच जाये।

रामाश्रय, रामाश्रय जो है, यह माननीय मुख्य मंत्री जी के इनीशिएटिव पर हुई थीं। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पर हैं। वन पॉइंट, जहां पर बूढ़े लोग टैस्ट भी करा सकें, फ्री मेडिसिंस भी करा सकें, ट्रीटमेंट भी करा सकें, फिजियो भी करा सकें और अभी 21 हजार बुजुर्गों ने बैनिफिट लिया है और 8.46 लाख इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, उनके लिए एक जो डेडिकेटेड रूम है, वह डॉरमेटरी होगी, जहां पर उनकी नर्सिंग केयर हो सके। मोदी जी ने तो अभी उदारता से 70 साल की उम्र से ज्यादा के लोगों को 5 लाख का जो इंश्योरेंस दिया है, उसका भी हमारे बुजुर्गों को फायदा मिलेगा।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसको कहते हैं ''आभा कार्ड''। यह आपका जो आधार कार्ड होता है, वैसा बनता है। अपन कभी भी किन्हीं डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, यहां जाते हैं, उदयपुर में जाते हैं और जब अपनी जांच कराते हैं तो वे पुरानी हिस्ट्री मांगते हैं कि कहां हैं आपकी स्लाइड्स, कहां हैं आपके प्रिस्क्रिप्शंस। आभा कार्ड वे सब चीजें ले लेगा और जब आप वह कार्ड लेकर जाएंगे तो डॉक्टर देख पायेगा कि आपका क्या ट्रीटमेंट किस डॉक्टर से हुआ, आपका क्या डायग्नॉसिस और आपका क्या प्रिस्क्रिप्शन है, यह भी काफी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। मैं सोचता हूं कि हमारे स्टेट में यह एक टैक्नोलॉजिकल

एडवांसमेंट आ गयी है और सब लोग इसका फायदा उठाएंगे।

मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना, इसके अन्दर आप लोगों ने 2023-24 में 1688 करोड़ दिये थे, खर्च किये थे, मतलब एक साल पहले हमारे से। हमने इसको बढ़ाकर 1,688 से 2,111 करोड़ कर दिया है। इसके अन्दर अभी तक 2024-25 में 16.5 करोड़ लाभार्थी फायदा उठा चुके हैं। मैं एक बार फिर सब सदस्यों को कहूंगा कि मेडिकल हेल्थ जो है, क्योंकि अपनी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो हमारी प्रोडक्टिविटी कम होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी तो हमारी जी डी पी नहीं बढ़ेगी, इसलिए मेडिकल और हेल्थ, यह एक ऐसी चीज है, इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिये और मैं विपक्ष के सब लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं कि कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे स्टाफिंग पैटर्न है...। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, दिनभर में आपको खूब समय मिला। दिनभर में आपको जो बोलना था, बोल लिये। अब नहीं। ...(व्यवधान)... नो, अब नहीं।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, जो हमने पोर्टल पर भर्तियां की हैं सबकी, फर्स्ट टाइम जो आये हैं और भर्तियां होने के बाद में जब वो फिल्टर्स लगकर और मेरिट और सब चीजें लीं और जब पोस्टिंग दी, हमने उस टाइम बोला कि स्वेच्छा से आप अदला-बदली कर सकते हो तो यह नहीं हुआ कि किसी को लेकर पटक दिया तो वह वहां दु:खी बैठा हुआ है। स्वेच्छा से बहुत लोगों ने चैंजिंग की थी, म्युचअल जिसको कहते हैं और मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि यह जो स्टेप हमने लिया है पोर्टल के थ्रू और खाली रिक्त पदों पर, यह जाहिर करता है कि हम कोई भी भेदभाव विपक्ष के साथ नहीं रखते हैं। हमारे लिए सब लोग बराबर हैं और मुझे आशा है कि आप लोगों का कोई भी भवन लेट बन रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, यह जो हेल्थ का मामला है, इसके अन्दर पॉलिटिक्स से ऊपर रहकर हमें एक-दूसरे की मदद करनी चाहिये तो आप अपने आपको विपक्ष मत समझना, हमसे घृणा मत करना और आपके जो भी इश्यूज हैं, उन्हें हम शॉर्ट आउट करेंगे, कोई भेदभाव नहीं रखेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया...। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मिस्टर विकास, फिर बैठे-बैठे बोल रहे हैं। नो।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय...।

श्री अध्यक्ष: बैठिये। माननीय सदस्य, आपने डिमांड पर इतना बोल लिया, और क्या है? ...(व्यवधान)... नो। बाकी अगली डिमांड पर बोलना। ...(व्यवधान)... शान्त रहिये।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इनको इतनी प्यारी-प्यारी बातें इनको कही, फिर भी ये नाराज हो रहे हैं। आपसे यह निवेदन है कि इस डिमांड को पास करें।

श्री अध्यक्ष: हो गया डिमांड का? आपने कह दिया कि डिमांड पारित की जाये? यह तो कहें।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन

है...।

श्री अध्यक्षः मांग संख्या बोलिये।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मांग संख्या 27 और 28 पारित की जाएं।

MKD/RTM/06.03.2025/22:20/5e

मांग संख्या 27 - चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का पारण

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है कि मांग संख्या 27 - चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,33,28,96,25,000/- (एक सौ तैंतीस अरब अट्ठाईस करोड़ छियानवे लाख पच्चीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 28 - चिकित्सा शिक्षा का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 28 - चिकित्सा शिक्षा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त 61,31,82,57,000/- (इकसठ अरब इक्तीस करोड़ बयासी लाख सतावन हजार) राज्यपाल महोदय को रुपये तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 07 मार्च, 2025 के प्रातः ...(व्यवधान)... बैठिए, नो। इधर भी कोई नहीं उठेगा, अभी स्थगित नहीं हुई है।

सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 07 मार्च, 2025 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 22.21 बजे, शुक्रवार, दिनांक 07 मार्च 2025 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

अनुदान की मांग संख्या 27 - चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर प्राप्त कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 27 - चिकित्सा एवं स्वास्थ्य_के अन्तर्गत मांग में से **100 रुपया** कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री ललित मीना (वि.सं.142)

1. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में बन्द पड़े एमटीसी केन्द्र पुन: चालू करवाने एवं चिकित्सा केन्द्रों पर उपकरण उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कंवरलाल (वि.सं.26)

2. विधान सभा क्षेत्र अंता में नये स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा पीएचसी को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र (वि.सं.128)

3. विधान सभा क्षेत्र महवा में जिला हॉस्पीटल, सीएचसी हुडला, बालाहेडी एवं सांथा में टैण्डर प्रक्रिया कर निर्माण कार्य चालू कराने, महवा जिला हॉस्पीटल को रैफरल कराने, हॉस्पीटल में ब्लड बैंक एवं कैंसर वार्ड की स्वीकृति, पीएचसी रसीदपुर को सीएचसी में क्रमोन्नत करने, सीएचसी मण्डावर को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (वि.सं.94)

4. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री दर्शनसिंह (वि.सं.77)

5. जयपुर के गोयल हॉस्पीटल, पुरानी चुंगी, आगरा रोड में "मुख्य मंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना" पुन: शुरू करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री शंकरसिंह रावत (वि.सं.159)

6. ब्यावर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बडाखेडा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

डॉ. जसवंत सिंह यादव (वि.सं.61)

7. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, इमरोली (नीमराणा) को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।
8. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के उप स्वास्थ्य केन्द्र, जादोज को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।
9. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के वंचित गांवों में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

डॉ. जसवंत सिंह यादव (वि.सं.61)

10. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के जिला अस्पताल में मोक्ष वाहिनी वाहन उपलब्ध कराने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

11. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बडौद (बहरोड़) में 50 बैड़ के अस्पताल को 75 बैड़ का किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रमेश खींची (वि.सं.125)

12. विधान सभा क्षेत्र कठूमर में डाक्टर्स व पैरा मेडीकल स्टाफ के रिक्त पदों को भरने, दउका, इसरौता, बल्देवपुरा, लाढरी, इरनियां में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करने, खेडामेदा, दांतिया, खोट में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करने, कठूमर में उप जिला अस्पताल स्वीकृत करने तथा बतलूकलां में सीएचसी स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री ललित मीना (वि.सं.142)

13. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहबाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, समरानिया, शाहबाद कस्बा थाना, नाहरगढ में एक्स-रे मशीन एवं समरानिया-शाहबाद एवं नाहरगढ़ में बायो केमेस्ट्री मशीन व समरानिया एवं कस्बा थाना में सोनोग्राफी की मशीन उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हमीर सिंह भायल (वि.सं.190)

14. विगत बजट 2024-25 में नये सब सेन्टर खोलने की घोषणा अनुरूप विधान सभा क्षेत्र सिवाना में नव स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना एवं अम्बों का वाड़ा (लाखेटा) में दोहरा सब सेन्टर संचालित करने के स्थान पर एक सब सेन्टर ग्राम पंचायत कोटडी (समदडी) में स्थानान्तरित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

15. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के नवीन पीएचसी, सिणेर, डन्डाली एवं इन्द्राणा में चारदीवारी एवं अन्य सुविधाओं के लिए अतिरिक्त बजट की आवश्यकता एवं पीएचसी, इन्द्राणा का संवेदक द्वारा भवन निर्माण प्रारम्भ नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

16. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में सिणधरी मुख्यालय पर ट्रोमा सेन्टर एवं नया पीएचसी भूका भगत सिंह तेलवाड़ा एवं ढीढ़स में खोलने एवं बजट घोषणा 2025-26 के तहत नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

17. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के उप जिला अस्पताल, सिवाना एवं क्रमोन्नत उप जिला अस्पताल, समदड़ी में रिक्त पदों को भरने, महिला चिकित्सक लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गोपाल लाल शर्मा (वि.सं.44)

18. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के उप स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री विक्रम सिंह जाखल (वि.सं.150)</u>

19. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ के जिला अस्पताल में ब्लड़ बैंक का भवन उपकरणों के अभाव में संचालित नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री शंकरलाल डेचा (वि.सं.158)</u>

20. विधान सभा क्षेत्र सागवाडा में पीएचसी, पाठवा को क्रमोन्नत करने व ओबरी सीएचसी में 100 शैय्याऐं करने तथा मोर्चरी स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री हरिसिंह रावत (वि.सं.193)</u>

21. विधान सभा क्षेत्र भीम में उप जिला चिकित्सालय को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

22. विधान सभा क्षेत्र भीम के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुआथल व कुन्दवा को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

23. विधान सभा क्षेत्र भीम के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरार व बार को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

24. विधान सभा क्षेत्र भीम में उप जिला चिकित्सालय के परिसर में चिकित्सक व अन्य मंत्रालयिक कर्मचारियों के निवास हेतु भवन का निर्माण करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री हंसराज पटेल (वि.सं.187)</u>

25. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के बीडीएम जिला चिकित्सालय को 250 से 300 बैड में क्रमोन्नत करने, जनाना अस्पताल को सेटेलाईट अस्पताल में क्रमोन्नत करने, सब सेन्टर लूरी भडाज व कल्याणपुरा को क्रमोन्नत करने तथा पीएचसी, चिमनपुरा को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री ललित मीना (वि.सं.142)</u>

26. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के सभी सीएचसी एवं पीएचसी पर नए एमटीसी वार्ड खोलने तथा जनजाति विभाग द्वारा वित्तीय स्वीकृति देने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री रेवन्तराम डांगा (वि.सं.189)</u>

27. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के सैनणी, माणकपुर एवं भदोरा उप स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

28. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के मेडास, गोलियासनी, छिलरा, चिताणी, मिरजास एवं आमण्डा की ढाणी में नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

29. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुचेरा को ट्रोमा सेन्टर में विकसित करने, चिकित्सकों व स्टाफ के रिक्त पदों को भरने तथा सोनाग्राफी व डिजिटल एक्स-रे मशीन लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

30. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कडलू, रूण, तांतवास, करणू, गुढा भगवानदास को क्रमोन्नत किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (वि.सं.54)

31. विधान सभा क्षेत्र आहोर में भाद्राजून, भूती, बागरा, आहोर, सिवाणा सीएचसी एवं पीएचसी-पावटा, उम्मेदपुर, चांदराई, नोरवा, सांकरणा, ऊण, वादनवाडी में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (वि.सं.54)

32. विधान सभा क्षेत्र आहोर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भूती, भाद्राजून, पादरली व पीएचसी नोरवा के भवन की स्वीकृति बजट घोषणा के अनुरूप देने के संबंध में चर्चा के लिए।

33. विधान सभा क्षेत्र आहोर के गुडाबालोतान, भवरानी, हरजी एवं चादराई में पीएचसी को क्रमोन्नत करने एवं आईपुरा, अजीतपुरा में पीएचसी की स्वीकृति देने के संबंध में चर्चा के लिए।

34. विधान सभा क्षेत्र आहोर में बजट घोषणा अनुसार सीएचसी में डिजीटल एक्स-रे मशीन लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

35. विधान सभा क्षेत्र आहोर के कुआरडा, रसियावास खुर्द नबी, बागुन्दा, गुडारामा में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री ललित मीना (वि.सं.142)

36. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के शाहबाद सीएचसी हॉस्पीटल को क्रमोन्नत करने के संबंध मं चर्चा के लिए।

37. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के नाहरगढ़ के सीएचसी अस्पताल को 30 बैड़ से 50 बैड़ के क्रमोन्नत करने व एक्स-रे मशीन स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अतुल भंसाली (वि.सं.03)

38. जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल परिसर में 4000 वर्ग मीटर जमीन आयुर्वेद जिला अस्पताल के लिए उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

39. जोधपुर महात्मा गांधी चिकित्सालय में कार्डियक केयर यूनिट, कैथ लैब एवं 10 डायलेसिस मशीनों की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र (वि.सं.128)

40. विधान सभा क्षेत्र महवा के पीएचसी, रसीदपुर को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

41. विधान सभा क्षेत्र महवा के सीएचसी, मण्डावर को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

42. विधान सभा क्षेत्र महवा के जिला अस्पताल में कैंसर वार्ड एवं ब्लड बैंक की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

43. विधान सभा क्षेत्र महवा के अस्पताल को रैफरल बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री अंशुमान सिंह भाटी (वि.सं.01)</u>

44. बीकानेर जिले के ग्रामीण अंचल में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व उप स्वास्थ्य केन्द्र में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री अंशुमान सिंह भाटी (वि.सं.01)</u>

45. विधान सभा क्षेत्र कोलायत के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरसलपुर, बीकमपुर, किल्चू, आ.डी.820 को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

46. बीकानेर जिला मुख्यालय के चिकित्सालयों में पदस्थापित आयुर्वेदिक चिकित्सकों के कार्य व्यवहार से जनता में व्याप्त रोष की स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

47. विधान सभा क्षेत्र कोलायत में उप स्वास्थ्य केन्द्र रणजीपुरा, चारणवाला, राओवाला, गोकुल, खींदासर, नोखडा, सुरजडा, जग्गासर, गुडा, कोलासर-मेघासर को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री अतुल भंसाली (वि.सं.03)</u>

48. जोधपुर के एमडीएम, एमजीएच एवं उम्मेद अस्पताल को संभागीय हॉस्पिटल का दर्जा देकर एम्स की तर्ज पर कार्य योजना बनाकर डवलपमेंट के कार्य किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री गणेश घोगरा (वि.सं.39)</u>

49. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के बिछीवाड़ा सीएचसी पर ट्रोमा सेन्टर खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

50. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के सामान्य अस्पताल में साफ-सफाई नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

51. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में सीएचसी और पीएचसी पर रात के समय स्टाफ उपलब्ध नहीं रहने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री कैलाश चन्द वर्मा (वि.सं.36)</u>

52. विधान सभा क्षेत्र बगरू के ग्राम अजयराजपुरा, बालावाला एवं पंवालिया स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री सुरेश मोदी (वि.सं.183)</u>

53. विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में चिकित्सा व्यवस्था दुरूस्त करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (वि.सं.51)</u>

54. विधान सभा क्षेत्र चित्तौडगढ के सांवलिया जी सामान्य जिला चिकित्सालय में कार्डियक व न्यूरोलोजी विभाग के सृजन के संबंध में चर्चा के लिए।

55. विधान सभा क्षेत्र चित्तौडगढ़ के सेमलपुरा चौराहा, रिवोला चौराहा व नरपत की खेड़ी के आस-पास ट्रोमा सेन्टर की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिए।

56. चित्तौड़गढ़ के उप स्वास्थ्य केन्द्र, आंवलहेडा, गिलुण्ड व मातजी की पाण्डोली को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

57. विधान सभा क्षेत्र चित्तौडगढ़ के सीएचसी एवं पीएचसी पर चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री हाकम अली खां (वि.सं.197)</u>

58. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के सीएचसी, पीएचसी, सब सेन्टरों के भवन निर्माण हेतु बजट आवंटन करने तथा रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री सुरेश गुर्जर (वि.सं.176)</u>

59. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में चिकित्सा विभाग के विभिन्न रिक्त पदों को अविलम्ब भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

60. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, वकानी, रटलाई, पनवाड एवं सारोलाकलां की बैड क्षमता 30 से बढाकर 50 बैड करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

61. झालावाड़ के उपखण्ड मुख्यालय खानपुर में ट्रोमा चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

62. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खानपुर को क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री हरिमोहन शर्मा (वि.सं.192)</u>

63. विधान सभा क्षेत्र बूंदी के विभिन्न पीएचसी व सीएचसी और बृजसुन्दर शर्मा सामान्य चिकित्सालय में विशेषज्ञों, चिकित्सकों और पैरा मेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों को भरने की आवश्कयता के संबंध में चर्चा के लिए।

64. प्रदेश में बजट घोषणानुसार विधान सभा क्षेत्र बूंदी के सीएचसी को मॉडल चिकित्सालय बनाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

65. विधान सभा क्षेत्र बूंदी के चिकित्सालयों में खराब उपकरणों के स्थान पर नवीन उपकरण उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

66. आर.जी.एच.एस. में समय पर भुगतान न करने के कारण पेंशनर्स को विक्रेता द्वारा दवाईयां उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

67. विधान सभा क्षेत्र बूंदी के दोलाडा, मीरागेट व मिलोड एवं नगर परिषद, बूंदी में जनता क्लिनिक खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री संजीव कुमार (वि.सं.171)</u>

68. विधान सभा क्षेत्र भादरा की नव क्रमोन्नत सीएचसी, नेठराना के लिए शीघ्र नवीन भवन निर्माण करवाकर चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

69. विधान सभा क्षेत्र भादरा के उप स्वास्थ्य केन्द्र, शेरड़ा को क्रमोन्नत करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

70. विधान सभा क्षेत्र भादरा में चिकित्सा सुविधाओं से पूर्णतया वंचित गांवों में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

71. विधान सभा क्षेत्र भादरा की एस.डी.एच, विभिन्न सीएचसी एवं पीएचसी में चिकित्सकों के रिक्त पद शीघ्र भरे जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

72. विधान सभा क्षेत्र भादरा के भवन रहित उप स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री जब्बर सिंह सांखला (वि.सं.57)

73. विधान सभा आसीन्द के आसीन्द सीएचसी को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

74. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के ब्रान्की सरेरी, दोलतगढ़ व कंवलियास पीएचसी को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

75. विधान सभा आसीन्द के भादली, कटार, बरसनी में सब सेंटरों को पीएचसी में क्रमोन्नत करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रोहित बौहरा (वि.सं.139)

76. विधान सभा क्षेत्र राजाखेडा की सीएचसी, मनियां पर सीनियर डॉक्टर को Head का चार्ज नहीं देने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री नाना लाल निनामा (वि.सं.85)

77. विधान सभा क्षेत्र घाटोल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खमेरा को क्रमोन्नत करने व इसमें बैड एवं स्टाफ बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामकेश (वि.सं.133)

78. विधान सभा क्षेत्र गंगापुरसिटी में निर्माणाधीन जिला अस्पताल के निर्माण में वित्तीय कठिनाईयों को दूर करने एवं वर्तमान अस्पताल को मातृ एक शिशु चिकित्सालय में परिवर्तित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री डूंगरराम गेदर (वि.सं.72)

79. प्रदेश में चिकित्सकों का पृथक कैडर बनाने, चिकित्सकों को चतुर्थ डीएसीपी ग्रेड पे 9500 देने तथा चिकित्सा शिक्षकों के समान चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री सुखवंत सिंह (वि.सं.65)

80. प्रदेश में चिकित्सकों का पृथक कैडर बनाने, चिकित्सकों को चतुर्थ डीएसीपी ग्रेड पे 9500 में देने तथा चिकित्सा शिक्षकों के समान चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बालमुकुन्दाचार्य (वि.सं.102)

81. प्रदेश में चिकित्सकों का पृथक केडर बनाने, चिकित्सकों को चतुर्थ डीएसीपी 9500 ग्रेड पे देने तथा चिकित्सा शिक्षकों के समान चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़) (वि.सं.112)</u>

82. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ के उप जिला चिकित्सालय में आईसीयू स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

83. उप तहसील मुख्यालय कातर छोटी, जिला चूरू के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री रामावतार बैरवा (वि.सं.137)</u>

84. विधान सभा क्षेत्र चाकसू में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, माधोराजपुरा, नेनवाल माजी एवं कोटखावदा को सैटेलाईट चिकित्सालयों में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री सोहन लाल नायक (वि.सं.186)</u>

85. श्री गंगानगर के ब्लॉक श्री विजयनगर में डाक्टरों की कमी को पूर्ण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री संजय कुमार (वि.सं.169)</u>

86. विधान सभा क्षेत्र बसेडी में नई पीएचसी व सीएचसी खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

87. विधान सभा क्षेत्र बसेडी में डॉक्टरों की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती कल्पना देवी (वि.सं.28)</u>

88. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

89. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के उप स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों की सार-संभाल, रंग-रोगन एवं भौतिक सुविधाए उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

90. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में जनसंख्या के निर्धारित मापदण्डों के आधार पर नये उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

91. कोटा के महाराव भीमसिंह चिकित्सालय में 3 टेसला मशीन, एम.आर.आई. मशीन एवं अनुपलब्ध जांच उपकरण उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

92. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में खराब उपकरणों को ठीक कराये जाने एव जांच के लिए अनुपलब्ध उपकरणों को उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम (वि.सं.50)

93. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम मे सभी चिकित्सालयों में विभिन्न रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

94. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गढमौरा कैमरी, रायसीना, पदमपुरा को क्रमोन्नत करने व विभिन्न पीएचसी/सीएचसी में नागरिक सुविधा केन्द्र बनवाने के संबंध में चर्चा की के लिए।

95. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के विभिन्न चिकित्सालयों की बैड क्षमता बढवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

96. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में मातृ एवं शिशु रोग ईकाई खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

97. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में ट्रोमा सेन्टर खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

डॉ. प्रियंका चौधरी (वि.सं.96)

98. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर मे राजस्व ग्राम अणदे का तला, असाड़ा की बेरी, नवलासर तथा नागाणा में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

99. विधान सभा क्षेत्र बाडमेर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सनावड़ा एवं बेरिवाला तला को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

100. विधान सभा क्षेत्र बाडमेर स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज व संबद्ध अस्पताल में कैथ लैब, एम.आर.आई. मशीन, उच्च क्षमता की सीटी स्कैन तथा डायलिसिस मशीन स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

101. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में जिला मुख्यालय पर राजकीय जिला चिकित्सालय स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री राधेश्याम बैरवा (वि.सं.131)

102. बारां जिला मुख्यालय पर ट्रोमा हास्पीटल खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

103. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू में स्थित जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकीय उपकरणों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

104. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू में स्थित सीएचसी/पीएचसी में विभिन्न स्टाफ की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हंसराज मीना (वि.सं.188)

105. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा के उप स्वास्थ्य केन्द्र, बालोती, चौडागांव, खेडली, निमेडा, महाराजपुरा, कल्याणी, बीजलपुर एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नारोली डांग को क्रमोन्नत किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री समरजीत सिंह (वि.सं.174)

106. राजकीय अस्पताल, भीनमाल का बजट वर्ष 2024-25 में उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत होने से चिकित्सकों के रिक्त पदों पर पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कुलदीप (वि.सं.33)

107. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भांकरी ब्लाक पावटा को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रफीक खान (वि.सं.123)

108. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर में सभी डिस्पेन्सरी एवं अस्पतालों में स्टाफ की कमी तथा बगराना, विजयपुरा एवं सुमेल की डिस्पेन्सरी के लिए भवन बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

109. जयपुर के एम.डी. रोड़ स्थित सैटेलाईट अस्पताल में टीबी की दवाइयों तथा बगराना, सुमेल, विजयपुरा डिस्पेन्सरी एवं जामडोली अस्पताल में दवाइयों की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री श्रवण कुमार (वि.सं.167)

110. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ की सी.एच.सी. को क्रमोन्नत करने एवं बैड बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता भदेल (वि.सं.4)

111. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में एन.यू.आर.एच.एम. के तहत निर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चन्द्रवरदायी एवं शहरी स्वास्थ्य केन्द्र नाका मदार में नियमित चिकित्सकों के पद सृजित किए जाने के साथ ही सी.एच.सी. चन्द्रवरदायी एवं सैटेलाईट चिकित्सालय, आदर्श नगर हेतु महिला चिकित्सकों के पद सृजित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

112. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में स्थित आदर्श नगर जिला चिकित्सालय से सम्बद्ध नवीन नर्सिंग कॉलेज की घोषणा के बावजूद कार्य प्रारम्भ नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

113. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण के धोला भाटा स्थित राजकीय स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र के भवन निर्माण हेतु डीएमएफटी फण्ड से कार्य नहीं कराए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

114. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में स्थित जिला चिकित्सालय में सीटी स्कैन मशीन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

115. अजमेर शहर के सैटेलाईट चिकित्सालय, आदर्श नगर के चिकित्सालय परिसर में विभिन्न स्टाफ के क्वार्टस बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री उदयलाल भडाणा (वि.सं.22)

116. विधान सभा क्षेत्र माण्डल के राजकीय चिकित्सालय, करेड़ा को सैटेलाईट चिकित्सालय में क्रमोन्नत किए जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

117. विधान सभा क्षेत्र माण्डल के मंगरोप पी.एच.सी. को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

118. विधान सभा क्षेत्र माण्डल के राजकीय चिकित्सालयों में एम्बुलेंस (104-108) के संचालन के संबंध में चर्चा के लिये।

119. विधान सभा क्षेत्र माण्डल के बागौर चिकित्सालय (सीएचसी) को पुन: बागौर कस्बे में संचालित किए जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

120. विधान सभा क्षेत्र माण्डल के ग्राम पालड़ी में नवीन सी.एच.सी. खुलवाए जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मण (वि.सं.140)

121. विधान सभा क्षेत्र बस्सी के अस्पतालों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री कान्ति प्रसाद (वि.सं.29)

122. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के अस्पतालों में समुचित चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं आर.जी.एच.एस. धारकों को दवाइयां उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री डूंगरराम गेदर (वि.सं.72)

123. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में 10 एसपीडी, रत्तासर, लघेर, 2 डीडब्ल्यूएम, 6 जीडीएम सूरजनसर, 3 एफडीएम एवं चाड़सर में सब सेन्टर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

124. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बीरमाना, उप केन्द्र, सरदारपुरा खर्था, पदमपुरा, भगवानसर को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

125. प्रदेश में प्रयोगशाला सहायक के नए पद सृजित करने एवं जिन चिकित्सा संस्थानों से उक्त केडर के पद विलोपित किए गए, उन्हें अन्य चिकित्सा संस्थानों में समायोजित करने तथा प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 में नियुक्त कर्मचारियों के स्थाईकरण आदेश जारी किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (वि.सं.101)

126. प्रदेश में कार्यरत मुख्य मंत्री नि:शुल्क निरोगी राजस्थान योजना (दवा) अन्तर्गत मशीन विद मैन (कम्प्यूटर ऑपरेटर) को संविदा सेवा नियम, 2022 में स्वीकृत 2532 पदों पर नियुक्त पत्र शीघ्र जारी करवाने एवं उक्त कार्मिकों के फिक्स मानदेय में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

127. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में उप स्वास्थ्य केन्द्र, सुवालिया, सोलंकिया तला, बेलवा खत्रियां एवं उटाम्बर को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

128. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चामू को 30 बैड से 50 बैड में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सोमेसर एवं चाबा को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

130. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बालेसर को जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भगवाना राम सैनी (वि.सं.104)

131. ग्राम रामपुरा, ग्राम पंचायत डूंगरी खुर्द, पंचायत समिति जोबनेर, जिला जयपुर में उप स्वास्थ्य केन्द्र प्रारम्भ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री रूपिन्द्र सिंह कुन्नर (वि.सं.200)

132. विधान सभा क्षेत्र करणपुर के चिकित्सा संस्थानों में जांच उपकरण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

133. श्रीगंगानगर में चिकित्सा विभाग के अधीन गबन के आरोपी अधिकारी (सीएमएचओ) को उसी कार्यालय में पदस्थापित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

134. राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गजसिंहपुर (श्रीगंगानगर) में मात्र एक चिकित्सक यू.टी.बी. पर होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

135. राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पदमपुर (श्रीगंगानगर) में बैड की क्षमता बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

136. राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 61-एफ (श्रीगंगानगर) में कार्यरत दो चिकित्सकों के पीजी करने से पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री आदू राम मेघवाल (वि.सं.19)

137. विधान सभा क्षेत्र चौहटन के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेड़वा को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

138. विधान सभा क्षेत्र चौहटन के पीएचसी, भूणिया को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

139. विधान सभा क्षेत्र चौहटन के उप स्वास्थ्य केन्द्र, केकड, जूना लखवारा, गिड़ा, नेहरों की नाड़ी, रोहिला एवं आलमसर को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

140. विधान सभा क्षेत्र चौहटन के जाटों की बस्ती, देवाणियों का तला, साकरिया तला (पंचायत समिति चौहटन) रड़वा, अंबावा, खारी मोगावा (पंचायत समिति फागलिया), मोती की बेरी, भांभुओं का तला (पंचायत समिति सेड़वां), ढाको का तला (पंचायत समिति धनाऊ) में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

141. जिला चिकित्सालय, चौहटन में मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र (एमसीएच यूनिट) खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन कागजी (वि.सं.9)

142. विधान सभा क्षेत्र किशनपोल में बन रहे सैटेलाईट हॉस्पिटल में संसाधनों की कमी के संबंध में चर्चा के लिये।

143. विधान सभा क्षेत्र किशनपोल में नई पी.एच.सी.एवं सी.एच.सी. खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

144. विधान सभा क्षेत्र किशनपोल के क्रमोन्नत हुए अरबन सी.एच.सी. में डॉक्टरों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

145. जयपुर के एस.एम.एस. अस्पताल की ओपीडी में मरीजों को हो रही परेशानियों के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (वि.सं.168)

146. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के ग्राम विरियाखेड़ी (ग्राम पंचायत मण्डलाचारण), ग्राम नवाबपुरी (ग्राम पंचायत टाई), ग्राम रठांजना (ग्राम पंचायत केली) एवं ग्राम कल्याणपुरा (ग्राम पंचायत जलिया) में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

147. जिला चिकित्सालय, निम्बाहेड़ा में महिला एवं बाल चिकित्सालय यूनिट तथा ट्रोमा सेन्टर की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिये।

148. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के आदिवासी बाहुल्य धोला पानी में सी.एच.सी. की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिये।

149. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अरनोदा एवं बाड़ी को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

150. पंचायत समिति छोटी सादड़ी के उप स्वास्थ्य केन्द्र, साटोला एवं स्वरूपगंज को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री प्रशान्त शर्मा (वि.सं.95)

151. विधान सभा क्षेत्र आमेर की ग्राम पंचायत अचरोल में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार एवं चिकित्सा केन्द्र हेतु भूमि तथा भवन उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

152. विधान सभा क्षेत्र आमेर के चन्दवाजी, मानपुरा माचेड़ी, खोरा श्याम दास में चिकित्सा सेवाओं के विस्तार एवं विद्यमान चिकित्सालयों, सब सेन्टर्स को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गोपीचन्द मीणा (वि.सं.46)

153. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के ग्राम लुहारी कलां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्राम बनका खेड़ा में सब सेन्टर को क्रमोन्नत करने, ग्राम पंचायत बावड़ी में पीएचसी खोलने, पीएचसी पिपलेवाल के नवीन भवन निर्माण करने तथा सीएचसी शक्करगढ़ मेड़ा के आवास भवन एवं चारदीवारी निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री समाराम (वि.सं.175)

154. पिण्डवाड़ा, आबू क्षेत्र में नया एएनएम सेन्टर खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

155. पिण्डवाड़ा, आबू क्षेत्र की ग्राम पंचायत मोरस, ठण्डीवेरी, ईसरा एवं पाबा आबू रोड में नई पीएचसी खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

156. पिण्डवाड़ा, आबू क्षेत्र में नए उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा स्वास्थ्य केन्द्रों के जर्जर भवनों को ठीक कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

157. पिण्डवाड़ा, आबू में डॉक्टर्स के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री युनूस खान (वि.सं.121)</u>

158. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में ग्राम गरदेज्याबासनी, बुडोद, आस की ढाणी, खुनखुना गांव एवं लाड़ाबास में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

159. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, साल्ट रोड़, डीडवाना में पद स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

160. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के ग्राम निम्बीकलां एवं बालिया में उप स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

161. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खाटू खुर्द के जर्जर भवन के स्थान पर नए भवन की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

162. जिला मुख्यालय डीडवाना में दवा गोदाम **(Drug Warehouse)** बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री मांगेलाल मीना (वि.सं.117)</u>

163. विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गढ़ीसवाईराम को 30 बेड से 50 बेड में परिवर्तित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

164. विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ की सी.एच.सी. राजगढ़ (अलवर) को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री मांगेलाल मीना (वि.सं.117)</u>

165. विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ की सी.एच.सी. पिनान एवं रैणी (अलवर) को 30 बेड से 50 बेड में परिवर्तित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

166. विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ की सी.एच.सी. लक्ष्मणगढ़ (अलवर) को 50 बेड से 100 बेड में परिवर्तित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

167. विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ के उप स्वास्थ्य केन्द्र, सालोली (अलवर) को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री रामबिलास (वि.सं.135)</u>

168. विधान सभा क्षेत्र लालसोट के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शिवसिंहपुरा को क्रमोन्नत किए जाने तथा लालसोट में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (वि.सं.51)

169. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के जिला चिकित्सालय में गार्डन को विकसित करने एवं आगन्तुकों के बैठने हेतु पर्याप्त व्यवस्था किए जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जब्बर सिंह सांखला (वि.सं.57)

170. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के हुरड़ा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दोलगढ़ को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अशोक कुमार कोठारी (वि.सं.17)

171. भीलवाड़ा मेडिसिटी योजनान्तर्गत चिकित्सालय हेतु आरक्षित भूमि पर टर्सरी कैंसरकेयर सेंटर मय सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के निर्माण पर चर्चा के लिए।

172. बजट घोषणानुसार भीलवाड़ा स्थित महात्मा गांधी चिकित्सालय को कैथ लैब एवं सीटी स्कैन मशीनें उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

173. भीलवाड़ा जिला मुख्यालय स्थित महात्मा गांधी चिकित्सालय में चिकित्सकों एवं नर्सिंगकर्मियों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

174. गत बजट घोषणानुसार भीलवाड़ा में मॉडल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु चयनित हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुर के कार्य की प्रगति पर चर्चा के लिए।

175. भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर नवीन सैटेलाईट हॉस्पिटल खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती रमीला खड़ीया (वि.सं.124)

176. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के उप जिला अस्पताल में चिकित्सकों के रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हरलाल सहारण (वि.सं.191)

177. विधान सभा क्षेत्र चुरू के राजकीय डी.सी. अस्पताल में जांच हेतु एम.आर.आई., डोपलर, टूडी ईको, सीटीएमटी आदि के उपकरणों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (वि.सं.12)

178. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के पीपाड़ शहर में जिला चिकित्सालय के भवन के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

179. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिलाड़ा के उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत होने से वित्तीय स्वीकृति जारी करने तथा नवीन उप जिला अस्पताल हेतु भवन निर्माण की स्वीकृति देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

180. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/मॉडल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बोरूंदा/उप जिला अस्पताल/जिला अस्पताल, पीपाड़शहर में डॉक्टर्स/पैरा मैडिकल स्टाफ/विशेषज्ञ एवं कनिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पडे पदों पर शीघ्रातिशीघ्र पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

181. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में केन्द्र सरकार की योजना अंतर्गत जनता क्लिनिक खोलने की घोषणानुसार पाँच जनता क्लिनिक प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र में खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

182. प्रदेश में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/उप जिला अस्पताल में निर्धारित मापदंड़ों के अनुरूप स्वास्थ्य जांचे नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए

<u>श्री अतुल भंसाली (वि.सं.3)</u>

183. जोधपुर के महात्मा गांधी चिकित्सालय, एमडीएम, यूएमईडी हॉस्पिटल एवं सभी सरकारी चिकित्सालयों में ठेकाकर्मियों की उपस्थिति डिजिटल माध्यम से सुनिश्चित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

184. प्रदेश में विभागीय अस्पतालों में उनके स्तर के अनुरूप सभी मूलभूत सुविधाएं, मानव संसाधन, भूमि-भवन, जांच उपकरण आदि समस्त संसाधनों की मानक अनुरूप उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (वि.सं.80)</u>

185. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद के प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आधुनिक जांच सुविधाएं उपलब्ध करवाने एवं भवनविहीन केन्द्रों के नवीन भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

186. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद के उप स्वास्थ्य केन्द्र, पछमता एवं जुडदा खेड़ी को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

187. राजसमंद के कमला नेहरू राजकीय चिकित्सालय, कांकरोली को उप नगरीय (सैटेलाईट) चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिए।

188. आर.के. राजकीय जिला चिकित्सालय, राजसमंद में ह्रदय रोग इकाई प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

189. आर.के. राजकीय जिला चिकित्सालय, राजसमंद को बहु विशेषज्ञता चिकित्सा संस्थान के रूप में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री अनिल कुमार शर्मा (वि.सं.5)</u>

190. सरदारशहर स्थित पंडित भंवरलाल शर्मा उप जिला अस्पताल में ब्लड बैंक की स्थापना करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

191. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के सभी राजकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप जिला अस्पताल के सभी संवर्गों के समस्त रिक्त पदों को तुरन्त भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

192. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भोजूसर उपाधियान व भोजासर छोटा का भवन निर्माण करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

193. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के उप स्वास्थ्य केन्द्र, पुनुसर, बनियासर, उदासर चारणान, खुण्डिया, मांगासर, कुसुमदेसर, राजासर चोर्डिया हेतु भवन निर्माण करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

194. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के गांव गोलसर (तहसील-रतनगढ़) के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु नए भवन का निर्माण करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री गोरधन (वि.सं.47)</u>

195. विधान सभा क्षेत्र धोद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खूड, किरड़ोली एवं सरवड़ी को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

196. विधान सभा क्षेत्र धोद के उप स्वास्थ्य केन्द्र, जगतपुरा (दूगोली) एवं जाना के भवन निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

197. विधान सभा क्षेत्र धोद के लाडवा, कंवरपुरा (जाचास) में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

198. विधान सभा क्षेत्र धोद के उप स्वास्थ्य केन्द्रों- सावलोदा धायलान, सा. पुरोहितान, बोसाणा, हर्ष, खाखोली, बाडलवास, सेवदबड़ी, मण्डावरा, सामी, चिराणा, राजपुरा एवं चिड़ासरा को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री संदीप शर्मा (वि.सं.172)</u>

199. कोटा के शहरी स्वास्थ्य केन्द्र विज्ञान नगर के क्रमोन्नत होने के उपरान्त सर्जन, मेडिसिन (एमडी), मेडिकल ऑफिसर आदि चिकित्साकर्मियों की नियुक्ति के संबंध में चर्चा के लिए।

200. कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज के सम्बद्ध चिकित्सालयों में सीमून्लेटर लेब, रॉबोटिक सर्जरी, इन्टरवेशन कैथ लैब की स्थापना, 128 स्लाइस सीटी स्केन मशीन फोर कार्डिक आदि की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिए।

201. विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण में स्थित बरड़ा बस्ती, क्रेशर बस्ती, बालाकुंड, श्रीनाथपुरम सी, दुर्गा बस्ती, घोड़ा बस्ती में आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

202. कोटा में आदर्श सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दादाबाड़ी (कोटा) स्वीकृत होने के बाद भी स्टाफ की स्वीकृति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

<u>श्री विनोद कुमार (वि.सं.153)</u>

203. पीलीबंगा में ट्रोमा सैंटर एवं रावतसर में उप जिला अस्पताल बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री थावर चन्द (वि.सं.75)</u>

204. प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

205. कोविड स्वास्थ्य सहायकों (सीएचए) एवं सभी चिकित्सा संविदाकर्मियों को स्थाई करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री उमेश मीणा (वि.सं.23)

206. विधान सभा क्षेत्र आसपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामगढ़ में एम्बुलेंस उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

207. विधान सभा क्षेत्र आसपुर के स्टेट रोड़ उदयपुर पर बने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आसपुर को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

208. विधान सभा क्षेत्र आसपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, दोवड़ा का नया भवन बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

209. विधान सभा क्षेत्र आसपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, साबला में मोर्चरी की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिए।

210. विधान सभा क्षेत्र आसपुर के प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टरों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (वि.सं.13)

211. विधान सभा क्षेत्र कपासन के प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उप जिला चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पदों पर पदस्थापन करने के संबंध में चर्चा के लिए।

212. विधान सभा क्षेत्र कपासन के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आक्या, भीमगढ़ तथा सोनियाना के भवन निर्माण हेतु बजट उपलब्ध कराने तथा भूमि आवंटन के संबंध में चर्चा के लिए।

213. विधान सभा क्षेत्र कपासन के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राशमी हेतु नवीन भवन बनाने के लिए बजट उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

214. उप जिला चिकित्सालय, कपासन तथा मण्डपिया में नवीन भवन बनाने के लिए बजट उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री बहादुर सिंह (वि.सं.99)

215. राजकीय चिकित्सालय, वैर तथा भुसावर में मरीजों हेतु आवश्यक कूलर एवं अन्य सुविधाओं हेतु बजट दिए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

216. राजकीय चिकित्सालय, वैर के चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री बहादुर सिंह (वि.सं.99)

217. राजकीय चिकित्सालय, वैर तथा भुसावर में स्त्री रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

सुश्री नौक्षम (वि.सं.86)

218. राजकीय चिकित्सालय, कामां में नवजात शिशुओं हेतु नर्सरी इकाई बनाए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

219. विधान सभा क्षेत्र कामां के ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्त चिकित्सकों के पदों को भरे जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

220. विधान सभा क्षेत्र कामां के चिकित्सालयों में मरीजों हेतु कूलर, वाटर कूलर सहित मूलभूत सुविधाएं दिए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

221. विधान सभा क्षेत्र कामां में ट्रोमा सेन्टर बनाए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

डॉ. ऋतु बनावत (वि.सं.24)

222. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रूदावल को मॉडल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

223. बयाना एवं रूपवास के क्रमोन्नत हुए जिला अस्पतालों की वित्तीय स्वीकृतियां जारी किए जाने तथा मिल्समा, पुरामालोनी, वीरमपुरा, थानाडांग, दाहिना गांव जारोली में स्थित सब सेन्टर को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

224. रूपवास, रूदावल, बंशी पहाड़पुर स्थित जटमासी, पिनउना, कोट कपुरामलूका में डॉक्टर्स एवं नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

225. बयाना के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बन्द बारेठा को क्रमोन्नत किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

226. भरतपुर-धौलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटनाओं से हो रही मौतों को रोकने हेतु रूपवास में ट्रोमा सेन्टर स्थापित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ताराचन्द जैन (वि.सं.74)

227. उदयपुर शहर हिरणमगरी में स्थित स्व. श्री खेमराज कटारा राजकीय सैटेलाईट चिकित्सालय में मरीजों की संख्या को देखते हुए चिकित्सालय में द्वितीय तल बनाने हेतु बजट की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

228. उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय में रिक्त पदों के साथ कैंसर के डॉक्टर ऑनकोलोजिस्ट एवं स्व. श्री सुन्दर सिंह भंडारी सैटेलाईट चिकित्सालय, अम्बामाता के साथ स्व. श्री खेमराज कटारा सैटेलाईट चिकित्सालय, हिरणमगरी में नवसृजित रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

229. उदयपुर शहर में महाराणा भूपाल चिकित्सालय में महिला चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु डीएमएफटी फण्ड/बजट उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री ताराचन्द जैन (वि.सं.74)

230. उदयपुर में स्थित महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय, चेटक के पास पशु चिकित्सालय की भूमि को चिकित्सा महाविद्यालय को हस्तान्तरित कर पशु चिकित्सालय को एवज में बड़ी में स्थित टी.बी. हॉस्पिटल के पास पड़ी चिकित्सा महाविद्यालय की भूमि पर हस्तान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

231. उदयपुर में महाराणा भूपाल चिकित्सालय हेतु एक और एमआरआई की मशीन उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री अरूण चौधरी (वि.सं.11)</u>

232. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के जिला अस्पताल, बालोतरा में पीपीपी मोड पर सीटी एवं एमआरआई की सेवा प्रारम्भ करने एवं अस्पताल में सर्जरी एवं डेन्टल में काम आने वाले उपकरणों को दिलाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

233. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा की ग्राम पंचायत, कालूड़ी, देरिया, मूल की ढाणी, नेवरी, कुड़ी एवं उपरलाई रोड़वा में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

234. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चान्देसरा, धोब, टापरा एवं आसोतरा में भवन की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

235. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के उप स्वास्थ्य केन्द्र रणिया देशीपुरा, गंगावास एवं अन्य उप स्वास्थ्य केन्द्रों के जर्जर भवनों की मरम्मत अथवा नया भवन बनाने की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

236. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के राजस्व ग्राम खेतलानाड़ी, सुथारों की ढाणी, जया नगर, ग्वालनाड़ा, बादू का बाड़ा, पोशाल नगर एवं बोको की ढाणी पारलू में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री गोविन्द प्रसाद (वि.सं.48)</u>

237. विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जावर को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

238. विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

239. विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

240. विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री भैरा राम चौधरी (सियोल) (वि.सं.108)</u>

241. विधान सभा क्षेत्र ओसियां के संचालित सरकारी अस्पतालों में स्वीकृत पदों में से रिक्त पदों पर चिकित्सा अधिकारियों एवं कार्मिकों को पदस्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

242. विधान सभा क्षेत्र ओसियां के राजकीय सैटेलाईट अस्पताल, मथानिया, उप जिला अस्पताल, ओसियां तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बावड़ी में ट्रोमा सेन्टर खोलने की घोषणा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री भैरा राम चौधरी (सियोल) (वि.सं.108)</u>

243. विधान सभा क्षेत्र ओसियां के अन्तर्गत संचालित भवन विहीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए भवन निर्माण स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

244. विधान सभा क्षेत्र ओसियां के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डावंटा एवं ब्लॉक बावड़ी को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

245. प्रदेश में विभाग के चयनित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों एफएसओ को अविलम्ब नियुक्ति प्रदान करने तथा इनके रिक्त स्थानों पर प्रतिनियुक्ति पर लगे लैब तकनीशियन कार्मिकों को रिक्त चल रहे मूल पदों के लिए तुरन्त कार्यमुक्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री कालीचरण सराफ (वि.सं.30)</u>

246. प्रदेश के जोधपुर, फलौदी, पाली, जैसलमेर, जालोर, सिरोही एवं बाड़मेर जिलों के 59 ब्लॉक में मोबाईल मेडिकल एम्बुलेंस बन्द करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

247. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में परबतसर ब्लॉक, जिला नागौर में वर्ष 2016 से नियुक्त रिहैबिलिटेशन वर्कर को वर्ष 2021 में पांच वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् भी अब तक लॉयल्टी बोनस नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

248. मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना की दवाइयों के समय पर क्रय नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

249. प्रदेश में फिजियोथैरेपी चिकित्सकों के कैडर का पुर्नगठन, स्टाफिंग पैटर्न में संशोधन एवं उक्त का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पद सृजन तथा इंटर्नशिप शुल्क माफी तथा स्टाईपेंड देने के संबंध में चर्चा के लिए।

250. प्रागपुरा, जिला कोटपूतली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए दिए गए भवन को स्वास्थ्य केन्द्र बन्द होने के उपरान्त भी विभाग द्वारा खाली नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

<u>श्री अमित चाचाण (वि.सं.8)</u>

251. राजकीय उप जिला चिकित्सालय, नोहर में स्वीकृत ब्लड बैंक का संचालन शुरू करवाने एवं अल्ट्रासांउड जांच मशीन व सीटी स्कैन जांच मशीन की स्थापना करवाए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

252. विधान सभा क्षेत्र नोहर में सेठ फकीर चंद लाल चंद कन्दोई शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नोहर को शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र या सैटेलाईट हॉस्पिटल में क्रमोन्नत किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

253. विधान सभा क्षेत्र नोहर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुईया, मन्दरपुरा एवं धानसिया को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र मालासर, जबरासर, थालड़का, रतनपुरा एवं दलपतपुरा को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

254. विधान सभा क्षेत्र नोहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र फेफाना के जर्जर व पुराने भवन की जगह नए भवन का निर्माण एवं बैडों की संख्या 30 से बढ़ाकर 50 किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अमित चाचाण (वि.सं.8)

255. राजकीय उप जिला चिकित्सालय, नोहर को जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने, बैड़ों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 करने एवं चिकित्सालय भवन का शेष निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु तीस करोड़ रूपए स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री सुखवंत सिंह (वि.सं.65)

256. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में स्थित छह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से किसी में भी महिला रोग विशेषज्ञ तथा अन्य विशेषज्ञ का पदस्थापन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

257. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाम्बोली को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने तथा बूंटोली एवं पांटा में नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

258. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जांच उपकरणों के अभाव में हो रही असुविधा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

259. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को आदर्श सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने तथा इसके भवन निर्माण हेतु राशि आवंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राम सहाय वर्मा (रेगर) (वि.सं.132)

260. विधान सभा क्षेत्र निवाई के प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य केन्द्र तथा बड़ी आबादी वाले ग्रामों में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

261. निवाई उप जिला अस्पताल के लिए भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त भी भवन निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

262. प्रदेश में चिकित्सकों का पृथक कैडर बनाने, चिकित्सकों को चतुर्थ डीएसीपी 9500 ग्रेड-पे देने तथा चिकित्सा शिक्षकों के समान चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री केसाराम चौधरी (वि.सं.35)

263. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खारची हेतु 50 बैड की स्वीकृति जारी करने के संबंध में चर्चा के लिए।

264. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खारची के जर्जर भवन के स्थान पर नया भवन बनाए जाने की स्वीकृति जारी करने के संबंध में चर्चा के लिए।

265. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खारची में सर्जन, फिजीशियन, शिशु विशेषज्ञ, चिकित्सा अधिकारी एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ के सभी रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

266. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खारची में डायलेसिस मशीन उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री पूसाराम गोदारा (वि.सं.91)

267. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के जिला अस्पताल एवं आदर्श सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजलदेसर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पडिहारा एवं दाउदसर में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने, जांच हेतु मशीनें तथा आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाने, उप स्वास्थ्य केन्द्र, सीतसर और लोहा को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करवाने, ग्राम प्रेम नगर में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करवाने तथा जिला अस्पताल का स्वीकृत भवन निर्माण कार्य शुरू करवाने एवं जर्जर तथा भवन विहीन उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण की स्वीकृति जारी करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री पब्बाराम विश्नोई (वि.सं.87)

268. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

269. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

270. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र, शेखासर को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गणेशराज बंसल (वि.सं.40)

271. हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर संचालित राजकीय जिला चिकित्सालय में मुख्य भवन के नव निर्माण पर चर्चा के लिए।

272. हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर संचालित राजकीय जिला चिकित्सालय में मुख्य भवन की बैड क्षमता 200 से 300 एवं एम.सी.एच. यूनिट की बैड क्षमता 50 से 100 किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

273. विधान सभा क्षेत्र हनुमानगढ़ की ग्राम पंचायत चौहिलांवाली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु स्वीकृति जारी किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री धर्मपाल (वि.सं.83)

274. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जसरापुर एवं बसई को क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

275. उप जिला अस्पताल, खेतड़ी को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

276. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के उप स्वास्थ्य केन्द्र, रामकुमारपुरा को क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

277. उप जिला अस्पताल, खेतड़ी में ट्रोमा सेन्टर की स्थापना करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री धर्मपाल (वि.सं.83)</u>

278. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के नव क्रमोन्नत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेहाड़ा में तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बबाई में एक्स-रे मशीन तथा सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री देवेन्द्र जोशी (वि.सं.82)</u>

279. जोधपुर के भीतरी शहर के बहुत ही उपयोगी सेटेलाइट अस्पताल, नवचौकिया में स्वीकृत भवन विस्तार कार्यों की तकनीकी बाधाओं को दूर कर कार्य सम्पादित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

280. जिला अस्पताल प्रताप नगर, जोधपुर को स्तर अनुरूप पूर्ण क्षमता से कार्यशील बनाकर इसे मुख्य अस्पतालों के मजबूत विकल्प के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

281. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के सभी सेटेलाइट अस्पतालों में मानक के अनुरूप समस्त पदों को भरकर एवं संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कर इनके 24 घण्टे खुलने एवं क्रियाशील अस्पताल और संस्थागत प्रसव केन्द्र के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

282. कार्यालय संयुक्त निदेशक एवं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर में विभागीय शिकायतों, संविदाकर्मियों के विरूद्ध शिकायतों, विभागीय जांचों के जानबूझकर लंबित रखने की कार्यपद्धति में सुधार के लिए कठोरतम उपायों को लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

283. प्रदेश में विभागीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं के निरीक्षकों के विरूद्ध लंबित शिकायतों, विभागीय जांच एवं भ्रष्टाचार प्रकरणों का निस्तारण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री बालमुकुन्दाचार्य (वि.सं.102)</u>

284. विधान सभा क्षेत्र हवामहल के राजकीय चिकित्सालय, गंगापोल का भवन निर्माण कराने तथा सेटेलाइट चिकित्सालय, करबला हेतु भूमि आवंटन कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

285. जयपुर के पण्डित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, गणगौरी बाजार में विशेषज्ञ चिकित्सकों का पदस्थापन तथा लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

286. विधान सभा क्षेत्र हवामहल के पण्डित दीनदयाल उपाध्याय, गणगौरी हॉस्पिटल में स्मार्ट सिटी के तहत कराये गये कार्यों में अनियमितताओं की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

287. विधान सभा क्षेत्र हवामहल के जयसिंहपुरा खोर में घोषित सेटेलाइट अस्पताल को रूपा की नांगल (आदर्श नगर) में किये जाने के प्रस्ताव को निरस्त कर जयसिंहपुरा खोर में ही बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (वि.सं.62)

288. विधान सभा क्षेत्र मकराना के उप जिला चिकित्सालय में तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बोरावड़, गच्छीपुरा, बुडसू आदि में विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने तथा एएनएम, नर्सिंग ऑफिसर व फार्मासिस्ट के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (वि.सं.62)

289. विधान सभा क्षेत्र मकराना के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिण्डालिया (मकराना) का भवन निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

290. विधान सभा क्षेत्र मकराना के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मनाना, बेसरोली व रानीगांव को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

291. विधान सभा क्षेत्र मकराना के उप स्वास्थ्य केन्द्र, सबलपुर, इन्द्रोखा, बाजोली, सरनावड़ा, डोबड़ीकलां, रामसिया बिंगालिया, खारडिया, सफेद बड़ी, बरवाली व आसरवा को क्रमोन्नत करने एवं दीपनगर, शिवरासी, धान्धोली, अखैपुरा, सफेद छोटी, ऊचेरिया व रामपुरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

292. उप जिला चिकित्सालय, मकराना में ट्रोमा सेन्टर, मदर एण्ड चाईल्ड केयर यूनिट एवं गम्भीर बिमारियों की जांच व इलाज के लिए एनसीडी क्लिनिक खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (वि.सं.84)

293. विधान सभा क्षेत्र तारानगर के गांव रतनपुरा व पिचकाई ताल के उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

294. विधान सभा क्षेत्र तारानगर के उप जिला अस्पताल में अनियमित दवाई वितरण व जांच बाहर से कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

295. विधान सभा क्षेत्र तारानगर के तारानगर शहर के उप जिला अस्पताल के निर्माण में हो रही देरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

296. उप जिला अस्पताल, तारानगर में डॉक्टर्स की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

297. उप जिला अस्पताल, तारानगर तथा सी.एच.सी, ददरेवा व भालेरी में मरीजों को हो रही परेशानी के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) (वि.सं.113)

298. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के रामपुरा, चादगोठी, हमीरवास व पहाड़सर की पीएचसी को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

299. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर की सभी पीएचसी एवं सीएचसी में चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

300. प्रदेश में डायलिसिस मशीन को उपयोग में लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

301. राज्य कर्मचारी को आरजीएचएस में सम्पूर्ण भुगतान करने के संबंध में चर्चा के लिए।

302. प्रदेश में नर्सिंग अधिकारी की नितांत आवश्यकता एवं रिक्त पदों को देखते हुए उनकी वार्षिक अभिवृद्धि जारी रखने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मण राम (वि.सं.141)

303. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के ग्राम बेड़ास खुर्द, धोलेराव कलां, थाट एवं ग्राम पीथास में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

304. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के उप स्वास्थ्य केन्द्र, भैंसड़ा कलां, मेतड़िया, लांबा जाटान, मोररा एवं लाडवा को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मण राम (वि.सं.141)

305. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रियाबड़ी में 30 बैड अस्पताल को 50 बैड़ अस्पताल में क्रमोननत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती गीता बरवड़ (वि.सं.41)

306. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के उप जिला चिकित्सालय, भोपालगढ़ में अव्यवस्थाओं एवं रिक्त पदों को भरने, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बावड़ी एवं आसोप को ट्रोमा सेन्टर में क्रमोन्नत करने, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सालवा कलां, खवासपुरा व सोयला को क्रमोन्नत करने तथा उप स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

डॉ. सुभाष गर्ग (वि.सं.178)

307. भरतपुर शहर में संचालित सेटेलाइट अस्पताल के भवन निर्माण की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

308. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के अवरा, बरसों, विलोठी व घुस्यारी में पीएचसी की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

309. भरतपुर के वहनेरा में सीएचसी के नये भवन के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विकास चौधरी (वि.सं.148)

310. राजकीय यज्ञनारायण अस्पताल, किशनगढ़ के जिला अस्पताल भवन निर्माण में हो रही देरी के संबंध में चर्चा के लिए।

311. राजकीय यज्ञनारायण हॉस्पिटल, किशनगढ़ में डॉक्टरों की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री चेतन पटेल कोलाना (वि.सं.53)</u>

312. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के प्रेमपुरा, तहसील दीगोद में राजस्व विभाग द्वारा आवंटित भूमि पर कोर्ट स्टे हटवा कर उप स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

313. कोटा मेडिकल कॉलेज के सहयोग से सीएचसी, सुल्तानपुर में बंद पड़ी सोनोग्राफी मशीन को चालू करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

314. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा की सीएचसी, खातोली को आदर्श सीएचसी बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

315. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के ग्राम बगतरी में उप स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

316. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के ग्राम बडौद पीएचसी पर एम्बुलेंस लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री रफीक खान (वि.सं.123)</u>

317. जयपुर की काजी का नला डिस्पेन्सरी के पास आबादी का घनत्व बढ़ने के कारण इसे 30 बैड का अस्पताल में कनवर्ट करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री रफीक खान (वि.सं.123)</u>

318. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर के ट्रांसपोर्ट नगर में डिस्पेन्सरी खोलने, जनता क्लिनिक की जगह वन विहार में 30 बैड का अस्पताल खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री देवी सिंह शेखावत (वि.सं.81)</u>

319. प्रदेश में दवा वितरण केन्द्रों पर संख्या के अनुपात में फार्मासिस्ट लगाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

320. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नारायणपुर व हरसौरा में ट्रोमा सेन्टर या प्राईमरी ट्रोमा सेन्टर की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिए।

321. उप जिला अस्पताल, बानसूर में ब्लड बैंक खोलने व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नारायणपुर में स्टोरेज यूनिट की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिए।

322. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में संचालित चिकित्सा संस्थानों में नर्सिंग पैरा मेडिकल, फार्मासिस्ट आदि के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

323. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में संचालित चिकित्सा संस्थानों में विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री लादु लाल पितलिया (वि.सं.144)</u>

324. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के उपखण्ड रायपुर मुख्यालय पर उप जिला चिकित्सालय को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

325. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के सेटेलाइट चिकित्सालय, गंगापुर में मानक अनुसार चिकित्सा अधिकारी एवं कर्मचारियों के पद एवं जांचों की संख्या में वृद्धि किए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में चर्चा के लिए।

326. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों ऑर्थोपेडिक, ऑप्थल्मलॉजिस्ट, जनरल मेडिसन, जनरल सर्जन, एनेस्थेसिया, ईएनटी आदि के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

327. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (वि.सं.126)

328. विधान सभा क्षेत्र शिव में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, शिव एवं गड़रा रोड़ को क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

329. राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवस्थित उपखण्ड मुख्यालय शिव पर आपातकालीन परिस्थितियों में तत्काल सहायता हेतु ट्रोमा सेन्टर की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिए।

330. विधान सभा क्षेत्र शिव के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में रिक्त चल रहे मेडिकल एवं पैरा मेडिकल संवर्ग के पदों को भरे जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

331. विधान सभा क्षेत्र शिव में चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता हेतु खोड़ाल, हेमानाडा, सुवाला, मणिहारी, धोलिया, अंबावाड़ी, रामदेवपुरा, सालमसिंह की बस्ती, करनाणियों का पार व जुडिया में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं नींबला, मुंगेरिया, नागड़दा, हड़वेचा, आरंग, देवका, बंधड़ा, खबडाला, सुंदरा, इंद्रोई, घोनिया व उपरला के उप स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

332. विधान सभा क्षेत्र शिव में चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता हेतु उण्डू, गिराब, जैसिंधर गांव, सियाणी व केलनोर पीएचसी को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री ललित यादव (वि.सं.143)

333. शाहजहानुपुर अलवर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्टाफ लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

334. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मुण्डावर (अलवर) एवं शाहजहानुपुर में ट्रोमा सेन्टर खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

335. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के नीमराणा, शाहजहानुपुर, मुण्डावर तथा करतारपुरा के स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

डॉ. सुभाष गर्ग (वि.सं.178)

336. भरतपुर में जिला चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

337. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में एक और जिला जनाना अस्पताल खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री सुरेश गुर्जर (वि.सं.176)

338. विधान सभा क्षेत्र खानपुर की विभिन्न सीएचसी/पीएचसी में लगाये गये संविदाकर्मी/ठेकाकर्मियों की नियुक्ति में अनियमितताओं की जॉच किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डॉ. विश्वनाथ मेघवाल (वि.सं.155)

339. विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला की ग्राम पंचायत 34 केवाईडी लूणखां, कानासर नाल व खरा के उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

340. विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला के उप जिला अस्पताल, खाजूवाला एवं एसडीएच पूगल में चिकित्सकों एवं पेरा मेडिकल के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

डॉ. शैलेश सिंह (वि.सं.164)

341. विधान सभा क्षेत्र डीग-कुम्हेर के खण्ड डीग में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कौरेर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं खण्ड कुम्हेर की पीएचसी पपरेरा को सीएचसी में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

342. विधान सभा क्षेत्र डीग-कुम्हेर में खण्ड डीग के उप स्वास्थ्य केन्द्र, सोनगांव को पीएचसी एवं खण्ड कुम्हेर के उप-स्वास्थ्य केन्द्र लांकी एवं तालफरा को पीएचसी में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हंसराज पटेल (वि.सं.187)

343. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में न्यूरोलोजिस्ट, कार्डियोलाजिस्ट एवं कैंसर विशेषज्ञ के नवीन पद स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

344. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के बीडीएम जिला अस्पताल को 300 बैडों में क्रमोन्नत कर सीटी स्कैन एवं एमआरआई मशीनों की स्वीकृति जारी करने के संबंध में चर्चा के लिए।

345. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली स्थित ग्राम कुहाडा-कल्याणपुरा में नवीन सब सेन्टर स्वीकृत करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

346. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के सब सेन्टर भुरी-भडाज को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लालाराम बैरवा (वि.सं.145)

347. जिला अस्पताल, शाहपुरा में कार्डियोलॉजी (हृदय) विभाग की ईकाई (यूनिट) खोलने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

348. शाहपुरा (भीलवाड़ा) में बनने वाले ट्रोमा सेन्टर बिल्डिंग की वित्तीय स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

349. शाहपुरा उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित जिला चिकित्सालय में ब्लड बैंक नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

350. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के राजकीय अस्पतालों में डॉक्टरों एवं अन्य नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

351. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) के सभी चिकित्सालय केन्द्रों पर चलने वाले आयुष्मान केन्द्रों पर वर्तमान में योग केन्द्रों का संचालन बंद होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री जेठानन्द व्यास (वि.सं.66)

352. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर-पश्चिम के प्रत्येक वार्ड में आरोग्य आयुष मन्दिर खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

353. प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी को राजस्थान संविदा सेवा नियम 2022 के अन्तर्गत मानदेय में वृद्धि करने के संबंध में चर्चा के लिए।

354. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर-पश्चिम में डिस्पेन्सरी नं. 3 को (माहेश्वरी भवन के पास) क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

355. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर-पश्चिम में डिस्पेन्सरी नं. 2 (भुजिया बाजार) का जीर्णोद्धार करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री विद्याधर सिंह (वि.सं.152)

356. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के उप स्वास्थ्य केन्द्र, सिणोदिया को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

357. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के उप स्वास्थ्य केन्द्र, कोरसीना को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

358. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के उप स्वास्थ्य केन्द्र, खण्डेला को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

359. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के उप स्वास्थ्य केन्द्र, पचकोडीया को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री विरेन्द्र सिंह (मसूदा) (वि.सं.154)

360. उप जिला चिकित्सालय, मसूदा में स्वीकृत पदों पर चिकित्सकों का पदस्थापन करने के संबंध में चर्चा के लिए।

361. विधान सभा क्षेत्र मसूदा के खरवा व जालिया-II मसूदा, नागोला व देवलिया-भिणाय पीएचसी को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

362. उप जिला चिकित्सालय, मसूदा हेतु भवन निर्माण की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मोतीराम (वि.सं.120)

363. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के विभिन्न उप जिला चिकित्सालयों, सीएचसी, पीएचसी व उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सा अधिकारियों व पैरा मेडिकल स्टाफ के विभिन्न रिक्त पदों को शीघ्र भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

364. रेवदर की सीएचसी के वर्तमान भवन को राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित ग्राम पंचायत लूणोल के गांव राजगढ में पूर्व में आवंटित ट्रोमा सेन्टर की भूमि पर स्थानान्तरित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

डॉ. शिखा मील बराला (वि.सं.162)

365. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में गोविन्दगढ़ सीएचसी पर जनरल फिजीशियन डॉक्टर की नियुक्ति किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मोतीराम (वि.सं.120)

366. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मेडिसिन, सर्जरी व अस्थि रोग विशेषज्ञों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कालूराम (वि.सं.31)

367. विधान सभा क्षेत्र डग में उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

368. विधान सभा क्षेत्र डग में सभी उप स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

369. विधान सभा क्षेत्र डग में उप स्वास्थ्य केन्द्र, उमरिया को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

370. विधान सभा क्षेत्र डग में मिश्रोली, आवर, उन्हेल व नागेश्वर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (वि.सं.136)

371. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के स्वास्थ्य केन्द्र, केसरपुरा, राजगढ, देराठू, लोहखाडा व पिचोलिया को क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

372. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जेठाना, करनोल व गोविन्दगढ़ को क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

373. राजकीय चिकित्सालय नसीराबाद में ट्रोमा सेंटर विकसित किये जाने, चिकित्सकों के रिक्त पदों एवं सोनोग्राफर के पद पर नियुक्ति दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

374. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, करनोस के नवीन भवन का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती शोभारानी कुशवाह (वि.सं.166)

375. विधान सभा क्षेत्र धौलपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की व्यवस्थाओं पर चर्चा के लिए।

<u>डॉ. शिखा मील बराला (वि.सं.162)</u>

376. उप जिला अस्पताल, चौमूं में नई 3-डी कलर डॉपलर सोनोग्राफी मशीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

377. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में कालाडेरा सीएचसी पर जनरल फिजीशियन डॉक्टर की नियुक्ति किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

378. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में कालाडेरा सीएचसी पर स्त्री रोग विशेषज्ञ लम्बे समय से नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

379. उप जिला अस्पताल, चौमूं में नई एक्स-रे मशीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री भगवाना राम सैनी (वि.सं.104)</u>

380. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी (झुंझुनूं) की सीएचसी को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

381. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी (झुंझुनूं) की सीएचसी एवं पीएचसी में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

382. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी (झुंझुनूं) की सीएचसी में ट्रोमा सेन्टर का सुचारू रूप से संचालन करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री भागचन्द टांकड़ा (वि.सं.106)</u>

383. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

384. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में कार्यरत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पद आईएफएमएस पोर्टल पर स्वीकृत नहीं होने के संबंध में चर्चा के लिए।

385. प्रदेश के निजी चिकित्सालयों में कार्यरत कार्मिकों को अनुभव के अंक प्रदान करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

386. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती सुशीला रामेश्वर डूडी (वि.सं.185)</u>

387. विधान सभा क्षेत्र नोखा के तहसील मुख्यालय नोखा पर स्वीकृत जिला चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु निविदा जारी कर यथाशीघ्र जिला भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ किये जाने व चिकित्सकों व चिकित्साकर्मियों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री कैलाशचन्द्र मीणा (वि.सं.37)</u>

388. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में नव क्रमोन्नत उप जिला चिकित्सालय, परतापुर के भवन निर्माण की वित्तीय स्वीकृति जारी करने एवं झोलाछाप डाक्टरों के खिलाफ कार्यवाही करने के संबंध में चर्चा के लिए।

389. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में पीएचसी बोरी, आंजना, चिडियावाला व कोहाला को सीएचसी में क्रमोन्नत करने एवं गढ़ी के समस्त सीएचसी व पीएचसी में डाक्टरों के रिक्त पद भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (वि.सं.37)

390. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी के उप जिला चिकित्सालय, परतापुर एवं ब्लॉक चिकित्सा गढ़ी, तलवाडा, अरथुना एवं समस्त सीएचसी, पीएचसी में वर्ष 2020 से 2024 तक विभिन्न प्रकार के स्वीकृत बजट में भ्रष्टाचार एवं अनियमितता की जांच के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री शंकरलाल डेचा (वि.सं.158)

391. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा के दीनदयाल सामुदायिक चिकित्सालय में ब्लड बैंक इकाई के स्टाफ की नियुक्ति के संबंध में चर्चा के लिए।

392. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा के दीनदयाल राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय के ट्रोमा सेन्टर में चिकित्सकों के रिक्त पद भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

393. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा के दीनदयाल राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय में 300 बैड की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में चर्चा के लिए।

394. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में पीएचसी पाडवा व चितरी को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री दर्शनसिंह (वि.सं.77)

395. विधान सभा क्षेत्र करौली के उप स्वास्थ्य केन्द्र, ताली को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

396. विधान सभा क्षेत्र करौली की सीएचसी, मासलपुर को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

397. विधान सभा क्षेत्र करौली की पीएचसी, फतेहपुर, ब्लाक मासलपुर को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

398. करौली सेटेलाईट हॉस्पीटल की बैड़ क्षमता में वृद्धि करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती अनीता जाटव (वि.सं.06)

399. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन सिटी के कुदावल व महमदपुर में मेडिकल स्टॉफ लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

400. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन सिटी में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने, जिला चिकित्सालय हिण्डौन सिटी में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

401. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन सिटी की सीएचसी, महावीरजी व सूरोठ में रिक्त पदों को भरने व हिण्डौन सिटी के खरेटा रोड़ पर पीएचसी खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अमीन कागजी (वि.सं.09)

402. जयपुर शहर में अनाधिकृत दवाओं की बिक्री एवं मेडिकेटेड नशे की दवाईयों की बिक्री में लगातार हो रही वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

परिशिष्ट 2

अनुदान की मांग संख्या 28 - चिकित्सा शिक्षा पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों

मांग संख्या–28 मुख्य शीर्षक चिकित्सा शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रूपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (वि.सं.94)

1. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में राजकीय मेडिकल कॉलेज खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री शंकरसिंह रावत (वि.सं.159)

2. जिला मुख्यालय ब्यावर में मेडिकल कॉलेज खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

डॉ. जसवंत सिंह यादव (वि.सं.61)

3. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में नर्सिंग कॉलेज खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।
4. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में मेडिकल कॉलेज खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।
5. प्रदेश में बढ़ते निजी चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालय की फीस से अभिभावकों पर बढ़ रहे आर्थिक भार को रोकने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।
6. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के बहरोड़ शहर में राजकीय पैरा-मेडिकल/फॉर्मेसी/डेंटल डिप्लोमा विषय के शिक्षण संस्थान खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
7. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में आयुर्वेद विज्ञान/होम्योपैथिक/यूनानी विज्ञान महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हमीर सिंह भायल (वि.सं.190)

8. सिवाना उप जिला अस्पताल में पर्याप्त भवन उपलब्ध होने से जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
9. नवसृजित जिला बालोतरा में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
10. सिवाना में नर्सिंग कॉलेज खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
11. जोधपुर स्थित एम्स (एआईआईएमएस) में जनप्रतिनिधियों को प्राथमिकता से चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री विक्रम सिंह जाखल (वि.सं.150)

12. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के जिला अस्पताल में प्रतिदिन 2500 की ओ.पी.डी. तथा 150 बैड स्वीकृत होने से राजकीय नर्सिंग कॉलेज स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (वि.सं.193)

13. विधान सभा क्षेत्र भीम में नर्सिंग कॉलेज खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री ललित मीना (वि.सं.142)

14. प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा हेतु मेडिकल कॉलेजों में एम.ओ. को शिक्षक लगाने एवं राजमेस द्वारा इंटरव्यू (साक्षात्कार) के माध्यम से सहायक आचार्य लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (वि.सं.54)

15. प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की घोषणा के अनुरूप जालोर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
16. आहोर में नर्सिंग कॉलेज के भवन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
17. आहोर में नवीन नर्सिंग कॉलेज एवं जी.एन.एम. सेन्टर की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिये।
18. आहोर में स्थित नर्सिंग कॉलेज में छात्रावास कार्य शीघ्र पूर्ण करने के संबंध में चर्चा के लिये।
19. आहोर में पैरामेडिकल कोर्स की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (वि.सं.51)

20. चित्तौड़गढ़ मेडिकल कॉलेज में कैंसर यूनिट एवं बर्न यूनिट की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिए।
21. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के मेडिकल कॉलेज को स्नातक से स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हरिमोहन शर्मा (वि.सं.192)

22. बून्दी जिले में मेडिकल कॉलेज का भवन, हॉस्टल और आवासों के निर्माण को शीघ्र पूर्ण करने के संबंध में चर्चा के लिए।
23. बून्दी मेडिकल कॉलेज में विभिन्न श्रेणी के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री संजय कुमार (वि.सं.169)

24. धौलपुर जिले के मेडिकल कॉलेज में एकेडमिक व नॉन एकेडमिक फैकल्टी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती कल्पना देवी (वि.सं.28)

25. कोटा के मेडिकल कॉलेज में स्नात्तक, स्नातकोत्तर एवं सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों की सीटों में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
26. कोटा में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय के तहत दन्त महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती कल्पना देवी (वि.सं.28)

27. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में नर्सिंग कॉलेज खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

28. कोटा के मेडिकल कॉलेज से संबंद्ध चिकित्सालयों में शैय्यायें बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
29. कोटा के मेडिकल कॉलेज से संबंद्ध चिकित्सालयों में भौतिक सुविधाओं से वंचित कार्यों की कमी को पूर्ण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री घनश्याम (वि.सं.50)</u>

30. करौली जिले के मेडिकल कॉलेज में रिक्त पदों को भरने व अत्याधुनिक सुविधायुक्त बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।
31. जयपुर स्थित एसएमएस मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्थाओं से उत्पन्न स्थिति एवं आरयूएचएस को एआईआईएमएस की तर्ज पर रिम्स आरआईआईएमएस बनाने व रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।
32. प्रदेश के सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।
33. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में राजकीय नर्सिंग कॉलेज खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>डॉ. प्रियंका चौधरी (वि.सं.96)</u>

34. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में स्थित राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय में पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग डिग्री कोर्स प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री समरजीत सिंह (वि.सं.174)</u>

35. प्रदेश में पूर्व बजट घोषणानुसार मेडिकल कॉलेज का कार्य प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री श्रवण कुमार (वि.सं.167)</u>

36. झुंझुनूं मेडिकल कॉलेज में पूर्ण स्टाफ व अन्य सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती अनिता भदेल (वि.सं.04)</u>

37. अजमेर के जेएलएन में कैंसर रोगियों के उपचार हेतु ऑकोलॉजिस्ट और ऑकोसर्जन लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

38. जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अजमेर के जीर्ण-शीर्ण भवन के नवनिर्माण हेतु चरणबद्ध रूप से 300 सौ करोड़ की राशि उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
39. जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अजमेर में किडनी रोगियों के उपचार हेतु नेफ्रोलॉजिस्ट लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती अनिता भदेल (वि.सं.04)</u>

40. अजमेर स्थित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में सन् 2015 से स्थापित सीटीवीएस में हार्ट की बाईपास सर्जरी प्रारम्भ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

41. जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अजमेर में रोगियों की सुविधा हेतु एम.आर.आई, पीईटी, सीटी स्कैन, डेक्सा स्कैन व यूरो माइक्रोस्कोप नवीन उपकरण उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री उदयलाल भडाणा (वि.सं.22)</u>

42. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेज, पालड़ी का कार्य जल्दी पूर्ण कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

43. भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज में सीटों की बढ़ोतरी करने के संबंध में चर्चा के लिए।

44. विधान सभा क्षेत्र माण्डल के करेड़ा में नर्सिंग कॉलेज खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री लक्ष्मण (वि.सं.140)</u>

45. प्रदेश में संचालित चिकित्सा शिक्षा संस्थानों के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री डूंगरराम गेदर (वि.सं.72)</u>

46. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में नर्सिंग कॉलेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री बाबूसिंह राठौड (वि.सं.101)</u>

47. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के बालेसर उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

48. डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

49. राजकीय एवं राजमेस चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रवेश की सीटों की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री रूपिन्द्र सिंह कुन्नर (वि.सं.200)</u>

50. विधान सभा क्षेत्र करणपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग स्टॉफ के पैटर्न अनुसार पद स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

51. विधान सभा क्षेत्र करणपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज का परिसर छोटा होने के कारण उसके विस्तार हेतु भूमि आवंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

52. राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीगंगानगर में विशेषज्ञ डॉक्टर का पदस्थापन करने के संबंध में चर्चा के लिए।

53. राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीगंगानगर में गम्भीर रोगों के इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री आदू राम मेघवाल (वि.सं.19)</u>

54. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में चौहटन उपखण्ड मुख्यालय पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री गोपीचन्द मीणा (वि.सं.46)</u>

55. जहाजपुर में नर्सिंग कॉलेज खुलवाने एवं प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में रिक्त पदों पर भर्ती करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री युनूस खान (वि.सं.121)</u>

56. नवगठित जिला मुख्यालय डीडवाना में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय (मेडिकल कॉलेज) खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

57. नवगठित जिला मुख्यालय डीडवाना में राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

58. नवगठित जिला मुख्यालय डीडवाना में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय (मेडिकल कॉलेज) के लिए भूमि का आवंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री जब्बर सिंह सांखला (वि.सं.57)</u>

59. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के आसीन्द शहर में मेडिकल कॉलेज की घोषणा करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री अशोक कुमार कोठारी (वि.सं.17)</u>

60. भीलवाड़ा स्थित विजियाराजे सिंधिया राजकीय मेडिकल कॉलेज में रिक्त पद फॉर्माकोलॉजी फैकल्टी आदि भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

61. भीलवाड़ा स्थित विजियाराजे सिंधिया राजकीय मेडिकल कॉलेज के छात्रावास में फर्नीचर व अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिए।

62. भीलवाड़ा स्थित विजियाराजे सिंधिया राजकीय मेडिकल कॉलेज लाइब्रेरी में बुक्स उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

63. भीलवाड़ा स्थित विजियाराजे सिंधिया राजकीय मेडिकल कॉलेज में मंत्रालयिक कर्मचारियों (एलडीसी एण्ड यूडीसी) के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

64. भीलवाड़ा स्थित विजियाराजे सिंधिया राजकीय मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री हरलाल सहारण (वि.सं.191)</u>

65. विधान सभा क्षेत्र चुरू के राजकीय मेडिकल कॉलेज में रिक्त पदों को भरने एवं निर्माण कार्यों के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री अर्जुन लाल (वि.सं.12)</u>

66. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में बिलाड़ा शहर/नगरपालिका पीपाड़शहर में पैरामेडिकल स्टाफ फार्मासिस्ट, लेब टैक्नीशियन नर्सिंग, बीएससी-नर्सिंग के लिए राजकीय/निजी शिक्षण कॉलेज/स्कूल संस्थान खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

67. प्रदेश में चिकित्सकों की कमी को देखते हुए जोधपुर स्थित एस.एन. मेडिकल कॉलेज/मारवाड़ मेडिकल विश्वविद्यालय में एम.बी.बी.एस. हेतु सीटों को बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री अतुल भंसाली (वि.सं.03)</u>

68. प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की सीटें बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

69. प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम रोग प्रतिरक्षा विषय पर शोध प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करने और इनसे प्राप्त निष्कर्षों के प्रचार-प्रसार की व्यापक योजना बनाकर क्रियान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

70. प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों से संलग्न चिकित्सालयों में आपातकालीन इकाइयों के केवल मात्र रेजीडेन्ट के भरोसे संचालन और वरिष्ठ चिकित्सकों के ड्यूटी पर उपस्थित नहीं होने के कारण आपातकालीन इकाइयों में उत्पन्न हो रही गंभीर जन-असंतोष की स्थितियों को रोकने के लिए कार्ययोजना बनाकर समयबद्ध क्रियान्वयन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

71. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर एवं संलग्न चिकित्सालयों में गत छः वर्ष में लगाये गये ठेका कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया, ठेका कर्मियों के ड्यूटी रोस्टर, ठेका कर्मियों को निजी कार्यों में लगाने, ठेका कर्मियों के भ्रष्टाचार प्रकरणों की लिप्तता की स्थितियों की उच्च स्तरीय जांच करवा कर विभागीय अधिकारियों/कार्मिकों के विरूद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

72. प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों से संलग्न चिकित्सालयों में ऐलोपैथी पद्धति पर अत्यधिक दबाव को समायोजित करने के लिए आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी आदि चिकित्सा पद्धतियों की उपचार सुविधा प्रत्येक चिकित्सालय स्तर पर अनिवार्यता से उपलब्ध कराने की समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री श्रीचन्द कृपलानी (वि.सं.168)</u>

73. उप जिला चिकित्सालय, छोटी सादड़ी, जिला प्रतापगढ़ में जीएनएम/एएनएम ट्रेनिंग सेन्टर की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

74. राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय, निम्बाहेड़ा में विभिन्न श्रेणी के सभी पदों पर पर्याप्त कार्मिक उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

75. जिला चिकित्सालय निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ में जीएनएम/एएनएम ट्रेनिंग सेन्टर की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (वि.सं.80)</u>

76. राजमेस द्वारा संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी के संबंध में चर्चा के लिए।

77. राजकीय एवं राजमेस चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रवेश की सीटों की संख्या में वृद्धि करने के संबंध में चर्चा के लिए।

78. राजसमन्द जिला मुख्यालय पर राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

79. राजसमन्द जिला मुख्यालय पर दन्त चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

80. राजसमन्द जिला मुख्यालय पर राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री संदीप शर्मा (वि.सं.172)</u>

81. कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज परिसर में नर्सिंग महाविद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

82. कोटा में फॉर्मेसी कॉलेज खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

83. कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज में स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री विनोद कुमार (वि.सं.153)</u>

84. हनुमानगढ़ जिले के एमबीबीएस कॉलेज में व्याप्त समस्याओं के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री उमेश मीणा (वि.सं.23)</u>

85. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर जिले के आसपुर में नर्सिंग कॉलेज खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री अर्जुन लाल जीनगर (वि.सं.13)</u>

86. जिला मुख्यालयों पर संचालित मेडिकल कॉलेजों में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>डा. ऋतु बनावत (वि.सं.24)</u>

87. भरतपुर के आरबीएम हॉस्पीटल के पास ही डॉक्टर्स एवं स्टाफ के लिए आवासीय परिसर निर्मित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

88. भरतपुर मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशियलिटी फैकल्टी न्यूरोकॉर्डियों, नेफ्रो व गैस्ट्रो में नियुक्ति किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

89. भरतपुर संभाग केन्द्र पर स्थित श्री जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज में सर्जरी, ओर्थो, गाइनिक, शिशु रोग, नाक-कान-गला, नेत्र रोग में पीजी खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

90. रूपवास में नर्सिंग महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री आदू राम मेघवाल (वि.सं.19)</u>

91. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में नर्सिंग महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री अरूण चौधरी (वि.सं.11)</u>

92. प्रदेश के समस्त मेडिकल कॉलेजों का एक कैडर बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

93. बाड़मेर मेडिकल कॉलेज का दायरा बढ़ाते हुए जिला अस्पताल, बालोतरा को बाड़मेर अथवा जोधपुर मेडिकल कॉलेज के अन्तर्गत रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

94. जयपुर स्थित आरयूएचएस अस्पताल को एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अन्तर्गत रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

95. बालोतरा में नवीन मेडिकल कॉलेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कालीचरण सराफ (वि.सं.30)

96. जयपुर के राजकीय जयपुरिया अस्पताल में चिकित्सकों व नर्सिंगकर्मियों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

97. जयपुर के एस.एम.एस. अस्पताल में बिना टेण्डर पार्किंग चलाने से सरकार को हुए नुकसान से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

98. जयपुर के एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज के सम्बद्ध चिकित्सालयों में नवजात स्क्रीनिंग व प्रसव पूर्व स्क्रीनिंग सुविधा उपलब्ध करवाने तथा प्रदेश में एन.बी.एस. कार्यक्रम चलाने पर चर्चा के लिए।

99. जयपुर के एस.एम.एस. अस्पताल में गलत खून चढ़ाने की जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने पर चर्चा के लिए।

100. एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर के संलग्न चिकित्सालयों में खराब उपकरणों को समय पर ठीक करवाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अमित चाचाण (वि.सं.08)

101. प्रदेश के निजी चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा मेडिकल छात्रों से मनमानी फीस वसूली पर अंकुश लगाने व फीस निर्धारण में एकरूपता लाने के संबंध में चर्चा के लिए।

102. कोविड-19 के दौरान जन स्वास्थ्य (पब्लिक हैल्थ) के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के 07 संभाग मुख्यालयों पर जन स्वास्थ्य में स्नातकोत्तर (एमपीएच) संस्थान की स्थापना व संचालन पर चर्चा के लिए।

103. प्रदेश में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों के निर्माण की प्रगति लक्ष्य के अनुरूप नहीं होने के कारण एवं लक्ष्य के क्रम में हुई निर्माण की भौतिक प्रगति पर चर्चा के लिए।

104. विधान सभा क्षेत्र नोहर में राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय स्थापित करवाए जाने पर चर्चा के लिए।

105. प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में सभी संवर्गों में एनएमसी के मापदण्ड अनुसार स्वीकृत पद, कार्यरत पदों का विवरण तथा रिक्त पदों को भरने पर चर्चा के लिए।

श्री सुखवंत सिंह (वि.सं.65)

106. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के ढाढोली में नर्सिंग कॉलेज का भवन निर्मित होने के उपरांत भी संचालित नहीं करने पर चर्चा के लिए।

107. प्रदेश के राजमेस के अन्तर्गत संचालित मेडिकल कॉलेज में मैस संचालकों द्वारा खाने की गुणवता अच्छी नहीं होने तथा अत्यधिक चार्जेज वसूलने पर चर्चा के लिए।

श्री राम सहाय वर्मा (रेगर) (वि.सं.132)

108. टोंक में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिए।

डॉ. शिखा मील बराला (वि.सं.162)

109. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में राजकीय नर्सिंग कॉलेज खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गणेशराज बंसल (वि.सं.40)

110. विधान सभा क्षेत्र हनुमानगढ़ में जिला मुख्यालय पर नवनिर्मित राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, हनुमानगढ़ में बुनियादी एल.ओ.पी. फर्नीचर उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

111. विधान सभा क्षेत्र हनुमानगढ़ में जिला मुख्यालय पर नवनिर्मित राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, हनुमानगढ़ में एनाटोमी एवं फार्माकोलॉजी विषय के प्रोफेसर लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मपाल (वि.सं.83)

112. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में राजकीय नर्सिंग कॉलेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

113. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में राजकीय पैरामेडिकल कॉलेज खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र जोशी (वि.सं.82)

114. प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजेज् एवं संलग्न चिकित्सालयों में चिकित्सा शिक्षकों/चिकित्सकों/कार्मिकों के विरूद्ध शिकायतों, विभागीय जांचों को जानबूझकर लंबित रखने की कार्यपद्धति में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

115. प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों के आचार्यों/सह-आचार्यों/विशेषज्ञों/वरिष्ठ चिकित्सकों के आपातकालीन और ट्रोमा सेन्टर में रोस्टर से ड्यूटी लगाने और लगाई गई ड्यूटी अनुसार उनकी उपस्थिति पूरे समय रहने की अनिवार्यता लागू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

116. प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों के रेडियोलॉजी विभागों से सुझाव प्राप्त कर इनके प्रभावी संचालन करने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

117. प्रदेश में कैंसर रोग के कारणों पर विशिष्ट शोध कर इस रोग से बचने के कैंसर रोग प्रतिरक्षण जन चेतना विकसित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) (वि.सं.113)

118. मेडिकल कॉलेज, चुरू में रिक्त प्रोफेसर के पद को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में राजकीय नर्सिंग कॉलेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

120. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में मेडिकल कॉलेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

121. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में डीएमसीटी कोर्स के लिए राजकीय कॉलेज या संस्थान खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती गीता बरवड़ (वि.सं.41)

122. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के मेडिकल कॉलेज में अध्यापकों का पदस्थापन एवं बिना पोलिसी स्थानान्तरण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रफीक खान (वि.सं.123)

123. प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मनमानी फीस वसूलने पर रोक लगाकर गरीब आदमी का एडमिशन रियायती दर पर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री देवी सिंह शेखावत (वि.सं.81)

124. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में फॉर्मासिस्ट कॉलेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

125. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में पैरामेडिकल कॉलेज खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

126. कोटपूतली-बहरोड़ जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने के संबंध में चर्चा के लिये।

127. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में राजकीय जीएनएम या एएनएम ट्रेनिंग सेन्टर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लादू लाल पितलिया (वि.सं.144)

128. प्रदेश में नव नियुक्त चिकित्सकों को एक वर्ष पश्चात चिकित्सा शिक्षा विभाग में प्रतिनियुक्ति नहीं दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (वि.सं.126)

129. विधान सभा क्षेत्र शिव में नवीन मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज एवं डी. फार्मा कॉलेज स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

130. जोधपुर संभाग के समस्त मेडिकल महाविद्यालयों में चल रहे रिक्त पदों को भरने एवं आवश्यकतानुसार नवीन पद सृजित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

131. जोधपुर संभाग के समस्त मेडिकल महाविद्यालयों में कार्यरत आचार्य व सह आचार्यों को महाविद्यालय परिसर में ही रहने हेतु सुविधा उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

132. प्रदेश में कार्यरत सभी विदेशी स्नातक चिकित्सा उत्तीर्ण छात्रों को मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप के दौरान स्टाईफण्ड भत्ता प्रदान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डॉ. सुभाष गर्ग (वि.सं.178)

133. भरतपुर मेडिकल कॉलेज में विभिन्न विशेषज्ञ सेवाओं में पी.जी. कोर्स शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री ललित यादव (वि.सं.143)</u>

134. मुण्डावर में नर्सिंग महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री सुरेश गुर्जर (वि.सं.176)</u>

135. मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय, झालावाड़ में संविदा कर्मियों की नियुक्ति में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की जांच कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

136. मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय, झालावाड़ की बेड क्षमता बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

137. मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय, झालावाड़ में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की सीटें बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

138. मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय, झालावाड़ में परम विशेषज्ञ सेवाओं को बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

139. मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय, झालावाड़ में विभिन्न रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री हंसराज पटेल (वि.सं.187)</u>

140. जिला मुख्यालय, कोटपूतली पर मेडिकल कॉलेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री लालाराम बैरवा (वि.सं.145)</u>

141. भीलवाड़ा के शाहपुरा में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

142. भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति को भी मेडिकल कॉलेज के पाठ्यक्रम में जोड़े जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

143. प्रदेश में निजी व सरकारी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स में ड्रग्स व नशाखोरी की लत को रोकने हेतु प्रभावी मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री मनोज कुमार (सुजानगढ) (वि.सं.112)</u>

144. सुजानगढ़ में नर्सिंग कॉलेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री विद्याधर सिंह (वि.सं.152)</u>

145. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में नर्सिंग कॉलेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री भगवाना राम सैनी (वि.सं.104)</u>

146. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी (झुंझुनूं) में ब्लॉक स्तर पर नर्सिंग कॉलेज खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री कैलाशचन्द्र मीणा (वि.सं.37)</u>

147. जिला बांसवाड़ा के मेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग कॉलेज में नवीन भवनों के कार्य पूर्ण कर नवीन भवनों में प्रशिक्षण प्रारम्भ करने एवं पदों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री थावर चन्द (वि.सं.75)

148. विधान सभा क्षेत्र धरियावद में नवीन नर्सिंग कॉलेज खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

149. प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों में फीस में रियायत कराने तथा एक मुश्त फीस लेने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।